{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 13 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

नागरिक उठायें विश्व शांति के पक्ष में आवाज़

मंगलवार को प्रकाशित हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसके अनुसार हाल में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 56 संघर्ष हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पिछले लगभग 8 दशकों में इतनी अधिक अशांति कभी नहीं रही। यह रिपोर्ट आंकड़ों में प्रकाशित हुई है लेकिन ऐसी अशांति दुनिया को किस ओर ले जा रही है, यह बतलाने की ज़रूरत नहीं। इन संघर्षों के कारण होती तबाही से विकास पीछे रह जाता है। रिपोर्ट दुनिया भर में शांति बहाली के नये प्रयासों की जरूरत को भी दर्शाती है। संघर्षों में एक ओर देशों को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेनाओं, गोला-बारूद आदि पर खर्च करना पड़ता है जिसके कारण नागरिकों की सुविधाओं में कटौतियां होती हैं। विस्थापन, मौतें, भुखमरी, बीमारियां, अशिक्षा आदि युद्धों का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, आवास व्यवस्थाएं या तो सीधी लड़ाइयों में बर्बाद होती हैं अथवा उन पर खर्च करना उन देशों की सरकारों के लिये कठिन हो जाता है जो संघर्षों में शामिल होते हैं। वैश्विक शांति के बिना मानव के विकास और उसकी गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह स्थिति सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ लोग लड़ाइयों के चलते विस्थापित हुए हैं या शरणार्थी शिविरों में जीवन जी रहे हैं।

रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 92 देशों की सीमाओं पर या तो युद्ध जारी हैं अथवा वहां युद्ध सदृश्य परिस्थितियां हैं। 97 देशों में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज की गयी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के तीन चौथाई देशों ने रक्षा बजट में व्यापक बढ़ोतरी की है। वहां पिछले दो वर्षों से अशांति बनी हुई है। ऐसे ही, इज़रायल के साथ फिलीस्तीन, ईरान आदि की लड़ाइयों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हजारों लोग मारे गये हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इन युद्धों के कारण अधोरचना का विनाश सर्वाधिक होता है। सड़कें, पुल, स्कूल भवन, अस्पताल, आवासों को जो क्षति होती है वह नागरिकों का सीधा नुकसान है। युद्ध चलते तक पुनर्निर्माण सम्भव नहीं होता और युद्ध रूकने के बाद देशों को बदहाली से उबरने में वर्षों लग जाते हैं। युद्ध के कारण माली हालत जर्जर हो जाती है। इन देशों के नागरिकों को अपना जीवन बदहाली में काटना होता है। अशांति का असर किस प्रकार से लोगों के जीवन पर पड़ता है वह इस तथ्य के आधार पर आंका जा सकता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़ाइयों के कारण 19 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है जो दुनिया की जीडीपी का 13.5 फीसदी है- अमूनन प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये का नुकसान।

इन स्थितियों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अक्सर माना जाता है; और जो बड़े पैमाने पर सही भी है कि बड़े व शक्तिशाली देशों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का बस नहीं चलता। उपरोक्त उल्लिखित दोनों ही देशों में ऐसा होता दिखा है। यहां यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि बहुत से शक्तिशाली देश हथियार उत्पादक भी हैं जिनकी दिलचस्पी शांति में कम युद्ध या तनाव की स्थिति को बनाये रखने में होती है। दुनिया में चाहे शीत युद्ध समाप्त हो गया हो और विश्व एकध्रुवीय बन गया हो तब भी किसी संघर्ष या युद्ध के दौरान देखा जाता है कि दुनिया दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। कुछ देश लड़ाई में शामिल एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो कुछ दूसरे पक्ष के साथ। लड़ाई हो या न हो, परन्तु तनाव की यह स्थिति भी शक्तिशाली व हथियार निर्माता देशों के मुफ़ीद होती है। लड़ने के लिये अथवा सुरक्षा के मद्देनज़र उनके हथियार बिकते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं तटस्थ देशों की शांति की अपीलों को अनसुना कर कई देश तनाव को बढ़ाने के प्रयास करते हैं।

इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वह कुछ सुकून भरी हो सकती है। पिछली रिपोर्ट के बाद भारत एवं उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की रैंकिंग सुधरी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरी दुनिया कहे जाने वाले एशियाई, अफ्रीकी व लातिन अमेरिका के अविकसित व विकासशील देशों को अशांति का खामियाजा अधिक भुगतना पड़ता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक तरह से निष्क्रिय हो जाने के बाद भारत की ओर से शांति की पहल होनी बन्द हो गयी है वरना इन परिस्थितियों में उसकी सुनी जाती थी। आंदोलन के पीछे महात्मा बुद्ध के पंचशील तथा महात्मा गांधी के अहिसा व शांति का संदेश होता था। आज भी इन दोनों के साथ जवाहरलाल नेहरू की बातें वैश्विक शांति के सन्दर्भ में प्रासंगिक बनी हुई हैं।

दुनिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाना हो तो सर्वप्रथम वैश्विक शांति ज़रूरी है। इसके लिये सभी देशों को संयम बरते जाने की ज़रूरत है। जो देश हथियारों के सौदागर हैं पहले वे ही युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं और अंततः युद्ध कराकर अपने हथियार बेचते हैं। अच्छी-खासी तबाही कराकर वे युद्ध रूकवा देते हैं। इसके बाद उन देशों में निर्माण कार्यों के ठेके आदि लेते हैं। देखें तो युद्ध एक कुटिल अर्थप्रणाली का हिस्सा है जिससे कुछ देश ही लाभान्वित होते हैं और ज्यादातर तबाह। कभी धर्म तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर होती लड़ाइयां सरकारों के लिये तो लाभप्रद हो सकती हैं पर नागरिकों की भलाई वैश्विक शांति में ही निहीत है। इसलिये शांति के पक्ष में जनता को आवाज उठानी चाहिये। देशों के बीच परस्पर सौहार्द्र व भाई-चारा ज़रूरी है। इसके लिये सम्पूर्ण निःशस्त्रीकरण और असैन्यीकरण अंतिम उपाय हैं।

मोहन भागवत ने जो कहा और जो नहीं कहा

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

एनडीए सरकार के गठन को जुम्मा-जुम्मा आठ दिन भी नहीं हुए कि अभी से इसमें बिखराव की खबरें आने लगीं हैं। तेदेपा और जदयू जैसे दलों के सहारे इस बार की एनडीए सरकार खड़ी हुई है। इसलिए इन दलों को मोदी की बैसाखी कहा जा रहा है। एक भी बैसाखी अलग हुई नहीं कि सरकार लड़खड़ा जाएगी या गिर जाएगी, यह राजनीति के जानकारों का कहना है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अतीत में एनडीए सरकार के साथ ऐसा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी भी तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन तीन में से दो बार उनकी सरकार गिर गयी थी, एक बार 13 दिन और एक बार 13 महीने में। केंद्र और राज्यों में कई उदाहरण मौजूद हैं, जब गठबंधन सहयोगियों के अचानक अलग हो जाने के कारण अच्छी-खासी चल रही सरकार गिर गई और सत्ताधारियों को विपक्ष में बैठना पड़ा। बिहार इसका ताजातरीन उदाहरण है, जहां नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देकर भाजपा का साथ दे दिया। हरियाणा में भी ऐसा होने के कयास लग रहे थे, लेकिन वहां अब तक भाजपा की सरकार कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब केन्द्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। वे संघ के दिनों के नरेन्द्र मोदी के साथी हैं, लिहाजा उन्हें यथोचित सम्मान मिल गया। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान को जब मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया, तो सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। संघ की शाखाओं में दीक्षित शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से जीत कर संसद पहुंचे और अब वे भी मंत्रिमंडल में सुशोभित कर दिए गए हैं।

तीसरी बार भाजपा नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार में संघ का क्या प्रभाव है, यह बात इन दो उदाहरणों से समझी जा सकती है। गठबंधन के साथी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी या रामदास अठावले इस प्रभाव से अनजान हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्हें भी शायद अब तक इससे तकलीफ नहीं है, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए जो थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, वे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि कब तक आपसी समझदारी दिखाई जाती रहेगी, यह सवाल अब भी अनुत्तरित ही हैं।

बहरहाल, सत्ता गठन के लिए किए गए समझौतों की इस पृष्ठभूमि में संघ के प्रभाव के साथ-साथ उसके उद्देश्यों को समझना कठिन नहीं है। हाल ही में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं, जिनसे इस बात को थोड़े और खुलासे के साथ समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने चुनावों में जनता के समर्थन के लिए मंगलवार को आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि वे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से 'मोदी का परिवार' का नारा हटा लें। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने जब परिवार के महत्व पर अपने भाषण में नरेन्द्र मोदी को घेरते हुए कहा था कि अपनी मां के देहांत के बाद भी उन्होंने बाल नहीं मुंडवाए थे, तो इसके जवाब में श्री मोदी ने पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार बताया था और फिर भाजपा नेताओं समेत कई मोदी समर्थकों ने सोशल मीडिया में अपनी पहचान में मोदी का परिवार लिखना शुरु कर दिया था। अब नरेन्द्र मोदी उन्हें इस पहचान को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। यह काफी अजीब बात है कि कोई परिवार किसी मकसद के पूरा हो जाने के बाद खत्म करने के लिए कहा जाए। क्या सनातनी संस्कृति को मानने वाले इस बात से सहमत होंगे कि परिवार कांट्रैक्ट के आधार पर बने और फिर खत्म भी हो जाए।

> सरकार गठन और मोदी का परिवार खत्म होने की हलचलों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में दिए एक भाषण में कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनके बाद यह कहा जाने लगा कि संघ और भाजपा के बीच दरार और बढ़ गई है। दरअसल मोहन भागवत ने मणिपुर में एक बरस से अधिक वक्त से जारी हिंसा का समाधान ढूंढने और शांति बहाली पर जोर दिया।

राजनीति में कुछ भी अकारथ नहीं होता, इसलिए नरेन्द्र मोदी की इस अपील के पीछे असल मकसद क्या है, यह शायद भविष्य में पता चले। एक अन्य आश्चर्य वाली बात यह है कि भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट में मार्गदर्शक मंडल विभाग में चार तस्वीरें हैं, जिनमें सबसे पहली तस्वीर नरेन्द्र मोदी की है, फिर लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी और फिर राजनाथ सिंह। 2014 में जब मार्गदर्शक मंडल बना था, तब भी नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम तो इनमें शामिल था, लेकिन इसका उल्लेख कभी नहीं किया जाता था। जिनकी आयु 75 पार की हो गई है, वे इसमें शामिल होंगे, यह सामान्य समझ थी। श्री मोदी अगले बरस 75 के होंगे और राजनाथ सिंह उनसे एक साल छोटे हैं। फिर इन दो नेताओं की तस्वीरें किसलिए भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शोभायमान हो रही हैं, यह भी चर्चा का विषय है।

सरकार गठन और मोदी का परिवार खत्म होने की हलचलों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में दिए एक भाषण में कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनके बाद यह कहा जाने लगा कि संघ और भाजपा के बीच दरार और बढ़ गई है। दरअसल मोहन भागवत ने मणिपुर में एक बरस से अधिक वक्त से जारी हिंसा का समाधान ढूंढने और शांति बहाली पर जोर दिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनसे आभास हुआ कि ये सब नरेन्द्र मोदी को नसीहत देने के लिए कहा गया है। जैसे, श्री भागवत ने कहा कि एक 'सेवक' को अपने काम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे 'असंबद्ध' और 'अहंकार से रहित' होना चाहिए। यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को नसीहत है या खुद को देश का प्रधानसेवक कहने वाले श्री मोदी को, यह स्पष्ट नहीं किया गया। फिर चुनाव परिणामों को सहजता से स्वीकार करके, उसके विश्लेषण के चक्कर में न पड़ने की राय देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि चुनावों को 'युद्ध' की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है और वह परिणामों के विश्लेषण में नहीं उलझता। संभवतः मोहन भागवत का आशय यह था कि श्री मोदी कितने वोट से हार से बच गए और भाजपा की कहां, कितनी सीटें कम हुईं, या राम मंदिर का मुद्दा काम क्यों नहीं आया, हिंदुत्व की धार भोथरी क्यों पड़ी, इस पर माथापच्ची करने से बेहतर है कि संघ जिस तरह जनमत को परिष्कृत यानी जनता की मानसिकता को प्रभावित करने का काम उसे पूर्ववत करता रहे, बल्कि उसमें तेजी लाए, ताकि इस बार जो कसर रह गई, वो अगली बार पूरी हो जाए।

ध्यान रहे कि अगले साल यानी 2025 में संघ की स्थापना के सौ बरस पूरे हो रहे हैं। जिस भारत को बनाने में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, उसकी आजादी के 75 बरस को जब श्री मोदी ने राजनैतिक फायदे के लिए इतना भुनाया, वो भला संघ की शताब्दी के अवसर को सूखे में कैसे जाने दें। इसलिए अभी से संघ और नरेन्द्र मोदी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यह मान ही लेना चाहिए। वैसे भी संघ इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा है। अक्टूबर 2022 में उप्र में संघ की चार दिन की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया था कि '2024 के अंत तक देश के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है, इसके अलावा संघ कार्य को लेकर समय देने के लिए देशभर में तीन हज़ार युवक शताब्दी विस्तारक के लिए निकल चुके हैं और एक हज़ार शताब्दी विस्तारक और निकलने वाले हैं।'

यह बात दो साल पहले की है, तो इसका मतलब कम से कम पांच-सात हजार विस्तारक यानी पूर्णकालिक प्रचारक की जगह अपने काम के साथ-साथ संघ का प्रचार करने वाले लोग देश भर में निकले होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हर घर अक्षत बांटने का काम ऐसे ही नहीं हुआ है।

इसलिए जे पी नड्डा का बयान कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है, या मोहन भागवत की मणिपुर और चुनाव को लेकर दी गई ताजा नसीहत या यह मानना कि इस बार भाजपा की सीटें कम हुईं क्योंकि संघ ने उसका साथ नहीं दिया, दरअसल एक छलावे से अधिक कुछ नहीं है। कार्पोरेट की मदद से नरेन्द्र मोदी को 2014 में सत्ता पर बिठाने में संघ ने सफलता हासिल की। उसके बाद राम मंदिर उद्घाटन, काशी-मथुरा पर नए सिरे से माहौल बनाना, जम्मू-कश्मीर से 370 का खात्मा और सांप्रदायिक वैमनस्य की खाई को और चौड़ा करने तक अपने कई एजेंडो को संघ ने पूरा किया। इन्हीं दस सालों में नाथूराम गोडसे को महान बताने वाले संसद पहुंचे। गोडसे और सावरकर पर फिल्में बनाकर जनमत को परिकृष्त करने का काम भी हुआ। गांधी के चश्मे को स्वच्छता अभियान के कचरे में डाल दिया गया और नरेन्द्र मोदी ने एक बार भी गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहा। इसका मतलब यही है कि संघ अब भी सत्ता में बैठे लोगों के लिए पहले जितना ही प्रासंगिक है।

अपने भाषण में मोहन भागवत ने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हुई हैं हमने अर्थव्यवस्था, रक्षा रणनीति, खेल, संस्कृति, प्रौद्योगिकी आदि जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति की है। और साथ में डॉ. आंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प आवश्यक है।

मोहन भागवत ने क्या कहा और लोगों को क्या समझाना चाहा, यह सब गड्ड-मड्ड है। लेकिन संघ का हिंदू राष्ट्र वाला उद्देश्य तो जनता जानती ही है। जिन लोगों ने गणेशजी को दूध पिलाने की अफवाह में एक झटके में पूरे देश को लपेट लिया था, उनके लिए अपने मकसद को जनता के बीच फैलाना क्या मुश्किल होगा। बस अबकी बार जनता को और सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस संविधान और लोकतंत्र को इस बार बचा लिया गया, अब उसकी रक्षा करना और ज्यादा जरूरी हो गया है, इस बार पंजे, नाखून सब छिपे हुए हैं।

रियासी आतंकी हमला दर्शाता है अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की सीमाएं

■ आशीष बिस्वास

सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

जो भी स्पष्टीकरण हो, सरकार की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और न ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में खालिस्तानी समर्थक के जीतने की संभावना पर विचार किया था। यहां तक कि एक नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन को देखते हुए एक नरम आधिकारिक प्रतिक्रिया भी राजनीतिक चर्चाओं को शांत करने में मदद कर सकती थी।

सच तो यह है कि अमृतपाल सिंह की जीत ने भारत सरकार को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नीति निर्माता नई दिल्ली में 'एनडीए गठबंधन' स्थापित करने में व्यस्त थे। बदलाव मुश्किल नहीं था, लेकिन ध्यान बंटाया नहीं जा सकता था। नयी एनडीए सरकार को काम पर लगना था और भाजपा के वर्चस्व वाले प्रशासन के पास खालिस्तानी समर्थकों के लिए समय नहीं था।

> एनडीए को इस मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, शत्रुतापूर्ण चीन और अविश्वासी पश्चिमी देशों के समूह का सामना करते हुए, उसे अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए काम तय है। खालिस्तानियों द्वारा पेश की गयी चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृतपाल सिंह ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 2,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जो पंजाब में सबसे अधिक है।

इसके अलावा, नयी सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की आतंकवादी हत्या, जहां अभी-अभी चुनाव हुए थे, उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, एक स्पष्ट चेतावनी थी कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर नहीं थी। आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

आतंकी हमले का समय सावधानी से चुना गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन 'नयी' नरेंद्र मोदी सरकार की परीक्षा लेना चाहते थे। यह भारत के खिलाफ एक स्पष्ट रूप से भड़काऊ कार्रवाई थी। जब पुलवामा हुआ, तो मोदी ने जोरदार तरीके से बात की थी और नियंत्रण रेखा के पार बालाकोट पर विनाशकारी जवाबी हमले का आदेश दिया था। उस समय मोदी की पार्टी भाजपा के पास लोकसभा की 543सीटों में से 303 सीटें थीं। आज स्थिति अलग है। भाजपा ने 63 सीटें खो दी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसके पास केवल 240 सीटें हैं। क्या मोदी 3.0 सीमा पार से उकसावे से निपटने की स्थिति में है?

रियासी आतंकी हमला एक अनूठी चुनौती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी बार स्थापित मोदी सरकार को प्रतिक्रिया देने में इतना समय लग गया। रिकॉर्ड के लिए, यह केवल पाकिस्तान ही नहीं है, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश भी यह जानना चाहेंगे कि नयी एनडीए सरकार विशिष्ट परेशानियों के खिलाफ कैसे काम करती है।

कांग्रेस ने रियासी की घटना की निंदा की है। लेकिन सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करना वाकई कारगर रहा? मोदी की कार्यशैली से परिचित अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत सरकार अपना समय और स्थान चुनकर प्रभावी ढंग से जवाब देगी।

रियासी हमले में पाकिस्तान (या आईएसआई) की संलिप्तता स्थापित की जानी है। लेकिन खालिस्तानी भारत विरोधी आंदोलन को इसके समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो, अमृतपाल सिंह के साथ क्या किया जाना चाहिए? कनाडा या यू.के. में सिख अलगाववादियों की भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि -भारतीय मिशनों, सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों को निशाना बनाना- एक क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है जिसे बहुत पहले तैयार किया गया था।

पर्यवेक्षकों का कहना है कि इमरान खान शासन के दौरान कुछ साल पहले पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिख तीर्थयात्रियों की आवाजाही और उनके लिए पवित्र करतारपुर साहिब स्थल पर जाने की सुविधा के लिए उदारीकरण किया गया था, जो खालिस्तान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोलकाता के कुछ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत सरकार को खालिस्तानी भारत विरोधी कूटनीतिक हमले के फिर से शुरू होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह स्थान भारत की सीमा के बहुत करीब है, इसलिए भारत के लिए यह सुविधाजनक स्थिति नहीं है।

सिखों के लिए नियमों में ढील दिए जाने से खालिस्तानी समर्थक तत्वों सहित भारतीय सिखों की संख्या में वृद्धि हुई है। केनेडा और अन्य जगहों पर भारत सरकार/भारतीय राजनयिकों के सामने आने वाली चुनौतियों ने पहले व्यक्त की गयी आशंकाओं की पुष्टि की है। वास्तव में ब्रिटेन, केनेडा या अमेरिकी राजनयिकों के एक वर्ग में खालिस्तानियों के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन भारत के लिए एक रहस्योद्घाटन, एक दर्दनाक सीखने के अनुभव से कम नहीं है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के लिए अपने सभी दिखावटी समर्थन के बावजूद, पश्चिम ने भारतीय राजनीतिक संस्थानों, इसकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, इसके आम चुनावों, इसके मानव संसाधन रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों को संभालने के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त करना कभी बंद नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों और भाजपा की ताकत में उल्लेखनीय गिरावट को लेकर पश्चिमी मीडिया के बड़े हिस्से के बीच आम तौर पर संतुष्ट स्वर में कोई गलती नहीं हो सकती है। स्पष्ट रूप से, भारत एशिया में एक क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन यह भारतीय नेताओं या उनके राजनीतिक दलों के लिए उन्नत पश्चिम के मुकाबले 'अहंकारी' होने के लिए ठीक नहीं होगा!

एनडीए को इस मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, शत्रुतापूर्ण चीन और अविश्वासी पश्चिमी देशों के समूह का सामना करते हुए, उसे अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए काम तय है। खालिस्तानियों द्वारा पेश की गयी चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटना होगा।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृतपाल सिंह ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 2,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जो पंजाब में सबसे अधिक है। इसके अलावा, सिंह संसदीय चुनाव जीतने वाले एकमात्र अलगाववादी नहीं हैं। इंजीनियर राशिद, एक अन्य अलगाववादी, ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीता। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद में जो बात समान है, वह यह है कि दोनों का भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है।

पावन प्रसंग

समय को साधें, जीवन को संवारें

अधिकांश लोग समय का महत्व नहीं समझते व इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, जिससे प्रमुख बाधाएं कुछ इस तरह से रहती है- समय के मूल्य को नहीं समझ पाना, प्राथमिकताओं का तय नहीं होना, काम को टालते जाना, एक समय पर बहुत से कार्य हाथ में लेना, असफल या गलती होने से भयभीत होना, कार्यस्थल पर अव्यवस्था का होना, ना न कह पाना, बिगड़ी जीवनशैली व आदतें होना आदि। समय के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए समय प्रबंधन से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अपने समय की बर्बादी की तह तक जाएं। सबसे पहले देखें कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। जब यह समझ में आएगा कि कौन सी चीज आपके समय व ऊर्जा को चौपट कर रही है, जिसके कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य कल पर टल रहे हैं, आपके जीवन में आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा, सतत आपात की स्थिति बनी हुई है और जीवन नरक बनता जा रहा है, तो आप इनको चिन्हित कर इनका सहज समाधान कर सकते हैं।

सभी को दिन भर में 24 घंटे मिले हैं, जिसका हर पल मिलकर दिवस बनता है और समय का हर पल नदी के प्रवाह की भांति निरंतर गतिशील है, जो सतत प्रवाहमान है, जो कभी रुकता नहीं। इसको यदि संभाला नहीं गया तो यह हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। सामान्यतया इंसान उपलब्ध समय के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे उसके पास अनंत समय हो, परंतु समय बीत जाने पर फिर वह पश्चाताप करता है। वास्तव में मनुष्य के पास जो यथार्थ वर्तमान ही होता है। वह जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, या बनना चाहता है, वह इस वर्तमान का सदुपयोग करते हुए ही संभव हो पाता है। इस तरह हर सुबह नए दिन के शुभारंभ का अवसर होता है, जिसमें हम दिन के श्रेष्ठतम उपयोग का खाका भली प्रकार खींच सकते हैं और हर रात दिन भर की उपलब्धियों के साथ भूलों-चूकों की समीक्षा व सुधार करते हुए अगले दिन को और बेहतर बनाने का सुअवसर होता है और दिन का हर पल इसके सदुपयोग के साथ दिन के श्रेष्ठतम उपयोग को करने का अवसर होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को संवार कर परमलक्ष्य को साध सकें।

इस तरह आने वाले कल का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह वर्तमान पर ही आधारित रहता है। बीत गए भूतकाल का भी अधिक महत्व नहीं। जो कुछ भी है वह वर्तमान है, जो हमारे हाथ में रहता है। यदि हम सफलचा व प्रसन्नता का सपना देखते हैं, तो हमें आज अभी से हर पल इसके लिए प्रयासरत रहना होगा तथा दिन के प्रत्येक घंटे, मिनट व पल का सदुपयोग करते हुए जीवन सी सकल संभावनाओं को यथाशीघ्र साकार करना होगा। अधिकांश लोग समय का महत्व नहीं समझते व इसका उपयोग नहीं कर पाते, जिसमें प्रमुख बाधाएं कुछ इस तरह से रहती हैं- समय के मूल्य को नहीं समझ पाना, प्राथमिकताओं का तय नहीं होना, काम को टालते जाना, एक समय पर बहुत सारे कार्य हाथ में लेना, असफल या गलती होने से मन में डर बैठ जाना इन बाधाओं को पार करते हुए समय को सदुपयोग कर हम अपना भविष्य संवार सकते हैं।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

राष्ट्र की आवश्यकता उत्तम शिक्षा एवं चरित्र

चरित्र अथवा सच्चरित्रता को यदि हम परिभाषित करें, तो अच्छे आचरण, चाल चलन, स्वभाव, गुणधर्म आदि इत्यादि को चरित्र तथा सचरित्रता का तात्पर्य अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव, अच्छे व्यवहार से है। मनुष्य समाज के बीच रहने वाला दोपाया है। अतः समाज के मध्य ऐसे गुणों का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा व समाज में शांतिपूर्वक रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मनुष्य के खराब आचरण से समाज का वातावरण भी प्रदूषित, खराब होता है। दूसरी तरफ अच्छे राष्ट्रीय चरित्र फलादेश हमेशा प्रगति के पथ पर चलकर एक महान राष्ट्र की संज्ञा पाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, संताप, निर्दयता और ऐसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव दुराचारी ही माना जाता है जो अच्छे आचरण या अच्छे चरित्र का ना हो। दूसरी ओर इसके जरा विपरीत निष्ठा, ईमानदारी, लगनशीलता, संयम तथा परोपकार इत्यादि पालन करने वाला मनुष्य चरित्रवान और सच्चरित्र वाला कहलाता है। इसके अलावा उदारता, विनम्रता, सहिष्णुता, सत्यभाषण किसी राष्ट्र को चरित्रवान बनाता है।

हमारे देश के महान नेता बापू महात्मा गांधी ने कूटनीति की चमक को बड़ा नहीं समझा, बुद्धि विकास को बड़ा नहीं समझा, चारित्रिक बल को ही मान दिया है। आज हमें अधिक से अधिक इस बात पर विचार करना है कि चरित्र बल केवल एक व्यक्ति का नहीं समूचे देश का होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र को अत्यधिक महत्व देने वाली पंक्तियां मूर्धन्य आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पंक्तियां से हम सब भली भांति परिचित हैं, उसका हिंदी भावार्थ है, यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। उनके इस कथन से चरित्र का महत्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। कर्म मानव की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन चरित्र की अभिव्यक्ति है। हारवर्ट स्पेंसर ने कहा कि किसी मनुष्य राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं चरित्र है, और यही सबसे बड़ा उसका रक्षक है। चरित्रवान व्यक्ति ही अच्छा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर सकता है। और अच्छा राष्ट्रीय चरित्र एक महान देश को जन्म देता है। जिसमें विश्व में शांति, सद्भावना एवं परस्पर सहयोग की भावना को बल मिलता है। चरित्रवान नेता पूरे देश को अच्छे से नेतृत्व देकर सही विकास और शिक्षा की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चरित्रहीन नेता देश को रसातल की ओर ले जाने में नहीं चूकता है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रतिनिधि के रूप में चरित्रवान नेताओं का ही चुनाव करें। राजनीति एक कठिन डगर है, जहां की पगडंडी बल खाकर आगे बढ़ती है और इस प्रयास में हमें समाज में सदाचार को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।

संजीव ठाकुर

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय : फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मोदी सरकार

महत्वपूर्ण मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार में भाजपा ने महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने का निर्णय किया है। भाजपा द्वारा अपनी घटी शक्ति और गठबंधन साझीदारों, जैसे तेलगूदेशम पार्टी–तेदेपा व जनता दल युनाईटेड–जदयू के कथित दबाव के बावजूद केन्द्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने का निर्णय किया है। इस प्रकार भाजपा ने सत्ता पर अपने केन्द्रीकरण की गारंटी की है जिससे वह महत्वपूर्ण मंत्रालयों के जरूरी निर्णय स्वयं ले सकेगी। निश्चित रूप से इससे नीतिगत निरंतरता तथा सुशासन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही 'लाल फीताशाही' पर लगाम रख कर सरकार के एजेंडे का तेजी से क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने से भाजपा जनता में अपनी उपलब्धियों तथा सुशासन की क्षमता का प्रचार कर सकेगी जो सत्ता तथा अपना समर्थन आधार बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्षी दलों को आशंका है कि शायद भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–राजग के गठबंधन सहयोगी इससे असहमत हों। संबंधों में इस कारण तनाव पैदा हो सकता है, तेदेपा और जदयू जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय क्षत्रप इसे अपना अपमान समझ सकते हैं तथा वे ज्यादा साझीदारी की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने न केवल शपथ ले ली है, बल्कि उन्होंने मंत्रालयों में अपना कामकाज भी संभाल लिया है। इसे देखते हुए फिलहाल ऐसी आशंका निराधार लगती है कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–राजग में मंत्रिमंडल गठन पर कोई गंभीर विवाद है। हालांकि, महाराष्ट्र के एक गठबंधन सहयोगी ने कुछ आपत्तियां की थीं। जहां तक गठबंधन सहयोगियों की ओर से उनके क्षेत्रीय विकास या विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए एजेंडे में कुछ परिवर्तन की संभावना है, प्रधानमंत्री इसके प्रति पूर्ण संवेदनशील हैं और उन्होंने इसके समुचित संकेत भी दिए हैं।

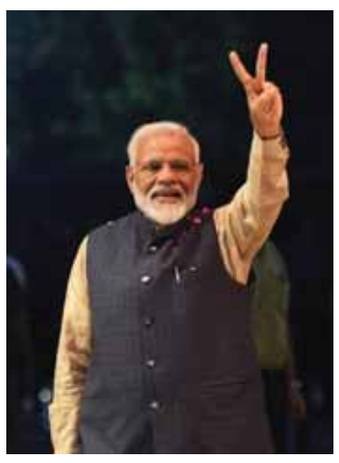

नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के अंत में ही अगली सरकार के लिए '100 दिन का एजेंडा' तैयार कर लिया था। यह एजेंडा सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मांगे गए हैं। सभी मंत्रियों के विचार मिल जाने के बाद इसे विस्तृत विचार-विमर्श के लिए नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में गठबंधन सहयोगियों की राय मिलेगी जिसका पूर्ण सम्मान किया जाएगा। गठबंधन की स्थिरता पर आशंका व्यक्त करने वालों को गौर करना चाहिए कि अतीत की तुलना में इस बार गठबंधन के प्रमुख दल- भाजपा की संख्या बहुत अधिक है और गठबंधन सहयोगी अनेक अन्य कारणों से भी इससे बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और भाजपा उनकी सरकार में शामिल है। बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार राजग गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वे राजग का 'मुख्यमंत्री चेहरा' होंगे। दोनों नेता अपने राज्यों के विकास के लिए केन्द्र से अधिकाधिक सहायता और सहयोग चाहते हैं। मोदी ने न केवल इसका वादा किया है, बल्कि नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति इसकी गारंटी भी है। इसके साथ ही पिछले दस वर्ष में मोदी सरकार द्वारा देश के विकास की त्वरित गति से गठबंधन साझीदार भी प्रसन्न हैं। इसे देखते हुए विश्वास किया जा सकता है कि वे अपने संकुचित क्षेत्रीय या दलीय हितों पर देश के हितों को वरीयता देंगे तथा भारत को विकसित देश बनाने में योगदान करेंगे। मोदी सरकार की स्थिरता व त्वरित कार्य क्षमता देश के विकास की गारंटी है।

प्रचार के बाद अब संवाद जरूरी

भाजपा की चुनाव मशीनरी ने आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया। अब संवाद की प्रकृति बदल कर इसे सहमति आधारित बनाने की आवश्यकता है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भाजपा की चुनाव मशीनरी ने हालिया लोकसभा चुनाव में आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया जिसका उसे कोई खास लाभ नहीं मिला। चुनाव परिणाम आने और मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब संवाद की प्रकृति बदल कर इसे सहमति आधारित बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लोकतांत्रिक इतिहास में उल्लेखनीय है। हालांकि, मतदाताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रखा, पर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–राजग को बहुमत से काफी अधिक सीटें मिल गईं। भाजपा को अपने दम पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 282 सीटें मिली थीं, जिनको बढ़ा कर उसने 2019 में 303 तक पहुंचा दिया था। इस बार उसे थोड़ा झटका लगा और उसकी सीटें 240 रह गईं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर उन लोगों को बहुत राहत मिली है जिन्होंने भारतीय बाजार में काफी निवेश किया है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों में बड़ी संख्या में छोटे निवेशक तथा अमीर कार्पोरेट पेशेवर, दोनों शामिल हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के अतीत पर सरसरी नजर डालने से कुछ चीजें बहुत स्पष्ट होती हैं। नरसिम्हा राव सरकार में 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डा. मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक सुधार शुरू किए थे, उनको नरसिम्हा राव के बाद के पांच प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में झटका लगा जिनमें स्वयं मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। इन सुधारों की निरंतरता का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि पिछले तीन दशकों में इन आर्थिक सुधारों ने 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 'अत्यधिक गरीबी' से बाहर निकालने में सहायता की है।

आर्थिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल में सरकार भारी जनादेश के बावजूद कृषि सुधार करने में सफल नहीं हुई। वह किसानों को 'नए कृषि कानूनों' और इससे किसानों को मिलने वाले लाभों के बारे में समझाने में विफल रही। इसका कारण किसानों से उसका ठीक से संवाद न होना था। मोदी सरकार की संचार मशीनरी द्वारा पैदा नकारात्मक विमर्श के कारण आर्थिक सुधारों व खासकर कृषि सुधारों को धक्का लगा। कहा जाता है कि पार्टी की संचार मशीनरी पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी–भाजपा के 'आईटी सेल' ने कब्जा कर लिया है। इस नकारात्मकता के कारण न केवल नए कृषि कानूनों का क्रियान्वयन संभव नहीं हुआ, बल्कि यह अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आने वाले महीनों में 'हिंदू गौरव' की भावना भी ठीक से जगा नहीं सकी।

संभवत: भाजपा के आक्रामक विमर्श में टेलीविजन चैनलों पर होने वाली तीखी बहसों को ज्यादा स्थान मिल गया। इनमें से अनेक को तथ्यों से समर्थन नहीं मिला था और इस कारण सोशल मीडिया पर होने वाली बहसें हानिकारक सिद्ध हुईं। तथ्यों की जांच करने वाले टूलों के वर्चस्व को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू की प्रेम कथाओं व ऐसी ही अन्य चीजों के प्रसारण से नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को पीछे धकेल दिया। भाजपा का 2024 में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान बहुत आक्रामक हो गया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त करने से पीछे रह गई। वैसे चुनाव के पहले भी भाजपा की संचार मशीनरी कई बार जनता के समक्ष मोदी सरकार की उपलब्धियों को प्राथमिकता पर रखने के बजाय निरर्थक बहसों में उलझ गई जिसका पार्टी को कोई लाभ नहीं हुआ। किसान आंदोलन के दौरान भाजपा के संचार माध्यमों तथा उसके सोशल मीडिया मंचों ने किसानों को नए कृषि कानूनों के लाभ बताने में सफलता नहीं पाई। इसके बजाय संचार में इस विकृति के कारण किसान आंदोलन को 'हिंदुस्तानियों' व 'खालिस्तानियों' के बीच युद्ध के रूप में पेश कर दिया। हालांकि, किसान आंदोलन में शामिल एक तबका काफी आक्रामक था, पर इसे 'खालिस्तानियों' के रूप में पेश करने से व्यापक रूप से किसानों की भावनायें आहत हुईं।

आर्थिक व खासकर कृषि सुधारों के विरोधियों के एजेंडे को 'देश तोड़ने के एजेंडे' के रूप में पेश करने का विचार गलत था और भाजपा को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके प्रभाव में न केवल प्रधानमंत्री मोदी को नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी, बल्कि भाजपा को इसका चुनावी नुकसान भी हुआ। वर्तमान लोकसभा चुनाव में किसानों की आहत भावनाओं के कारण भाजपा को न केवल पंजाब में नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कृषि सुधार व किसान कल्याण के अनेक उल्लेखनीय कदमों के बावजूद उसे इसका नुकसान देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी उठाना पड़ा।

अनेक पहलों ने लोगों को मोदी की दूसरी सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया था, पर प्रचंड बहुमत के क्रूर शक्ति प्रदर्शन के कारण उसकी इन पहलों का जमीन पर असर प्रभावित हुआ। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि सरकार की पहलें जमीनी स्तर पर उतनी प्रभावशाली नहीं थीं जिनका दावा अवस्थापना की प्रचार शाखा द्वारा किया जा रहा था। इस गलत दृष्टिकोण के कारण अमर्त्य सेन के 'आर्गुमेंटेटिव इंडियन' की भावना प्रकट करने वाले लोगों को 'राष्ट्रविरोधी' तक कह दिया गया। ऐसा लोगों द्वारा सरकार से असहमति की स्थिति में हुआ। इस कारण सरकार ने न केवल कुछ लोगों में सरकार-विरोधी दृष्टिकोण मजबूत किया, बल्कि वे सरकार के साथ आने के बजाय मजबूती से उसके विरोधी बन गए।

भाजपा नेतृत्व को परेशान करने वाला सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि जब उत्तर प्रदेश के निवासियों ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का 'अत्यधिक उत्साह' से स्वागत किया तो उन्होंने इतने ही जोश के साथ चुनावी संघर्ष में पार्टी का समर्थन क्यों नहीं किया? इस मामले में एक बार फिर भाजपा की संचार मशीनरी ने भारी गलती की और उसने एक आनन्ददायक व उत्साहवर्धक क्षण को 'स्वामिभक्ति परीक्षा' में बदल दिया। इस कारण ऐसा लगा कि विपक्षी नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण एक प्रकार का 'छद्म राजनीतिक' कार्य बन गया तथा इसे स्वीकारने से इनकार करने वालों को 'हिंदू-विरोधी' के रूप में पेश कर दिया गया। कोई भी संचार विशेषज्ञ ऐसा माडल नहीं तैयार करेगा जो उसके गौरव के क्षण को विरोधियों पर खर्च करे। इस प्रकार भाजपा संचार मशीनरी द्वारा तैयार विमर्श अंतत: ऐसी स्थिति तैयार करने में लग गया जिससे भगवान रामलला की 'घर वापसी' विपक्षी नेताओं की 'अयोध्या वापसी' में बदल गई।

आज भाजपा सरकार तेलगू देशम पार्टी–तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू तथा जनता दल युनाईटेड के नीतीश कुमार से समर्थन प्राप्त कर रही है। ये दोनों नेता भले ही अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल न हुए हों, पर उन्होंने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार बनी तीसरी भाजपा नीत राजग सरकार का समर्थन किया है। विडंबना है कि अतीत में भाजपा के विरोध में खड़े होने की स्थिति में इन्होंने रामजन्मभूमि आंदोलन को भाजपा की 'राजनीतिक परियोजना' तक कहा था। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और खासकर अयोध्या के मतदाताओं की सोशल मीडिया मंचों पर खुली निन्दा हो रही है। भले ही यह भाजपा-विरोधी या पहले भाजपा विरोधी रहे नेताओं को पसंद न आए, पर सोशल मीडिया पर आम जनता द्वारा व्यक्त भावनाओं को 'भाजपा के विस्तारित परिवार' की आलोचना बताना संभवत: अतिरंजना होगी।

तथ्य यह है कि जो जातियां और समुदाय भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उन्होंने उनके राज्यों में नीतीश कुमार और नायडू को वोट दिया है। ऐसे में समय की आवश्यकता है कि संवाद की प्रकृति को टकराव से बदल कर सहमति में लाया जाए। यह सहमति न केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–राजग के साझीदारों, बल्कि भारत के सभी हितधारकों के बीच बनना जरूरी है। वर्तमान स्थिति की मांग है कि राजनय के रूप में आर्थिक व रणनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता दी जाए तथा सरकार का विरोध करने वालों को शत्रु के रूप में पेश न किया जाए।

केमिकल मुक्त कृषि की ओर बढ़ते कदम

“स्वास्थ्य और संधारणीयता के बारे में उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ने के साथ ही भारत में जैविक खाद्य बाजार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है।”

अजीत गोदारा
(लेखक, स्तम्भकार हैं)

एक समय था जब देश में उत्पादित सभी चीजें जैविक होती थीं, किसान अपने खेतों में गाय के गोबर और खाद जैसी प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करते थे। उपज कम थी, लेकिन यह स्वस्थ, स्वादिष्ट और सबसे बढ़कर संधारणीय अभ्यास था। फिर रासायनिक उर्वरक आए, जिससे निस्संदेह उपज कई गुना बढ़ गई, लेकिन कई दुष्प्रभाव भी हुए। यह संधारणीय नहीं है और इसमें जैविक उत्पादों का स्वाद नहीं है और सबसे बढ़कर यह उतना स्वस्थ नहीं है जितना होना चाहिए। इसके अलावा किसान अपने स्वास्थ्य के मामले में भी कीमत चुका रहे हैं और यूरिया और अन्य रसायनों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है और जल स्तर को कम कर रहा है। इस परिदृश्य में, जैविक खेती ही एकमात्र रास्ता है। अब नई जागरूकता के साथ बड़ी संख्या में लोग जैविक उत्पादों की ओर रुख कर रहे हैं और अपनी थाली में स्वस्थ रसायन मुक्त उत्पाद पा रहे हैं, भारत के जैविक उत्पाद बाजार में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व उछाल देखा गया है, जो स्वास्थ्य, संधारणीयता और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में बढ़ती उपभोक्ता जागरूकता से प्रेरित है।

शहरी आबादी के स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों की तलाश करने के कारण, जैविक खाद्य उत्पादों की मांग में उछाल आया है। यह प्रवृत्ति केवल एक खास वर्ग तक सीमित नहीं है; इसने मुख्यधारा के उपभोक्ता वरीयताओं को भी प्रभावित किया है, जिससे जैविक उत्पाद खाद्य उद्योग में सबसे आगे आ गए हैं। भारत में जैविक खाद्य बाजार, जिसका मूल्य 2023 में 1,582.2 मिलियन डालर था, 2032 तक तेजी से बढ़कर 8,918.5 मिलियन डालर होने की उम्मीद है, जो प्रति वर्ष

21.19 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर दर्शाता है। यह उल्कापिंड वृद्धि देश भर में एक बड़ी हरित लहर का संकेत है, जहां उपभोक्ता तेजी से टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की ओर झुकाव रखते हैं। आज उपभोक्ता ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हैं जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हों। यह टिकाऊ और नैतिक उपभोग की ओर व्यापक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिससे जैविक खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं। आज जैविक कंपनियों के पास सैकड़ों एसकेयू का प्रभावशाली पोर्टफोलियो है, जिसमें दालें, बाजरा, गेहूं, सरसों, जौ, चावल और तेल जैसे स्टेपल शामिल हैं। जैविक कंपनियों के उत्पाद न केवल उनकी वेबसाइट के माध्यम से बल्कि अमेजान फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वे व्यापक उपभोक्ता आधार तक पहुंच पाते हैं। ब्रांड ने अपने उत्पाद रेंज का विस्तार बीज वर्टिकल में भी किया है, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों और अन्य अनाज शामिल हैं। ऐसा करके, जैविक कंपनियों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उनकी जैविक खेती की प्रथाएं कृषि प्रक्रिया की शुरुआत से ही शुरू हो जाएँ। दिलचस्प बात यह है कि जैविक कंपनियाँ टिकाऊ खेती के तरीकों और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वे किसानों को फसल प्रबंधन कौशल बढ़ाने और पैदावार बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। किसानों को उनके खाद्य आपूर्ति में किसी भी संभावित संदूषक से सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जैविक उत्पाद मिल सके। जैविक खेती में उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने की निश्चित रूप से आवश्यकता है अन्यथा उपभोक्ता का भरोसा टूट जाएगा और पूरे उद्योग को नुकसान होगा। ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाणन प्रक्रियाओं के साथ इस क्षेत्र में अधिकांश धोखाधड़ी की प्रथाएँ समाप्त हो गई हैं। लेकिन यह क्षेत्र चुनौतियों से रहित नहीं है। हालाँकि, रासायनिक से जैविक में परिवर्तन सरल नहीं है। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है लेकिन पुरस्कार संतोषजनक हैं। कृषि भूमि को जैविक खेती में बदलने में लगभग तीन साल लगते हैं।

और जिन जगहों पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बहुत ज़्यादा है, वहाँ यह तीन साल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा, धोखेबाज़ अक्सर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर कीमतें अवास्तविक रूप से बढ़ा दी जाती हैं। भारत में जैविक उत्पादों की वृद्धि उपभोक्ता परिदृश्य में बदलाव और स्वास्थ्य और स्थिरता के बारे में बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। अभी भी, जैविक उत्पादों की बाज़ार हिस्सेदारी सिर्फ़ एक प्रतिशत है, लेकिन वृद्धि घातीय है। यह क्षेत्र 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जो जैविक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग और उनमें लोगों की रुचि को दर्शाता है।

आप की बात

मोदी की तीसरी पारी

आम चुनाव में गठबंधन सरकार के जनादेश के बाद मोदी सरकार की तीसरी पारी शुरू हुई है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं देकर जनता ने ऐसी स्थिति निर्मित कर दी है कि राजनीतिक दल चाह कर भी इतरा नहीं सकते हैं। ऐसे में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता की इच्छा के अनुरूप काम करें। इसमें विपक्ष को भी सकारात्मक रूख अपनाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी काम में फिजूल अड़चन पैदा करने से जवाबदेही तो उसकी भी तय होगी। भले ही मोदी की तीसरी पारी में उनके पास पहली दो पारियों जितना भाजपा का बहुमत न हो, पर देश-दुनिया में उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो गया है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता बन गए हैं। उनके नेतृत्व में देश ने पिछले दस साल में अभूतपूर्व व असाधारण प्रगति की है जिसे स्वयं मोदी ने केवल ट्रेलर कहा है। ऐसे में विपक्षी दलों को संसद में बवाल और सरकारी योजनाओं पर निरर्थक सवाल उठा कर देश की प्रगति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यदि विपक्ष अपनी आदत में सुधार नहीं करता है तो देश की जनता आगामी आम चुनाव में उसे पुन: मूषको भव का शाप दे सकती है। भाजपा को भी सहमति व सर्वानुमति बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा।

– **अमृतलाल मारू,** इंदौर

नीट पर विवाद

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी–एनटीआई संचालित नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होते ही पेपर लीक और नंबर देने में गड़बड़ी से जुड़े वे आरोप फिर सामने आ गए जो पहले भी सिर उठा चुके हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कौसिलिंग रोकने के आदेश नहीं दिए, पर उसने केन्द्र सरकार तथा एनटीआई से जवाब मांगा है। नीट पर हालिया विवाद को देखते हुए मोदी की नई सरकार को पूरी व्यवस्था की गहन समीक्षा करनी चाहिए। उच्च स्तरीय अध्ययन और नौकरी के लिये दी जाने वाली परीक्षाओं मे पहले भी पेपर लीक होने और कई तरह की अनियमितता के आरोप लगाते रहे हैं। इस बार भी एक ही कोचिंग इंस्टिट्यूट से 67 छात्रों का शत प्रतिशत अंक लाना हेराफेरी की आशंका उजागर करता है। इन परीक्षाओं केलिए प्रतिभाशाली छात्र कठोर परिश्रम करते हैं, महंगी कोचिंग क्लासेस अटेंड करते हैं और बड़े शहरों में आकर हॉस्टल व खाने का भारी खर्च उठाते हैं जो लाखों रुपए प्रतिवर्ष होता है। बेईमानी और अनियमितता रोकने के लिए कई तरह के आश्वासन दिए जाते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप तथा सरकार की सक्रियता से ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो छात्रों व उनके माता-पिता को संतुष्ट कर सके।

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

आत्मावलोकन का समय

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें मिलने पर अनेक प्रकार की चर्चा हो रही है। यदि ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो यह परिणाम भी एक प्रकार से भाजपा की विजय और लोकप्रियता का ही प्रतीक है।10 वर्षों के शासन के उपरान्त भी भाजपा को मात्र 8 प्रतिशत ही मत कम मिले। फिर भी कम सीटें मिलने के कारण समझने होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी उन लोक हितकारी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा जिनसे वही वर्ग लाभान्वित हुआ है जिसके बूथों पर उसे एक भी वोट नहीं मिला। दूसरे, अन्य दलों की तुलना में भाजपा ने रेवड़ी की घोषणाएं नहीं की जिनसे बदलने वाला मतदाता अधिक प्रभावित होता है। संभवत: अन्य दलों की तुलना में जातीय समीकरण को बिठाने में भी भाजपा पीछे रह गई। भाजपा अध्यक्ष का यह बयान भी घातक सिद्ध हुआ कि अब हमें संघ के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान चुनाव पूरा मोदी बनाम समस्त विपक्ष बनकर रह गया था। भाजपा को आत्मवलोकन कर इस बात पर भी गौर करना होगा कि उसके अनेक सांसदों व विधायकों ही नहीं, सामान्य कार्यकर्ताओं में भी अहंकार व्याप्त हो गया था। देखना होगा कि इस झटके के बाद भाजपा अपने भीतर कितना सुधार लाती है।

– **नरेन्द्र टोंक,** मेरठ

हिंदुत्व की राजनीति

हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होना हिंदुत्व की राजनीति का फेल होना नहीं है। यदि ऐसा होता तो मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा आदि प्रदेशों में उसे एकतरफा जीत नहीं मिलती। विडंबना है कि इस बार विपक्ष ने मुसलमानों को हर तरह से साधने के प्रयास किया हैं, उनके साथ गुप्त बैठकें हुई हैं और वोट जिहाद जैसा नारा भी उभर कर सामने आया है। इसके साथ ही जहां मुस्लिम मतदाता शत-प्रतिशत वोटिंग करते हैं वहीं बहुत से हिंदू मतदाता घर से निकल कर वोट डालने की जहमत भी नहीं उठाते। आंकड़ों से स्पष्ट है कि हिंदुओं का वोटिंग प्रतिशत 60, एग्जिट पोलमें इंटरेस्ट 99 प्रतिशत और चुनाव परिणाम में 10 पर्सेंट रुझान होता है। खासकर हिंदुओं में खातेपीते लोग मतदान, चुनाव व राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऐसे लोग लगातार आलसी होते जाते हैं और हर काम के लिए नौकरों पर आश्रित हैं। उनको मतदान करना फिजूल लगता है, लेकिन उनको देश के उन मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं की स्थिति पर गौर करना चाहिए जो बढ़ते मुस्लिम वर्चस्व से लगातार असुरक्षित अनुभव करते हैं।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

"राजनीति इतना गंभीर मसला है कि इसे राजनेताओं पर नहीं छोड़ सकते।
- चार्ल्स डी गॉल

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में तीन आतंकी घटनाएं होना आतंकियों और उनके आका की हताशा व बौखलाहट को ही दर्शाता है। देश के सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

बौखलाहट के हमले

बीते रविवार की शाम जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के दो दिनों के भीतर एक ही रात में पहले कठुआ और फिर डोडा जिलों में हुए आतंकी हमले आतंकियों की बौखलाहट को ही दिखाते हैं ही, पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में जारी शांति और सुकून को लेकर उनकी हताशा को भी बयां करते हैं। कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में आतंकियों के पहले हमले और इसके कुछ घंटों बाद डोडा जिले में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की चेक पोस्ट पर हुए दूसरे हमले पर भारतीय सुरक्षा बल स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बावजूद, तीन दिनों में हुई तीनों आतंकी वारदात को देखें, तो इनमें कई श्रद्धालुओं की मौत और एक जवान का बलिदान होना वाकई दुखद है। दरअसल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की बदली स्थितियां पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहीं और इसी वजह से उसके द्वारा समर्थित आतंकी गुटों ने इस क्षेत्र में अपनी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, जबकि सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां शांति व सद्भाव का नया अध्याय शुरू हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है और सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान तो हुआ ही, पर्यटकों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में अस्सी लाख से ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे व रोजमर्रा की दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी व अव्यवस्था के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलन तो कर ही रहे थे, भारतीय ध्वज का समर्थन करना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, बलूचिस्तान में भी लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जाहिर है कि इससे पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और भी अधिक बौखला गया है। रविवार को हुए हमलों की जिम्मेदारी जहां पाकिस्तान से संचालित हो रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट

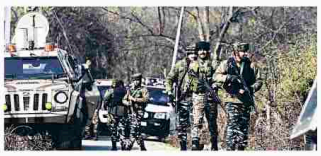

टीआरएफ ने ली थी, तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी गुट ने ली है, जो जैश-ए-मोहम्मद का ही एक गुट है। पहले जहां आतंकी घटनाएं कश्मीर घाटी के क्षेत्र तक सीमित रहती थीं, पिछले दिनों हुई वारदात दिखाती हैं कि अब जम्मू क्षेत्र पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो वाकई चिंताजनक है। देश के सुरक्षा बल ऐसे आतंकी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आसन्न घोषणा को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी जरूरत है।

पांडियन का पराभव

चुनाव खत्म होने तक हर जगह दिखाई देने वाले पांडियन ने परिणाम आने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि पार्टी में उनके खिलाफ फैले आक्रोश के मद्देनजर यह 'टैक्टिकल रिट्रीट' ज्यादा लगती है और मामला ठंडा होने पर परोक्ष रूप से ही सही, उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

मोहन चरण माझी ने ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन इन चुनावों में चर्चाओं में रहे आईएएस अफसर से नेता बने वीके पांडियन की अविश्वसनीय कहानी की मिसाल भारतीय राजनीति में पहले शायद ही कभी देखी गई होगी। राजनीति में इतना छोटा कैरियर भी शायद ही किसी और नेता का होगा। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 27 नवंबर, 2023 को उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा के तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) में शामिल हुए। लेकिन चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद नौ जून को उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर डाला। उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ 195 दिनों का रहा।

संदीप साहू
वरिष्ठ पत्रकार

सन 2000 में आईएएस बनने के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अपनी मेहनत और लीक से हटकर काम करने की असाधारण क्षमता के कारण उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। पहले मयूरभंज, फिर गंजाम जिले के कलेक्टर के रूप में उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को लोग आज भी याद करते हैं। दोनों ही जिलों में कामों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया । ये सब भी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पांडियन की उपलब्धियां। लेकिन सत्ता की राजनीति में उनका प्रवेश तब हुआ, जब गंजाम के जिलाधीश के रूप में उनके काम से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें सन 2011 में अपना निजी सचिव बनाया। अपनी काबिलियत के जरिये पांडियन ने नवीन का विश्वास जीता और धीरे-धीरे अपनी काया विस्तार करने लगे ।

2019 में लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक ने सरकार को अधिक लोकाभिमुखी करने के लिए 5टी (टीमवर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमलाइन) नामक एक नया विभाग खोला और पांडियन को इसका सचिव बना दिया। सरकार के

सभी विभागों को इस नए विभाग के अंदर लाया गया। इसके बाद सरकार में पांडियन का दबदबा और भी बढ़ गया। पांडियन के नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्हें इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि सरकार में उनकी पकड़ बनी रहे। और 2019 के चुनाव के बाद नवीन ने अपने निवास से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया और दल व सरकार दोनों का पूरा जिम्मा पांडियन को सौंप दिया। कोविड के बाद मुख्यमंत्री न सचिवालय गए, न विधानसभा। कैबिनेट की बैठक में भी वे वीडियो लिंक के जरिये अध्यक्षता करने लगे। अपने दल के नेता, मंत्री, विधायकों से मिलना उन्होंने लगभग बंद कर दिया। यहां तक कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिए भी सलाह-मशवरे के लिए मुख्यमंत्री से मिलना दूभर हो गया और वे पांडियन के आदेश पर काम करने लगे। अब पांडियन की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह राज्य सरकार के चांपर का इस्तेमाल कर पूरे राज्य का दौरा करने लगे। बहाना था कि लोगों से उनकी शिकायतें लेकर तत्काल कार्रवाई करना। बाद में पता चला कि पांडियन राजनीति में प्रवेश करने के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। वह जहां भी गए पूरा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, विधायक और मंत्री उनकी सेवा करते हुए नजर आए। मंच पर पांडियन के अलावा कोई भी दिखने को नहीं मिला। साफ था कि उनकी ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। इस बात की जमकर चर्चा हुई कि वह नवीन के उत्तराधिकारी हैं। नवीन ने ऐसी चर्चाओं का खंडन करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे ओडिशा के लोगों में यह धारणा और भी पुख्ता होती गई कि नवीन ने पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। इस धारणा को तब और बल मिला, जब पांडियन ने औपचारिक रूप से बीजद में योगदान किया। इस वर्ष मार्च में जब बीजद और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, तब बीजद की ओर से पांडियन ही इसके सूत्रधार थे। प्रेक्षकों का मानना था कि भाजपा से गठबंधन कर वह अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नवीन के डर से पार्टी के जो नेता चुप बैठे हैं, वे नवीन के बाद उनके खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे, तब उन्हें भाजपा के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि बात बनी नहीं और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

इस बार चुनाव का पूरा मोर्चा पांडियन ने संभाला। उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति तैयार करने और आर्थिक संसाधन के उपयोग से लेकर मीडिया कैंपेन तक लगभग सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ। करीब डेढ़ महीने के चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर अकेले पांडियन ही प्रचार करते नजर आए। मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक बीच-बीच में उनके साथ प्रचार के लिए जाते रहे, लेकिन पार्टी के 40 'स्टार प्रचारकों' में से 38 पूरे चुनाव के दौरान नदारद रहे। और पार्टी को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा ने भी एक सोची-समझी रणनीति के तहत 'ओड़िया अस्मिता' को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा नेता हर आमसभा में इसी बात को दोहराते रहे कि नवीन साढ़े चार करोड़ ओड़िया लोगों की अस्मिता को पैरों तले रौंदते हुए तमिलनाडु में जन्मे एक आदमी को ओडिशा के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा की यह रणनीति काम कर गई। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले नवीन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

चुनाव में हार के बाद अब तक सहमे हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब पांडियन को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ खुलकर नारेबाजी करने लगे हैं। चुनाव खत्म होने तक हर जगह दिखाई देने वाले पांडियन परिणाम आने के बाद से कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद नवीन ने पांडियन को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराने या उनकी निंदा करने से साफ इन्कार कर दिया है। इसके उलट उन्होंने पांडियन की जमकर प्रशंसा की है और उनके खिलाफ हो रही बयानबाजी को अनुचित बताया है। नवीन के इसी आचरण और उच्चारण के कारण राजनीति से संन्यास लेने की पांडियन की घोषणा के बाद भी बहुत कम लोग यह मानने के लिए तैयार हैं कि अब राजनीति में कभी उनकी वापसी नहीं होगी। ज्यादातर प्रेक्षक मानते हैं कि पार्टी में उनके खिलाफ फैले आक्रोश के मद्देनजर यह एक 'टैक्टिकल रिट्रीट' भर है और मामला ठंडा होने पर प्रत्यक्ष नहीं, तो परोक्ष रूप से उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

जीवन धारा

स्वामी विवेकानंद

सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए।

दुर्बलता ही मनुष्य को गुलाम बनाती है

हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से बेहद आकर्षित रहते हैं। लक्ष्य ही हमारे लिए इतना ज्यादा आकर्षक और मोहक हो जाता है और हमारे मानस पर इतना विशाल बन जाता है कि इन सबके चलते बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से इसकी छानबीन करें, तो निन्यानबे प्रतिशत यही पाएंगे कि असफलता का प्रमुख कारण साधनों की ओर ध्यान न दिया जाना था। इसलिए हमें जरूरत है अपने साधनों को पुष्ट कर उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं, तो साध्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब तक कारण अपरिष्कृत, समुचित और सशक्त न हों, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें, तो कार्य स्वतः ही सम्पन्न हो जाएगा।

इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है।

हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम कोई काम हाथ में लेते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसमें असफलता मिलने पर भी उसे छोड़ते नहीं हैं। हम जानते हैं कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पा रहे, उससे चिपके हुए हैं। यह ठीक वैसा ही है, जैसे मधुमक्खी आई तो शहद पीने थी, लेकिन उसके पैर ही शहद में धंस गए और फिर वह वहां से निकल नहीं सकती। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। यही आसक्ति है, जो दुख की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में छोटी-छोटी बातों में यह चीज मौजूद है और हम इसे अनुभव भी करते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है-निरंतर काम करते रहो, पर बंधन में मत पड़ो, आसक्त मत हो। प्रत्येक वस्तु से अपने को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। कोई वस्तु तुम्हें कितनी प्यारी क्यों न हो, तुम्हारा मन उसके लिए कितना ही लालायित क्यों न हो, उसे त्यागने में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, फिर भी उसे त्यागने की शक्ति को अपने भीतर संजोए रखो। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सारे शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। पर आसक्ति ही हमारे सुखों की जननी भी है। हम अपने मित्रों, सगे-संबंधियों में आसक्त रहते हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त रहते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनसे हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी और कारण से हम पर दुख आता है? इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए।

अनासक्ति की शक्ति

सूत्र

यदि हमारे भीतर इच्छामात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती, तो हमें कभी दुख नहीं होता। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है, जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही, अपनी इच्छा से उससे अलग होने की शक्ति भी जुटा लेता है। सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का रहस्य यही है कि बदले में कुछ भी न चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति ही सबसे सफल व्यक्ति होता है।

दूसरा पहलू

लाइलाज बीमारी से लड़ते हुए चालीस साल की महिला ने दिखाया कि इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आत्मबल।

अपार्टमेंट की खिड़कियां साफ रहने लगी हैं

वह (गुप्त नाम) चालीस वर्ष की थी। अपने अपार्टमेंट को गंदी खिड़कियां देख रही थी। वह उन्हें साफ करना चाहती थी। चालीस वर्ष की उम्र इतनी भी नहीं होती कि कोई कुर्सी से खड़ा भी न हो सके। लेकिन यह काम उसके लिए असंभव था। वह जानती थी कि अगर वह खड़ी हो भी गई, तो कुछ ही मिनट में उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। जब वह अपनी उम्र के पहले ही दशक में थी, तभी उसे पता चला कि वह लिम्फ-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोग से पीड़ित है।

लिसा सैंडर्स, एमडी

वह अपनी उम्र के पहले ही दशक में थी, तभी उसे पता चला कि वह लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एलजीएमडी) रोग से पीड़ित है।

डॉ. पप्पास ने ही उसे बताया कि उसकी बीमारी लाइलाज नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दवाएं चलीं। कुछ ही महीने में फर्क दिखने लगा।

यह मांसपेशियों का एक वंशानुगत विकार है, जिसमें मरीज अपने बाल काढ़ने व दांतों को ब्रश करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। उसके इस दर्द को सिर्फ डॉ. मैरी लिन चू ही समझती थीं, जो एनवाईयू लैंगोन ऑर्थोपेडिक अस्पताल में बाल चिकित्सा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसोसिएशन केयर सेंटर की चिकित्सा निदेशक हैं और शुरुआत से ही इस महिला का इलाज कर रही हैं। चू इस महिला के बारे में सब जानती हैं। उसकी मां ने बैले नृत्य, ताइक्वांडो और टैप डांसिंग सिखाने के लिए भेजा, ताकि उसके हाथ-पैर में ताकत आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। न्यूयॉर्क शहर का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था, जिसे उसे दिखाया न गया हो। आखिरकार एक डॉक्टर ने बताया कि उसे लाइलाज एलजीएमडी है। तब एक दिन, उसकी डॉक्टर मेरी लिन ने उससे कहा कि वह किसी जेनेटिक काउंसलर से मिले। लेकिन वर्षों से इस बीमारी से लड़ते-लड़ते वह इतना थक गई थी कि वह कहीं जाना नहीं चाहती थी। मेरी लिन के समझाने पर उसने जीनों की जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट नकारात्मक आई। मेरी लिन ने हिम्मत नहीं हारी और न ही उसने। दो साल बाद, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन की तरफ से उसकी जांच हुई, लेकिन सब बेकार। उसने सोच लिया कि वह अब कभी कोई परीक्षण नहीं कराएगी। वह टूट चुकी थी। लेकिन उस रोज, जब वह खिड़कियां भी साफ नहीं कर पाई, उसने सोच लिया कि वह लड़ेगी इस बीमारी से। डॉ. मैरी लिन ने उसे तीसीन बाल रोग विभाग में क्लिनिक जेनेटिक्स के प्रमुख डॉ. जॉन पप्पास के पास भेजा। जांच हुई। तीन महीने बाद डॉ. पप्पास का फोन आया। उसे दरअसल जन्मजात मायस्थेनिक सिंड्रोम यानी सीएमएस नामक बीमारी थी, जो एक खास जीन में असामान्यता की वजह से होती है। डॉ. पप्पास ने ही उसे बताया कि उसकी बीमारी लाइलाज नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दवाएं चलीं। कुछ ही महीने में फर्क दिखने लगा। अब उसके अपार्टमेंट की खिड़कियां साफ रहने लगी हैं।

आंकड़े

पढ़ी-लिखी सरकार

नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में 80 फीसदी मंत्री स्नातक या इससे ज्यादा शिक्षित हैं। 2019 में यह आंकड़ा 84 फीसदी था।

नोट : ये आंकड़े शपथ ग्रहण करने के दौरान के हैं। | स्रोत : ADR

मां के कहने पर बालक उपमन्यु ने घोर तप किया। पिशाचों के बाधा डालने पर भी वह डिगे नहीं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए।

शिव ने उपमन्यु को दी खीर

अंतर्यात्रा
संकलित

महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र उपमन्यु ने एक दिन अपनी मां से दूध मांगा। मां ने चावल का आटा घोलकर बेटे को दिया। उन्होंने कहा कि मां यह दूध तो नहीं है। मां बोलीं-बेटा, हम तपस्वियों को यहां दूध कहां से मिल सकता है। यदि तुम दूध चाहते हो, तो भगवान शिव को प्रसन्न करो। उपमन्यु ने पूछा, वे कैसे प्रसन्न होंगे। मां ने कहा, नमःशिवाय महामंत्र का जाप करो।

माता के उपदेश से उपमन्यु घर से निकल गए। उन्होंने घोर तप किया, पर पिशाच बाधा डालने लगे। उपमन्यु डरे नहीं। उल्टा नमःशिवाय मंत्र सुनकर पिशाचों को मुक्ति मिल गई। उपमन्यु का तप बढ़ने पर भगवान शिव भक्त की परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में पहुंचे। उन्होंने कहा- बालक हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बताओ क्या चाहिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज हमें भगवान शिव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। काफी जतन के बाद भी बालक उपमन्यु नहीं डिगे, तो इंद्र के वेश में भोलेनाथ भगवान शिव की निंदा करने लगे।

भगवान की निंदा सुनने पर उपमन्यु क्रोधित हो गए और इंद्र को भस्म करने के लिए आग्नेय धारण करने लगे। यह देख भगवान शिव असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा आज से तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम मेरे अनन्य भक्त हो। भोलेनाथ ने दूध-भात से बनी खीर उपमन्यु को प्रदान की। मान्यता है कि उपमन्यु ने ही भगवान श्रीकृष्ण को शिवमंत्र की दीक्षा दी थी।

आज का इतिहास

उपहार सिनेमाघर में फिल्म देखने पहुंचे लोगों पर भारी गुजरी शाम

आज का दिन कहने को तो साल के बाकी दिनों की तरह ही एक सामान्य सा दिन है, लेकिन वर्ष 1997 में यह दिन दक्षिण दिल्ली के उपहार सिनेमाघर में फिल्म 'बॉर्डर' देखने पहुंचे कई लोगों के जीवन का अंतिम दिन साबित हुआ था। दरअसल, शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैल गई। आग की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना की जांच के दौरान पता चला कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। 1290 में खिलजी वंश का प्रमुख जलालुद्दीन फिरोजशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इसके साथ ही गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ। लंबे समय से अफगानिस्तान में बसे खिलजी कबीले ने 1320 तक शासन किया।

अपनी ही जिंदगी से यह कैसी लापरवाही

सुरेश भाई

पहाड़

अप्रैल से जून तक बर्फ पिघलती है। स्थानीय लोग भी जुलाई से सितंबर के बीच सहस्रताल जाते हैं। बिना जानकारी ट्रैकिंग जानलेवा साबित होती है।

बीते 29 मई को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सिल्ला गांव की ओर कुस-कल्याण होते हुए सहस्रताल (14,500 फुट) तक ट्रैकिंग के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के 22 लोग बर्फीली हवा में फंस गए थे, जिनमें छह महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हो गई। शेष 13 लोगों को राज्य एवं केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन एजेंसी और वायुसेना की मदद से बचाया गया।

वर्ष 2021 में आईटीबीपी पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन से तीन कुलियों की मौत हो गई थी। वर्ष 2022 में द्रौपदी का डांडा-2 चोटी पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन में 28 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2023 में रूनसारा-ताला ट्रैक और गंगोत्री कालिंदी खाल में तीन ट्रैकर्स की मौत हो गई थी, जबकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था।

हिमालय में साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण के लिए लाखों देशी-विदेशी सैलानी प्रतिवर्ष ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियों पर पहुंचकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन पीढ़ियों से रह रहे स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि किस महीने में किस चोटी पर जाना अधिक उचित और सुरक्षित हो सकता है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष सहस्रताल पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई पार करते हैं। लेकिन उनके वहां जाने का समय जुलाई के अंतिम सप्ताह से सितंबर के अंत तक है। वहां ऐसे अनेकों रास्ते हैं, जहां से बहुत सारे लोग बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। अप्रैल से जून तक तेजी से बर्फ पिघलने का समय होता है, इसलिए बर्फीले तूफान भी आते हैं। जुलाई के बाद बारिश होने से बर्फीले तूफान की गति धीमी पड़ जाती है और बर्फ पिघलना कम हो जाता है। इन महीनों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बहुत पतली बर्फ देखने को मिलती है, जिसमें भीगने पर पर्यटकों को आनंद महसूस होता है। यहां ब्रह्मकमल के पुष्प और बुग्याल के मनोरम दृश्य, सामने ऊंची चोटियों पर चांदी की तरह चमकने वाली बर्फ स्वर्ग का एहसास कराती है। सहस्रताल ग्लेशियर लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 'सहस्रताल' नाम इसलिए है कि यहां पर बर्फ की सैकड़ों झीलें हैं, जहां से धर्मगंगा, बालगंगा, भिलंगना, पिलंगना जैसी पवित्र नदियां बहकर टिहरी बांध के जलाशय में भागीरथी में मिलती हैं। इसलिए सहस्रताल ट्रैकिंग के लिए टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ बूढ़ा केदारनाथ और भिलंग से होकर भी जाते हैं।

चूंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वहां पहुंचने में कठिनाई होती है। यहां ट्रैकिंग पर निकले 22 लोगों की टीम में चार लोग 60 वर्ष से ऊपर थे, जिनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया गया था। उनके पास ट्रैकिंग संबंधी पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने एक स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसी पर रोक लगाई है, क्योंकि उसने 22 ट्रैकर्स के साथ मात्र तीन पोर्टल गाइड ही भेजे थे। इसके लिए कोई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) भी नहीं बनाई गई है। सच्चाई यह भी है कि स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसियों का काम सिंगल विंडो सिस्टम में पंजीकरण और गाइड उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। बड़ी ट्रैकिंग कंपनियों से कम बजट मिलने से भी स्थानीय एजेंसियां नियमों के पालन पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। स्थानीय मौसम और उपयुक्त समय को नजर अंदाज करने वाली बंगलूरू, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता आदि की मुनाफाखोर ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां जाने के लिए पर्वतारोहण जैसे अभियान के स्तर की तैयारी होनी चाहिए।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमन भदौरिया कहते हैं कि ट्रैकिंग व पर्वतारोहण अभियान के दौरान मौसम पूर्वानुमान लेना जरूरी होता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में कम और अनुभवहीन कर्मचारी को 20-25 पर्वतकों को संभालने का दायित्व सौंपना खतरनाक हो सकता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 118 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

दैनिक
जलते दीप

जयपुर, गुरुवार 13 जून 2024

हिंसा से सुलगता मणिपुर

एक वर्ष से अधिक समय बीत गया, मगर अभी तक मणिपुर में खूनी संघर्ष समाप्त नहीं हो पाया है। शुरू से ही वहां शांति बहाली के प्रयास शिथिल नजर आते हैं। प्रशासन और सुरक्षाबलों ने इच्छाशक्ति दिखाई होती, तो बहुत पहले इस समस्या का समाधान निकल गया होता। मगर उनकी भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि सोमवार को उपद्रवियों ने घात लगा कर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के काफिले पर हमला कर दिया। गनीमत है कि उसमें सिर्फ एक सिपाही घायल हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इससे वहां के उपद्रवियों के हौसले का अंदाजा लगाया जा सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर जाहिर की चिंता अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से वहां अशांति का वातावरण है, मगर उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई। इसे प्रथमिकता में रखते हुए शांति बहाली का प्रयास किया जाना चाहिए। पिछले दस वर्षों से वहां शांति का वातावरण था। हालांकि भागवत ने भी इस मामले में बयान देने में काफी वक्त लगा दिया। इसे लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहे हैं। संसद में भी प्रश्न पूछे गए, मगर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। अभी तक पूछा जाता है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष, एक भ्रमपूर्ण बयान की वजह से भड़क उठा था। हालांकि अब वहां की अदालत खुद इस संभावना को खारिज कर चुकी है कि मैतेई समुदाय के लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। मगर न तो राज्य और न केंद्र सरकार मणिपुर के खूनी संघर्ष को रोक पाई है। शुरू में जरूर केंद्रीय गृहमंत्री वहां गए थे, मगर फिर कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई के लिए समितियां गठित कर दी, मगर उसका भी कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। पिछले वर्ष मई में शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक सवा दो सौ से अधिक लोगों के मारे जाने, चार सौ से अधिक लोगों के घायल होने, हजारों घरों के जलाए जाने और साठ हजार से अधिक लोगों के विस्थापित होकर राहत शिविरों में शरण लेने के तथ्य उजागर हैं। सरकारों को अब यह बहाना जरूर मिल गया है कि मणिपुर के संघर्ष को रोकने की कार्रवाई सर्वोच्च अदालत की निगरानी में चल रही है, इसलिए वे इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। मगर यह उनका अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेने का एक और तरीका है। यह समझना मुश्किल है कि कैसे कोई भी कल्याणकारी सरकार अपने नागरिकों को इस तरह मारकाट करते देखती रह सकती है। राज्य सरकार तो इस मामले में शुरू से नाकाम साबित हुई है, मगर केंद्र सरकार ने इस पर अपेक्षित गंभीरता क्यों नहीं दिखाई, समझ से परे है। जिस तरह वहां महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उससे पूरी दुनिया में देश की छवि खराब हुई। मणिपुर के लोगों का सरकार और प्रशासन पर से भरोसा उठ चुका है। गांव वाले खुद सुरक्षा दल बना कर पहरेदारी करते और उपद्रवियों से बचने की कोशिश करते हैं। यानी वहां के लोगों को एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। संघ प्रमुख की मणिपुर को लेकर प्रकट की गई चिंता को केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, देखने की बात है।

मोदी का जंबो मंत्रिमंडल

गठबंधन धर्म की जरूरतों के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी का जंबो मंत्रिमंडल अपरिहार्य था। जाहिरा तौर पर मंत्रिमंडल के गठन में अनुभव,युवा, जातीय समीकरण, गठबंधन के दायित्व और आगामी विधानसभा चुनाव की प्राथमिकताएं स्पष्ट नजर आती हैं। जिसके चलते तीस कैबिनेट मंत्रियों की ताजपोशी हुई है। बहत्तर सदस्यीय मंत्रिमंडल में तीस कैबिनेट मंत्रियों में बिहार को तरजीह देना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू गठबंधन में एक बड़ा सहयोगी घटक है। वहीं मंत्रिमंडल में बड़े घटक टीडीपी व जद (सेक्यूलर) की भी उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण गड़बड़ाने के बाद चालीस से अधिक ओबीसी, एससी व अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मध्यप्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। दरअसल, महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी इन राज्यों के ज्यादा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में तेरह सीटों में एक भी प्रत्याशी के सफल न होने के बावजूद 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नया युवा नेतृत्व तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। पूर्व कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा है। कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन में संवेदनशील ढंग से रणनीति को अंजाम दिया गया। विश्वास किया जाना चाहिए कि लंबे चले चुनाव प्रचार अभियान में जो राजनीतिक व सामाजिक तौर पर कथित बांटने की कवायद वोटों के लिए की गई, उस पर अब विराम लगना ही चाहिए। आशा करें कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो पहली शर्त यही होगी कि कथित तौर पर विभाजनकारी राजनीति से परहेज करके सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। आरोप-प्रत्यारोपों की राजनीति पर विराम लगाकर मिलजुलकर देश को नई दिशा देने का प्रयास होना चाहिए। बहरहाल, अब कहा जा रहा है कि आजादी के बाद यह दूसरा अवसर है जब पं. नेहरू की तरह लगातार तीसरी बार भाजपा नीत सरकार बनी है। ऐसे कहने का अर्थ है कि सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तब तुलना यह भी की जाएगी कि किस सरकार के कार्यकाल में हकीकत के धरातल पर ज्यादा विकास हुआ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर देश-दुनिया की निगाहें लगी हैं। गठबंधन सरकार को पिछली सरकारों से बेहतर प्रदर्शन करके भी दिखाना होगा। राजग सरकार को स्वीकारना होगा कि यह एक गठबंधन सरकार है। यूं तो पिछली सरकार में भी राजग गठबंधन अस्तित्व में था, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण भाजपा की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। जिसके चलते मोदी सरकार के लिये पिछले कार्यकाल की तरह पार्टी के एजेंडे को लागू करने में खुला हाथ न मिलेगा। जाहिर है कि भाजपा को कई महत्वाकांक्षी मुद्दों मसलन 'एक देश, एक चुनाव' व यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि के क्रियान्वयन को ठंडे बस्ते में डालना पड़ सकता है। गठबंधन की मजबूरी के साथ ही सरकार को अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत विपक्ष से सामना करना पड़ेगा। निस्संदेह, शासन-प्रशासन का नरेंद्र मोदी के पास लंबा अनुभव है, लेकिन इस बार लचीलेपन का भी सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि, राजग में नेतृत्व तय करने व मंत्रिमंडल गठन में सहयोगी दलों का बड़ा दबाव नजर नहीं आया, लेकिन भविष्य की चुनौतियों से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, विकास कार्यों को गति देने में सरकार को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू विकास के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्रियों के रूप में याद किये जाते हैं। कोशिश हो कि राजनीतिक विरोधियों को भी साथ लेकर चला जाए ताकि संसद के पिछले कार्यकाल में पैदा हुआ गतिरोध फिर से न दोहराया जाए। बहरहाल, अब चाहे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हो या फिर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात, यह काम गठबंधन के सहयोगी दलों व व विपक्ष के साथ बेहतर सामंजस्य के साथ ही संभव हो सकता है। विकास के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से पहले देश में बेरोजगारी कम करने व समतामूलक विकास की स्थापना मोदी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रसंगतः महात्मा गांधी की नम्रता

गुजरात के राजकोट में काठियावाड़ राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन हो रहा था। बापू अन्य बड़े नेताओं के साथ मंच पर बैठे थे। तभी उनकी निगाह दूर नीचे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उन वृद्ध को पहचान लिया। वे बापू के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक थे। बापू तुरंत मंच से उतरकर उनके पास पहुंचे और चरण छूकर प्रणाम किया। फिर वे वहीं उनके पैरों के पास बैठ गए। शिक्षक भावविभोर हो गए और बोले, ''अब आप बहुत बड़े नेता हैं। आपका यहां बैठना अच्छा नहीं लगता। अब आप ऊपर मंच पर चले जाइये।'' बापू बोले, ''आपके लिए तो मैं सदैव आपका शिष्य ही रहूंगा।'' इसके बाद बापू पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठे रहे। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद शिक्षक ने बापू को आशीर्वाद देते हुए कहा, ''तुम जैसा विनम्र और अहंकाररहित व्यक्ति ही महान कहलाने का सच्चा अधिकारी है।'' विनम्रता, सादगी और अहंकाररहित जीवन जीने वाला ही महान बनता है।

संविधान एवं सर्वसम्मति के लिए जनादेश

भाजपा ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा लगभग 430 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे 240 सीटें ही मिल सकीं। उसने 63 सीटें खो दी, जिनमें अधिकांश उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के खाते में गयीं। इस बार यह मोदी 3.0 नहीं, बल्कि एनडीए 3.0, जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। इसके पहले दो संस्करणों के नेता वाजपेयी थे। फिर भी भाजपा को हाल के वर्षों में किसी भी सत्ताधारी दल से अधिक सीटें मिली हैं। वर्ष 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी, पर पांच साल बाद वह 197 पर ही जीत सकी। साल 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थीं। बहरहाल, प्रधानमंत्री और भाजपा के लिए इस चुनाव ने अनेक प्रश्न खड़े किये हैं और भविष्य में शासन के मॉडल के बारे में निर्देश भी दिया है। पार्टी को अभी यह स्वीकार करना है कि 370 सीटें भाजपा और 400 एनडीए के लिए जीतने का अवास्तविक लक्ष्य नहीं मिल सका है।

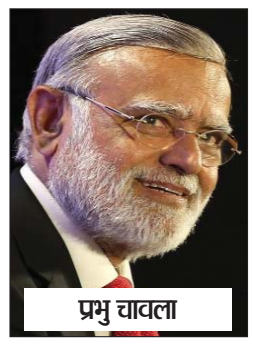

प्रभु चावला

कुछ लोग हार से तबाह हो जाते हैं और कुछ जीत कर ओछे हो जाते हैं। महानता उसमें होती है, जो हार व जीत को समान भाव से लेता है। प्रतिष्ठित अमेरिकी लेखक जॉन स्टीनबेक ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के हालिया लोकसभा चुनाव के नतीजे के विश्लेषण के बारे में उनकी टिप्पणी इतनी सटीक साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले ऐसा केवल जवाहरलाल नेहरू ही कर सके थे। यह रिकॉर्ड बनाने वाले वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे संघ प्रचारक भी हैं। फिर भी नेहरू और मोदी में गणित का अंतर है। नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव लगभग दो-तिहाई बहुमत से जीता था, पर भाजपा तीसरी बार अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और सरकार बनाने के लिए सहयोगियों का साथ लेना पड़ा है। इस जनादेश ने एक पार्टी के बहुमत की सरकार की अवधारणा पर गहरी चोट की है। भारत एक दशक बाद गठबंधन के युग में लौट आया है, जिसकी शुरुआत 1989 में राजीव गांधी की हार के साथ हुई थी।

भाजपा ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा लगभग 430 सीटों पर लड़ी थी, पर उसे 240 सीटें ही मिल सकीं। उसने 63 सीटें खो दी, जिनमें अधिकांश उसके पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के खाते में गयीं। इस बार यह मोदी 3.0 नहीं, बल्कि एनडीए 3.0, जिसका नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। इसके पहले दो संस्करणों के नेता वाजपेयी थे। फिर भी भाजपा को हाल के वर्षों में किसी भी सत्ताधारी दल से अधिक सीटें मिली हैं। वर्ष 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 404 सीटें जीती थी, पर पांच साल बाद वह 197 पर ही जीत सकी। साल 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली थीं।

मोदी अभी भी सबसे ताकतवर नेता हैं। उनकी अजेयता को झटका लगा है, लेकिन अभी भी उच्चतम नेता की उपाधि उन्हीं के पास है। उनकी दीर्घकालिक सफलता और तीसरा कार्यकाल पूरा कर इतिहास बनाने के लिए यह देश टकराव नहीं, बल्कि सर्वसम्मति की नयी राजनीति की ओर देख रहा है। केवल यही उपलब्धि उनकी महानता सुनिश्चित कर देगी।

दो माह के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री ने 200 से अधिक सभाएं कीं और लगभग 80 इंटरव्यू दिये। लेकिन इन आयोजित कार्यक्रमों से संविधान पर खतरा एवं बढ़ती बेरोजगारी के विपक्ष के नैरेटिव को बेअसर नहीं किया जा सका। साथ ही, निचले स्तर पर चुनाव प्रबंधन के लिए बाहरी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता से भ्रम पैदा हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बहुत कम सक्रियता से भी वोट घटे। लालकृष्ण आडवाणी ने 2004 में हार के तुरंत बाद कहा था कि भाजपा अपने मुख्य जनाधार की अनदेखी करने के कारण हारी है। आर्थिक नीतियों की कमी भी भाजपा की हार के लिए कुछ जिम्मेदार है। बीते एक दशक में भाजपा सरकार अपनी व्यवसाय समर्थक विचारधारा के बारे में गर्व से बोलती रही है। मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया है। यह जनादेश अच्छी राजनीति और न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था देने के लिए है। जनता को बाजार मॉडल पर बहुत अधिक जोर रास नहीं आया। ऐसा न के बराबर होता है कि शासन के प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री लोगों को नतीजों की घोषणा से पहले शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कहें। देश के समूचे स्वास्थ्य को कृत्रिम रूप से बढ़ायी गयी बाजार पूंजी के साथ जोड़ना नीतियों के लिए समर्थन मांगने का एक भ्रामक नैरेटिव है। अधिक से अधिक इससे बड़े कारोबारियों को ही फायदा हो सकता है, इससे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता।

नेताओं को भविष्य की तैयारी करते समय अतीत से सीखना चाहिए। अगर बाजार के सम्मोहन से राजनीतिक लाभ होता, तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को करारी हार नहीं देखनी पड़ती। अल्पमत की पहली सरकार बनाने वाले राव ने बड़े आर्थिक सुधार लागू किये। उनके पांच साल के कार्यकाल में शेयर सूचकांक 180 प्रतिशत से अधिक बढ़ा था। पर 1996 में राव हार गये क्योंकि लोगों को लगा कि कांग्रेस धनिकों की पक्षधर है। मनमोहन सरकार के दौर (2004-2014) में सेंसेक्स 400 प्रतिशत बढ़ा था, पर कांग्रेस लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल भी नहीं बन सकी। स्पष्ट है कि ट्रिकल डाउन (ऊपर से नीचे की ओर) का पश्चिमी पूंजीवादी सिद्धांत भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कारगर नहीं है, जहां 80 करोड़ से अधिक लोग सरकार की मुफ्त योजनाओं पर निर्भर हैं। मोदी के आर्थिक मॉडल में नायडू-नीतीश के सामाजिक समता के मॉडल को भी शामिल करना होगा। अच्छी अर्थनीति आवश्यक रूप से बेहतर राजनीति नहीं होती। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने या खरबपतियों की संख्या में वृद्धि होने से सरकार को मजबूती, भरोसा और स्वीकार्यता हासिल नहीं होती। किसी गठबंधन सरकार की सफलता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है कि गणित की नयी वास्तविकताओं को प्रधानमंत्री किस तरह निभाते हैं।

बीते 22 वर्षों में मोदी एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल के रूप में स्थापित हुए हैं, जिसमें वे अकेले निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वे राय मांगते हैं, पर वे सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अनुरूप नहीं चल पाते। इससे शीघ्र निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में मदद मिली है। वे नारे गढ़ने में भी माहिर हैं। स्वच्छ भारत से लेकर डिजिटल इंडिया तक, अपनी गारंटियों से उन्होंने देश को सम्मोहित किया है। अब तक वे ऐसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें वे असमान लोगों में प्रथम थे। लेकिन अब नयी संख्या और गणित से नीति-निर्धारण निर्देशित होगा। मोदी अभी भी सबसे ताकतवर नेता हैं। उनकी अजेयता को झटका लगा है, लेकिन अभी भी उच्चतम नेता की उपाधि उन्हीं के पास है। देश टकराव नहीं, बल्कि सर्वसम्मति की नयी राजनीति की ओर देख रहा है। केवल यही उपलब्धि उनकी महानता सुनिश्चित कर देगी। नयी सरकार को संख्या के बजाय नेकी, खरबपतियों से हाथ मिलाने के बजाय आम जन के स्पर्श तथा निर्देश के बजाय प्रतिनिधित्व की राह पर चलने की आवश्यकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर है)

https://t.me/AllNewsPaperPdf

मोदी-बीजेपी से खटास के बीच संघ प्रमुख का यूपी में प्रवास

- संजय सक्सेना

एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और मोदी सरकार के बीच दूरियां नजर आ रही हैं,वहीं उसी समय सरसंघचालक मोहन भागवत पांच दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंच गये हैं। भागवत यहां संघ के चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में वह स्वयंसेवकों को विकास की टिप्स देने का कार्य करेंगे।माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में मिली करारी हार को लेकर भी मंथन कर सकते हैं. हालांकि, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हैं. भागवत 16 जून तक यहां वास करेंगे और कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम के अलावा, गोरखपुर के किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. 17 जून की सुबह को वह गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे। 13 जून दिन गुरुवार को उनका विकास वर्ग में स्वयंसेवकों के बीच संबोधन होगा। संघ के प्रचार अभियान से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत कार्यकर्ता विकास वर्ग में, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आयोजित हो रहे स्वयंसेवक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं. यह संघ के ऐसे कार्यकर्ताओं का विकास वर्ग है जिनके ऊपर संघ का कोई दायित्व है।इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं।

गोरखपुर में आयोजित आरएसएस विकास का वर्ग कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कानपुर, गोरक्ष प्रांत, अवध और काशी प्रांत के कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें करीब 280 लोग प्रतिभागी कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों का पूरी तरह से यहां ही प्रवास रहेगा। इस दौरान यह किसी से संपर्क में नहीं आ सकते। सरसंघचालक मोहन भागवत अपने 5 दिन के प्रवास के दौरान संघ के पदाधिकारी को संगठन के आगामी कार्य योजनाओं से भी अवगत कराएंगे और उसके संचालन की रणनीति बताएंगे.संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत गोरखपुर में छठवीं बार पधार रहे हैं. पहली बार वह कार्यकारी मंडल की बैठक में गोरखपुर हिस्सा लेने के लिए आए थे. जिसमें देशभर के संघ के पदाधिकारी गोरखपुर में इकट्ठा हुए थे. इसके पहले और पिछली बार उनका 20 मार्च 2022 को गोरक्ष प्रांत के स्वयंसेवकों की बैठक को, संबोधित करने के लिए तीन दिन के लिए गोरखपुर में आना हुआ था. उनका यह ताजा दौरा स्वयंसेवकों को सक्रियता के जरिए संगठन को मजबूती पर लाने का है. इस कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक रमेश और क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र जायसवाल की भी उपस्थित रहेगी.भागवत का यह दौरा तब हो रहा है जब आरएसएस और बीजेपी एवं मोदी सरकार के बीच कुछ दूरियां नजर आ रही हैं।

गौरतलब हो, लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और भाजपा में दूरी दिखी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उससे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिखे हों। जिलों में न तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखीं और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे-छोटे स्तर पर अमूमन होने वाली संघ परिवार की बैठकें होती नजर आईं। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह भी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे।

सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ ने चुनाव से किनारा कर लिया। संघ से जुड़े कुछ वर्तमान, पूर्व पदाधिकारियों व प्रचारकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह भाजपा के एकांगी निर्णय और संघ परिवार के संगठनों के साथ संवादहीनता रही। माना जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान कि भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है। इसलिए उसे अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है, ने भी स्वयंसेवकों उदासीन कर दिया। संघ के एक पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि संघ अचानक तटस्थ होकर नहीं बैठा था। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद आत्ममुग्धता से लबरेज भाजपा ने अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था।

भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह की अनदेखी कर एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर डाले, जिनसे संगठन की साख और सरोकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजिमी था, इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे।

बात सियासत की कि जाये तो बताया जाता है कि संघ ने उत्तर प्रदेश की कौशांबी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी वयक्त की थी। जानकारी के मुताबिक, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा था कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को शामिल करना उचित नहीं है। इससे गुटबाजी बढ़ रही है। साथ ही संगठन की साख पर भी सवाल उठ रहा है। पर, उसकी सलाह नहीं मानी गई। लिहाजा संघ उदासीन हो गया। संघ से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने कई क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इसमें भी संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई। खासतौर से गोरक्ष प्रांत और काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

यही नहीं, इस बार के चुनाव भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किया था, जो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें न तो संबंधित लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी थी और न ही जातीय समीकरण व मुद्दों की। मतदाताओं के बीच भी बाहरी प्रभारियों की कोई पकड़ नहीं थी। लिहाजा तमाम प्रभारियों ने जमीन पर काम करने के बजाय सिर्फ क्षेत्रों में होने वाले बड़े नेताओं के सभाओं में चेहरा दिखाने तक ही खुद को सीमित रखा।

जानकारों का कहना है कि इस बार भाजपा का चुनाव प्रबंधन सिर्फ कागजों पर नजर आया था। संघ भी उदासीन हुआ तो ज्यादातर स्थानों पर न तो भाजपा के वोटरों को निकालने वाले दिखे और न उन्हें समझाने वाले। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर 2014, 2019, 2017 और 2022 वाला प्रबंधन नहीं दिखा।यह दूरियां तब बढ़ी हैं जबकि चुनाव की घोषणा के एक साल पहले ही संघ परिवार ने अपने वैचारिक कार्यक्रम के तहत जनता से संवाद शुरू कर दिया था। घोषणा होने तक हर लोकसभा क्षेत्रों में एक-एक लाख बैठकें हो चुकी थीं।संघ के जमीनी कार्यकर्ता 10-20 परिवारों के साथ बैठकें करके मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर हुए कार्यों की चर्चा कर माहौल बनाया था, लेकिन भाजपा, संघ के इस कवायद का भी फायदा नहीं उठा पाई। संघ से दूरी बनाने का दुष्परिणाम यह भी रहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला भाजपा का संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहा। माना जा रहा है कि संघ से बेहतर समन्वय नहीं बनने की वजह से भाजपा की अधिकांश बूथ कमेटियां व पन्ना प्रमुख भी निष्क्रिय बैठे रहे। वहीं संघ के स्थानीय कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच काम करते हैं और संगठन से जनता को जोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। समन्वय नहीं होने की वजह से दोनों तरफ के कार्यकर्ता उदासीन रहे। नतीजा यह हुआ कि तमाम घरों पर परिवारों तक पर्चियां तक नहीं पहुंच पाई।आरएसएस के स्वयं सेवक दबी जुबान से इस बात पर संतोष भी व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार ने मनमानी की उसमें ऐसे नजीजे आना स्वभाविक ही था।अब देखना है कि बीजेपी और मोदी सरकार क्या आरएसएस से संबंध सुधारने के लिये कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर आत्ममुग्ध रहेगी।

सम्पादकीय

संघ की नाराजगी कहां तक ले जाएगी भाजपा को

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भाजपा के लिए क्या मायने रखता है ये इन लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया है। संघ सक्रिय तो भाजपा मस्त और संघ निष्क्रिय तो भाजपा अस्त। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ की आवश्यकता नहीं बताई थी तो संघ ने बताया कि अब भी उसके बिना भाजपा की रेल पटरी पर नहीं चल सकती। दो दिन पहले नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में जो कुछ कहा, वह अपरोक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर चलाए गए तीर थे। अहंकार, झूठ, चुनावी युद्ध, विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष, मर्यादा का पालन जैसे शब्द उन्होंने ऐसा लगता है मानो प्रधानमंत्री को नसीहत देने के लिए ही कहे हो। भागवत में कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष हमेशा से अहंकारी होने का आरोप लगाता रहा है। भाजपा में भी कहा जाता है कि सरकार सिर्फ दो लोग मोदी और अमित शाह ही चलाते हैं। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 2014 से 2019 तक जो सरकार भाजपा की थी। वो 2019 से 24 के बीच मोदी सरकार बनकर रह गई और 24 के चुनाव में तो गारंटी भी मोदी की दी जाने लगी यानी भाजपा पूरी तरह से गौण और मोदी प्रमुख हो गए। सत्ता में आने के बाद खुद को प्रधान सेवक बताने वाले मोदी के इस बार 400 के पार, लोग चुनाव के बाद विपक्ष को ढूंढेंगे, मोदी को कम मत आंकना, अपनी पर आ गया तो तुम्हारी (विपक्षी नेताओं) की सात पीढ़ियों की पोल खोल देगा, घमंडिया गठबंधन, एक-एक को जेल में डाल दूंगा जैसे नारे और चुनावी भाषण भी मोदी के इसी अहंकार के परिचायक माने गए।

भागवत ने कहा है कि चुनाव में मुकाबला जरूरी है और एक दूसरे को पीछे भी धकेलना होता है लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि चुनाव में बहुमत के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन यह चुनाव ऐसे लड़ा गया, जैसे युद्ध हो। दोनों पक्षों ने कमर कस कर हमला किया। इससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं कि इस बार चुनाव में जितना हिंदू- मुस्लिम खुलकर हुआ और किया गया, पहले ना कभी हुआ है और न भविष्य में इससे ज्यादा होने की संभावना है। भाजपा ने जहां मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने को लेकर खुलेआम बयान दिए। मोदी ने तो हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांटने, मंगलसूत्र छीन लेने, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए जैसे भाषण दिए। वहीं विपक्ष अपने वोट बैंक के लिए मुसलमानों के रक्षण में लगा रहा। चुनाव परिणामों ने बताया कि इस बार मुसलमान ने जितना एक होकर मतदान किया, पहले कभी नहीं किया था। भाजपा को बहुमत से कम सीटें मिलने का एक बड़ा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में मुसलमानों का थोक मतदान रहा। जो एकता मुस्लिम मतदाताओं ने दिखाई, वह जाति-वर्ग में बंटे हिंदू मतदाताओं में दूर तक नहीं दिखाई दी।

मालदीव के बिगड़े संबंध सुधरने की संभावना बढ़ी

मोहम्ममद नशीद की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत-मालदीव के रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। नशीद ने भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू के शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री मोदी को उनके धैर्य और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी है। उन्होंने मुइज्जू के इस फैसले को भारत के प्रति मालदीव की विदेश नीति में सुधार की संभावना वाला बताया है। इसके साथ ही अब मालदीव के संबंध चीन के साथ कैसे होंगे इस बात पर विश्लेषकों की नजर है।

अशोक भाटिया

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर उनके ही सबसे बड़े विरोधी का भी समर्थन मिला है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा, भारत-मालदीव संबंधों के वर्तमान संभावनाओं को देखते हुए उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स मोहम्मद मुइज्जू का समर्थन करती है। मुइज्जू 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन अब मुइज्जू को दिल्ली दौरे के बाद एक बार फिर नए रिश्तों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मालदीव के मीडिया पोर्टल सन ने मोहम्मद नशीद के हवाले से कहा कि प्रत्येक चुनाव में देश की विदेश नीति बदल देना मालदीव के लिए लोगों के लिए बड़ा नुकसान है।

मोहम्मद नशीद ने कहा, मालदीव के लोग इस बात से काफी खुश हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए उनके राष्ट्रपति नई दिल्ली में मौजूद रहे। नशीद ने विपक्ष में रहते हुए मोहम्मद मुइज्जू के इंडिया आउट कैंपेन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मुइज्जू के इस कदम को मालदीव के लोगों के लिए भारत खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया था। दरअसल, साल 2008 से 2012 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ गहरा संबंध बनाए रखा था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के कुछ समय बाद ही भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट अभियान चलाने वाले मुइज्जू ने सत्ता संभालने के बाद मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया, जो दो हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए वहां मौजूद थे। बाद में इन सैनिकों की जगह भारत ने नागरिक कर्मियों की तैनाती की। भारत के बजाय राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इसी साल जनवरी में अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जुबानी हमलों में जहर उगला था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण मिलने के बाद मुइज्जू ने कहा था कि वे भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यात्रा मालदीव के लिए बहुत सफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और (विदेश मंत्री) एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करने के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध भविष्य में मालदीव के लिए आकांक्षाओं को और बढ़ाएंगे। भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने

मंगलवार को कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा संपन्न होने के बाद सरकारी मीडिया पीएसएम से कहा, यह यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए भी सफल रही है। मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। मुइज्जू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण पाकर खुशी हुई और वह इस कार्यक्रम में शामिल होकर भी ''उतने ही खुश'' हैं।

उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और एस जयशंकर (विदेश मंत्री) के साथ उच्चस्तरीय बैठकों के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध भविष्य में मालदीव के लिए आकांक्षाओं को और मजबूती देंगे।' मुइज्जू ने कहा, ईश्वर की इच्छा से, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के परिणामस्वरूप मालदीव और मालदीववासियों के लिए समान रूप से समृद्धि बढ़ेगी। इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा था कि राष्ट्रपति (मुइज्जू) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इसमें कहा गया, यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणमान्य अतिथियों के सम्मान में आयोजित भोज में भाग लिया। बयान में बताया गया कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि मुर्मू ने मालदीव की नयी सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दीं। बयान में कहा गया, ''उन्होंने (मुर्मू) विश्वास व्यक्त किया कि मुइज्जू के नेतृत्व में द्वीप राष्ट्र समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।'' नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुर्मू ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत-मालदीव के संबंध मजबूत होंगे ।दरअसल भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक विवाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों तक पहुंच गया। यह सब 4 जनवरी को शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और खूबसूरत द्वीप की तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब भारत में इतनी खूबसूरती है तो कोई मालदीव क्यों जाए। इसका एक संदर्भ भी है। सरकार में बदलाव के कारण मालदीव में भारत विरोधी गुट सत्ता में आ गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मिलकर द्वीपीय राज्य में चुनावों के दौरान %इंडिया आउट% अभियान चलाया था ।सोशल मीडिया पर एक बड़े युद्ध के चलते मालदीव के तीन उप-मंत्रियों और कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था । ट्रोल्स के बीच चल रही जंग कूटनीतिक स्थिति में बदल गई। भारत को इसका जवाब देना पड़ा था ।भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया था ।मुइज़्ज़ू प्रशासन अपनी ओर से दोनों पक्षों - चीन और भारत - को साधने की कोशिश कर रहा है। सावधानी बरतते हुए मुइज़्ज़ू प्रशासन ने तीन अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि उसी समय कई मालदीववासी इस घटनाक्रम से नाखुश थे ।उस समय छुट्टियों के लिए माले आए भारतीय पर्यटकों से बात करते हुए मीडिया को जो एहसास हुआ, वह यह था कि ज़्यादातर मालदीवियों की तरह वे भी दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास नहीं चाहते। एक भारतीय पर्यटक ने कहा था इस विवाद से मालदीव में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लक्षद्वीप में रोज़गार बढ़ सकता है।

आज का इतिहास

13 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

1420 - जलालुद्दीन फ़िरोजशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
1940 - जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लेने वाले भारतीय ऊधमसिंह को लंदन में फाँसी दे दी गई।
1993 - किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।
1997 - दिल्ली के उपहार सिनेमाघर् में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 100 से अधिक लोग घायल हो गए।
2001 - नेपाल शाही परिवार हत्याकांड में दीपेन्द्र की प्रेमिका देवयानी का जांच आयोग के समक्ष गवाही से इन्कार।
2002 - 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते की समय सीमा समाप्त।
2003 - डेनियल अखमितोव कजाकिस्तान के नये प्रधानमंत्री नियुक्त।
2004 - लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ़ कबीला के ख़िलाफ़ तख़्ता पलट का प्रयास विफल। ईराक के विदेश उपमंत्री बासम सालिह कुन्बा की हत्या।
2005 - ईरान 2009 के अन्त से 25 वर्षों के लिए भारत को तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात करने पर सहमत।
2006 - नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया।
2008 - टेलिकॉम मलेशिया (टीम) ने आइडिया सेलुलर कम्पनी की 15% हिस्सेदारी ख़रीदी।
चीन और ताइवान ने विमान सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

13 जून को जन्मे व्यक्ति

1994 - दीपिका कुमारी - भारतीय महिला तीरंदाज हैं।
1964 - पीयूष गोयल - भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं में से एक हैं।
1944 - बान की मून - संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवें महासचिव थे।
1923 - प्रेम धवन, हिंदी सिनेमा जगत् के मशहूर गीतकार

13 जून को हुए निधन

2016 - मुद्राराक्षस - भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार थे।
2012 - मेहदी हसन - प्रसिद्ध ग़ज़ल गायक
2008 - कीर्ति चौधरी - तीसरे सप्तक की एकमात्र कवयित्री
1999 - मेजर मनोज तलवार - भारतीय सेना के जाबांज सैनिकों में से एक थे।
1999 - मेजर विवेक गुप्ता - %महावीर चक्र% से सम्मानित भारत के जांबाज सैनिक थे।
1994 - राज कुमार जयचंद्र सिंह - मणिपुर के भूतपूर्व सातवें मुख्यमंत्री थे।
1967 - विनायक पांडुरंग करमरकर - भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे।
1922 - नानक भील - अंग्रेज़ों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे।
1719 - रफ़ीउद्दाराजात - दसवाँ मुग़ल बादशाह था।

विशेष आलेख

भाजपा जानती है गठबंधन सरकार का धर्म

आर.के. सिन्हा

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना कामकाज संभाल लिया है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेगी। वास्तव में, भाजपा की पहली सरकार, जो 1996 में गठित हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक गठबंधन की सफल प्रयोग वाली सरकार थी। भले ही वह केवल 13 दिन चली। अटल जी 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पुन: वापस आए थे। इसलिए यह कहना सरासर गलत होगा कि भाजपा को गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है। भाजपा को 2014 में 283 और 2019 में 303 सीटें मिली थीं। उन जीतों में मोदी जी की सबसे अहम भूमिका रही थी। लेकिन, पूर्ण बहुमत के बाद भी मोदी जी ने गठबंधन का धर्म निभाया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं- बहुमत से 32 कम। यह तय मानिए कि जो विकास का पहिया 2014 में घूमना शुरू हुआ था, वह अब गठबंधन सरकार के दौर में भी आगे बढ़ता ही रहेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में 14 पार्टियां शामिल हैं। उसमें भाजपा को 240 सीटों पर विजय मिली और शेष 53 सीटें हासिल कीं, उसकी सहयोगी दलों ने। अगर हम गुजरे दौर के पन्नों को खंगाले तो पता चलेगा कि कि भारत में सबसे पहले 1977-1979 गठबंधन सरकार बनी थी। कांग्रेस के 1977 में चुनाव हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार देश में बनी थी। 1977 के चुनाव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की स्थिति लागू करने के लगभग दो साल बाद हुए थे। श्रीमती गांधी ने आपातकाल हटा दिया और जनवरी 1977 में अचानक चुनावों की घोषणा की। श्रीमती गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस को जनता पार्टी नामक कई पार्टियों के एक गठबंधन द्वारा हराया गया था, जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ शामिल थी। जनता पार्टी को देश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेशमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारणमंत्री थे। उस सरकार में बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, जॉर्ज फर्नाडीज जैसे जननेता भी शामिल थे। बहरहाल, जनता पार्टी की उस चुनाव में जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार दो साल तक चली। उसके बाद वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई सरकार में गृहमंत्री चरण सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। संयोग देखिए कि अब चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी उस एनडीए सरकार का हिस्सा हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। बहरहाल, चरण सिंह 1979 में जनता पार्टी के बिखरे हुए समूहों के समर्थन और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। लेकिन चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 23 दिन तक चला क्योंकि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे चरण सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस स्थिति के कारण देश में लोकसभा भंग करने के बाद 1980 में फिर चुनाव हुआ। इस बार इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गईं। कांग्रेस ने 353 सीटें जीतीं। लोकसभा के 1989 के चुनाव परिणाम भारत के लिए एक नये दौर को लेकर आए। यह पहली बार था जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा 529 सीटों में से 197 जीतने के बाद किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया था। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार 1990 में गिर गई जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया , जब उस समय के सबसे बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आयोजित उनकी यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था।1989 से 2004 तक, छह आम चुनाव में एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इनमें से कुछ गठबंधन विशेष रूप से अराजक रहे। 1989 और 1999 के बीच, आठ गठबंधन बनाए गए और कई जल्दी ही ढह गए। इस बीच, ये मानना होगा कि भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों के समय ही आए। अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे, जिन्होंने 1998 से 2004 तक एक सफल बहु-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्वकाल में भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेज हुआ। व्यापार बाधाओं को कम किया गया। देश में आईटी क्रांति का जन्म हुआ। उनके ही दौर में देश ने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान के साथ तनाव को कम किया और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। और अतीत में, सफल अल्पसंख्यक सरकारें और भी कम सीटों के साथ चलाई गई हैं। कांग्रेस 1991 में 232 सीटों के साथ और 2004 और 2009 में केवल 145 और 206 सीटों के साथ एक सफल अल्पसंख्यक सरकार चलाने में सक्षम कोशिश की थी। मैं मानता हूं कि मोदी जी जनता दल (यू) के नेता नीतीश कुमार और तेलुगू देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जैसे तपे हुए नेताओं के सहयोग से देश को एक मेहनती और ईमानदार गठबंधन सरकार देने में सफल रहेंगे। उन्हें अपनी पार्टी के अनेक अनुभवी नेताओं का समर्थन और सहयोग तो मिलेगा ही। अब लोकसभ चुनाव के बाद केन्द्र में सरकार गठित हो गई है। अब इंडी गठबंधन को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। उन्हें हर बात पर सरकार को कोसना छोड़ना होगा। रोज विधवा विलाप करने की आदत छोड़नी होगी। आप चुनाव प्राचर के समय तो कुछ भी बोलते हैं। पर चुनाव नतीजों के आने के बाद आपको अपनी बयानबाजी सोच-समझकर करनी होती है। हां, विपक्ष को सरकार को राष्ट्र हित के मसलों पर सजग करते रहना होगा। लोकतंत्र में वाद, विवाद, संवाद लगातार जारी रहना चाहिए। इसके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है।

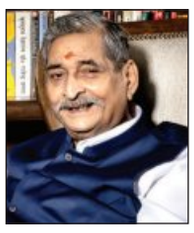

निरंतरता, अनुभव और उत्साह का संगम है केंद्रीय मंत्रिमंडल

डॉ.संजय द्विवेदी

केंद्र सरकार का नया मंत्रिमंडल निरंतरता की गवाही देता है। यह बात बताती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी टीम पर भरोसा कायम है। प्रमुख विभागों में अपनी आजमाई जा चुकी टीम को मौका देकर मोदी ने बहुत गंभीर संदेश दिए हैं। मंत्रिमंडल में अनुभव, उत्साह और नवाचारी विचारों के वाहक नायकों को जगह मिली है। यह मंत्रिमंडल गहरी राजनीतिक सूझबूझ वाले नायकों से संयुक्त है। लंबे समय तक राज्य सरकारों को चलाने वाले सात पूर्व मुख्यमंत्री इस सरकार में शामिल हैं। कैबिनेट में मोदी सहित सात पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। जिनमें मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश), शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश), जीतनराम मांझी (बिहार), एचडी कुमारस्वामी (कर्नाटक), मनोहरलाल (हरियाणा), सर्वानंद सोनोवाल (असम) मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत सरकार के विदेश सचिव और पिछली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके एस .जयशंकर अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। आईएएस अधिकारी रहे अश्विनी वैष्णव अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनके सचिव रहे, विविध अनुभव संपन्न वैष्णव सरकार में नवाचारों के वाहक हैं। पिछली सरकार उनके प्रदर्शन की गवाही है। इसी क्रम में नौकरशाह रहे हरदीप सिंह पुरी सरकार की शक्ति हैं। नितिन गडकरी का महाराष्ट्र सरकार से लेकर अब केंद्र में 10 साल का कार्यकाल सबकी नजर में है। देश में हुई परिवहन और सड़क क्रांति के वे वाहक हैं। वे केंद्र में सबसे लंबे समय तक परिवहन मंत्री रहने का रिकार्ड बना चुके हैं। भाजपा के पास अनुभवी मंत्रियों की टीम सरकार के संकल्पों की वाहक बनेगी, इसमें दोराय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी,किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव,जोएल ओराम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉ.वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी हस्ताक्षर बन चुके हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रभावी संचालन का रिकार्ड इनके नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और अमित शाह इस सरकार के संकटमोचक हैं। राजनाथ सिंह के साथ जहां सहयोगी दलों का शानदार संवाद है, वहीं अमित शाह अपने कुशल राजनीतिक प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। इस सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री हैं। जबकि 2014 में पांच और 2019 में सहयोगी दलों के चार मंत्री शामिल थे। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार में कुशल प्रबंधन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव भी होने हैं। यही इस सरकार का पहला सार्वजनिक टेस्ट भी है। मंत्रिमंडल में प्रतिबद्धता, निरंतरता और वरिष्ठता का ख्याल रखते हुए भी युवाओं को खास मौके दिए गए हैं। इसके साथ ही यह अखिल भारतीय चरित्र की सरकार भी है, केरल, तमिलनाडु से लेकर जम्मू-कश्मीर तक का प्रतिनिधित्व इस सरकार में है। पांच अल्पसंख्यक समुदायों से भी सरकार में मंत्री बने हैं। साथ ही सामाजिक समरसता की दृष्टि से यह समावेशी सरकार कही जा सकती है। अभी तक की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सुशासन को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आज आप नए काम आसानी से शुरू कर सकेंगे, परंतु आपके विचारों में स्पष्टता न होने से उलझन बढ़ने की आशंका है। व्यापार में प्रतियोगी को पछाड़ना मुश्किल होगा। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे लाभ होगा।

वृष
साहित्य में रुचि रखने वाले बौद्धिक लोगों से मिलकर ज्ञान की चर्चा में समय व्यतीत होगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाना हो सकता है। विदेशगमन और विदेश स्थित आपके रिश्तेदार या दोस्तों से बातचीत की संभावना है।

मिथुन
आपको समय से भोजन नहीं मिलने की आशंका बनी रहेगी। आपको गलत और गैरकानूनी काम से आज दूर ही रहना चाहिए। किसी बात का डर हो, तो ध्यान करके मन को शांत रखें। आज का दिन तर्क-वितर्क के लिए अच्छा है।

कर्क
नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी। यात्रा होने की भी संभावना है। नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे। सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

सिंह
पारिवारिक जीवन में मेल और शांति रहेगी। व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है। विदेश गमन होगा और वहां रहने वाले अपनों का समाचार प्राप्त कर सकेंगे। आपका स्वास्थ्य खराब होगा। संतान का स्वास्थ्य चिंता में डालेंगे।

कन्या
वित्तीय लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार में लोगों के साथ मतभेद हो सकता है। किसी उलझन के कारण महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने की सलाह दी जाती है। आपको खर्च पर काबू रखना होगा।

तुला
आज आपको लाभ होने की संभावना है, परंतु आपका मनोबल स्पष्ट न हो, तो मिला हुआ अवसर भी खो सकते हैं। मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

वृश्चिक
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी कामों में आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। संतान के लिए पूंजी निवेश करेंगे। नई योजना का आरंभ करने के लिए आज अनुकूल दिन है। सरकारी काम में लाभ होगा।

धनु
उलझनपूर्ण मानसिकता के कारण महत्वपूर्ण अवसर खो सकते हैं। जिद्दी स्वभाव के कारण किसी के साथ मतभेद हो सकता है। अपनी मीठी वाणी से आप किसी को भी आकर्षित कर सकेंगे। आपके परिवार में शांति बनी रहेगी।

मकर
आज आपको लाभ होने की संभावना है, परंतु आपका मनोबल स्पष्ट न हो, तो मिला हुआ अवसर भी खो सकते हैं। मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा। व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

कुंभ
आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। संतान के मामले में चिंता रहेगी। आज सावधानीपूर्वक आगे बढ़े और महत्वपूर्ण काम आज हाथ में न लें, तो अच्छा होगा। उग्र स्वभाव और खराब व्यवहार के कारण आप तकलीफ में आ सकते हैं।

मीन
किसी के साथ संघर्ष या विवाद होने की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सजग ना रहने पर सेहत खराब हो सकती है। कानूनी मामलों में सजगता के साथ आगे की ओर बढ़ें। आपकी प्रतिष्ठा को कलंक लगने या आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सफल भी एवं सक्षम भी होगी मोदी की तीसरी पारी

-ललित गर्ग

एक और इतिहास रचते हुए नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। यह देश ही नहीं दुनिया के लिए एक अद्भुत एवं विलक्षण राजनीतिक घटना है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम शासनाध्यक्षों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोदी के इस तीसरे कार्यकाल पर देश-दुनिया की नजरें इसलिये भी टिकी हैं कि मोदी सरकार 3.0 का अजेंडा पिछली गठबंधन सरकारों से अलग होकर भी सशक्त है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली इस सरकार में 71 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ शपथ ली। मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पिछले दस साल में देश को विकास के कहीं ज्यादा ऊंचे मुकाम पर खड़े करते हुए दुनिया को चौंकाया है। 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जीडीपी के आकार के हिसाब से हमने पिछले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और 2026 तक जापान तो 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इन लक्ष्यों की ओर तेजी से कदम बढ़ाना नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसक साथ ही सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास इस सरकार का ध्येय है।

प्रधानमंत्री मोदी इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए एक नया इतिहास बनायेंगे, उम्मीद की जा रही है कि बिना बाधा एवं गठबंधन की शर्तों के वे देश-विकास के अपने एजेंडे को सफलतापूर्वक एक नई ऊंचाई देंगे। उनकी लोकसभा चुनाव-2024 की उपलब्धि की महत्ता इसलिये भी कम नहीं हो जाती, क्योंकि भाजपा बहुमत से कुछ ही दूर है। चूंकि सहयोगी दल मोदी सरकार को सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मंत्रियों का चयन सुगम तरीके से हो गया इसलिए यह आशा की जाती है कि मोदी की तीसरी पारी भी सुगमता एवं त्वरित गति से चलेगी। इसका एक कारण यह भी है कि उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता तथा समन्वय की राजनीति करने का कौशल भी। गठबंधन दलों को भी समन्वय एवं सौहार्द का वातावरण बनाना होगा, इसी में उनका राजनीतिक हित है। वे विपक्षी दलों के बहकावे में न आये, वरना यहां मोदी एवं शाह के पास अन्य विकल्प हैं जो मोदी सरकार को संकट में नहीं जाने देंगे। मोदी की राजनीतिक यात्रा को देखा जाए तो उन्होंने अनेक ऐसी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी-पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में।

मोदी के सामने चुनौतियां पूर्ण बहुमत के दौर में भी रही है और अब भी कायम है। इस राह पर दो बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं, जिनकी अनदेखी करते हुए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ये हैं बेरोजगारी और असमानता। इंटरनैशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के मुताबिक देश में 80 प्रतिशत बेरोजगार युवा हैं। गरीब मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य भी सामने हैं। पूर्व के दौ कार्यकाल में मोदी ने इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। जहां तक असमानता की बात है तो उसे अक्सर तेज विकास के आगे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन याद रखने की बात है कि तेज विकास को अगर टिकाऊ बनाना हो तो असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी मौलिक सोच एवं दृष्टि से मोदी सरकार 3.0 का अजेंडा दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला होगा। संभावना है कि मोदी की तीसरी पारी में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे में निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी की गारंटियों पर बल दिया जायेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल और सामाजिक विकास की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति दी जायेगी। वन नेशन, वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों पर राजनीतिक मजबूरी की विशेष छाप देखने को मिल सकती है। लेकिन मोदी की कोशिश रहेगी कि वे अपने इन मुद्दों को भी आकार दे सके। इनमें कुछ विलम्ब हो सकता है, लेकिन ये और ऐसे अनेक मुद्दें मोदी की प्राथमिकता बने रहेंगे।

पिछले दस वर्षों का मोदी का कार्यकाल यह बताता है कि जहां उन्होंने देश विकास की एक अमिट गाथा लिखी, वहीं वे देश में सबसे सशक्त और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे और विश्व पटल पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ते हुए भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इससे विश्व में भारत का मान बढ़ा और इसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल साहसिक फैसले लिए, बल्कि विकास और जनकल्याण के ऐसे कार्य किए जिसने देश की तस्वीर बदली, भारत का विकास हुआ। अब वह विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि गठबंधन सरकार के बावजूद कमान प्रधानमंत्री के हाथ में है और उन्होंने यह कहा है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस एजेंडे के प्रति सहयोगी दलों और विशेष रूप से टीडीपी और जेडीयू ने भी अपनी संकल्पबद्धता जताई है इसलिए मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पारी निरंतरता, साहसिकता, दृढ़ता का परिचायक ही होगी। राजनीति की लंबी पारी ने मोदी को दृढ़ता के साथ ही लचीलेपन का भी पाठ पढ़ाया है। कोई कारण नहीं कि राजनीतिक विरोधियों को साथ लेने में दिखाया गया लचीलापन सहयोगियों को बनाए रखने में काम नहीं आएगा। दूसरी बात यह कि चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार, दोनों विकास की राजनीति का चेहरा रहे हैं।

मंत्रिमण्डल का गठन करते हुए ऐसा नजर नहीं आया कि भाजपा गठबंधन सहयोगियों के किसी तरह के दबाव में हो। पिछली सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले भाजपा के सांसद वरिष्ठता क्रम में शपथ लेते नजर आए। मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन के हितों के साथ ही जातीय संतुलन और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। हरियाणा में भले भी पांच सांसद इस बार चुने गए हों, लेकिन इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कैबिनेट व राव इंद्रजीत सिंह तथा कृष्णपाल सिंह को राज्यमंत्री बनाया गया। वहीं पंजाब से कोई भाजपा सांसद नहीं चुना गया लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। झारखंड में इस साल चुनाव होने हैं तो राज्य को तीन मंत्री दिये गए हैं। मोदी का मंत्रिमण्डल देश विकास के साथ राजनीतिक अपेक्षाओं के अनुरूप प्रभावी एवं सशक्त एक तीर से अनेक निशाने साधते हुए दिखा।

निश्चित रूप से भाजपा अपने सहयोगी दलों के प्रति उदार एवं समन्वयमूलक रवैये अपनाएगी। राजग की कोशिश है कि गठबंधन को मजबूत करके इस बार सशक्त होकर उभरे विपक्ष का मुकाबला किया जा सके। इतना तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अग्निपथ, समान नागरिक संहिता, बेरोजगारी व महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजग सरकार के लिये कड़ी चुनौती पेश करेगा, लेकिन सहयोगी दलों के साथ भाजपा उनका मुकाबला करने के लिये तैयार है। एक सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली राजग सरकार सहयोगी दलों की आकांक्षाओं के बीच पिछले दो कार्यकाल की गति से काम कर पाएगी? निश्चित ही मोदी उसी अंदाज एवं दबंगता से अपनी योजनाओं एवं नीतियों को आगे बढ़ायेंगे। मोदी के विजन में जहां हर हाथ को काम का संकल्प साकार होगा, वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर होगा। मोदी के नये संकल्पों एवं योजनाओं से देश विकास की दशा एवं दिशा स्पष्ट होगी। आदिवासी समुदाय एवं अर्थव्यवस्था के उन्नयन एवं उम्मीदों को आकार देने की दृष्टि से मोदी सरकार मील का पत्थर साबित होगी। साथ-ही-साथ समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास सुनिश्चित होगा। सशक्त होती अर्थव्यवस्था इस मायने में उम्मीद की छांव देने वाली साबित होगी, जिससे शहर एवं गांवों के संतुलित विकास पर बल मिल सकेगा। जिससे नया भारत- सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी बलशाली बन सकेगा। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक सरकार के विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

मालदीव के बिगड़े संबंध सुधरने की संभावना बढ़ी!

अशोक भाटिया

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर उनके ही सबसे बड़े विरोधी का भी समर्थन मिला है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा, 'भारत-मालदीव संबंधों के वर्तमान संभावनाओं को देखते हुए उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स मोहम्मद मुइज्जू का समर्थन करती है।' मुइज्जू 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे।

राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन अब मुइज्जू को दिल्ली दौरे के बाद एक बार फिर नए रिश्तों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मालदीव के मीडिया पोर्टल सन ने मोहम्मद नशीद के हवाले से कहा कि प्रत्येक चुनाव में देश की विदेश नीति बदल देना मालदीव के लिए लोगों के लिए बड़ा नुकसान है।

मोहम्ममद नशीद की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत-मालदीव के रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। नशीद ने भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू के शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री मोदी को उनके धैर्य और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी है। उन्होंने मुइज्जू के इस फैसले को भारत के प्रति मालदीव की विदेश नीति में सुधार की संभावना वाला बताया है। इसके साथ ही अब मालदीव के संबंध चीन के साथ कैसे होंगे इस बात पर विश्लेषकों की नजर है। मोहम्मद नशीद ने कहा, मालदीव के लोग इस बात से काफी खुश हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए उनके राष्ट्रपति नई दिल्ली में मौजूद रहे। नशीद ने विपक्ष में रहते हुए मोहम्मद मुइज्जू के 'इंडिया आउट कैंपेन' का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मुइज्जू के इस कदम को मालदीव के लोगों के लिए भारत खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया था। दरअसल, साल 2008 से 2012 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ गहरा संबंध बनाए रखा था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के कुछ समय बाद ही भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया आउट' अभियान चलाने वाले मुइज्जू ने सत्ता संभालने के बाद मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया, जो दो हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए वहां मौजूद थे। बाद में इन सैनिकों की जगह भारत ने नागरिक कर्मियों की तैनाती की। भारत के बजाय राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इसी साल जनवरी में अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जुबानी हमलों में जहर उगला था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण मिलने के बाद मुइज्जू ने कहा था कि वे भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यात्रा मालदीव के लिए बहुत सफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और (विदेश मंत्री) एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करने के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध भविष्य में मालदीव के लिए आकांक्षाओं को और बढ़ाएंगे। भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा को मालदीव और क्षेत्र के लिए सफलता बताते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मंगलवार को कहा कि ईश्वर की इच्छा से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों से मालदीव के लोगों के लिए समृद्धि बढ़ेगी। चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपनी पहली भारत यात्रा संपन्न होने के बाद सरकारी मीडिया पीएसएम से कहा, यह यात्रा मालदीव और क्षेत्र के लिए भी सफल रही है। मोदी ने रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।

मुइज्जू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण पाकर खुशी हुई और वह इस कार्यक्रम में शामिल होकर भी ह्यह्यउतने ही खुशह्लह्ल हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और एस जयशंकर (विदेश मंत्री) के साथ उच्चस्तरीय बैठकों के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध भविष्य में मालदीव के लिए आकांक्षाओं को और मजबूती देंगे ह्ल मुइज्जू ने कहा, ईश्वर की इच्छा से, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के परिणामस्वरूप मालदीव और मालदीववासियों के लिए समान रूप से समृद्धि बढ़ेगी। इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा था कि राष्ट्रपति (मुइज्जू) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इसमें कहा गया, यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणमान्य अतिथियों के सम्मान में आयोजित भोज में भाग लिया। बयान में बताया गया कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि मुर्मू ने मालदीव की नयी सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दीं। बयान में कहा गया, ह्यह्यउन्होंने (मुर्मू) विश्वास व्यक्त किया कि मुइज्जू के नेतृत्व में द्वीप राष्ट्र समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुर्मू ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत-मालदीव के संबंध मजबूत होंगे। दरअसल भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक विवाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों तक पहुंच गया। यह सब 4 जनवरी को शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और खूबसूरत द्वीप की तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब भारत में इतनी खूबसूरती है तो कोई मालदीव क्यों जाए। इसका एक संदर्भ भी है। सरकार में बदलाव के कारण मालदीव में भारत विरोधी गुट सत्ता में आ गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मिलकर द्वीपीय राज्य में चुनावों के दौरान 'इंडिया आउट' अभियान चलाया था।सोशल मीडिया पर एक बड़े युद्ध के चलते मालदीव के तीन उप-मंत्रियों और कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था । ट्रोल्स के बीच चल रही जंग कूटनीतिक स्थिति में बदल गई। भारत को इसका जवाब देना पड़ा था।भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया था ।

मुइज्जू प्रशासन अपनी ओर से दोनों पक्षों - चीन और भारत - को साधने की कोशिश कर रहा है। सावधानी बरतते हुए मुइज्जू प्रशासन ने तीन अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि उसी समय कई मालदीववासी इस घटनाक्रम से नाखुश थे।उस समय छुट्टियों के लिए माले आए भारतीय पर्यटकों से बात करते हुए मीडिया को जो एहसास हुआ, वह यह था कि ज्यादातर मालदीवियों की तरह वे भी दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास नहीं चाहते। एक भारतीय पर्यटक ने कहा था इस विवाद से मालदीव में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लक्षद्वीप में रोजगार बढ़ सकता है। एक अन्य प्रवासी ने प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर बात करते हुए कहा था कि यह यात्रा विवाद पैदा करने के लिए नहीं थी। वह भारत को बढ़ावा दे रहे थे और मालदीव का अपना आकर्षण है। एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता।मालदीव में विपक्ष ने इस विवाद पर वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया था तथा संसद से विदेश मंत्री और उप मंत्रियों को बुलाने की मांग की थी ।

विपक्षी एमडीपी के नेता और सांसद मीकाईल अहमद नसीम, जिन्होंने सम्मन के साथ संसद का दरवाजा खटखटाया, ने कहा था कि उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार द्वारा इसे उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है, जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम, मालदीव के लोग, इस मुद्दे को हल करने के लिए मालदीव सरकार क्या करेगी, इस बारे में एक मजबूत और अधिक निश्चित जवाब के हकदार हैं।

सोशल मीडिया पर #BoycottMaldives या #ExploreIndia जैसे हैशटैग के साथ आह्वान किया गया, लेकिन बाद वाला पहले वाले की जगह नहीं ले सकता या इसके विपरीत। भारत-मालदीव संबंध दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपने नजदीकी पड़ोसी के रणनीतिक महत्व पर ध्यान नहीं खोया है।

वहां के लोगों को याद होगा कि राजनीतिक रूप से, भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में, ये संबंध आम तौर पर घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हालाँकि, इनमें उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है, खासकर मालदीव की उन सरकारों के तहत जो चीन की ओर झुकी हुई थीं, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय। अब बदलते समय व बदलती जरूरतों के अनुसार दोनों देशों की नजदीकी शुभ संकेत ही माना जा सकता है ।

मोदी-बीजेपी से खटास के बीच संघ प्रमुख का यूपी में प्रवास

-संजय सक्सेना

एक तरफ जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और मोदी सरकार के बीच दूरियां नजर आ रही हैं,वहीं उसी समय सरसंघचालक मोहन भागवत आज 12 जून को पांच दिवसीय यात्रा पर गोरखपुर पहुंच गये हैं। भागवत यहां संघ के चल रहे कार्यकर्ता विकास वर्ग में वह स्वयंसेवकों को विकास की टिप्स देने का कार्य करेंगे।माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में मिली करारी हार को लेकर भी मंथन कर सकते हैं. हालांकि, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हैं. भागवत 16 जून तक यहां वास करेंगे और कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम के अलावा, गोरखपुर के किसी अन्य कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे. 17 जून की सुबह को वह गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे। 13 जून दिन गुरुवार को उनका विकास वर्ग में स्वयंसेवकों के बीच संबोधन होगा। संघ के प्रचार अभियान से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत कार्यकर्ता विकास वर्ग में, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आयोजित हो रहे स्वयंसेवक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं. यह संघ के ऐसे कार्यकताओं का विकास वर्ग है जिनके ऊपर संघ का कोई दायित्व है।इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संघ प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं।

गोरखपुर में आयोजित आरएसएस विकास का वर्ग कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के कानपुर, गोरक्ष प्रांत, अवध और काशी प्रांत के कार्यकर्ता शामिल हैं, जिसमें करीब 280 लोग प्रतिभागी कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों का पूरी तरह से यहां ही प्रवास रहेगा। इस दौरान यह किसी से संपर्क में नहीं आ सकते। सरसंघचालक मोहन भागवत अपने 5 दिन के प्रवास के दौरान संघ के पदाधिकारी को संगठन के आगामी कार्य योजनाओं से भी अवगत कराएंगे और उसके संचालन की रणनीति बताएंगे.संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत गोरखपुर में छठवीं बार पधार रहे हैं. पहली बार वह कार्यकारी मंडल की बैठक में गोरखपुर हिस्सा लेने के लिए आए थे. जिसमें देशभर के संघ के पदाधिकारी गोरखपुर में इकट्ठा हुए थे. इसके पहले और पिछली बार उनका 20 मार्च 2022 को गोरक्ष प्रांत के स्वयंसेवकों की बैठक को, संबोधित करने के लिए तीन दिन के लिए गोरखपुर में आना हुआ था. उनका यह ताजा दौरा स्वयंसेवकों को सक्रियता के जरिए संगठन को मजबूती पर लाने का है. इस कार्यक्रम में संघ के क्षेत्र प्रचारक अनिल, प्रांत प्रचारक रमेश और क्षेत्र कार्यवाह वीरेंद्र जायसवाल की भी उपस्थित रहेगी.भागवत का यह दौरा तब हो रहा है जब आरएसएस और बीजेपी एवं मोदी सरकार के बीच कुछ दूरियां नजर आ रही हैं।

गौरतलब हो, लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हों, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया। लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेटे रखा। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और भाजपा में दूरी दिखी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उससे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिखे हों। जिलों में न तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखीं और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए छोटे-छोटे स्तर पर अमूमन होने वाली संघ परिवार की बैठकें होती नजर आईं। कम मतदान पर लोगों को घर से निकालने वाले समूह भी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो संघ ने चुनाव से किनारा कर लिया। संघ से जुड़े कुछ वर्तमान, पूर्व पदाधिकारियों व प्रचारकों के अनुसार इसकी मुख्य वजह भाजपा के एकांगी निर्णय और संघ परिवार के संगठनों के साथ संवादहीनता रही। माना जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बयान कि भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है। इसलिए उसे अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है, ने भी स्वयंसेवकों उदासीन कर दिया। संघ के एक पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि संघ अचानक तटस्थ होकर नहीं बैठा था। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले परिणामों के बाद आत्ममुग्धता से लबरेज भाजपा ने अपने सियासी फैसलों में संघ परिवार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था।

भाजपा ने जब संघ परिवार की सलाह की अनदेखी कर एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर डाले, जिनसे संगठन की साख और सरोकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ना लाजिमी था, इसलिए संघ ने भी अपनी भूमिका समेट ली। अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर भी कुछ मतभेद उभरे।

बात सियासत की कि जाये तो बताया जाता है कि संघ ने उत्तर प्रदेश की कौशांबी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की लगभग 25 सीटों के उम्मीदवारों पर असहमति जताई थी। साथ ही बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोगों को भाजपा में शामिल करने पर भी नाराजगी वयक्त की थी। जानकारी के मुताबिक, संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा था कि दूसरे दलों के दागी और अलोकप्रिय चेहरों को शामिल करना उचित नहीं है। इससे गुटबाजी बढ़ रही है। साथ ही संगठन की साख पर भी सवाल उठ रहा है। पर, उसकी सलाह नहीं मानी गई। लिहाजा संघ उदासीन हो गया। संघ से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा ने कई क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इसमें भी संघ परिवार के फीडबैक की अनदेखी की गई। खासतौर से गोरक्ष प्रांत और काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर संघ ने नाराजगी व्यक्त की थी। वाराणसी समेत कई लोकसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत में भारी कमी आने के पीछे पदाधिकारियों की मनमानी नियुक्ति को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

यही नहीं, इस बार के चुनाव भाजपा ने हर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त किया था, जो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें न तो संबंधित लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी थी और न ही जातीय समीकरण व मुद्दों की। मतदाताओं के बीच भी बाहरी प्रभारियों की कोई पकड़ नहीं थी। लिहाजा तमाम प्रभारियों ने जमीन पर काम करने के बजाय सिर्फ क्षेत्रों में होने वाले बड़े नेताओं के सभाओं में चेहरा दिखाने तक ही खुद को सीमित रखा। जानकारों का कहना है कि इस बार भाजपा का चुनाव प्रबंधन सिर्फ कागजों पर नजर आया था। संघ भी उदासीन हुआ तो ज्यादातर स्थानों पर न तो भाजपा के वोटरों को निकालने वाले दिखे और न उन्हें समझाने वाले। ज्यादातर मतदान केंद्रों पर 2014, 2019, 2017 और 2022 वाला प्रबंधन नहीं दिखा।यह दूरियां तब बढ़ी हैं जबकि चुनाव की घोषणा के एक साल पहले ही संघ परिवार ने अपने वैचारिक कार्यक्रम के तहत जनता से संवाद शुरू कर दिया था। घोषणा होने तक हर लोकसभा क्षेत्रों में एक-एक लाख बैठकें हो चुकी थीं।संघ के जमीनी कार्यकर्ता 10-20 परिवारों के साथ बैठकें करके मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर हुए कार्यों की चर्चा कर माहौल बनाया था, लेकिन भाजपा, संघ के इस कवायद का भी फायदा नहीं उठा पाई। संघ से दूरी बनाने का दुष्परिणाम यह भी रहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाला भाजपा का संगठन भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहा। माना जा रहा है कि संघ से बेहतर समन्वय नहीं बनने की वजह से भाजपा की अधिकांश बूथ कमेटियां व पन्ना प्रमुख भी निष्क्रिय बैठे रहे। वहीं संघ के स्थानीय कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच काम करते हैं और संगठन से जनता को जोड़ने में उनकी प्रमुख भूमिका होती है। समन्वय नहीं होने की वजह से दोनों तरफ के कार्यकर्ता उदासीन रहे। नतीजा यह हुआ कि तमाम घरों पर परिवारों तक पर्चियां तक नहीं पहुंच पाई।आरएसएस के स्वयं सेवक दबी जुबान से इस बात पर संतोष भी व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और मोदी सरकार ने मनमानी की उसमें ऐसे नजीजे आना स्वभाविक ही था।अब देखना है कि बीजेपी और मोदी सरकार क्या आरएसएस से संबंध सुधारने के लिये कोई बड़ा कदम उठाती है या फिर आत्ममुग्ध रहेगी।

चरित्र निर्माण राष्ट्रीयता का सूत्रधार

संजीव ठाकुर

चरित्र अथवा सच्चरित्रता को यदि हम परिभाषित करें, तो अच्छे आचरण, चाल चलन, स्वभाव, गुणधर्म, आदि इत्यादि को चरित्र तथा सचरित्रता का तात्पर्य अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव, अच्छे व्यवहार से है। मनुष्य समाज के बीच रहने वाला दोपाया है। अतः समाज के मध्य ऐसे गुणों का होना आवश्यक है, जिनके द्वारा व समाज में शांति पूर्वक रहते हुए देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मनुष्य के खराब आचरण से समाज का वातावरण भी प्रदूषित, खराब होता है। दूसरी तरफ अच्छे राष्ट्रीय चरित्र फलादेश हमेशा प्रगति के पथ पर चलकर एक महान राष्ट्र की संज्ञा पाता है। काम, क्रोध,लोभ, मोह, संताप, निर्दयता और ऐसे अवगुण मनुष्य के सामाजिक जीवन में अशांति उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव दुराचारी ही माना जाता है जो अच्छे आचरण या अच्छे चरित्र का ना हो। दूसरी ओर इसके जरा विपरीत निष्ठा, ईमानदारी, लगन शीलता, संयम तथा परोपकार इत्यादि पालन करने वाला मनुष्य चरित्रवान और सच्चरित्र वाला कहलाता है। इसके अलावा उदारता, विनम्रता,सहिष्णुता, सत्यभाषण किसी राष्ट्र को चरित्रवान बनाता है।

हमारे देश के महान नेता बापू महात्मा गांधी ने कूटनीति की चमक को बड़ा नहीं समझा,बुद्धि विकास को बड़ा नहीं समझा, चरित्रिक बल को ही मान दिया है। आज हमें अधिक से अधिक इस बात पर विचार करना है कि चरित्र बल केवल एक व्यक्ति का नहीं समूचे देश का होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र को अत्यधिक महत्व देने वाली पंक्तियां मूर्धन्य आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई पंक्तियां से हम सब भली भली भांति परिचित हैं,उसका हिंदी भावार्थ है, यदि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। उनके इस कथन से चरित्र का महत्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। कर्म मानव की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन चरित्र की अभिव्यक्ति है। हारवर्ट स्पेंसर ने कहा कि किसी मनुष्य राष्ट्र की सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा नहीं चरित्र है, और यही सबसे बड़ा उसका रक्षक है। चरित्रवान व्यक्ति ही अच्छा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर सकता है। और अच्छा राष्ट्रीय चरित्र एक महान देश को जन्म देता है। जिसमें विश्व में शांति, सद्भावना एवं परस्पर सहयोग की भावना को बल मिलता है। चरित्रवान नेता पूरे देश को अच्छे से नेतृत्व देकर सही विकास और शिक्षा की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चरित्रहीन नेता देश को रसातल की ओर ले जाने में नहीं चूकता है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रतिनिधि के रूप में चरित्रवान नेताओं का ही चुनाव करें। राजनीति एक कठिन डगर है, जहां की पगडंडी बल खाकर आगे बढ़ती है। और इस प्रयास में हमें समाज में सदाचार को बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। भ्रष्टाचार कदाचार की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस प्रयास में हमें बच्चों को प्रारंभ से ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।चरित्रवान नेता सदैव अपने नागरिकों को महान बनने की प्रेरणा देता है। और सचरित्र ही हमेशा उदाहरण बनके आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्त्रोत होते हैं। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं ने चारित्रिक प्रबलता के दम पर ही ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। सदाचारी व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है,और दुराचारी नेता सदैव निंदा का पात्र बनता है। जिस राष्ट्र के नेता नागरिक दुराचारी हो उसकी प्रगति कभी ठीक से नहीं होती। अतः देश की सही व निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है कि उसके अग्रणी नेता नागरिक आने वाली पीढ़ी सच्चरित्र एवं निष्ठावान हो।

किसी भी व्यक्ति या नागरिक का चरित्र होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कितना शिक्षित है।एक अशिक्षित व्यक्ति भी अपने मयार्दापूर्ण जीवन से अच्छे चरित्र की संज्ञा पा सकता है, और यदि उच्च शिक्षित व्यक्ति भ्रष्टाचार दुराचार में लिप्त हो तो वह दुष्ट चरित्र ही कहलाता है। कई अति शिक्षित व्यक्ति दुराचार एवं विचार में लिप्त होकर अपने पढ़े लिखे होने को कलंकित करते हैं। और वही कम पढ़ा लिखा या अशिक्षित ऑटो ड्राइवर यात्री द्वारा भूल से छोड़े गए लाखों रुपए पुलिस थाने में जमा कर आता है, यह उस अनपढ़ व्यक्ति की उत्तम चरित्र की परिभाषा है। आज बड़े-बड़े पढ़े-लिखे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल तक की हवा खाने के लिए मजबूर हैं। यह लोग समाज के चरित्र,राष्ट्र के चरित्र के लिए अत्यंत घातक है। अच्छे चरित्र सही हमारे आत्मबल में वृद्धि होती है जिससे हम विपरीत परिस्थितियों में मयार्दा पूर्वक जीवन की शक्ति पाते हैं। अतः नागरिकों की राष्ट्रीय चरित्र की भावना एवं व्यक्तिगत चरित्र के कारण हम विश्व में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई भाषण या उपदेश नहीं है,इसे जीवन में अपनाकर देखिए आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएंगे। शुभकामनाओं के साथ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत
सम्पादकीय

अहंकार और मर्यादा पर संघ प्रमुख के विचार, चर्चाओं में

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकासवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर आम सहमति के महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने मणिपुर में पिछले 1 वर्ष से जो हिंसा हो रही है। उस पर चिंता जाहिर की। निश्चित रूप से उन्होंने सरकार से पूछा है, कि वहां की जमीनी हकीकत पर कौन ध्यान देगा। मणिपुर के मामले को प्राथमिकता से निपटने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, जो बड़ा सेवक होता है। वह मर्यादा के साथ चलता है। मर्यादा में रहते हुए कर्म का पालन करता है। वह कर्मों से लिपटा नहीं रहता है। उन्होंने कहा कि कर्म करने के बाद जिसे अहंकार नहीं आता है, वही सेवक बनने का अधिकारी होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद दिया है। जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं। उनकी नसीहत शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थी। चुनाव को युद्ध की नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाना चाहिए। चुनाव के दौरान जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। उस पर उन्होंने दोनों पक्षों को सबक देते हुए कहा, जो वर्तमान में हो रहा है। वह सामाजिक विभाजन पैदा कर रहा है। इसमें संघ को अकारण घसीटा जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा वह प्रतिपक्ष को विरोधी नहीं मानते हैं। प्रतिपक्ष भी एक पक्ष को उजागर करता है। सभी विचारों पर विचार विमर्श होना ही चाहिए। चुनाव के लिए आवश्यक शिष्टाचार का होना जरूरी है। इस लोकसभा के चुनाव में किसी भी पक्ष द्वारा मर्यादा का पालन नहीं किया गया। मोहन भागवत ने यह भी कहा, सरकार और प्रतिपक्ष के बीच प्रति स्पर्धा होती है, दुश्मनी नहीं। दोनों का उद्देश्य आम सहमति बनाते हुए समाज कल्याण का काम करना होता है। मतभेदों के बावजूद भी हम सभी को एक साथ चलना होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो कहा है। निश्चित रूप से उसका पालन करने की जिम्मेदारी सबसे पहले सत्ता पक्ष की होती है। केंद्र में 2014 से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला हुआ है। पिछले 10 सालों के कार्यकाल में जिस तरह से कांग्रेस मुक्त भारत विपक्ष मुक्त भारत, एक राष्ट्र एक चुनाव, 100 फीसदी विदेशी निवेश, रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश का प्रवेश पिछले 10 सालों में जिस तरह से हुआ है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सामाजिक वेमनष्यता, संवैधानिक संस्थानों पर सत्ता का दबाव बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समय रहते अपने प्रभाव का इस्तेमाल ना तो मर्यादा के लिए किया। नाही नैतिकता के लिए किया है। भाजपा संगठन में अन्य विचारधाराओं के लोग बड़ी तेजी के साथ प्रमुख पदों में बैठाये जा रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान संघ को ही हो रहा है। संघ के पास अब वैसे स्वयंसेवक और प्रचारक नहीं बचे हैं। जो एक विचारधारा को लेकर जन समुदाय के बीच लगातार सक्रिय होते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ और भाजपा का विशाल संगठन होते हुए, जिस तरह की पराजय का सामना करना पड़ा है। उससे सबक लेने की जरूरत है।

भारत में 12वीं के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनें?

– विजय गर्ग

भारत में, एक आयकर अधिकारी (आईटीओ) आयकर कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि व्यक्ति और व्यवसाय अपने करों का सही भुगतान करें। आईटीओ के कुछ प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं-

कर निर्धारण – दावा की गई आय और कटौतियों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए आयकर रिटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करें।

कर जांच – संदिग्ध कर चोरी के मामलों में जांच करना।

कर संग्रहण – बकाया कर की वसूली के लिए उपाय शुरू करना।

टैक्स रिफंड – आयकर रिफंड संसाधित करना।

सार्वजनिक आउटरीच – विभिन्न आयकर कानूनों और विनियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

स्नातक की डिग्री अर्जित करें –

पहला कदम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करना है। वाणिज्य, कानून, अर्थशास्त्र, या व्यवसाय प्रशासन में डिग्री विशेष रूप से मूल्यवान हैं लेकिन अनिवार्य नहीं हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हों –

आईटीओ बनने के लिए, आपको दो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक को उत्तीर्ण करना होगा।

एसएससी सीजीएल परीक्षा – कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तर (एसएससी सीजीएल) परीक्षा सरकार के भीतर विभिन्न समूह 'बी' और समूह 'सी' पदों के लिए भर्ती की अनुमति देती है, जिसमें आयकर निरीक्षक का पद भी शामिल है।

यूपीएससी सीएसई परीक्षा – संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी सीएसई) और भी अधिक प्रतिष्ठित परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने और भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) का चयन करने से ग्रुप 'ए' पद पर सहायक आयकर आयुक्त बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।

प्रशिक्षण और परिवीक्षा – इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद, आपको एक कठोर प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा जिसके दौरान आप आयकर कानूनों, प्रक्रियाओं और जांच तकनीकों के बारे में सीखेंगे। प्रशिक्षण के बाद, अनुभवी आईटीओ के तहत परिवीक्षा अवधि होती है।

आयकर अधिकारी के रूप में नियुक्ति – अपना प्रशिक्षण और परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आपको आयकर अधिकारी के रूप में पूर्ण नियुक्ति प्राप्त होगी। आयकर अधिकारियों के लिए आवश्यक कौशल एक आयकर अधिकारी के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, ये कौशल आपको अच्छी स्थिति में रखेंगे।

विश्लेषणात्मक कौशल – कर रिटर्न और वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल।

विवरण पर ध्यान – किसी भी अशुद्धि को पकड़ने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विवरण पर गहरी नजर।

संचार कौशल – निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और करदाताओं के साथ बातचीत करने के लिए लिखित और मौखिक संचार दोनों में दक्षता।

समस्या-समाधान कौशल – जटिल कर मुद्दों को हल करने और कानून का पालन करने वाले समाधान प्रदान करने की क्षमता।

सत्यनिष्ठा और नैतिकता – आप जिस जिम्मेदारी को निभाएंगे, उसे देखते हुए निर्विवाद सत्यनिष्ठा और नैतिकता की मजबूत भावना महत्वपूर्ण है। वेतन और कैरियर विकास आयकर अधिकारी भारत सरकार में एक सम्मानित और वित्तीय रूप से पुरस्कृत करियर पथ का आनंद लेते हैं। सरकारी सेवा में विशिष्ट वेतन संरचना योग्यता और अनुभव के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है, जिसमें वृद्धि और पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होते हैं।

संसद में दागी नेताओं की संख्या बढ़ना चिन्ताजनक

सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सवाल है कि देश के लिये नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे?

– ललित गर्ग –

देश में 18वीं लोकसभा चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां हैं वहीं चिन्ताजनक, विचलित एवं परेशान करने वाली स्थितियां भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है।

भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना-हर नागरिक के माथे पर चिंता की लकीर लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विश्लेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी, वहीं अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है। आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है कि अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच जाते हैं। अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता आम चुनाव में कहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि मैं जेल जाने से बच जाऊं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं अपराधी तत्वों को जिम्मेदारी के पद देकर कैसे सुशासन एवं ईमानदार व्यवस्था स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? कैसे संसद में दागियों के पहुंचने के लिये द्वार बंद होंगे? दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सजग पहल पर ही वर्ष 2020 से सभी राजनीतिक दल लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने लगे है। निश्चित ही इस आदेश का मकसद देश की राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से मुक्त करना ही था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्राथमिकता जीतने वाले उम्मीदवार थे, अब चाहे उनका आपराधिक रिकॉर्ड ही क्यों न हो। बड़ा प्रश्न है कि आखिर राजनीति में तब कौन आदर्श उपस्थित करेगा? क्या हो गया उन लोगों को जिन्होंने सदैव ही हर कुर्बानी करके आदर्श उपस्थित किया। लाखों के लिए अनुकरणीय बने, आदर्श बने। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, अपने वचन की रक्षा हो अथवा अपनी संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा का प्रश्न हो, उन्होंने फर्ज़ और वचन निभाने के लिए अपना सब कुछ होम दिया था। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, दुर्गादास, छत्रसाल, शिवाजी जैसे वीरों ने अपनी तथा अपने परिवार की सुख-सुविधा को गौण कर बड़ी कुर्बानी दी थी। गुरु गोविन्दसिंह ने अपने दोनों पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया और पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों का तो मन्दिर बनना चाहिए। इनके मन्दिर नहीं बने, पर लोगों के सिर श्रद्धा से झुकते हैं, इनका नाम आते ही। लेकिन आज जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन और सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं संकीर्ण बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यादा नकाबें ओढ़ रखी हैं, उसने हमारे सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया।

राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोह में हैं। वक्त आ गया है जब देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर संरक्षण देने की कोशिश या राजनीतिक लाभ उठाने की कुचेष्ठा पर विराम लगाना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त राजनीति को सदैव प्राथमिकता दी लेकिन चुनाव जीतने के रण में वे भी अपराधी राजनेताओं को प्रश्रय देते हुए दिखे हैं।

सभी राजनीतिक दलों ने ही दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। जो राजनीतिक दलों की कथनी और करनी के भारी अंतर को ही उजागर करता है। सवाल है कि देश के लिये नीति निर्धारण करने वाले ऐसे दागी लोग हमारे भाग्यविधाता बने रहेंगे तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? क्या होगा हमारे समाज व व्यवस्था का भविष्य? क्यों तमाम आदर्शों की बात करने वाले और दूसरे दलों के नेताओं की कारगुजारियों पर सवाल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वर्चस्व से मुक्त कराने की ईमानदार पहल नहीं करते? क्यों सभी राजनीतिक दल भारतीय लोकतंत्र में शुचिता एवं पवित्रता के लिये सहमति नहीं बनाते? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं होती तो आने वाले वर्षों में दागियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। इसके साथ ही बड़ा संकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन-केन-प्रकारेण करोड़पति बने नेताओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है। इस बार संसद में चुनकर आए सांसदों में 504 करोड़पति हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विडम्बना एवं विसंगति बनते जा रहे हैं। बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ होता है। यह कैसी विवशता है राजनीतिक दलों की? अक्सर राजनीति को अपराध मुक्त करने के दावे की हकीकत तब सामने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का मौका आता है। यह खुशी की बात है कि केन्द्र में बनी गठबंधन सरकार के मंत्रिमण्डल में ऐसी विवशता को काफी सीमा तक नियंत्रित किया गया है। सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा करने वालों की केवल एक ही मांग सुनने में आती है कि मरने के बाद हमारी लाश हमारे घर पहुंचा दी जाए। ऐसा जब पढ़ते तो हमारा मस्तक उन जवानों को सलाम करता है, लगता है कि देश भक्ति और कुर्बानी का माद्दा अभी तक मरा नहीं है। लेकिन राजनीति में ऐसा आदर्श कब उपस्थित होगा। राजनीति में चरित्र एवं नैतिकता के दीये की रोशनी मन्द पड़ गई है, तेल डालना होगा। दिल्ली सरकार में मंत्रियों के घरों पर सीबीआई के छापे और जेल की सलाखें हो या बिहार मंत्री परिषद के गठन में अपराधी तत्वों की ताजपोशी-ये गंभीर मसले हैं, जिन पर राजनीति में गहन बहस हो, राजनीति के शुद्धिकरण का सार्थक प्रयास हो, यह नया भारत -सशक्त भारत की प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए। सभी अपनी-अपनी पहचान एवं स्वार्थपूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई पैसे से, कोई अपनी सुंदरता से, कोई विद्वता से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हैं। राजनीति की दशा इससे भी बदतर है कि यहां जनता के दिलों पर राज करने के लिये नेता अपराध, भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का सहारा लेते हैं। जातिवाद, प्रांतवाद, साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर जनता को तोड़ने की कोशिशें होती है। पर हम कितना भ्रम पालते हैं। पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती। बाकी सब अस्थायी है। चरित्र एक साधना है, तपस्या है। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज़ कुछ न कुछ चाहिए। उसी प्रकार राजनीतिक चरित्र को रोज़ संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि, ईमानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीति में चरित्र-नैतिकता सम्पन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल (सम्माननीय) हो और वही एक्सेप्टेबल (स्वीकार्य) हो।

(ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

यूपी में समाजवादी पार्टी को मिला नवजीवन

– बाल मुकुंद ओझा

देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ का रास्ता रोक कर अपनी समाजवादी पार्टी को जीवनदान देने में सफलता हासिल की है । यह सफलता सपा संस्थापक मुलायम सिंह की सफलता से भी अधिक आंकी जा रही है। सपा ने 80 में से 37 सीटें अपनी झोली में डाल दी। पिछली बार सपा के पास केवल 5 सीटें थी। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर अपना परचम लहराया है। इससे पहले सपा को सबसे बड़ी सफलता 2004 में मुलायम की अगुआई में 35 सीटें जीतकर मिली थी। समाजवादी नेता डॉ लोहिया के सिद्धांतों और विचारों का अनुसरण करने का दावा करने वाली सपा अब देश के विपक्षी दलों में दूसरी बड़ी पार्टी हो गई है। इसे अखिलेश की कड़ी मेहनत और सूझबूझ को बताया जा रहा है। उन्होंने पूरे यूपी में सपा के पक्ष में जोरदार अभियान चलाया। यादव और मुस्लिम समीकरण को पिछड़ों को साथ लेकर बनाया। मुस्लिमों के मत एकमुश्त लेने में सफलता हासिल की। बसपा से मुस्लिम और दलित छिटक कर सपा की झोली में आ गिरे। सपा के इतिहास में इस बार अखिलेश ने सबसे कम मुस्लिम-यादवों को टिकट दिया, जिनको खास तवज्जो देने की तोहमत पार्टी पर लगती है। अपने कोर वोटर (मुस्लिम-यादव) को समझाने के साथ नए को जोड़ने का ताना-बाना उन्होंने पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसख्ंयक) के जरिए बुना। अखिलेश के भाषण, बैठकों से लेकर लोकसभा के प्रचार अभियान का यही मूल मुद्दा बन गया। भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप मढ़ने के साथ रोजगार, भर्ती, पिछड़ों-दलितों की भागीदारी छीनने के आरोप के इर्द-गिर्द ही अखिलेश टिके रहे। भाजपा की ध्रुवीकरण से जुड़े बयानों पर चुप्पी साधी और पार्टी के भीतर से इस पर सुर उभरे तो उसे चुप करा दिया, जिससे भाजपा को कोई मौका न मिले। बिहार में तेजस्वी वह करिश्मा नहीं दिखा पाए जो यूपी में अखिलेश ने अपने बलबूते पर दिखाया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है जिसमें बताया गया कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में फंस रहा है जबकि अखिलेश पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव का भरपूर साथ मिला जबकि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह का निधन हो गया था।

लोकसभा चुनाव में इससे पहले सपा को सबसे बड़ी सफलता 2004 में मुलायम की अगुआई में 35 सीटें जीतकर मिली थी। इस बार सपा ने अपने दम पर 37 सीटें जीती हैं। पहली बार उसका वोट शेयर लोकसभा में 32 फीसदी के पार चला गया है। यूपी में पहले और देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों भाजपा व कांग्रेस के बाद सपा देश में तीसरे पायदान पर है। इससे पहले 2004 में वह लोकसभा में चौथे नंबर की पार्टी थी। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में इस बार भाजपा को सपा नेता अखिलेश यादव की चुनौती भारी पड़ी। अखिलेश अकेले ही अपनी विजय रथ यात्रा पर निकले और मतदाताओं से धुंवाधार प्रचार में जुटे। उनकी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ जुटी जो अखिलेश का मनोबल और हौसला बढ़ाने में सफल हुई। महाभारत के अभिमन्यु की तरह वे भाजपा के चक्रव्यूह को राहुल गाँधी को साथ लेकर तोड़ने में सफल हुए है। उनका मुकाबला यूपी के सीएम योगी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री आमित शाह जैसे योद्धाओं से हुआ। भाजपा में चुनावी तीरंदाजों की कमी नहीं है। सपा में वे अकेले महारथी थे। सपा के इतिहास में इस बार अखिलेश ने सबसे कम मुस्लिम-यादवों को टिकट दिया, जिनको खास तवज्जो देने की तोहमत पार्टी पर लगती है। अपने कोर वोटर (मुस्लिम-यादव) को समझाने के साथ नए को जोड़ने का ताना-बाना उन्होंने पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसख्ंयक) के जरिए बुना। अखिलेश के भाषण, बैठकों से लेकर लोकसभा के प्रचार अभियान का यही मूल मुद्दा बन गया। भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की साजिश के आरोप मढ़ने के साथ रोजगार, भर्ती, पिछड़ों-दलितों की भागीदारी छीनने के आरोप के इर्द-गिर्द ही अखिलेश टिके रहे। भाजपा की ध्रुवीकरण से जुड़े बयानों पर चुप्पी साधी और पार्टी के भीतर से इस पर सुर उभरे तो उसे चुप करा दिया, जिससे भाजपा को कोई मौका न मिले।

कविता

पिता

बच्चों की बात झट से
लेते मान,
पिता है खुला नीला
आसमान,
परिवार की खुशियों
की चमक,
घर का मान- सम्मान-
अभिमान।

जिनसे मिलती पहली
पहचान,
सलाहकार, रक्षक,
भगवान,
छांव में जिनके मिलती
ठंडक,
घर की जगमग आन-
बान-शान।

जीवन हमारा करते पूरी
उम्र प्रकाशवान,
अपने आंसुओं को छुपाते
तप उनका महान,
राहों में हमारी गुलाब
बिछाकर चुनते कंटक,
घर की मजबूत नींव-
तेज-प्राण।

गुरु, आदर्श, मित्र,
शक्तिमान,
चेहरे पर दमकती
जिनके हरदम
मुस्कान,
मां की पायल,
झुमके, चूड़ी की
खनक,
घर का सौंदर्य
'आनंद'-संगीत-
मूलधन।

न जाने सह जाते
चुपचाप कितने
तूफ़ान,
फिर भी पूरे करते हैं
हमारे सारे अरमान,
वंदन करते हम
चरणों में नतमस्तक,
घर को बनाते मधुबन
तन-मन-धन।

मोनिका डागा 'आनंद'
(चेन्नई, तमिलनाडु)

संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं,लेकिन भारत ने कभी भी अपने नजदीकी पड़ोसी के रणनीतिक महत्व पर ध्यान नहीं खोया है। वहां के लोगों को याद होगा कि राजनीतिक रूप से,भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में,ये संबंध आम तौर पर घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हालाँकि,इनमें उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है,खासकर मालदीव की उन सरकारों के तहत जो चीन की ओर झुकी हुई थीं,जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय।

मालदीव के बिगड़े संबंध सुधरने की संभावना बढ़ी

– अशोक भाटिया

हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर उनके ही सबसे बड़े विरोधी का भी समर्थन मिला है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा, 'भारत-मालदीव संबंधों के वर्तमान संभावनाओं को देखते हुए उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स मोहम्मद मुइज्जू का समर्थन करती है।' मुइज्जू 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू पहली बार भारत यात्रा पर आए थे। मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन अब मुइज्जू को दिल्ली दौरे के बाद एक बार फिर नए रिश्तों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मालदीव के मीडिया पोर्टल सन ने मोहम्मद नशीद के हवाले से कहा कि प्रत्येक चुनाव में देश की विदेश नीति बदल देना मालदीव के लिए लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। मोहम्मद नशीद की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब भारत-मालदीव के रिश्तों में सुधार होता दिख रहा है। नशीद ने भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद मुइज्जू के शामिल होने का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और प्रधानमंत्री मोदी को उनके धैर्य और दूरदर्शिता के लिए बधाई दी है। उन्होंने मुइज्जू के इस फैसले को भारत के प्रति मालदीव की विदेश नीति में सुधार की संभावना वाला बताया है। इसके साथ ही अब मालदीव के संबंध चीन के साथ कैसे होंगे इस बात पर विश्लेषकों की नजर है। मोहम्मद नशीद ने कहा, मालदीव के लोग इस बात से काफी खुश हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए उनके राष्ट्रपति नई दिल्ली में मौजूद रहे। नशीद ने विपक्ष में रहते हुए मोहम्मद मुइज्जू के 'इंडिया आउट कैंपेन' का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने मुइज्जू के इस कदम को मालदीव के लोगों के लिए भारत खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया था। दरअसल, साल 2008 से 2012 के बीच मालदीव के राष्ट्रपति रहे मोहम्मद नशीद ने भारत के साथ गहरा संबंध बनाए रखा था। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार संभालने के कुछ समय बाद ही भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में 'इंडिया आउट' अभियान चलाने वाले मुइज्जू ने सत्ता संभालने के बाद मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों की वापसी पर जोर दिया, जो दो हेलिकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान को संचालित करने के लिए वहां मौजूद थे। बाद में इन सैनिकों की जगह भारत ने नागरिक कर्मियों की तैनाती की। भारत के बजाय राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। इसी साल जनवरी में अपनी पहली चीन यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के खिलाफ जुबानी हमलों में जहर उगला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण मिलने के बाद मुइज्जू ने कहा था कि वे भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। एक साथ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि यात्रा मालदीव के लिए बहुत सफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया। मुइज्जू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण पाकर खुशी हुई और वह इस कार्यक्रम में शामिल होकर भी "उतने ही खुश" हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) और एस जयशंकर (विदेश मंत्री) के साथ उच्चस्तरीय बैठकों के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि मजबूत द्विपक्षीय संबंध भविष्य में मालदीव के लिए आकांक्षाओं को और मजबूती देंगे।' मुइज्जू ने कहा, ईश्वर की इच्छा से, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों के परिणामस्वरूप मालदीव और मालदीववासियों के लिए समान रूप से समृद्धि बढ़ेगी। इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा था कि राष्ट्रपति (मुइज्जू) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। इसमें कहा गया, यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणमान्य अतिथियों के सम्मान में आयोजित भोज में भाग लिया। बयान में बताया गया कि दोनों राष्ट्रपतियों ने एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने मालदीव और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें कहा गया कि मुर्मू ने मालदीव की नयी सरकार और लोगों को शुभकामनाएं दीं। बयान में कहा गया, "उन्होंने (मुर्मू) विश्वास व्यक्त किया कि मुइज्जू के नेतृत्व में द्वीप राष्ट्र समृद्धि और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।"

नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मुर्मू ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत-मालदीव के संबंध मजबूत होंगे। दरअसल भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक विवाद सोशल मीडिया पर शुरू हुआ और दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों तक पहुंच गया। यह सब 4 जनवरी को शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया और खूबसूरत द्वीप की तस्वीरें पोस्ट कीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोस्ट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब भारत में इतनी खूबसूरती है तो कोई मालदीव क्यों जाए। इसका एक संदर्भ भी है। सरकार में बदलाव के कारण मालदीव में भारत विरोधी गुट सत्ता में आ गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को चीन समर्थक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ मिलकर द्वीपीय राज्य में चुनावों के दौरान 'इंडिया आउट' अभियान चलाया था।सोशल मीडिया पर एक बड़े युद्ध के चलते मालदीव के तीन उप-मंत्रियों और कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ़ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। ट्रॉल्स के बीच चल रही जंग कूटनीतिक स्थिति में बदल गई। भारत को इसका जवाब देना पड़ा था।भारत में मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहीब को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया था। मुइज़्ज़ू प्रशासन अपनी ओर से दोनों पक्षों – चीन और भारत – को साधने की कोशिश कर रहा है। सावधानी बरतते हुए मुइज़्ज़ू प्रशासन ने तीन अधिकारियों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। बताया जाता है कि उसी समय कई मालदीववासी इस घटनाक्रम से नाखुश थे।उस समय छुट्टियों के लिए माले आए भारतीय पर्यटकों से बात करते हुए मीडिया को जो एहसास हुआ, वह यह था कि ज़्यादातर मालदीवियों की तरह वे भी दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास नहीं चाहते। एक भारतीय पर्यटक ने कहा था इस विवाद से मालदीव में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लक्षद्वीप में रोज़गार बढ़ सकता है। संबंधों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन भारत ने कभी भी अपने नजदीकी पड़ोसी के रणनीतिक महत्व पर ध्यान नहीं खोया है। वहां के लोगों को याद होगा कि राजनीतिक रूप से, भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में, ये संबंध आम तौर पर घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। हालाँकि, इनमें उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है, खासकर मालदीव की उन सरकारों के तहत जो चीन की ओर झुकी हुई थीं, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय। अब बदलते समय व बदलती जरूरतों के अनुसार दोनों देशों की नजदीकी शुभ संकेत ही माना जा सकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विकास के एजेंडे पर आगे बढ़े सरकार

गठबंधन धर्म की जरूरतों के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरी पारी का जंबो मंत्रिमंडल अपरिहार्य था। जाहिरा तौर पर मंत्रिमंडल के गठन में अनुभव,युवा, जातीय समीकरण, गठबंधन के दायित्व और आगामी विधानसभा चुनाव की प्राथमिकताएं स्पष्ट नजर आती हैं। जिसके चलते तीस कैबिनेट मंत्रियों को ताजपोशी हुई है। बहत्तर सदस्यीय मंत्रिमंडल में तीस कैबिनेट मंत्रियों में बिहार को तरजीह देना स्वाभाविक ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू गठबंधन में एक बड़ा सहयोगी घटक है। वहीं मंत्रिमंडल में बड़े घटक टीडीपी व जद (सेक्युलर) की भी उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण गड़बड़ाने के बाद चालीस से अधिक ओबीसी, एससी व अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मध्य प्रदेश, हरियाणा व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। दरअसल, महाराष्ट्र, हरियाणा व झारखंड के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी इन राज्यों के ज्यादा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में तेरह सीटों में एक भी प्रत्याशी के सफल न होने के बावजूद 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नया युवा नेतृत्व तैयार करने की कवायद शुरू की गई है। पूर्व कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल में शामिल करना इसी रणनीति का हिस्सा है। कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन में संवेदनशील ढंग से रणनीति को अंजाम दिया गया। विश्वास किया जाना चाहिए कि लंबे चले चुनाव प्रचार अभियान में जो राजनीतिक व सामाजिक तौर पर कथित बांटने की कवायद वोटों के लिए की गई, उस पर अब विराम लगना ही चाहिए। आशा करें कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद विकास को अपनी प्राथमिकता बनाएगी। जब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो पहली शर्त यही होगी कि कथित तौर पर विभाजनकारी राजनीति से परहेज कर-के सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। आरोप-प्रत्यारोपों की राजनीति पर विराम लगाकर मिलजुलकर देश को नई दिशा देने का प्रयास होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि आजादी के बाद यह दूसरा अवसर है जब पं. नेहरू की तरह लगातार तीसरी बार भाजपा नीत सरकार बनी है। ऐसा कहने का अर्थ है कि सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। तब तुलना यह भी की जाएगी कि किस सरकार के कार्यकाल में हकीकत के धरातल पर ज्यादा विकास हुआ। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर देश-दुनिया की निगाहें लगी हैं। गठबंधन सरकार को पिछली सरकारों से बेहतर प्रदर्शन करके भी दिखाना होगा। राजग सरकार को स्वीकारना होगा कि यह एक गठबंधन सरकार है। यूं तो पिछली सरकार में भी राजग गठबंधन अस्तित्व में था, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण भाजपा की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ गई है। जिसके चलते मोदी सरकार के लिये पिछले कार्यकाल की तरह पार्टी के एजेंडे को लागू करने में खुला हाथ न मिलेगा।

याद रखे देश ईस्ट दिल्ली में शिशुओं के जलने के हादसे को

आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

अभी एक महीना भी नहीं हुआ और देश की राजधानी में हुए एक दर्दनाक अग्निकांड को भुला दिया गया है। पिछली 25 मई को जिस दिन दिल्ली में लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई थी उसी दिन ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार के एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने के कारण सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। जैसा कि हमारे यहां होता आ रहा है- घटना के बाद नेताओं की तरफ से अफसोस जता दिया गया, स्थानीय प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा कर दिया और कुछ गिरफ्तारियां भी हो गईं। यह सब कुछ दिनों तक चला और फिर दुनिया अपनी रफ्तार से चलने लगी और फिर एक तरह से अगले हादसे तक के लिए सब कुछ सामान्य हो गया। हमारी नींद तो किसी हादसे के बाद ही खुलती है और पुनः हम कुंभकर्णी निद्रा में चले जाते हैं ।

हमारे यहां अस्पतालों में आग लगने के कारण लगातार बड़े हादसे होते रहे हैं। 2011 में कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में आग लगने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में, कोविड-19 महामारी के चरम पर, मुंबई के पास विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। उसी वर्ष, मुंबई में फिर से सनराइज अस्पताल में आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई। 2022 में, जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से आठ मरीजों की मौत हो गई और 2016 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 50 मरीजों की मौत हो गई। अपना इलाज कराने आए रोगियों का जलकर मरने के मामलों को सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल दहल जाता है।

क्या हम इतने भयावह हादसे को लेकर पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं? लगता तो यही है। अगर इस तरह की स्थिति न होती तो इतनी जल्दी विवेक विहार में हुई त्रासदी पर अफसोस जताना बंद न हो जाता।

यह तो मानना ही होगा कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से निजी हाथों में चली जा रही हैं। मतलब प्राइवेट अस्पताल खुलते ही चले जा रहे हैं। तंग गलियों में चलने वाले गंदे क्लीनिकों से लेकर पॉश कॉरपोरेट इलाकों में अस्पतालें चल रहे हैं। ये ही देश में 70 फीसद तक जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार अब 25-30 करोड़ लोगों को ही स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। जब इतने बड़े स्तर पर प्राइवेट क्षेत्र हेल्थ सेक्टर को देखने लगा है, तो क्या इस पर किसी का नियंत्रण है? विवेक विहार की घटना साबित करती है कि इन प्राइवेट अस्पतालों पर किसी को कोई खास नियंत्रण नहीं हो रहा है। जिस दो मंजिला बेबी डे केयर सेंटर में आग लगी वहां नवजात शिशुओं का इलाज और देखरेख एक आयुर्वेदिक डॉक्टर करता था। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहां स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कितनी पतली हो चुकी है। आग लगने के कारण सेंटर में भर्ती 12 नवजात में से सात ने दम तोड़ा। इसमें से कुछ झुलस गए थे तो कुछ नवजात ऑक्सीजन सपोर्ट हटने से जीवित नहीं रह पाए।

मुझे ईस्ट दिल्ली के सोशल वर्कर जितेंद्र सिंह शंटी बता रहे थे कि सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से आग ने फौरन विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर केयर सेंटर से दूर दूर जाकर गिरे। स्थानीय लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। शंटी और उनके साथियों ने आग बुझाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में दिन-रात एक कर दी थी।

हमारे यहां अस्पतालों में आग लगने के कारण लगातार बड़े हादसे होते रहे हैं। 2011 में कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में आग लगने से 90 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2021 में, कोविड-19 महामारी के चरम पर, मुंबई के पास विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। उसी वर्ष, मुंबई में फिर से सनराइज अस्पताल में आग लगने से 11 मरीजों की मौत हो गई। 2022 में, जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से आठ मरीजों की मौत हो गई और 2016 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 50 मरीजों की मौत हो गई। अपना इलाज कराने आए रोगियों का जलकर मरने के मामलों को सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी दिल दहल जाता है। सवाल यह है कि निजी अस्पतालों में होने वाले हादसों पर कब लगाम लगेगी? दिल्ली के अधिकांश निजी अस्पताल गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज और बिस्तर उपलब्ध कराने में भी विफल रहते हैं, जबकि यह उनके निर्माण के समय दी गई जमीन के बदले में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज कानूनी आवश्यकता है। अगर देश की राजधानी में ऐसा हो सकता है, तो हम छोटे शहरों और कस्बों की स्थिति की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अस्पतालों में आग लगने का सामान्य कारण आम तौर पर खराब इमारत संरचना, जिसमें भागने का कोई रास्ता नहीं होता, आसपास के क्षेत्र में ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसों की उपस्थिति और अनुचित भंडारण और, सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि सुरक्षा मानक संचालन प्रोटोकॉल की कमी है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आग लगने पर अग्नि शमन गाड़ियाँ तक इन इमारतों तक पहुँच तक नहीं सकते क्अगर बात अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं स हटकर करें तो क्या कोई 3 दिसम्बर,1995 को मंडी डबवाली (हरियाणा) और 13 जून,1997 को राजधानी के उपहार सिनेमाघर में लगी आग की घटनाओं को भूल सकता है? मंडी डबवाली में डीएवी स्कूल में चल रहे सालाना आयोजन में 360 अभागे लोग, जिनमें स्कूली बच्चे अधिक थे, स्वाह हो गए थे। हालांकि, कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि मृतकों की तादाद साढ़े पांच सौ से भी अधिक थी। उधर उपहार में लगी भयंकर आग के चलते 59 जिंदगियां आग की तेज लपटों की भेंट चढ़ गईं थीं।

जैसा कि हमारे देश में होता चला आ रहा है और न जाने कब तक होगा, हादसों के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। हालांकि, जांच रिपोर्ट आने के बाद उसे कोई देखता भी नहीं है। उसकी सिफारिशें धूल चाटती रहती हैं। हादसों में शिकार हुए मृतकों के परिजनों और घायलों को कुछ मुआवजा दे दिया जाता है।

इस बीच, पिछले लगभग ढाई दशकों से बंद उपहार सिनेमा परिसर को फिर से खोलने का पटियाला हाउस कोर्ट आदेश दिया है। उपहार में जो कुछ हुआ था, उसके बाद बहुत सारे दिल्ली वाले सिनेमा घरों से दूर हो गए थे। उस भयानक हादसे से सारा देश दहल गया था। उस मनहूस शुक्रवार को बॉर्डर फिल्म देखने आए करीब पांच दर्जन लोग दम घुटने या जलने के कारण मारे गए थे। तब से उपहार बंद था। पिछले कुछ समय पहले मुझे उसके अंदर का डरावना नजारा देखने का मौका मिला था। वहां पर जली सीटें,राख के ढेर, चिप्स के पैकेट, पेप्सी की बोतलें यहां-वहां पड़ी थीं। यह सब उस दिन की यादें ताजा करवा रही थे जब इधर मौत के आगे इंसान बेबस था। उस शाम बेसमेंट में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से लगी आग की लपटें और धुआं काल बन कर आए थे। इधर हाल के दिनों में देश भर से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। इनमें मासूम जान गंवा रहे हैं। क्यों संबंधित सरकारी महकमे देखते नहीं और सख्ती नहीं बरतते ताकि आग लगने के हादसे होने थम जाएं ?

अच्छे काम के बाद भी भाजपा क्यों पिछड़ी ?

प्रवीण बागी

खुद प्रधानमंत्री मोदी की काशी से एक लाख 52 हजार वोटों से जीत यह दशार्ती है कि वहां के वोटर भी उनसे खुश नहीं हैं। काशी के लिए इतना काम करने के बाद भी मोदी के वोट क्यों घटे ? इस पर खुद मोदी जी को विचार करना चाहिए। अयोध्या की हार भाजपा के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। कहां चूक हुई ? वहां के मतदाता क्यों मुंह फेर लिए ? 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे' का नारा क्यों हवा में उड़ गया ? 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' और 'पन्ना प्रमुख' की परिकल्पना क्यों नाकाम रही? पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा काम और मजबूत नेता की छवि के बाद भी यूपी में भाजपा के औंधे मुंह गिरने के पीछे क्या पार्टी के अंदर की गुटबाजी जिम्मेदार है ? पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है लेकिन यह चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए साजिश के तहत कमजोर और बदनाम उम्मीदवार दिए गए ? अगर ऐसा हुआ है तो फिर भाजपा का पतन तय है। यह भी लांक्षन लग रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। भाजपा का केंद्रीकरण और उसके नेताओं की आत्ममुग्धता उसके लिए घातक हुई। मोदी ने अपने मंत्रियों को उभरने नहीं दिया। हर जगह वे ही वे नजर आए। मंत्रियों की हैसियत सहयोगियों की नहीं सहायक की कर दी गई थी। इस ओर संघ प्रमुख ने भी इशारा किया है। हालांकि यह भी सही है कि हमारा देश व्यक्ति पूजक है, समाज पूजक नहीं। इस वजह से मोदी का एकछत्र नेता के रूप में खुद को स्थापित करना भाजपा के लिए लाभदायक भी रहा। व्यक्ति पूजा के कारण ही नेहरू वंश इतने वर्षों तक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने में सफल रहा।

लोकसभा चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेतावनी है। मतदाताओं ने इस बार उसे सिर्फ हड़का कर छोड़ दिया है। अगर इसपर भी वह नहीं चेतती है और पार्टी तथा सरकार की कार्यशैली में बदलाव नहीं आता है तो अगली बार उसे विपक्ष में बैठने को तैयार रहना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सार्वजनिक रूप से मोदी सरकार के कामकाज और व्यवहार से अप्रसन्नता व्यक्त कर उसे सुधरने की नसीहत दी है। हर काम का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खुद लेने को भी उन्होंने अच्छा नहीं माना है। मणिपुर में एक साल से जारी हिंसा पर केंद्र की उदासीनता पर भी संघ प्रमुख ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है।

बेशक मोदी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक काम किये जो आजादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे। देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। विश्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया है। आतंकी कार्रवाईयां और नक्सली हिंसा पर करीब करीब काबू पा लिया गया है। डिजर्विंग व्यक्तियों के चयन से पद्म सम्मान का 'सम्मान' बढ़ा है। हर घर शौचालय और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की दिशा में सराहनीय कार्य हुए हैं। और भी कई अच्छे काम हुए हैं। इसके बाद भी जनता ने इस सरकार को अपेक्षित समर्थन क्यों नहीं दिया, इस पर गहन चिंतन की जरुरत है।

खुद प्रधानमंत्री मोदी की काशी से एक लाख 52 हजार वोटों से जीत यह दशार्ती है कि वहां के वोटर भी उनसे खुश नहीं हैं। काशी के लिए इतना काम करने के बाद भी मोदी के वोट क्यों घटे ? इस पर खुद मोदी जी को विचार करना चाहिए।

अयोध्या की हार भाजपा के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। कहां चूक हुई ? वहां के मतदाता क्यों मुंह फेर लिए ? 'जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे' का नारा क्यों हवा में उड़ गया ? 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' और 'पन्ना प्रमुख' की परिकल्पना क्यों नाकाम रही? पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए।

अच्छा काम और मजबूत नेता की छवि के बाद भी यूपी में भाजपा के औंधे मुंह गिरने के पीछे क्या पार्टी के अंदर की गुटबाजी जिम्मेदार है ? पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है लेकिन यह चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए साजिश के तहत कमजोर और बदनाम उम्मीदवार दिए गए ? अगर ऐसा हुआ है तो फिर भाजपा का पतन तय है। यह भी लांक्षन लग रहा है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण होता जा रहा है।

भाजपा का केंद्रीकरण और उसके नेताओं की आत्ममुग्धता उसके लिए घातक हुई। मोदी ने अपने मंत्रियों को उभरने नहीं दिया। हर जगह वे ही वे नजर आए। मंत्रियों की हैसियत सहयोगियों की नहीं सहायक की कर दी गई थी। इस ओर संघ प्रमुख ने भी इशारा किया है। हालांकि यह भी सही है कि हमारा देश व्यक्ति पूजक है, समाज पूजक नहीं। इस वजह से मोदी का एकछत्र नेता के रूप में खुद को स्थापित करना भाजपा के लिए लाभदायक भी रहा। व्यक्ति पूजा के कारण ही नेहरू वंश इतने वर्षों तक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने में सफल रहा। मोदी ने उसी के अस्त्र से उसे धराशाई किया। लेकिन वह अस्त्र भोथरा हो रहा है।

अपने भाषणों में अन्य नेताओं की तरह कई बार मोदी ने भी मयार्दाएं लांघी, जिसे लोगों ने पसंद नहीं किया। यह याद रखना होगा की अपने ऊटपटांग भाषणों के चलते ही राहुल गांधी को 'पप्पू' की संज्ञा से विभूषित किया गया था और उनके भाषणों के मीम बनते रहे हैं। प्रधानमंत्री समेत भाजपा के अनेक नेता भी कई बार वही गलती करते दिखे। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होना और अग्निवीर योजना से युवा वर्ग मोदी सरकार से उदासीन नजर आता है। वोटिंग के दिन वह घर बैठा रहा। वोट देने नहीं निकला। वेतन भोगी मध्यम वर्ग की तरफ भाजपा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसे यह वर्ग भी मुंह फुलाए हुए है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

भाजपा विपक्ष के संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के प्रचार का प्रभावी काट नहीं कर पाई। इससे भी उसे क्षति उठानी पड़ी। पंडित नेहरू के लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी तो नरेंद्र मोदी ने कर ली, अगर उससे आगे निकलना है तो फीलगुड से बाहर निकल कर अपने अंदर झांकना होगा। कमजोर कड़ी की पहचान कर उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। संघ से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना होगा तभी भाजपा अपनी बढ़त बनाए रख सकती है। देश को अभी मजबूत और राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार की जरूरत है। इसलिए भाजपा को कुछ कड़े फैसले लेने होंगे।

क्या भाजपा इसके लिए तैयार है?

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 101

व्यापार शर्तों में बदलाव

सरकार के नए कार्यकाल का आरंभ यह अवसर प्रदान करता है कि नीतिगत मसलों पर दोबारा नजर डाली जाए और लंबी अवधि के दौरान टिकाऊ वृद्धि हासिल करने के लिए जरूरी हस्तक्षेप किए जाएं। ऐसा ही एक क्षेत्र है व्यापार। यह बात अच्छी तरह स्थापित है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समेकित मांग को गति प्रदान करता है और कोई भी देश बिना निर्यात में महत्त्वपूर्ण इजाफा किए तेज वृद्धि हासिल नहीं कर सकता। निर्यात में इजाफा विदेशी बचत पर भारत की निर्भरता कम कर देगा और बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार तैयार करेगा। इससे घरेलू मांग को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी और गुणक प्रभाव उत्पन्न होगा। अगर तुलना की जाए तो भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। बहरहाल वैश्विक वस्तु निर्यात में उसकी हिस्सेदारी की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2023 में यह केवल 1.8 फीसदी थी। अमेरिका और चीन के आंकड़ों से तुलना करें तो वहां यह क्रमशः 8.5 और 14.2 फीसदी थी। भारत का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह वैश्विक वस्तु निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में इजाफा करे। वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तु निर्यात में 3.09 फीसदी की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

भारत को निरंतर उच्च निर्यात वृद्धि हासिल करने के लिए अपनी व्यापार नीति की व्यापक समीक्षा करनी होगी। भारत में टैरिफ ऊंचा है जो घरेलू विनिर्माताओं खासकर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उपक्रमों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है। इसके अलावा भारत किसी बड़े क्षेत्रीय या प्राथमिकता वाले व्यापार समझौते से भी नहीं जुड़ा है। अगर उसका ऐसा कोई जुड़ाव होता तो कच्चे माल की लागत में कमी आती और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने में मदद मिलती। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से भी बाहर रहने का निर्णय लिया। यह एक अहम व्यापार समझौता है जो दुनिया के सर्वाधिक गतिशील क्षेत्रों में से एक में हो रहा है। भारत इससे शायद इसलिए बाहर रहा क्योंकि उसे इसमें चीन का दबदबा होने की आशंका है। बहरहाल, इससे चीन के आयात पर हमारी निर्भरता में कोई कमी नहीं आई। हालांकि भारत ने कई देशों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन शायद यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में सहायक नहीं है। भारत को जलवायु को लेकर बढ़ती चिंताओं के हिसाब से भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यूरोपियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (ईबीएएम) जैसे उपाय भारतीय निर्यात को काफी हद तक प्रतिबंधित कर सकते हैं।

सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत ने बीते वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे इसकी गति को बरकरार रखने की जरूरत है। भारत सेवा क्षेत्र में दुनिया का सातवां सबसे बड़ा निर्यातक है और उसने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी काफी मजबूती दिखाई है। वास्तव में देश का सेवा क्षेत्र केवल आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर विकास और शोध के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है। जैसा कि रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों के हालिया शोध से पता चला है, 2015-16 की तुलना में 2022-23 में देश में वैश्विक क्षमता केंद्र करीब 60 फीसदी बढ़े। यह बताता है कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि बढ़ी है। हालांकि इस मजबूती के बावजूद सेवा निर्यात ने 2023-23 में 4.9 फीसदी के साथ तीन वर्षों की सबसे कम वृद्धि दर्ज की। इसका अध्ययन करना आवश्यक है।

सेवा निर्यात बढ़ाने के लिए भारत को मानव संसाधन में निवेश करना होगा। चूंकि सेवा क्षेत्र कुशल कर्मियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है इसलिए बुनियादी और उन्नत शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण, शोध और विकास में भारी निवेश आवश्यक हैं। सेवा निर्यात केंद्रों में विविधता लाना भी मददगार होगा। देश का आधा से अधिक सेवा निर्यात अमेरिका और कनाडा जाता है। ऐसे में वहां आर्थिक उथलपुथल हमें भी प्रभावित करेगी। व्यापक नीतिगत स्तर पर भारत को वस्तु निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। भूराजनीतिक हालात को देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से दूर विविधता लाना चाहती हैं। यह बात भारत के सामने निवेश जुटाने और विनिर्माण बढ़ाने का बड़ा अवसर लाती है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

बिनय सिन्हा

चीन प्लस वन रणनीति भारत के लिए अवसर

मौजूदा वैश्विक हालात की बात करें तो आर्थिक और भूराजनीतिक दृष्टि से भारत की स्थिति बेहतर है। ऐसे में उसे चीन प्लस वन की रणनीति का लाभ मिल सकता है। बता रही हैं सोनल वर्मा

आर्थिक विकास के लिए 'वाइल्ड गीज-फ्लाइंग पैटर्न' जापानी शब्द गांको केईताई का अनुवाद है जिसे अर्थशास्त्री कनामे अकामात्सु ने जापान में देखे गए आर्थिक विकास के रुझान की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल किया था।

युद्ध के बाद जापान ने कपड़ों जैसे सस्ते उत्पादों का उत्पादन शुरू किया। सन 1960 के दशक में इनकी लागत बढ़ने के बाद उसने इस उत्पादन को नई औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं हॉन्गकॉन्ग, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान को स्थानांतरित कर दिया। सन 1990 के दशक में जब ये अर्थव्यवस्थाएं जापान के करीब पहुंचने लगीं तो उन्होंने आसियान-4 और चीन की उड़ान में मदद की।

अकामात्सु के नजरिये से देखें तो चीन से आपूर्ति श्रृंखला का स्थानांतरण आर्थिक विकास की एक स्वाभाविक प्रगति की परिणति है। हालांकि अमेरिका-चीन तनाव तथा महामारी ने भी इस रुझान को बल दिया है क्योंकि कई बहुराष्ट्रीय देश के चीन के अलावा विकल्प तलाश रहे हैं ताकि आपूर्ति श्रृंखला में विविधता ला सकें।

भारत को क्या लाभ हो सकता है?

उपलब्ध आंकड़े मिलेजुले हैं लेकिन संकेत बताते हैं कि भारत को अहम लाभ संभव हैं। ग्रीनफील्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में विदेशों में नए प्रतिष्ठानों की स्थापना शामिल है और यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हो रहे बदलावों को मापने का अहम मानक है। एफडीआई मार्केट्स के अनुसार 2023 में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहले और दुनिया भर में दूसरे स्थान पर रहा और उसने 83.7 अरब डॉलर मूल्य की 1,006 ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाएं अपने यहां आकर्षित कीं। करीब 30 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता राशि ऊर्जा क्षेत्र के अलावा विनिर्माण एफडीआई परियोजनाओं के लिए जताई गई। यह 2022 के 34.7 अरब डॉलर से कम है लेकिन 2003 में आंकड़े लिए जाने के बाद से किसी भी अन्य वर्ष से अधिक है।

हमारा सर्वेक्षण भी ऐसे ही लाभों के संकेत देता है। हमने करीब 130 कंपनियों के आंकड़े जुटाए जो या तो अपना उत्पादन चीन से बाहर ले जाना चाह रही हैं या जो एशिया में या कहीं और नया उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही हैं।

हमारे परिणाम दिखाते हैं कि 129 में से 28 कंपनियों ने भारत में रुचि दिखाई। वियतनाम में 23, मेक्सिको में 19, थाईलैंड में 16 और मलेशिया में 14 देशों ने रुचि दिखाई। ये परिणाम 2019 के सर्वे से अलग हैं जब वियतनाम सबसे बड़ा लाभार्थी था और भारत शीर्ष पांच से बाहर था। भारत को होने वाले लाभ भी बहुत व्यापक और तमाम क्षेत्रों तक विस्तारित हैं। कंपनियां स्मार्ट फोन, वाहन और वाहन कलपुर्जा, पूंजीगत वस्तुओं, सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण तथा वस्त्र क्षेत्र में निवेश करना चाहती हैं। चीन के जोखिम को कम करना अहम कारक है लेकिन भारत आ रही कंपनियां घरेलू उपभोक्ता बाजार, यहां की बड़ी और कुशल श्रम शक्ति तथा प्रगतिशील नीतियों से भी प्रभावित हैं।

निवेश करने वाले देशों के स्रोत भी भारत को अच्छी स्थिति में रखते हैं। हमारा सर्वेक्षण बताता है कि नए निवेशों में चीन एक अहम निवेशक है लेकिन उसका अधिकांश निवेश आसियान देशों में है। इसके विपरीत भारत आने वाले निवेश में बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों तथा जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान जैसे विकसित एशियाई देशों का है। आसियान देशों में चीनी कंपनियों का निवेश आंशिक रूप से कारोबारी टैरिफ से बचाव के लिए है लेकिन अब जबकि पश्चिमी देश उन कमियों को दूर करना चाहते हैं जिनकी वजह से चीनी कंपनियां अपने व्यापार को तीसरे देशों के रास्ते से पुनर्निर्देशित करती हैं, हम मानते हैं कि भारत में होने वाले निवेश में और विविधता आएगी।

प्रतिकूल विचार

हमें अपने नजरिये को लेकर तीन आपत्तियां सुनने को मिलीं। पहली, भारत का व्यापार संतुलन सुधर नहीं रहा है। ऐसे में लाभ कहां है? हमारा जवाब यह है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला अथवा जीवीसी के साथ एकीकरण एक प्रक्रिया है जहां भारत अभी शुरुआती चरण में है। अभी वह आयातित कच्चे माल पर अधिक निर्भर है क्योंकि घरेलू विकल्प सीमित हैं। बहरहाल घरेलू व्यवस्था विकसित होने के बाद घरेलू उत्पादन आयात को प्रतिस्थापित कर देगा और निर्यात में इजाफा होगा। इससे व्यापार संतुलन सुधरेगा। दूसरी आपत्ति यह है कि अगर भारतीय निर्यात को आयात संरक्षण चाहिए तो यह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कैसे बन सकता है? भारत की नीति में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। जापान और दक्षिण कोरिया की औद्योगिक नीतियों को देखें तो शुरुआती दौर में ऐसा संरक्षण आम है। बहरहाल यह अस्थायी होना चाहिए और सरकार की सब्सिडी की मदद से ही सही समय पर इससे निजात पाई जा सकती है।

तीसरी आपत्ति यह है कि निर्यात संचालित वृद्धि की नीति क्या वैश्वीकरण से रहित दुनिया में कामयाब होगी? यह एक चुनौती है क्योंकि भारत के सामने प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य है। बहरहाल, चूंकि आज कंपनियां लागत कम करने के बजाय विविधता लाना चाह रही हैं और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाह रही हैं इसलिए चीन के अलावा एक अन्य निवेश केंद्र के लिए पर्याप्त अवसर रहेंगे।

चीन की चुनौती

भारत के वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण के बावजूद हम औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण के लिए कच्चा माल जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जे, सोलर पैनल आदि पाने के क्रम में चीन पर बहुत निर्भर होंगे। इससे चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ेगा लेकिन इससे भी अधिक अहम बात है कि इससे सूक्ष्म, मझोले और छोटे घरेलू उपक्रमों का विकास सीमित होगा। भारत के लिए बेहतर होगा कि वह घरेलू मूल्यवर्द्धन पर ध्यान दे।

गतिशील हों सरकारी नीतियां

भारत का प्रारंभिक लक्ष्य होना चाहिए कम प्रौद्योगिकी वाली विनिर्मित वस्तुओं के क्षेत्र में निर्यात बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना जो कि लागत के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील होती हैं। इसके लिए मध्यवर्ती वस्तुओं की शुल्क दर कम करने की आवश्यकता है।

साथ ही नए मुक्त व्यापार समझौते करने, श्रम बाजार नियमों को सरल बनाने, बेहतर अधोसंरचना, लॉजिस्टिक लागत में कमी करने तथा अनुकूल निवेश माहौल बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय निर्माताओं के संरक्षण के लिए सब्सिडी की मियाद तय होनी चाहिए और घरेलू उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

अगला चरण होगा मूल्य श्रृंखला में सुधार करके सामान्य से उन्नत उत्पादों की ओर बढ़ना। इसके लिए बेहतर मानव संसाधन की जरूरत होगी और नवाचार पर ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकती है कि वे शोध एवं विकास पर अधिक व्यय करें।

उच्च प्रौद्योगिक विनिर्माण में भारत से बेहतर स्थिति वाले देश मसलन दक्षिण कोरिया आदि ने अपने निर्यात की गुणवत्ता को नवाचार के जरिये बदला है और वे उन्नत विनिर्माण करने लगे हैं। भारत को भी इस दिशा में बढ़ना चाहिए।

कुल मिलाकर भारत आर्थिक और भूराजनीतिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में है और वह चीन प्लस वन की नीति से लाभ उठा सकता है। सरकारी नीतियों को घरेलू मूल्यवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि मूल्य श्रृंखला में अपनी स्थिति बेहतर की जाए। कहा जा सकता है कि भारत के लिए तो यह अभी शुरुआत है।

(लेखिका नोमूरा में मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

ऊर्जा के बदलते स्रोत और महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ऊर्जा संक्रमण यानि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सौर, पवन, जल विद्युत, हाइड्रोजन आदि वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हुए थे। हालांकि, इन प्रयासों पर लोगों एवं समाचार माध्यमों का कम ध्यान गया था। हाल ही में इस समाचारपत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अफ्रीका के दर्जनों देशों के साथ नए समझौते करने या पुराने समझौते अद्यतन करने से जुड़े प्रयासों रेखांकित किए गए थे।

इसी वर्ष भारत सरकार ने अर्जेन्टीना में पांच लीथियम ब्राइन खदानों के अन्वेषण और विकास के लिए लिए वहां की सरकार के साथ समझौता किया था। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में उपयोग होने वाली बैटरियों के लिए लीथियम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अर्जेन्टीना के साथ यह समझौता हुआ है।

कुछ महीने पहले सरकार ने भारत में महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए देसी एवं विदेशी निजी खनन कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयास किए थे। बोलीदाताओं की तरफ से ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद 20 महत्त्वपूर्ण खनिज खदानों की नीलामी की पेशकश पिछले महीने रद्द करनी पड़ी। मगर यह बात सिद्ध हो गई कि सरकार अति महत्त्वपूर्ण खनिजों के महत्त्व को बखूबी समझ रही थी।

अब शपथ लेने के बाद नई सरकार को इन प्रयासों को जारी रखने एवं इन्हें तेज करने की जरूरत है। पूर्व की तुलना में अपने प्रयासों के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए नीतियों में थोड़े बदलाव की भी आवश्यकता होगी। पिछले पांच वर्षों के दौरान मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह महसूस किया कि महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत आयात, खासकर चीन, पर काफी निर्भर है। हालांकि, इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार ने जो प्रयास किए हैं वे अधिक सार्थक सिद्ध नहीं हुए हैं। सौर ऊर्जा उपकरण (सोलर पैनल) और ईवी बैटरियों के लिए लीथियम, कोबाल्ट, निकल, कैडमियम, जर्मेनियम, नायोबियम, बेरिलियम, वैनेडियम और कई अन्य खनिजों की आवश्यकता होती है। लीथियम सबसे अधिक चर्चा में रहता है क्योंकि वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहनों में लीथियम-आयन बैटरी रसायन का इस्तेमाल होता है।

प्रसेनजित दत्ता

इसके अलावा मोबाइल एवं टैबलेट में भी इसका उपयोग होता है। दूसरे खनिजों की भी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है मगर उनमें प्रत्येक ऊर्जा संक्रमण के लिए उतने महत्त्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। हम इनमें सभी खनिजों के लिए आयात पर (विशेषकर चीन पर) निर्भर हैं। भारत को यह बात समझने में थोड़ी देर हो गई कि चीन से आपूर्ति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य आसानी से नहीं साधा जा सकता है। भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसे देरी से इस सच्चाई का भान हुआ है। अमेरिका ने अब जाकर यह अनुभव किया है कि उसने को महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति व्यवस्था में चीन को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दे दिया। जहां तक इन महत्त्वपूर्ण खनिजों के प्रामाणिक भंडार की बता है तो चीन इस मामले में सबसे आगे नहीं है मगर वह अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में खनिज संपन्न संपन्न देशों के साथ दशकों से अपने संबंध मजबूत करता रहा है। चीन की कंपनियों ने आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन खनिज संपन्न देशों में खनन अधिकार हासिल किए हैं जबकि अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया इन संभावनाओं का लाभ उठाने में सुस्त रहे हैं। चीन ने इन खनिजों के प्रसंस्करण एवं परिष्करण की विशाल क्षमता हासिल कर ली है। इसका अभिप्राय हुआ कि विभिन्न देशों में खनन के बाद लीथियम से लेकर कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्व सभी महत्त्वपूर्ण खनिज अयस्क प्रसंस्करण के लिए चीन भेजे जाते हैं। भारत को महत्त्वपूर्ण खनिजों के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए त्रि-आयामी नीति अपनानी होगी। सबसे पहले इस बात का पता लगाना और भौगोलिक अध्ययन करना होगा कि भारत में इनमें एक या उससे अधिक खनिजों के भंडार उपलब्ध हैं या नहीं। पूर्व में यह धारणा रही थी कि भारत में इन खनिजों का अभाव रहा है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अब तक गंभीर स्तर पर अन्वेषण नहीं हुए हैं क्योंकि इन खनिजों की बहुत अधिक आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी। खबरों के अनुसार पिछली मोदी सरकार ने भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (जीएसआई) एवं अन्य एजेंसियों को देश के 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और नई तकनीक सहित नए डेटा संसाधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। यह कदम काफी आवश्यक है क्योंकि जब जरूरत महसूस हुई तो पिछले वर्ष जीएसआई ने जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लीथियम भंडार खोज निकाला था। फिलहाल जिन खनिजों की खोज हो रही है सरकार को उनका दायरा भी बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए इस समय सफेद हाइड्रोजन की सक्रियता से खोज नहीं हो रही है जबकि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि यह भारत की भौगोलिक सीमा में मौजूद हो।

यह सच है कि जितने भी भंडार खोजे जाएंगे वे सभी इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकेंगे। इनमें कुछ पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में हो सकते हैं जहां सुरक्षा या अन्य चिंताओं के कारण जाने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। उसके बाद सरकार को इस बात का भी विश्लेषण करना होगा कि क्यों नीलामी में कंपनियां अक्सर अधिक दिलचस्पी नहीं दिखती है। नीलामी में बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नीतियों में बदलाव की जरूरत हो सकती है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को मिलकर नीलामी एवं मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मसलों का समाधान खोजना होगा।

महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए देश से बाहर खनन अधिकार प्राप्त करना एक दूसरा महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। चीन एवं दूसरे देश इस बात को समझते हैं। कई यूरोपीय देश और अमेरिका पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण अपने कुछ लीथियम भंडारों को विकसित नहीं करना चाहते हैं और लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से इनका आयात करने को तरजीह देते हैं।

अंत में, नई सरकार को भारत में इन खनिजों के परिष्करण एवं प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर कच्चा माल परिष्करण या प्रसंस्करण के लिए चीन या दूसरे देश भेजा जाते रहा तो यह भारत के लिए लाभ की स्थिति नहीं होगी। भारत के ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस पहलू पर वाजिब ध्यान दिया जाए।

(लेखक बिज़नेस टुडे और बिज़नेसवर्ल्ड के संपादक रह चुके हैं और संपादकीय सलाहकार संस्था प्रोजेक व्यू के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

खूबियां अधिक हैं गठबंधन सरकार की

गठबंधन सरकार के कामकाज में हमेशा विविध हितों के लिए जगह होती है। राजनीतिक दलों की विचारधाराएं और एजेंडे अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन भारत में गठबंधन सरकार आम सहमति पर आधारित राजनीति पर चलती है जो किसी भी राजनीतिक प्रणाली के संघीय ताने-बाने को मजबूत करती है। चूंकि सभी सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। इसलिए इस तरह की सरकार में तानाशाही शासन की संभावना कम हो जाती है। गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष भी बहस का एक प्रमुख विषय रहे हैं। गठबंधन सरकार के लाभ और नुकसान दोनों है। गठबंधन सरकार की मुख्य खूबियां यह है कि यह कई नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक जगह प्रदान करती है। इससे लोकतंत्र और संघवाद मजबूत होता है। गठबंधन सरकार के उदय का श्रेय इस तथ्य को दिया जाता है कि यह समाज के कई वर्गों के लिए सुरक्षा के रूप में काम करती है, जिनकी चिंताओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र के युग में गठबंधन सरकार के और भी कई फायदे हैं। गठबंधन सरकार समाज के सभी वर्गों की शिकायतें दूर करने में सक्षम है और राष्ट्र का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। यह निरंकुश नेतृत्व और शासन में बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि सभी दल सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। चूंकि साझा शासन और संयुक्त शासन गठबंधन सरकार के दो स्तंभ हैं इसलिए इसके कुछ नुकसान भी हैं। दृष्टिकोण और विचारों में अंतर, सरकार में असंतुलन और अस्थिरता पैदा कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को नेता माना जाता है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री को निर्णय लेने के लिए गठबंधन के सहयोगियों से सुझाव और सलाह लेनी होगी। क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय मुद्दों और संघर्षों को सामने लाते हैं तथा सरकार को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करते हैं।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

राजग के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मंगलवार को एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार संभाला

दरों में कुछ कटौती जरूरी

भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार रीपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। यह लगभग आठवीं बार है कि रिजर्व बैंक ने ऐसा किया है। इससे उन लोगों को निराशा हाथ लगी जिन्हें रीपो दर में कमी की इसलिए उम्मीद थी कि इससे उनका आवास या वाहन ऋण सस्ता हो सकता है। वैश्विक महामारी के आसपास जिन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई ऋण लिया था, उनके लिए वह ऋण आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला सिद्ध हुआ और महंगी ब्याज दरों के कारण अभी भी परेशानी बना हुआ है क्योंकि कोरोना काल में लोगों के कमाई के साधन लगभग ठप हो गए थे। लेकिन ऋण की किस्त उन्हें किसी न किसी तरह चुकानी पड़ती थी। हालांकि उस समय रिजर्व बैंक ने किस्तों को आसानी से भरने के लिए कुछ कदम भी उठाए थे। उस समय सरकार पर आर्थिक संकट था। लेकिन अब सरकार की कमाई के साधन सुचारु रूप से चल रहे हैं। इसलिए आरबीआई को चाहिए कि वह रीपो दरों में कटौती कर लोगों को राहत पहुंचाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित छह मंजिला इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में अधिकतर भारतीय हैं। इस इमारत में करीब 160 लोग रहते थे जो एक ही कंपनी के कर्मचारी हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 13 जून 2024

दो बार दाखिला सही

यूनिवर्सिटियों को साल में दो बार एडमिशन की इजाजत देने का UGC का फैसला सतर्कता के साथ, सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले कई सवालों से दो-चार होना पड़ेगा।

धीरे-धीरे बदलाव | अपवादों को छोड़ दिया जाए तो देश के सारे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन साल में एक बार जुलाई-अगस्त में होता है। इस सिस्टम का स्कूल-कॉलेजों के सत्र से तालमेल बना हुआ है। फिर, यूनिवर्सिटियों के UG कोर्सों में एडमिशन CUET के जरिए हो रहा है। ऐसे में इस प्रक्रिया को बदलना हो तो कई स्तरों पर बदलाव की जरूरत होगी। जाहिर है, यह धीरे-धीरे ही हो सकता है।

AI Image

छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा

एकरूपता | दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटियों में साल में दो बार एडमिशन का चलन काफी पहले से है। भारत में भी यह शुरू हो जाए तो न केवल एडमिशन साइकल में एकरूपता आएगी बल्कि अलग-अलग सत्रों के अलग पाठ्यक्रम रखने की गुंजाइश भी बनेगी।

बढ़ेगा एनरोलमेंट | नई व्यवस्था का एक और फायदा यह माना जा रहा है कि इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) यानी उच्च शिक्षा के लायक उम्र समूह वाली कुल आबादी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स का अनुपात बढ़ेगा। जब एक साल में दो बार एडमिशन का मौका मिलेगा तो जो स्टूडेंट्स स्वास्थ्य कारणों से या बोर्ड परीक्षा परिणामों में देरी के चलते या अन्य निजी कारणों से एडमिशन लेने से चूक गए हों, उन्हें एक साल इंतजार नहीं करना होगा।

पहले का अनुभव | UGC डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए साल में दो बार एडमिशन का जो सीमित प्रयोग पहले कर चुका है, उसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इसका फायदा यह हुआ कि करीब 5 लाख अतिरिक्त स्टूडेंट्स का साल बर्बाद होने से बच गया।

व्यावहारिक दिक्कतें | वैसे, जमीनी हकीकत यह है कि देश के ज्यादातर विश्वविद्यालय इस नई व्यवस्था को अपनाने की स्थिति में नहीं हैं। स्कूलों-कॉलेजों के मौजूदा शैक्षिक सत्र के मद्देनजर दूसरी बार एडमिशन का आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी संभवतः काफी कम होगी। अगर स्टूडेंट्स आ भी जाएं तो इन्फ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी जैसी चुनौतियों से निपटना उनके लिए आसान नहीं होगा।

वैकल्पिक स्वरूप | संभवतः इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर UGC ने इस व्यवस्था को वैकल्पिक ही रखा है। अपनी तरफ से इजाजत दे दी गई है, लेकिन यह यूनिवर्सिटियों पर छोड़ दिया गया है कि इस नए सिस्टम को कब, कैसे और कितना अपनाना है। जाहिर है, UGC ने अभी बदलाव की दिशा का संकेत भर किया है। पर इसमें दो राय नहीं कि ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम से एकरूपता कायम करना भारतीय शिक्षा जगत के लिए एक अच्छा लक्ष्य है।

साड्डी दिल्ली

हैदराबाद हाउस कथा

विवेक शुक्ला

हैदराबाद हाउस में खड़े नीम के पेड़ों ने बीते नौ दशकों में बहुत कुछ बनते-बदलते देखा है। ये दरख्त तब लगे थे जब एडवर्ड लुटियंस के डिजाइन पर हैदराबाद हाउस बन रहा था। आजकल जब सूरज देवता आग उगल रहे हैं, इन पेड़ों से बहने वाली मीठी बयार सुकून देती है। करीब आठ एकड़ में फैले हैदराबाद हाउस को 1928 में हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने बनवाया था। 1911 में जब दिल्ली देश की नई राजधानी बनी तो कई रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से उन्हें नई राजधानी में अपना कोई 'हाउस' बनाने के लिए जमीन देने की गुजारिश की। तब यहां हैदराबाद, जोधपुर, त्रावणकोर, कोटा, जैसलमेर, बड़ौदा, बीकानेर, ग्वालियर, पटियाला, मंडी जैसी रियासतों को लैंड मिली। इनमें 26 कमरों वाला हैदराबाद हाउस सबसे भव्य माना जाता है। जब हैदराबाद हाउस बना था, तब आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का नामो-निशान भी नहीं था। आगे चलकर हैदराबाद आंध्रप्रदेश की राजधानी बना। लेकिन, बीती 2 जून से यह सिर्फ तेलंगाना की राजधानी रह गया है। इस बीच, हैदराबाद हाउस में अब भी कुछ इस तरह के परिवार रहते हैं जिनके बुजुर्ग इधर तब नौकरी करने आए थे जब यह निजाम के नियंत्रण में था। फुटबॉल कमेंटेटर गौस मोहम्मद के पिता 1940 के दशक में हैदराबाद हाउस में नौकरी करने देवबंद से आए थे। वह तब इधर ही रहते थे जब सरदार पटेल ने अपने 1, औरंगजेब रोड (अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड) स्थित आवास से हैदराबाद में 'ऑपरेशन पोलो' प्लान किया था। देश आजाद होने के बाद हैदराबाद हाउस को सरकार ने टेकओवर कर लिया था। इधर ही राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी का रिसेप्शन भी हुआ था, 25 फरवरी 1968 को। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के दौर में हैदराबाद हाउस विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ही अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों- बराक ओबामा और डॉनल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात और राजकीय भोज की व्यवस्था की। अब सरकार साउथ ब्लॉक के पास एक नया भवन बनाने जा रही है। इसका नाम होगा 'इंडिया हाउस'। आइंदा शिखर वार्ताएं उसमें ही होंगी। देखना है कि इंडिया हाउस बनने के बाद हैदराबाद हाउस का किस रूप में इस्तेमाल होगा। यह जानना जरूरी है कि हैदराबाद हाउस का ही हिस्सा था आंध्र प्रदेश भवन। अब यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बंट गया है। पुराने आंध्र प्रदेश भवन का 58% आंध्र प्रदेश सरकार के पास है और बाकी 42% तेलंगाना के हिस्से में है। आंध्र प्रदेश भवन का निर्माण 1975 में पूरा हो गया था। इसका डिजाइन जे.एम. बेंजामिन ने तैयार किया था।

Subrata Dhar

एकदा

नहीं चाहिए इनाम

ब्रिटिश राज के दौरान लखनऊ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था। वहां नवाबों की महफिलें तो जमती ही थीं, मुशायरे भी उन दिनों खासे आम थे। इस माहौल में मीर तकी मीर जैसे महान शायर का होना एक अद्वितीय आकर्षण था। मीर साहब अपनी शायरी के लिए तो हर जगह सम्मान पाते ही थे, एक दरवेश परिवार से होने के कारण उनकी खास इज्जत थी। लेकिन इसी समय अंग्रेज भी दस्तक दे रहे थे, कई जगह उनका कब्जा हो चुका था। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल और अन्य उच्च अधिकारी जब भी लखनऊ आते, तो नवाबों की तरह मीर तकी मीर की महफिल का आयोजन करते। उन्हें लगता था कि हुक्मरान होने के नाते उनके लिए मीर साहब का कलाम सुनना जरूरी है। इसलिए, मीर को नियमित रूप से दावतनामे भेजे जाते थे। लेकिन मीर फिरंगियों की दावतों से कतराते। एक बार किसी ने पूछ लिया कि इनाम और रुतबा तो हर कोई हासिल करना चाहता है, फिर आप इससे क्यों कतराते हैं? मीर बोले, 'मुझसे जो मिलता है, इसलिए मिलता है कि मैं फकीर यानी दरवेश के परिवार से हूं। दूसरी वजह मेरी शायरी है। इन गोरे साहबों पर मेरे सूफी होने का तो कोई असर नहीं होता और मेरा कलाम भी उनकी समझ में नहीं आता। फिर भी ये कलाम के लिए इनाम देते हैं। अब कोई बताए, ऐसी मुलाकात से जिल्लत के सिवा क्या हासिल?' मीर की यह कैफियत पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन पा वही सकता है जो मीर की तरह ऐसे हुक्मरानों को अपनी ठोकर पर रखे।

Shital Verma

संकलन : **जमील गुलरेज**

5 साल के कार्यकाल में सांसद के लिए इस निधि के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है

क्या सांसद निधि की अब भी ज़रूरत है

उमेश चतुर्वेदी

मोदी की अगुआई वाली NDA सरकार के पहले कार्यकाल में श्रम राज्यमंत्री रहे संतोष गंगवार के पास साल 2014 में एक सुबह कुछ लोग किसी कार्यक्रम के लिए वक्त मांगने पहुंचे। गंगवार के पास लोगों की भीड़ लगी थी। सबके बीच ही साधारण से कप में चाय पीते हुए उन्होंने कार्यक्रम के दिन के बारे में पूछा। वह दिन शनिवार का था। गंगवार ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि वह हर शुक्रवार की रात अपने निर्वाचन क्षेत्र बरेली के लिए निकल जाते हैं और बहुत जरूरी काम नहीं रहा तो सोमवार की सुबह ही दिल्ली लौटते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन वह क्षेत्र के लोगों के साथ बिताते हैं। यही उनकी पूंजी है और इसी के दम पर वह 1989 से लगातार सांसद हैं।

सांसदों से असंतोष | सवाल है कि BJP में ऐसे कितने सांसद रहे, जो जनता के सुख-दुख का साथी बने रहने का दावा कर सकते हैं। जानकार इस बात पर एकमत हैं कि हालिया नतीजों में BJP के आशा के मुताबिक प्रदर्शन न करने की एक बड़ी वजह उसके ज्यादातर सांसदों के खिलाफ एंटीइनकंबेंसी भी रही है। आंकड़े भी इस तथ्य की गवाही देते हैं। पार्टी के पास बीती लोकसभा में 300 सांसद रह गए थे, जिनमें से उसने 168 सांसदों को फिर से मैदान में उतारा। उनमें से 66% यानी 111 सांसदों को जनता ने नकार दिया। पार्टी ने जिन 132 जगहों पर नए प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 95 को जीत मिली।

लहर का सहारा | हारे हुए सांसदों में से ज्यादातर के बारे में धारणा है कि वे मोदी लहर के सहारे ही एक बार फिर अपनी चुनावी नैया पार होने की उम्मीद लगाए हुए थे। हार को लेकर ये पूर्व सांसद कई बातें बना रहे हैं। लेकिन लोक की सेवा के लिए उनके पास तमाम अवसरों के अलावा सांसद निधि भी उपलब्ध थी। कुछ सांसदों ने इस निधि को ठीक से खर्च भी किया है, लेकिन ज्यादातर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

AI Image

छोटी नहीं रकम | यह रकम छोटी-मोटी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से हर सांसद को पांच करोड़ रुपये सालाना खर्च करने का अधिकार होता है। इस लिहाज से हर लोकसभा सांसद के हिस्से पांच साल में 25 करोड़ रुपये आते हैं। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। यानी हर साल में सांसद निधि में 2,515 करोड़ रुपये मिलते हैं। लोकसभा के कार्यकाल में यह रकम 12 हजार 575 करोड़ रुपये होती है। अगर यह रकम हर सांसद के जरिए ठीक से खर्च हो जाए तो आम लोगों की तमाम छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बदले में सांसदों को लोक सहयोग की अनमोल निधि मिलेगी।

सांसद निधि के नफा-नुकसान?
- छोटी-मोटी समस्याओं के लिए सही
- प्रशासनिक लालफीताशाही से बचाव
- भ्रष्टाचार और लापवाही की शिकायतें

राव ने की थी शुरुआत | इस फंड की जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही है। अगर सांसद इसी रकम को अपने क्षेत्र में संतुलित रूप से खर्च कर रहे होते तो BJP के मौजूदा सांसदों की हार के आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सांसदों की नाकामी पर चर्चा से पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत नरसिंह राव शासनकाल में साल 1993-94 में हुई थी। तब इसके तहत हर सांसद को हर साल पांच लाख रुपये अलॉट किए जाते थे।

बढ़ती रही रकम | सालाना पांच लाख रुपये को सांसदों ने तब नाकाफी बताया था। अगले ही साल यानी वित्तीय वर्ष 1994-95 में इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये सालाना कर दिया गया। उसके बाद वाजपेयी सरकार के दौरान साल 1998-99 में इसे दोगुना करके सालाना दो करोड़ रुपये कर दिया गया। मनमोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में इसे पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया।

रकम और बढ़ाने की मांग | इस बीच, AIADMK सांसद थंबीदुरई की अध्यक्षता में बनी सांसदों की एक समिति इसे बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये सालाना करने की मांग कर चुकी है। वैसे कोविड महामारी के चलते 6 अप्रैल 2020 से 9 नवंबर 2021 तक इस फंड का आवंटन निलंबित रखा गया था। साल 2020-21 में इस योजना के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि यानी 10 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के लिए प्रति सांसद महज दो करोड़ रुपये अलॉट हुए।

भ्रष्टाचार की शिकायतें | इदिलचस्प है कि इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष रहते सोमनाथ चटर्जी ने 2008 में इसे बंद करने की बात कही थी। कांग्रेसी सांसद वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाला दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भी इस योजना को बंद करने का सुझाव दे चुका है।

क्या है औचित्य | जिस योजना का जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा, उसे क्यों जारी रखा जाए? जो सांसद अपने बजाय किसी और के काम पर भरोसा करते हों, जो एक बार जीत कर सत्ता की हनक का इस्तेमाल करते रहे हों, उन्हें यह फंड क्यों दिया जाना चाहिए? जनता की गाढ़ी कमाई की इस रकम का इस्तेमाल लोक के लिए किसी और जरिए से क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

(लेखक राजनीतिक समीक्षक हैं)

कोटे पर BJP से SC खफा, ST क्यों नहीं

दीपांकर गुप्ता

लोकसभा चुनावों के नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति (SC) के वोटरों ने BJP के खिलाफ मतदान किया। उन्हें डर था कि अगर NDA फिर से सत्ता में आता है, तो आरक्षण खत्म कर देगा। SC का BJP से दूर जाने का सिलसिला चुनाव के पहले ही शुरू हो चुका था। हालांकि अनुसूचित जनजाति (ST) के मतदाताओं के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

BJP संग ST | ST ने SC की तरह रिएक्ट क्यों नहीं किया? अगर BJP कोटा हटाती है तो इससे दोनों ही समुदाय बराबर प्रभावित होंगे। ST समाज के BJP के साथ बने रहने का नतीजा यह निकला कि जिन इलाकों में इस समुदाय की आबादी राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में ज्यादा है, वहां NDA का प्रदर्शन अच्छा रहा। यूपी के नतीजे दिखाते हैं कि SC समुदाय ने बड़े पैमाने पर NDA से किनारा कर लिया। BJP की अगुआई वाले गठबंधन को उन 22 सीटों में से 17 पर हार झेलनी पड़ी, जहां SC कम्युनिटी की कुल आबादी 20% से ज्यादा है।

NDA को वोट | जिन 6 बड़े राज्यों में ST की आबादी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, वहां NDA का प्रदर्शन यूपी के बिल्कुल उलट रहा। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा, झारखंड और त्रिपुरा। इन सभी जगह गठबंधन ने आराम से जीत दर्ज की। झारखंड में भी NDA ने क्लीन स्वीप किया होता, लेकिन वहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजी सहानुभूति लहर ने I.N.D.I.A. ब्लॉक को फायदा पहुंचाया।

कम भेदभाव | इन बातों से यह नतीजा निकलता है कि भले ही SC और ST, दोनों को आरक्षण का लाभ मिलता हो, लेकिन उनकी दुनिया एक जैसी नहीं है। इसका पहला कारण यह समझ आता है कि ST के पास SC की तरह बाबा साहब आंबेडकर जैसा अपना कोई नैशनल हीरो नहीं है। एक जवाब यह भी है कि गरीब और ऐतिहासिक रूप से वंचित होने के बावजूद उनका सामाजिक पिछड़ापन ऐसे कामों की वजह से नहीं है जिसे अछूत समझा जाता है। ST के पिछड़ेपन की वजह रही भौगोलिक दूरी।

समाज का सम्मान | ST समाज के पेशे को बुरा नहीं समझा गया, कोई दाग नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम। आज भी 80% समुदाय खेती-किसानी, बागवानी, मछली पालन वगैरह करता है। जनरल पॉपुलेशन के 53% आंकड़े से यह बहुत ज्यादा है। Anthropologist और गांधीवादी एनके बोस के मुताबिक, आधुनिक युग के पहले कुछ जनजातीय शासक थे, जिन्हें क्षत्रिय माना जाता था। उनमें से कुछ आज भी हैं।

AI Image

कॉमन रूम

हिंदुत्व से नाता | कुछ जनजातियों की जड़ें भक्ति आंदोलन के जरिये हिंदुत्व से जुड़ती हैं, मसलन - मुंडा, ताना भगत और त्रिपुरी। इनके पड़ोसी हिंदू इन्हें अपने से नीचा नहीं समझते। यह भी दावा किया जाता है कि ओडिशा के जगन्नाथ पंथ का शायद जनजातीय अतीत रहा है। All-Adivasi Cultural Committee ने 1973 में दावा किया था कि कई हिंदू देवता असल में संथाली हैं।

SC की स्थिति | ST की इन ऐतिहासिक विशेषताओं से जाहिर होता है कि आरक्षण के मुद्दे पर वे चुप क्यों रहे। अगर SC समाज को देखें, तो उनकी स्थिति ST की तुलना में बिल्कुल अलग रही। वे लोग हिंदू समाज के भीतर रहते थे और उन्हें ऐसे पेशे अपनाने पड़े जिन्हें गंदा कहा जाता है। SC के लिए समाज में आगे बढ़ने का रास्ता शिक्षा और नौकरी है। इससे पता चलता है कि उनके लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है।

विकास में पीछे | एक जैसे संघर्ष के बावजूद अगर ST और SC समाज एक आम नेतृत्व नहीं बना पाया है, तो उसके पीछे कारण यही मूल अंतर है। हालांकि यह विडंबना है कि भले ही ST समाज को SC की तरह कमतर नहीं आंका गया, लेकिन विकास के तमाम पैमानों पर वे बहुत पीछे हैं। अगर इस चुनाव में आरक्षण प्रभावी मुद्दा नहीं बनता, तो हम शायद ST और SC के अंतर को नजरअंदाज कर देते।

(लेखक समाजशास्त्री हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

अध्यात्म सिखाता है हार में छिपी जीत को देखना

हफीज किदवई

क्या हर पराजय केवल पराजय भर है। क्या हर विजय महज विजय भर है। अध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हार-जीत केवल परिणाम पर आकर नहीं रुकती। अध्यात्म में मार्ग प्रमुख होता है। इसी वजह से दुनिया भर में तमाम महापुरुषों की हार को जीत जैसा ही सम्मान मिलता है। परिणाम में उनके हिस्से भले ही पराजय आई हो, मगर उनके मार्ग की महत्ता ने उन्हें विजय जैसा सत्कार दिया है। विजय-पराजय उन्हीं लोगों के लिए है, जो परिणाम से आगे सोच नहीं सकते हैं। जिनको केवल परिणाम ही आकर्षित करता है, वे उस मार्ग के संघर्ष को नहीं समझ सकते, जो व्यक्ति चलते वक्त करता है।

सुकरात को जहर पिला कर मार दिया गया। यदि परिणाम देखेंगे तो लगेगा कि सुकरात हार गए। ईसा को फांसी दी गई। यदि परिणाम देखेंगे तो सामने यही है कि एक राजा ने ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। कर्बला में हजरत हुसैन परिवार समेत शहीद हो गए, तो क्या यजीद जीत गया? महात्मा गांधी ने तो स्वतंत्रता प्राप्त करते ही शहादत को गले लगाया, तो क्या गांधी हार गए? दधीचि अपनी अस्थियां दान में देने के बाद भी विजयी ही तो कहलाए।

यह धरती ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरी पड़ी है जिनमें जीतने वाले का गुणगान नहीं है, बल्कि परिस्थितियों में हारे हुए व्यक्ति को ही विजयी की तरह याद किया गया है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों हार को जीत की तरह बरता जाता है? यहीं से शुरू होता है अध्यात्म। अध्यात्म परिणाम पर नहीं, मार्ग पर अपना दृष्टिकोण बनाता है। जब देखा जाता है कि पराजित व्यक्ति ने पल भर भी मानवता नहीं त्यागी। छल-कपट का सहारा नहीं लिया। अन्याय, अहंकार और अत्याचार का सहारा नहीं लिया। उसके शक्ति प्राप्त करने के हर साधन को छीन लिया गया। उसके मित्र और परिजनों को उससे दूर कर दिया गया। उसके भरोसेमंद लोगों ने उसे धोखा दिया लेकिन वह डिगा नहीं। वह डटा रहा और आत्मबल से सभी परिस्थितियों को चुनौती देता रहा, तो उस व्यक्ति की हार को भी जीत ही कहा गया है।

यह उसके मार्ग की विजय है। उसकी प्रशस्ति उसके मार्ग के चुनाव के कारण है। यही मार्ग उसे हर किसी से अलग करता है। अपने मार्ग पर चलते हुए यदि पराजय भी हो जाए, तो उसे सम्मान मिलता है। यह शक्ति है मार्ग की, ना कि परिणाम की। इसी कारण हार की जीत को भारत में सदैव प्रोत्साहित किया गया है।

अध्यात्म हार की जीत को देखना सिखाता है तो जीत की हार को भी देखना सिखाता है। जीत और हार के इस अंतर को समझना सिखाता है। व्यक्ति का मार्ग, उस मार्ग के संघर्ष और संघर्ष के लिए किए त्याग और समर्पण की महत्ता को समझना सिखाता है। साधारण व्यक्ति केवल परिणाम से अपनी समझ विकसित करते हैं। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति परिणाम के स्थान पर पूरे मार्ग को देखता है और उससे अपनी समझ बनाता है। इसीलिए कहा जाता है, अध्यात्मिक चेतना विकसित कीजिए ताकि परिणाम देखने से पहले उस रास्ते को देख सकें, जो इंसान को गढ़ता है। आध्यात्मिक चेतना सतह के अंदर देखना सिखाती है। इसे विकसित कीजिए, ताकि कभी किसी भी विद्यार्थी या परीक्षार्थी का संपूर्ण अवलोकन कर सकें।

हिमाचल का वह अंग्रेज़ तपस्वी

संतोष ओझा

टाइम मशीन

अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पिता का बड़ा कारोबार था, लेकिन सैमुएल इवांस स्टोक्स जूनियर की उसमें कोई रुचि न थी। साल 1904 में 22 साल की उम्र में वह भारत पहुंचे और शिमला के पास सुबाठू की कोढ़ियों की बस्ती में काम करने लगे। उस समय कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि सारे कोढ़ी समाज से अलग रखे जाएं। सैमुएल तरनतारन और कोटगढ़ में ईसाई पादरियों की ओर से चलाई जा रही कोढ़ियों की बस्तियों में भी गए। जब कांगड़ा में भूकंप आया तो वहां लोगों की सेवा में जुट गए। भारतीय साधुओं का तपस्वी जीवन उन्हें भाया। वेश-भूषा हिंदू साधु की, फर्क बस इतना कि हाथ में ईसाइयों की मनकों वाली माला रोजरी और गर्दन पर लटका क्रॉस।

भारत से लगाव | स्टोक्स ईसाई संन्यासी थे, लेकिन भारत से उनका जुड़ाव ऐसा था कि उन्होंने तय कर लिया कि यहां रहकर काम करना है तो भारतीय गृहस्थ की तरह रहना ठीक होगा। उन्होंने 1912 में ईसाई पादरियों की संस्था से किनारा कर एक ईसाई लड़की एग्नेस से विवाह किया। लड़की के पिता राजपूत परिवार से थे और ईसाई धर्म अपना लिया था।

सेब की खेती | स्टोक्स उन्हीं दिनों कोटगढ़ के पास एक जमीन खरीदना चाहते थे। उस जमीन की अंग्रेज मालकिन ने 30 हजार रुपये में 200 एकड़ का सौदा मंजूर किया। रुपयों का इंतजाम फिलाडेल्फिया में रह रहीं उनकी मां ने किया। स्टोक्स वहां फलों की खेती करना चाहते थे, खासतौर से सेब की। तब इलाके में सेब की खेती छोटे पैमाने पर होती थी। फल काफी खट्टे हुआ करते थे और बाजार में उनकी पूछ न थी। 1916 में जब स्टोक्स अमेरिका गए, तो वहां से सेब, नाशपाती और प्लम के पौधे ले आए। अपने घर के आसपास उन्होंने ये पौधे लगाए। इसके पहले भी जब वह अमेरिका गए थे तो कोटगढ़ की मिट्टी के सैंपल ले गए थे। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने 5-6 तरह के सेब तैयार किए। इनमें रेड डेलीशियस और गोल्डन डेलीशियस काफी लोकप्रिय हुए।

किसानों को सलाह | सेब की उपज बढ़ने से स्टोक्स को थोड़ा मुनाफा होने लगा। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि कोटगढ़ के किसानों की गरीबी दूर करने का एक अच्छा उपाय है सेब की खेती। शुरू में किसानों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। वे आलू और मक्के की खेती से ही संतुष्ट थे। वैसे भी सेब के पौधे लगाने के बाद पहली उपज आने में 4-5 साल लगते थे। तब स्टोक्स ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने खेतों में आलू और मक्के के साथ सेब की खेती करें। यह योजना कामयाब हुई।

समस्या सुलझी | एक बड़ी समस्या थी खराब सड़कों की। रोड खराब होने के कारण उपज समय पर मंडियों तक कैसे पहुंचाई जाती। स्टोक्स ने पंजाब के गवर्नर से अनुरोध किया और सड़क बन गई। इसके बाद तो बाकी जगहों के किसान भी सेब की खेती करने लगे।

स्टोक्स बने सत्यानंद | जीवन के बाद के वर्षों में स्टोक्स हिंदू धर्म के अधिक करीब होते गए। 1932 में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वह अपने भारतीय परिवेश में पूरी तरह घुलमिल जाना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे अमेरिकी और भारतीय पहचान के बीच झूलते रहें। उन्हें नया नाम मिला- सत्यानंद स्टोक्स। उनकी पत्नी का नाम प्रियादेवी। मई 1946 में एक सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।

स्पेस में कमाल

प्रणव प्रियदर्शी

आधी दुनिया

तीस वर्ष की हैं सरानिया पेरियास्वामी और 27 साल की उमा माहेश्वरी के.। दोनों में अंतर बहुत सारे हैं, लेकिन समानता यह है कि दोनों ने दुनिया के पहले 3D इंजन युक्त रॉकेट को अंतरिक्ष पहुंचाने के मिशन में अहम भूमिका निभाई। इस तरह ये दोनों उन गिनी-चुनी महिलाओं के क्लब में शामिल हो गईं जो स्पेस सेक्टर में अपने अमूल्य योगदान से ध्यान खींच रही हैं। कुछ समय पहले तक यह सेक्टर महिलाओं के लिए अनजाना ही था। लेकिन हाल के वर्षों में निगार काजी (सूर्य मिशन आदित्य L 1 की प्रॉजेक्ट डायरेक्टर), कल्पना के. (चंद्रयान 3 की डेप्युटी डायरेक्टर), एम. वनिता (चंद्रयान 2 की प्रॉजेक्ट डायरेक्टर) और रितु श्रीवास्तव (चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर) जैसी महिलाओं ने साबित किया कि स्पेस सेक्टर उनकी पहुंच से दूर नहीं है। इसी तथ्य को नए सिरे से रेखांकित किया है सरानिया पेरियास्वामी और उमा माहेश्वरी ने। अग्निबाण सॉरटेड (Agnibaan SorTeD) की वीइकल डायरेक्टर सरानिया और अग्निकुल कॉस्मोस की मिशन-01 की प्रॉजेक्ट डायरेक्टर उमा माहेश्वरी शुरू से आखिर तक इस पूरे प्रॉजेक्ट में शिद्दत से शामिल रहीं। खासकर, सरानिया के लिए यह उपलब्धि इस मायने में भी विशिष्ट कही जाएगी कि उनका बैकग्राउंड एयरोस्पेस का नहीं है। उन्होंने ओशन टेक्नॉलजी में पोस्ट ग्रैजुएट किया और अग्निकुल में अपनी यात्रा सिस्टम इंजीनियर के तौर पर शुरू की। सिस्टम इंजीनियर की जिम्मेदारी लॉन्च वीइकल की देखरेख से जुड़ी थी। स्पेस सेक्टर में लड़कियों के कम अनुपात को लेकर उनका यह बयान गौर करने लायक है कि यह कॉलेज स्तर पर STEM (साइंस, टेक्नॉलजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स) में लड़कियों के कम अनुपात से ही तय हो जाता है। ओशन टेक्नॉलजी की उनकी क्लास में भी 33 लड़कों के बीच महज 3 लड़कियां थीं। बहरहाल उन जैसों की कामयाबी बताती है कि भविष्य में यह अनुपात तेजी से बदलने वाला है।

AI Image

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ पारदर्शिता जरूरी

12 जून का संपादकीय 'संदेह न रहे' पढ़ा। NEET का रिजल्ट घोषित होते ही पेपर लीक और नंबर देने में गड़बड़ी से जुड़े आरोप सामने आ गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब दाखिल करने को कहा है। सवाल इस बात का है कि 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें 720 में 720 नंबर मिले। इन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। इस साल लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। अगर इसमें पारदर्शिता नहीं रहेगी तो स्टूडेंट्स का मनोबल गिरेगा और माता-पिता भी निराश होंगे। इन आरोपों की जांच कर सारे संदेह दूर किए जाने चाहिए।

मीना धानिया, ईमेल से

■ सियासत में संतुलन

12 जून के लेख 'हिंदुत्व की राजनीति कितनी काम आई' में पढ़ने को मिला कि हिंदी बेल्ट में BJP को हिंदू वोट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिले। इस वजह से उसकी सीटें कम हुईं। लोकतांत्रिक देश की सियासत में संतुलन जरूरी है। इस बार के लोकसभा चुनाव परिणामों का यही संदेश है। भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। ऐसे राष्ट्र में शासन करने के लिए सभी धर्म, संप्रदाय और जातियों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह संतुलन देश-समाज के हित में तो है ही, चुनावी हितों के लिए भी आवश्यक है। अगर आप सिर्फ एक धर्म की बात करेंगे तो दूसरे मजहब के लोग अपने-आप एकजुट हो जाएंगे। इसलिए संतुलन होना जरूरी है।

चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

■ महाराष्ट्र में होगा खेला

यह पत्र 11 जून के संपादकीय 'क्या बदलेंगे समीकरण' से संबंधित है। गठबंधन की सरकार चलाना टेढ़ी खीर है। इसमें सभी दलों को खुश रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भले ही NCP और शिवसेना अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार न करें लेकिन यह तय है कि आने वाले महीनों में चीजें काफी बदलेंगी। महाराष्ट्र में कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उनमें काफी खेल होने की आशंका है।

बाल गोविंद, नोएडा

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

वेटिंग लिस्ट और सफाई के लिए रेलवे को करना होगा काम- खबर
- मतलब इतने दिनों तक रेलवे में काम ही नहीं हुआ!

प्रीति अग्रवाल

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 13 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हमारी पहचान हमेशा हमारे द्वारा छोड़ी गई उपलब्धियों से होती है
-अमेरिकी कहावत

'सुप्रीम' फैसला

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 में फिलहाल काउंसलिंग जारी रखने का सर्वोच्च अदालत का निर्णय बिल्कुल उचित है। इस परीक्षा के परिणाम में कई सारी गड़बड़ियों की बात पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल विद्यार्थी परिणाम में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल, नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। गौरतलब है कि नीट परीक्षा पांच मई को हुई थी और चार जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं। किसी भी परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता होती है। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि ज्यादातर प्रवेश परीक्षा और नौकरियों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो प्रश्न पत्र लीक हुए या उनमें जमकर धांधली की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश इस मामले में खासे बदनाम हैं। इसलिए सरकार को अब बिना वक्त गंवाए ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी होगी। शीर्ष अदालत ने फिलवक्त राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी करते हुए ये कहा कि वह इस मामले में आठ जुलाई तक जवाब दाखिल करे। हालांकि अदालत ने न तो परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई फैसला सुनाया न काउंसलिंग पर रोक लगाई। एक बात तो साफ तौर पर परिलक्षित होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं का स्तर काफी निम्न हुआ है। यह चिंता का सबब भी है और शर्मिंदगी का भी। बच्चों की अनथम मेहनत और परिवारवालों का अनकहा संघर्ष ऐसे धत् कर्म से एक झटके में खत्म हो जाता है। इस मसले पर भी अदालत और सरकार को ज्यादा संवेदना के साथ दिखना होगा। निश्चित तौर पर अदालत के समक्ष कई लाख बच्चों और उनके घरवालों का भरोसा भी है। एनटीए देश में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली शीर्ष संस्था है। उसका भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। इसलिए उसके जवाब का इंतजार तो करना ही होगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि एनटीए की कार्यशैली में कमी है, तो नए सिरे से परीक्षा का आयोजन कराने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं रहेगा।

सुविधा में असुविधा

भारतीय विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में अब साल में दो बार प्रवेश देने की अनुमति मिल जाएगी। यूजीसी ने विदेशों की तर्ज पर इस योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना इसी शिक्षण सत्र 2024-25 जुलाई-अगस्त के साथ जनवरी-फरवरी में भी प्रवेश प्रक्रिया चालू हो जाएगी। माना जा रहा है, जो छात्र किन्हीं कारणों से जुलाई-अगस्त में प्रवेश लेने से चूक जाते हैं, उन्हें पूरा साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल में दो बार प्रवेश सुविधा से उच्च शिक्षण संस्थानों को संसाधन वितरण, जैसे संकाय, प्रयोगशाला, कक्षाएं व सहायक सेवाओं की योजना को अधिक कुशलतापूर्वक बनाने में मदद मिलेगी। इससे विश्वविद्यालय के भीतर सुगमता से काम-काज होगा। ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार, उच्च शिक्षा सिस्टम के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर आता है। यहां अट्ठावन हजार से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें तकरीबन चार करोड़ से अधिक छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश लेते हैं। यह औसत साल-दर-साल बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों को शिक्षा का महत्त्व समझ आ गया है। वे अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए शिक्षा दिलाने में कोई कोताही नहीं करते। हाल के वर्षों में पढ़ाई के प्रति न केवल बच्चों बल्कि उनके परिजनों की भूमिका ज्यादा अच्छे तरीके से जगजाहिर हुई है। छात्र-छात्राएं तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही जागरूकता हुए हैं। निःसंदेह यह सुविधा छात्रों व संस्थानों के लिए वैश्विक शैक्षिक मानकों के अनुरूप लाने वाली साबित हो सकती है, मगर यह कहना कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में होने वाली देरी के कारण प्रवेश लेने से चूकने वाले छात्रों को सुविधा होगी। कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसके लिए बोर्ड जिम्मेदार है। सरकार व शिक्षा विभाग को अपनी इस गलती को स्वयं सुधारना होगा। दूसरे, शिक्षण संस्थानों को दो बार प्रवेश लेने के पूर्व सुविधाओं, व्यवस्था, स्थान या शिक्षा-कक्षों को हर हाल में जरूरतनुसार बढ़ाना होगा। खासकर शिक्षकों की तादाद, परिवहन व छात्रावास के प्रति भी संस्थानों को जिम्मेदार बनाया जाए। दरअसल, अच्छा-खासा शिक्षा शुल्क वसूलने वाले संस्थान ज्यादा से ज्यादा छात्रों को प्रवेश देने को स्वयं लालायित रहते हैं। उन पर यदि नकेल न कसी गई तो यह सुविधा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली साबित हो सकती है।

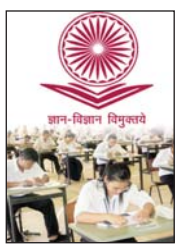

कटाक्ष/ सहीराम

वो नहीं तो तू

वो नहीं तो तू सही, अब खा गाली। दस साल की पढ़ाई है। दस-बारह साल की पढ़ाई के बाद गरीब का बच्चा बेरोजगार होने के काबिल हो जाता है। दस साल नफरत की पढ़ाई के बाद हम क्या तुम्हें गाली देने के काबिल भी न होंगे। कल तक उनको दे रहे थे तो बड़े काबिल थे, अब नाकाबिल या नाकाबिले बर्दाश्त कैसे हो गए। ट्रेनिंग-व्रेनिंग लेकर अग्निवीर चार साल में रिटायर होने के काबिल हो जाता है जनाब। फिर हमारी तो दस साल की ट्रेनिंग है।

हम क्या इस काबिल भी न होंगे कि किसी को भी गाली देने में सक्षम हो सकें। यह क्या बात हुई कि जब तक मुसलमानों को गाली दे रहे थे, तो ठीक था। अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। देखिए हमने नफरत करनी सीखी है। अगर उनसे नहीं करेंगे तो आपसे करेंगे। हमने भेदभाव करना सीखा है। हम तो वही कर रहे हैं। अगर उनसे करेंगे तो आपसे भी तो करेंगे। नहीं क्या? इस पर आपको ऐतराज क्यों है। अगर मुसलमानों को हिंदुओं से अलगाएंगे तो हिंदुओं को भी तो हिंदुओं से अलगाएंगे कि नहीं अलगाएंगे। हमने गालियां देना सीखा है। अगर गालियां नहीं दी तो हम क्या उन्हें भूल नहीं जाएंगे। हमारी आदत नहीं छूट जाएगी। देखिए हमने गालियां सीखने में मेहनत की है, माना कि काम धंधा करने वालों से कम मेहनत की है। पढ़ाई-लिखाई करने वालों से कम मेहनत की है। हमने भाषा नहीं सीखी, संस्कार नहीं सीखे, अदब नहीं सीखा। पर गाली तो सीखी हैं न। मेहनत तो की है न। आप कहेंगे मेहनत को बदनाम मत करो। पर हम करेंगे। हम तो हर किसी को बदनाम करेंगे। जरा अमितजी से पूछकर देखो कितनी मेहनत की है और करवाई है। जैसे वे अपनी मेहनत को जाया नहीं होने दे रहे, हम भी अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। हम तो गाली देंगे। उनको नहीं देंगे तो आपको देंगे। मुसलमानों को नहीं तो हिंदुओं को देंगे और अयोध्या फैजाबादवालों को अवश्य ही देंगे। विपक्ष वाले कहते हैं कि प्रधानमंत्री गालियां देते हैं। तो हम क्यों न दें। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे रोज गालियां खाते हैं तो तुम भी खा लो। तो गालीबाजों से यह शिकायत मत करो कि वे गाली दे रहे हैं। वे तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वे तो अपना धर्म निभा रहे हैं। उन्हें कर्त्तव्य पथ से विचलित मत करो, उन्हें धर्म की राह से विचलित मत करो।

कमी तो प्रबंधन की है

दिल्ली में जल संकट

पंकज चतुर्वेदी

इस बार गर्मी तीखी और लंबी चल रही है, ऐसे में पानी की मांग बढ़ना लाजिमी है। बीते आठ वर्षों की तरह दिल्ली की सरकार का जल आपूर्ति में कमी के लिए हरियाणा को कोसना और फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना इस बार भी जारी रहा। इस बार यह तथ्य उभर कर आया कि राजधानी में पानी की उतनी कमी नहीं है, जितनी उसके प्रबंधन की। भारत सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने जब इस बात के दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए कि दिल्ली को मिल रहे पानी की बड़ी मात्रा में बर्बादी हो रही है तो अदालत ने भी इसे गंभीरता से लिया। मेहता ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि दिल्ली को मिलने वाले प्रत्येक 100 लीटर पानी में से केवल 48.65 लीटर पानी ही लोगों तक पहुंच पाता है। इसका 52.35% हिस्सा, रिसाव, टैंकर माफिया और औद्योगिक इकाइयों द्वारा चोरी का शिकार है।

राजधानी दिल्ली में इस बार पूरी गर्मी जल संकट स्थाई रूप से डेरा डाले रहा। सरकारी अनुमान है कि दिल्ली की आबादी तीन करोड़ चालीस लाख के करीब पहुंच गई है और यहां हर दिन पानी की मांग प्रतिदिन 1290 मिलियन गेलन (एमएलडी) है जबकि उपलब्ध पानी महज 900 एमएलडी है। इसमें से लगभग आधे पानी का जरिया यमुना ही है, शेष जल ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा बांध आदि से आता है। दिल्ली के 9 में से 7 जल शोधन संयत्र तभी काम करते हैं जब उन्हें मुनक नहर से यमुना का पानी मिले।

मुनक नहर का निर्माण 2003 और 2012 के बीच हरियाणा सरकार ने किया था। यह करनाल जिले में यमुना का पानी लेकर खूबरू और मंडोरा बैराज से होकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। करनाल के मुनक गांव से दिल्ली के हैदरपुर तक नहर 102 किमी लंबी है और यह दिल्ली में महज 16 किलोमीटर का ही सफर करती है। विदित हो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यमुना जल के बंटवारे के समझौते के ठीक से पालन हेतु गठित ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) के विशेषज्ञों का एक दल पिछले 10 जून को नहर के निरीक्षण पर गया था। इनकी रिपोर्ट है कि हरियाणा से तो पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली तक पहुंचते-पहुंचते उसका बड़ा हिस्सा गुम जा रहा है। जैसे कि हरियाणा ने मूनक नहर में 2,289 क्यूसेक पानी छोड़ा। काकोरी से भी निर्धारित मात्रा 1050 क्यूसेक की तुलना में 1161.084 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। काकोरी वह जगह है, जहां से पानी सीधे दिल्ली पहुंचता है, लेकिन 16 किलोमीटर के रास्ते चल कर बवाना में मूनक नहर को 960.78 क्यूसेक पानी ही पहुंचा। जाहिर है कि लगभग 200 क्यूसेक पानी बीच में ही गायब हो गया। नियमानुसार इस तरह के प्रवाह में पांच फीसद तक जल की क्षति हो सकती है, लेकिन यहां तो 18 प्रतिशत पानी कम हो गया।

आखिर जल प्रबंधन में दिल्ली का प्रशासन किस तरह पीछे है? इसकी बानगी है वजीराबाद जल शोधन संयत्र। वजीराबाद बैराज के पास बने जलाशय से यह पानी लेता है। अब जलाशय की गहराई हुआ करती थी 4.26 मीटर, इसकी गाद को किसी ने साफ करने की सोची नहीं और अब इसमें महज एक मीटर से भी काम 0. 42 मीटर जल-भराव क्षमत रह गई। तभी 134 एमजीडी क्षमता वाला संयत्र आधा पानी भी नहीं निकाल रहा। दिल्ली में पानी का कुप्रबंधन यहीं नहीं रुकता, 40 फीसद पानी जल बोर्ड की पाइप से रिसाव व 18 फीसद चोरी की वजह से उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता। कितना दुखद है कि दिल्ली में जिस पानी को पीने लायक बनाने में भारी धन और तंत्र लगता है उसका 70 फीसद सिंचाई, वाहनों की सफाई, शौचालय जैसे गैर पेयजल कार्यों में होता है, जबकि एसटीपी से शोधन कर निकला पानी नाले में बहा दिया जाता है। ईमानदारी से गैर पेयजल कार्यों के लिए इस पानी का इस्तेमाल हो तो दिल्ली में आठ से दस घंटे जल आपूर्ति संभव है। एक बात समझना होगा कि दिल्ली की आबादी अब तीन करोड़ 40 लाख के करीब पहुंच रही है और इस विशाल जन समुदाय को साल भर पर्याप्त पानी देने के लिए अस्थाई या तदर्थ तरीकों से काम चल नहीं सकता। आज तो दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, लेकिन यह कोई तकनीकी और दूरगामी हल नहीं है। दिल्ली शहर के पास यमुना जैसे सदा नीर नदी का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। इसके अलावा छह सौ से ज्यादा तालाब हैं जो कि बरसात की कम से कम मात्र होने पर भी सारे साल महानगर का गला तर रखने में सक्षम हैं।

यदि दिल्ली में की सीमा में यमुना की सफाई के साथ-साथ गाद निकाल कर पूरी गहराई मिल जाए। इसमें सभी नाले गंदा पानी छोड़ना बंद कर दें तो महज 30 किलोमीटर नदी, जिसकी गहराई दो मीटर हो तो इसमें इतना निर्मल जल साल भर रह सकता है जिससे दिल्ली के हर घर को पर्याप्त जल मिल सकता है। विदित हो नदी का प्रवाह गर्मी में कम रहता है, लेकिन यदि गहराई होगी तो पानी का स्थाई डेरा रहेगा। दिल्ली में यमुना, गंगा और भूजल से 1900 क्यूसेक पानी प्रतिदिन प्रयोग में लाया जाता है। इसका 60 फीसद यानी करीब 1100 क्यूसेक सीवरेज का पानी एकत्र होता है। यदि यह पानी शोधित कर यमुना में डाला जाए तो यमुना निर्मल रहेगी और दिल्ली में पेयजल की किल्लत भी दूर होगी। एक बात और दिल्ली में यमुना का पानी अधिक या खतरे के निशान से ऊपर होने की दशा में सराय काले खां के पास बारापूला, साकेत में खिड़की के पास सात पूला जैसी संरचनाओं को फिर से जीवित कर दिया जाए तो महानगर के कई जलाशय पानीदार हो जाएंगे।

कभी दिल्ली में यमुना के पानी के घटने बढ़ने को नियंत्रित करने वाली नजफगढ़ प्राकृतिक नहर को नाला बना देने और नजफगढ़ झील को पुनर्जीवित आकर दिया जाए तो दिल्ली के पास अपनी क्षमता से दोगुना जल होगा। नजफगढ़ नाला कभी जयपुर के जीतगढ़ से निकल कर अलवर, कोटपुतली, रेवाड़ी व रोहतक होते हुए नजफगढ़ झील व वहां से दिल्ली में यमुना से मिलने वाली साहिबी या रोहिणी नदी हुआ करती थी। यदि इस नाले को फिर नहर में तब्दील कर दें तो दिल्ली को हरियाणा को हर साल कोसना नहीं पड़ेगा। यह केवल पानी की कमी ही नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की मार के चलते चरम गर्मी, सर्दी और बारिश से जूझने में भी सक्षम हैं। और फिर पानी चाहे जितना भी हो, यदि लीकेज और चोरी नहीं रोकी जाए तो यमुना- तालाब लबालब होने के बाद भी दिल्ली जल-कंगाल ही रह जाएगी।

> कभी दिल्ली में यमुना के पानी के घटने बढ़ने को नियंत्रित करने वाली नजफगढ़ प्राकृतिक नहर को नाला बना देने और नजफगढ़ झील को पुनर्जीवित आकर दिया जाए तो दिल्ली के पास अपनी क्षमता से दोगुना जल होगा। नजफगढ़ नाला कभी जयपुर के जीतगढ़ से निकल कर अलवर, कोटपुतली, रेवाड़ी व रोहतक होते हुए नजफगढ़ झील व वहां से दिल्ली में यमुना से मिलने वाली साहिबी या रोहिणी नदी हुआ करती थी

भारत में तांबे की प्रति व्यक्ति खपत 600 ग्राम

- चीन और अन्य देशों की तरह भारत भी तांबे का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए तांबा एक महत्त्वपूर्ण धातु है
- ऊर्जा बदलाव के लिए महत्त्वपूर्ण ौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग अवसंरचना, सौर ोटोवोल्टिक, पवन ऊर्जा और बैटरी सभी में तांबे की जरूरत होती है
- भारत में प्रति व्यक्ति तांबे की खपत लगभग 600 ग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 3.2 किग्रा.है

मीडिया इन्पुट्स

शपथ-ग्रहण पर बुलाए गए, खुशी की बात है। झूलती सरकार सही, आप इतिहास के साक्षी बने। पर कार्ड लहरा कर क्यों इतरा रहे हैं। वहां पहुंच कर पता चला होगा कि आगे कोई मीर भी था। 8000 लोग मौजूद थे। शाहरुख ही जब पीछे बैठे थे, तब हमें क्या कि आप कहां थे। यह अमृतकाल ठेठ आत्ममुग्धता का दौर है।

ओम थानवी, पत्रकार
@omthanvi

स्थिर सरकार से है सीधा संबंध

शेयर बाजार **ऋषभ मिश्रा**

बीता हफ्ता शेयर बाजार के लिए अभूतपूर्व रहा। इस दौरान इसने गिरने और उछलने के दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब बाजार ने इतना तीव्रता से परिवर्तन (शार्प रिएक्ट) किया हो। दरअसल, पिछले एक हफ्ते यानी कि एग्जिट पोल आने के बाद से ही शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली है। एग्जिट पोल आने के अगले कारोबारी दिन (3 जून) को शेयर बाजार में उछाल देखा गया, लेकिन उसके अगले दिन यानी मतगणना के दिन बाजार में हाहाकार मच गया। उस दिन बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 8 फीसद से भी ज्यादा अंकों से नीचे लुढ़क गया। जिस वजह से बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप में 31 लाख करोड़ रुपए की कमी देखी गई। हालांकि उसके अगले तीन दिनों में बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई और 7 जून को तो बीएसई सेंसेक्स अपने सर्वोच्च स्तर पर (आल टाइम हाई) यानी कि 76,693 अंक के आंकड़ों पर पहुंच गया।

शेयर बाजार में इतनी तेजी से (शार्प) उठापटक को सामान्य तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मगर यह कोई अनहोनी भी नहीं है, इस स्तर की या थोड़ी कम-ज्यादा उठा-पटक अथवा उतार-चढ़ाव पहले भी होता आया है। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे ऊपर या नीचे करने वाले बड़े निवेशकों में से अहम हिस्सेदारी संस्थागत निवेशकों की होती है। ये निवेशक बड़े वित्तीय संस्थान पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, म्युचुअल फंड, हेज फंड वगैरह होते हैं। ये देसी और विदेशी दोनों हो सकते हैं। इनके पास कंपनियों की माली स्थिति से लेकर देश के आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य वगैरह को समझने और उसकी थाह लेने के लिए पर्याप्त संसाधन और सक्षम टीम होती है। इसलिए ये ऐसी स्थिति को भांपकर बाजार में अपनी चाल तय करते हैं, और उन्हीं की चालों से बाजार की गति भी तय होती है। अब सवाल यह है कि वे कौन से प्रमुख कारक होते हैं, जिनसे शेयर बाजार अचानक इतना 'रिएक्ट' करता है और निवेशकों की कमाई को एक झटके में ऊपर या नीचे पहुंचा देता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध वहां के सियासी हालात से होता है। अगर देश में सियासी स्थितियां स्थिर होती हैं, तो बाजार को मजबूती मिलती है। खासकर विदेशी निवेशक घरेलू शेयर बाजार में निवेश करने से पहले उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर गौर करते हैं। सियासी हालात प्रतिकूल महसूस होने पर वे बाजार से दूर भागने लगते हैं। उदाहरण के रूप में बीते हफ्ते यानी 3 जून को सेंसेक्स 2507 अंकों यानी 3.55 फीसद की बढ़त पर बंद हुआ। वजह थी एग्जिट पोल में मोदी सरकार की हैट्रिक बनने की संभावना, लेकिन जब अगले ही दिन यानी 4 जून को भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक अस्थिरता की आशंका गहरा गई, और सेंसेक्स 4,389 अंक गिरकर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं: किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बंद नहीं रह सकती। वैश्विक स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ता है। वर्ष 2008 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी मंदी छाई रही, जिसके असर से भारत भी नहीं बच सका था। साल भर में बीएसई सेंसेक्स में कुल मिलाकर 63 फीसद की गिरावट दर्ज हुई थी। यह 2007 के 20,000 प्वाइंट्स से गिरकर 7,700 तक पहुंच गया था। उदाहरण के तौर पर लगातार बढ़ रहे बीएसई सेंसेक्स ने 24 अगस्त 2015 को अचानक से 1,625 अंकों की डुबकी लगा ली। यह गिरावट आज के हिसाब से 3,000 अंकों से भी अधिक की होती। इसकी वजह थी चीनी मुद्रा 'युआन' का अवमूल्यन। इससे चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती की आशंका गहरा गई। जिसने भारतीय बाजार को भी अपनी चपेट में ले लिया।

अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति : वैश्विक स्तर पर होने वाली भू-राजनितिक गतिविधियों का भी सीधा असर शेयर बाजार पर होता है। मौजूदा समय में मध्य पूर्व में चल रहे इस्राइल हमास युद्ध और यूक्रेन रूस सैन्य संघर्ष इसी तरह के भू-राजनीतिक फैक्टर हैं। इस तरह के तनाव ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिसके फलस्वरूप शेयर बाजार पर दबाव बनता है। उदाहरण के रूप में 24 फरवरी 2022 को एक रात पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की खबर आई और इसके अगली ही सुबह भारत के शेयर बाजार पर भी 'नेगेटिव सेंटिमेंट्स' का जबरदस्त हमला हो गया। एक दिन में ही बीएसई सेंसेक्स में 2,702 अंकों की गिरावट आ गई। तेजी में निवेश करना आम निवेशकों के लिए आमतौर पर फायदेमंद नहीं होता है। यदि उस समय निवेश करना भी है तो ऐसे शेयरों से बचना चाहिए जो अपने उच्चतम स्तर के आस-पास हों।

रणनीति **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

जीवन एक निरंतर बहती धारा है, किंतु विडम्बना यह भी है कि इस धारा को रोकने के लिए बीच में अनेक रुकावटें हैं। हां, बाधाएं और विघ्न मनुष्य जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसी से जीवन में संघर्ष चलता रहता है। ये विघ्नरूप शत्रु जब रास्ता रोककर खड़े हो जाएं तो हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, यह ज्ञान भी होना चाहिए। बिना रणनीति के साथ यदि हम संघर्ष में उतरते हैं तो जीत के स्थान पर हार भी हो सकती है। इसीलिए युद्ध से पहले अर्जुन श्रीकृष्ण भगवान से कहते हैं-'हे केशव! दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ ले जाइए। वहां खड़ा होकर मैं देखना चाहता हूं कि कौरव पक्ष के कौन-कौन से योद्धा मेरे सामने लड़ने के लिए आए हैं।' यहां अर्जुन एक उत्कृष्ट योद्धा के साथ एक योग्य रणनीतिकार प्रतीत होते हैं। यदि दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी ताकत और कमजोरियों का पता होना चाहिए। और यह तभी पता लगता है, जब शत्रुसेना का यथार्थ रूप से पर्यवेक्षण हो चुका हो। यहां अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जाकर यह देखना चाहता है कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में लड़ने के लिए उसके पास विरोधी कौरव सेना में किस तरह के हथियार और बख्तरबंद दिग्गज हैं! यह युद्ध जीतने की रणनीति है। एक व्यक्ति ने बाजार से एक तोता खरीदा। वह सज्जन रोज तोते के खाने-पीने का ख्याल रखता था। एक बार उसने सोचा, 'यह तोता तो घर में खुलेआम घूमता है, लेकिन घर के बाहर बिल्ली भी घूमती है। यदि वह घर में आएगी तो तोता अवश्य मारा जाएगा। उसने तोते को एक पाठ पढ़ाया कि 'बिल्ली आए तो भाग जाना', तोते ने दो-तीन बार सुना और पाठ याद कर लिया। एक दिन उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। घर में तोते के अलावा कोई नहीं था। बिल्ली तोते को पिंजरे से बाहर देखकर घर में आ गई। तोता अभी भी रटन कर रहा था -'बिल्ली आए तो भाग जाना।' बिल्ली तोते के पास पहुंच गई। तोता गुनगुनाने में मग्न था। बिल्ली ने झटके से तोते का गला पकड़ लिया। तोते के अंतिम शब्द थे-'बिल्ली आए तो भाग जाना।' मालिक ने तोते को तो शाब्दिक ज्ञान तो दिया था किंतु बिल्ली को कभी सच नहीं बताया था। यहां तोते ने अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा।

रीडर्स मेल

शीघ्र फैसला ले सरकार

अब चूंकि केंद्र में नई सरकार ने शपथ ले लिया है और मंत्रियों ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है, लिहाचा केंद्र की नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आचार संहिता के कारण रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करना होना चाहिए। सबसे पहले किसानों के लिए बीज एवं खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होना चाहिए। बारिश के मौसम को देखते हुए आपदा प्रबंधन के पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि बेमौसम बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकवादी हिंसक वारदातों पर लगाम लगना चाहिए।

ललित महालकरी, इंदौर

भारत उठाए सख्त कदम

पिछले दिनों जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी हमला निहायत ही शर्मनाक और निंदनीय है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है, मोदी ने इसे सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी, लेकिन यह फिर भी यह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू-कश्मीर की बात की जाए तो यह सवाल उठता है कि आखिर आतंकवाद अभी भी यहां समस्या क्यों बना हुआ है? आतंकवाद आज विश्वव्यापी समस्ता बन चुका है, लेकिन भारत को अपने यहाँ आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए खुद ही गंभीर होना पड़ेगा। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलो को रोकने के लिए भारत को सबसे पहले भारत-पाक सीमा पर सुरक्षातंत्र को मजबूत करना चाहिए। लालच में आकर भारत के प्रति जहर उगलने वालों पर भी भारतीय खुफिया एजेंसियों को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ सरकार को वहां जीपीएस सिस्टम, खुफिया एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ाने और वहां सुरक्षा कर्मियों को बुलेटप्रूफ वस्त्र, वाहन भी दिए जाने पर विचार करना चाहिए। पाकिस्तना को आर्थिक रूप से कमजोर करने से भी पाकिस्तान की बर्बादी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अब गठबंधन सरकार

अब तक नरेन्द्र मोदी अपनी मनमर्जी करते रहे हैं। विपक्षी दल हो या उनके सहयोगी अपनी हनक कायम रखी है। इस चुनाव में नजारा बदल गया है। अब मोदी को उन नेताओं से भी सहयोग लेना होगा जो उनके धुर विरोधी हैं। अपनी सत्ता के रहते मोदी ने अनेक कड़वे निर्णय लिए। एक देश एक चुनाव, जातिगत जनगणना जिसमें मुसलमानों, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण मोदी के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। सहयोगी दलों के नेताओं को अपने राज्य में विशेष दर्जा देना। अब अगर सरकार चलानी है तो इनकी बात माननी पड़ेगी। अब तक देख चुके हैं वह अनेक विरोधी नेताओं का वजूद मिटा चुके हैं। अनेक सरकारी संस्थाओं पर उनका कब्जा है। अब लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। अब लोगों ने मजबूत विपक्ष दिया है। देखना बाकी है वह अपना सत्ता पक्ष के आगे कितना विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे या सरकार की जी हुजूरी करेंगे। हम कहेंगे जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है तो अपने विरोधी तेवर बरकरार रखें।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 300
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पीओके : सच का आइना

आप सबने भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, नारे की गूंज तो सुनी ही होगी लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वह पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुका है। मैं यह कह रहा हूं कि भारत 75 वर्षों से कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान आज कहां पर है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वह यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या भविष्य में पाकिस्तान सचमुच विश्व के नक्शे पर बच पाएगा? चुनावों में आप सभी ने पीओके यानि पाक अधिकृत कश्मीर का शोर तो सुना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक समूचे भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें इस देश से बेपनाह मोहब्बत है। उन्हें इस बात की पीड़ा है कि हम पीओके को आज तक पाकिस्तान से वापिस नहीं ले सके। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य कई नेताओं ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए स्पष्ट कहा कि हम उसे लेकर रहेंगे। पीओके का आवाम बार-बार सड़कों पर आता है और अपने अधिकारों की बात करता है। पीओके का आवाम आजाद होकर भारत के साथ मिलने की इच्छा रखता है।

सोशल मीडिया के तौर में पीओके की जनता भारत के कश्मीर का विकास देख रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जिस उत्साह के साथ रिकॉर्ड मतदान किया है, उससे स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आस्था भारत के संविधान में है। पाकिस्तान के सियासतदान हर मंच पर भारत के जम्मू-कश्मीर पर अपना दावा जताते हैं पर दुनिया देख रही है कि उसके कब्जे वाला कश्मीर जल रहा है। पीओके में पिछले महीने आया उबाल बिजली के भारी-भरकम बिलों और आटे के आसमान छूते दामों के कारण आया था। तब पाकिस्तान की सरकार ने पोओके के लोगों को बड़ी मुश्किल से शांत किया था। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। आवाम में लगातार आक्रोश फैल रहा है। उसके पीछे पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा पीओके की जनता पर अत्याचारों और संसाधनों की लूट का लम्बा इतिहास है। मैं यह लेखमाला आज के किशोरों और युवा पीढ़ी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सच्चाई से अवगत कराने के लिए ही लिख रहा हूं। मेरी इच्छा रहती है कि राष्ट्र के लोग तथ्यों को जानें, क्योंकि युवा शक्ति से हमारी बड़ी अपेक्षाएं हैं। मेरे पास पूजनीय दादा रमेश चन्द्र जी और पिता श्री अश्विनी कुमार द्वारा लिखे गए लेखों का विस्तृत संग्रह है। उनका अध्ययन करने के बाद मैं आप को प्रमाणित तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं।

> **चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अन्य कई नेताओं ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए स्पष्ट कहा कि हम उसे लेकर रहेंगे। पीओके का आवाम बार-बार सड़कों पर आता है और अपने अधिकारों की बात करता है। पीओके का आवाम आजाद होकर भारत के साथ मिलने की इच्छा रखता है। सोशल मीडिया के तौर में पीओके की जनता भारत के कश्मीर का विकास देख रही है। लोकसभा चुनावों के दौरान जम्मू-कश्मीर के लोगों ने जिस उत्साह के साथ रिकॉर्ड मतदान किया है, उससे स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आस्था भारत के संविधान में है।**

बात 15 अगस्त, 1947 से ही प्रारम्भ करें। अहिंसा औंधे मुंह जा गिरी। भारत दो टुकड़े हो गया। भारत का बुढ़ापा जीत गया और भारत की जवानी समय से एक दिन पूर्व ही तख्ते पर झूल गई। अंग्रेज गए और भारत को दोफाड़ कर गए। उधर लियाकत अली जिन्ना नए मुल्क का सृजन दिवस 14 अगस्त को मना रहे थे। इधर 14 अगस्त की आधी रात को इसे 'ट्रीस्ट विद डैस्टिनी' कहकर नेहरू भारत देश की जनता से प्रधानमंत्रित्व की बधाइयां ले रहे थे।

पर एक मंजर ऐसा भी था, जिसे केवल सच की कलम से ही बयान किया। लाखों लोग पाकिस्तान से उजड़ कर आ गए। दस लाख से ज्यादा हिन्दू, मुस्लिम और सिख मार दिए गए। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2 लाख से अधिक बच्चे नृशंसता का शिकार हो गए। मानवता कालकवलित हो गई। चिनाव लहूलुहान हो गई। लेकिन इस मुल्क के नेताओं ने सतियों के शवों से भरे हुए वे कुएं नहीं देखे जो हिन्दू और सिख नारियों द्वारा सतीत्व बचाने के लिए भर दिए गए थे।

आज के दिन किसी को यह आज्ञा नहीं थी कि वह उस साबरमती के संत को अमृता द्वारा रचित इन पंक्तियों को सुना दें :-

''इक रोई सी धी पंजाब दी,
तूं लिख-लिख मारे वैंण
अज्ज लखां धीयां रोंदीयां,
तैनूं वारिस शाह नूं कैण।
उठ दरदमंदा दया दरदीया,
चल तक आपणा पंजाब,
अज्ज वेड़े लाशां विछियां,
ते लहू नाल भरी चनाब।''

अगर बापू ने उपरोक्त दृश्य देख लिए होते, तो इतनी सच्चाई उनमें अवश्य थी कि वे 'अहिंसा और कायरता' को फिर से परिभाषित करने को विवश हो जाते। बस यहीं से शुरू होती है वह दर्दनाक कहानी जो आज मैं सुनाना चाह रहा हूं।

उधर पाकिस्तान बना, हरा झंडा लहराया और वहां के नेताओं के हौंसले बुलंद हो गए। जिसे देखो वही स्वयं को तीसमारखां समझने लगा। 'ये आजादी हमने अपनी कुव्वते बाजू से हासिल की है' जिन्ना ने ऐलान कर दिया। नारा-ए-तकबीर-अल्ला हो अकबर। के नारों से पाकिस्तान गूंज उठा। (क्रमश:)

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

कितने घरों के दीपक बुझाए

"जो निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाएं,
और ईद के पाक महीने में मासूमों का खून बहाएं,,
वो सच्चे मुसलमान तो क्या, इंसान भी नहीं बन पाए,
और अपनी नापाक हरकतों से न जाने कितने घरों के दीपक बुझाएं... ।"

गीता पाढा

पांच हजार कश्मीरी पंडित खीरभवानी मेले के लिए रवाना

नगरोटा (जम्मू),(पंजाब केसरी) कश्मीर में वार्षिक खीर भवानी मेले के लिए 5,000 से अधिक लोग कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को यहां से रवाना हुए। इन तीर्थयात्रियों में अधिकतर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह यात्रा चार दिन तक चलेगी। संभागीय आयुक्त (जम्मू) रमेश कुमार, राहत आयुक्त डॉ. अरविंद करवानी और प्रमुख कश्मीरी पंडित नेताओं ने नगरोटा क्षेत्र से तीर्थयात्रा को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। भजन गाते और मंत्रोच्चार करते हुए श्रद्धालु 176 बसों में सवार होकर कश्मीर घाटी में पांच धार्मिक स्थलों के लिए रवाना हुए। राहत आयुक्त डॉ. अरविंद करवानी ने यहां बताया, 'खीरभवानी मेले में भाग लेने के लिए 5,000 से अधिक कश्मीरी पंडित कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं।

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

पंजाब से चिन्ताजनक परिणाम

पंजाब का लोकसभा परिणाम देश और प्रदेश दोनों को चिन्ताजनक छोड़ गया है। जहां यह संतोष की बात है पटियाला से डा. धर्मवीर गांधी और होशियारपुर से डा. राजकुमार छब्बवाल को छोड़ कर जनता ने किसी भी 'फसली बटेर' को दाना नहीं डाला,पर दो चुनाव क्षेत्रों का परिणाम जहां लोगों ने अच्छे बहुमत से रेडिकल पृष्ठभूमि के दो आज़ाद उम्मीदवारों को विजयी बना दिया, से एक वर्ग की दिशा को लेकर चिन्ता पैदा हो रही है। अमृतपाल सिंह जो राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है खडूर साहिब से लगभग दो लाख वोट से विजयी हुआ है। दूसरा कट्टरपंथी उम्मीदवार जो विजयी हुआ है वह इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का पुत्र सरबजीत सिंह खालसा है जो फरीदकोट से 70 हज़ार वोट से जीता है। अमृतपाल सिंह को भारी 4 लाख वोट मिले और सरबजीत सिंह को 3 लाख। इन दोनों को मिले भारी समर्थन से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पंजाब दोबारा उग्रवाद की तरफ़ बढ़ रहा है?

सरबजीत सिंह पहले भी तीन बार चुनाव लड़ चुका है पर असफल रहा था। अब समर्थन क्यों मिला है? माहौल क्यों बदला है? इसी के साथ अगर यह देखा जाए कि अकाली दल का लगातार पतन जारी है और वह मुश्किल से बठिंडा की सीट जीत सके हैं, तो लगता है कि एक उग्र पंथक लहर का यहां फिर आग़ाज़ हो रहा है। क्या इसका कारण है कि अकाली दल के पतन से सिख राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसे उग्रवादी भर रहे हैं? पर यह बात भी आंशिक तौर पर सही लगती है क्योंकि यहां राजनीतिक शून्य नहीं है जो विधानसभा चुनाव में आप की जीत और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले भारी समर्थन से पता चलता है। यह भी दिलचस्प है कि जिस कांग्रेस को ब्लू स्टार के लिए ज़िम्मेवार ठहराया गया उसी को पंजाब की जनता ने सबसे अधिक, सात सीटें, देकर समर्थन दिया है। कांग्रेस को मिले समर्थन से तो प्रतीत होता है कि पंजाब के लोग उस त्रासदी से उभर चुके हैं पर अमृतपाल और सरबजीत को मिला समर्थन तो विपरीत दिशा बताता है। पंजाब दो विपरीत दिशाओं में क्यों चल रहा है?

पहली बात तो यह है कि यहां खालिस्तान का समर्थन नहीं है। यह लहर विदेशी एजेंसियां क़ायम रखे हुए हैं। न ही यहां आतकंवाद ही है जैसे नई सांसद कंगना रनोत ने आरोप लगाया है। उनके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो हुआ वह अत्यंत निन्दनीय है। उत्तेजना कुछ भी हो सुरक्षा कर्मी का काम सुरक्षा देना है हमला करना नहीं पर कंगना का यह कहना कि "पंजाब में आतंकवाद और हिंसा बहुत बढ़ रहें हैं", भी अनुचित है। एक सांसद को ज़िम्मेवारी दिखानी चाहिए और संवेदनशील मामलों पर लापरवाह बयान नहीं देने चाहिए। पंजाब में न हिंसा बढ़ी है और न ही आतंकवाद का मसला है। पर हां,यहां उग्रवाद रहता है। सिख उग्रवाद यहां बार-बार उभरता है और बार बार ठंडा पड़ जाता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल को बहुत श्रेय जाता है कि उन्होंने पंजाब को सही रास्ते पर रखा था। अगर वह परिवारवाद को इतना बढ़ावा न देते और भ्रष्टाचार के इतने आरोप न लगते तो अकाली दल अभी भी महत्वपूर्ण खिलाड़ी होता। इस बार अकाली दल के 10 उम्मीदवार अपनी ज़मानत नहीं बचा सके। लम्बे चले किसान आन्दोलन जिस दौरान 700 के क़रीब किसान मारे गए, ने भी उग्रवाद के लिए उपजाऊ मैदान तैयार कर दिया है। पंजाब और पंजाबियों से निपटने के लिए जो संवेदनशीलता चाहिए वह नज़र नहीं आ रही।

पंजाब का संकट बहुआयामी है। कृषि के संकट का कोई समाधान नज़र नहीं आता। केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद बिल्कुल टूट चुका है। दोनों तरफ़ ज़िद्द है। इस गतिरोध को ख़त्म करने कि लिए नए मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहल करनी चाहिए और किसान संगठनों को भी समझना चाहिए कि केन्द्र सरकार की भी मजबूरियां हैं। बार बार धरने लगा कर और यातायात रोक कर वह पंजाब का अहित कर रहे हैं। उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं रहा जिस कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है और पंजाबी युवक बाहर भाग रहें हैं। पर्यावरण बिगड़ रहा है और पानी का स्तर भयावह तरीक़े से नीचे गिर रहा है। 2015 में हुई बरगाड़ी बेअदबी और बहिबल कलां गोली कांड के मामले अभी तक लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं। बंदी सिखों की रिहाई भी बड़ा मसला बन चुका है जिससे उग्रवादी तत्वों को कहने का मौक़ा मिल जाता है कि पंजाब और विशेष तौर पर सिखों से 'धक्का' हो रहा है। यह भावना अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह जैसे नेता पैदा करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय को साथ जोड़ने का बहुत प्रयास किया है पर सफलता नहीं मिली। एक कारण है कि जिन नेताओं को कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से इम्पोर्ट किया गया वह सब चले हुए कारतूस निकले। किसान आन्दोलन के कारण भाजपा के उम्मीदवारों को गांवों में घुसने नहीं दिया गया। लेकिन असली कारण है कि माईनारिटी अर्थात अल्पसंख्यक भाजपा की नीतियों से घबराते हैं क्योंकि समझा जाता है कि वह बहुसंख्यक शासन क़ायम करना चाहते हैं। यहां भाजपा का वोट विधानसभा चुनाव के 6 प्रतिशत बढ़ कर 18 प्रतिशत हो गया है पर ग्रामीण क्षेत्रों में वॉशआउट ने काम तमाम कर दिया। भाजपा को 23 विधानसभा क्षेत्रों में 8 बढ़त मिली है जबकि कांग्रेस को 37 और आप को 33 पर। अकाली दल को दयनीय 9 पर। अकाली दल अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वह भाजपा से भी नीचे आ गए हैं।

आप सरकार ने निराश किया और इस परिणाम को वेक अप कॉल ही समझना चाहिए। लोग ज़मीन पर जो बदलाव चाहते थे वह उन्हें नहीं मिल रहा। जिसे गवर्नन्स अर्थात् शासन कहा जाता है, में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, मुफ्त आम आदमी मुहल्ला क्लीनिक शुरू कर दिए, 43000 सरकारी नौकरियां देने का दावा किया है पर लोग संतुष्ट नहीं। लम्बे किसान आन्दोलन का भी कुछ असर पड़ा है।

महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वायदा भी पूरा नहीं हुआ। न ही ड्रग्स के मामले में कुछ ठोस ही किया गया। आप के पंजाब यूनिट का यह दुर्भाग्य है कि उन्हें अब दिल्ली का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। पार्टी से भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा छिन गया है। आप के प्रति लोगों के असंतोष का कांग्रेस फ़ायदा उठा गई है। कांग्रेस का प्रदर्शन उस वक्त अच्छा रहा जब कई बड़े नेता दलबदल कर गए हैं। परनीत कौर को पटियाला में तीसरे नम्बर पर रख कर लोगों ने बता दिया कि दलबदलुओं की कैसी इज्जत है। कांग्रेस के प्रादेशिक नेताओं ने आप से दूरी बनाकर खुद को शासन विरोधी भावना से बचा लिया। अकाली दल के पतन के बाद कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई है। इसका फ़ायदा होगा।

अकाली दल की दुर्गत का नुक़सान हो रहा है क्योंकि उनकी जगह जिन्हें गर्म ख्याली कहा जाता है, ले रहे हैं। खडूर साहिब और फ़रीदकोट दोनों अकाली गढ़ रहे हैं। इससे क्या नतीजा निकाला जाए? कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसे ख़तरे की घंटी नहीं समझना चाहिए। प्रमुख अर्थशास्त्री डा. लखविनदर सिंह का कहना है कि अमृतपाल और सरबजीत सिंह की जीत को "विकास से सम्बन्धित मसला समझना चाहिए न कि अलगाववादी समस्या"। उनका कहना है कि पंजाब में अर्थिक संकट है। तीन दशक पहले हरित क्रान्ति का प्रभाव ख़त्म हो गया था और तब से पंजाब का लगातार पतन हो रहा है। उनका कहना है कि "लोग बदलाव के लिए बेताब हैं। इसलिए उन्होंने नए परीक्षण के लिए वोट दिया है"। यह भी कहा जा रहा है कि पंजाबी भावना में बह जाते हैं इसलिए इसे किसी विचारधारा की जीत नहीं समझना चाहिए। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी नौ कट्टरपंथी चुनाव जीते थे जिनमें सरबजीत सिंह की माता बिमल कौर भी शामिल थी, फिर सब कुछ सामान्य हो गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि इन दोनों की जीत से उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों ने बैलेट बाक्स का सहारा लिया है और सदस्य बनते वक्त संविधान की शपथ लेंगे। और इस बार सिमरनजीत सिंह मान हार गए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इन दो की जीत और कुछ नहीं पंजाब की हालत के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति है।

मैं इतना आशावान नहीं हूं। पंजाब में हालात बहुत जल्द उल्टा करवट ले लेते हैं। यह दोनों नए सांसद समय-समय पर खालिस्तान का समर्थन करते रहे हैं। आर्थिक परेशानी, बेरोज़गारी, खेती का संकट कहां नहीं है? बिहार, उड़ीसा, यूपी, मध्यप्रदेश जैसे प्रदेश जो पंजाब से बहुत पिछड़े हैं वहां विरोध की ऐसी उग्रवादी आवाज़ें क्यों नहीं उठती? इन दोनों की जीत से पंजाब से बाहर बहुत ग़लत संदेश गया है। निवेश पर प्रभाव पड़ेगा।

इस बहाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को मिल कर कदम उठाने चाहिए। प्रदेश सरकार को अपना शासन सही करना चाहिए। ड्रग्स के मामले पर और सख्त कदम उठाने चाहिए। युवाओं में जो बेचैनी और असंतोष है उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। और, जैसे मैं दो सप्ताह पहले लिख कर हटा हूं, केन्द्र सरकार को पंजाब की सुध लेनी चाहिए। केन्द्र सरकार मस्त नहीं बैठ सकती।

पंजाब के प्रति बेरुख़ी की नीति त्यागनी होगी नहीं तो आगे चल कर बहुत बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है। दो उग्रवादियों, जो खालिस्तान का समर्थन कर चुके हैं, को विजयी बना कर चेतावनी भेज दी गई है। पंजाब से बात करने का समय अब है।

> **अमृतपाल सिंह जो राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है खडूर साहिब से लगभग दो लाख वोट से विजयी हुआ है। दूसरा कट्टरपंथी उम्मीदवार जो विजयी हुआ है वह इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का पुत्र सरबजीत सिंह खालसा है जो फरीदकोट से 70 हज़ार वोट से जीता है। अमृतपाल सिंह को भारी 4 लाख वोट मिले और सरबजीत सिंह को 3 लाख। इन दोनों को मिले भारी समर्थन से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पंजाब दोबारा उग्रवाद की तरफ़ बढ़ रहा है?**

शहीदी पर्व पर छबील का क्या है इतिहास

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

सिख पंथ में शहादतों का दौर पांचवें गुरु अर्जुन देव जी से शुरू होता है जिन्हें समय के मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अनेक तरह के कष्ट दिए गए। उबलते हुए गर्म पानी में उन्हें बिठाया गया, वहां से निकालकर गर्म तवे पर बिठाकर ऊपर से गर्म रेत गुरु जी के सिर पर डाली गई पर गुरु जी के मुख पर कोई शिकन नहीं आई बल्कि उन्होंने चुपचाप सारी यातनाओं को अकाल पुरख का हुकम समझकर माना। गुरु जी ने उस समय कहा था ''तेरा कीया मीठा लागै,

हर नाम पदार्थ नानक मांगे''। इतिहास बतलाता है बादशाह अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना तो उसने केवल इस्लाम की ही बात की। वह कट्टरपंथ में अधिक विश्वास रखता था।

जहांगीर का पुत्र अमीर खुसरो अपने पिता के विचारों से सहमत नहीं था और बागी होकर घर छोड़ने के पश्चात जब गुरु दरबार में पहुंचा तो गुरु जी ने उसे शरण दी। यह गुरु घर की परंपरा है कि जो भी गुरुघर आये उसे पनाह अवश्य दी जाती है पर यह बात जहांगीर को रास नहीं आई और उसने गुरु अर्जुन देव जी को बुलाकर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने का आदेश जारी कर स्वयं कश्मीर रवाना हो गया। जहांगीर के आदेश पर उसके सेनापति चंदू ने गुरु जी को अपनी हवेली पर कैद करके उन्हें यातनाएं देनी आरंभ कर दीं। दूसरी ओर चंदू की पत्नी, उसकी पुत्रवधू और साईं मियांमीर फकीर गुरु जी को यातनाएं देने के पक्ष में नहीं थे उन्होंने इसका पुरज़ोर विरोध भी किया पर चंदू ने किसी की एक ना सुनी। चंदू की पत्नी और पुत्रवधू गुरु जी से मिलने जेल में पहुंची और ठण्डे मीठे जल का गिलास गुरु जी को दिया तो गुरु जी ने चंदू के घर का पानी भी पीने से मना कर दिया पर एक वरदान उसे दिया कि समय आने पर संगत मीठा जल पिया करेगी। गुरु जी ने स्वंय इससे पहले प्लेग फैलने पर ठंडे मीठे जल की छबीलें संगत के लिए लगा दी थीं इसलिए हर वर्ष जब भी गुरु जी का शहीदी पर्व आता है तो संगतों द्वारा खासकर स्त्री सतसंग जत्थों के द्वारा 2 माह पूर्व से ही सुखमनी साहिब की बाणी के पाठ की लडी़ चलाई जाती है और शहीदी दिवस पर ठण्डे मीठे जल की छबील लगाई जाती है। गर्मी के मौसम में छबील लगाकर मानवता को ठण्डा जल पिलाना पुण्य का कार्य है मगर सभी लोग एक ही दिन छबील लगाने के बजाए अगर गर्मी के पूरे मौसम में अलग-अलग दिन छबील लगाएं तो बेहतर होगा। अब तो शहीदी पर्व पर छबील के साथ तरह-तरह के पकवानों के लंगर भी लगाने लगे हैं। एक एक ऐरिया में अनेकों स्थानों पर लंगर व छबील लगाई जाती है जो कि पूरी तरह से सिख परम्परा के विपरीत जाकर पैसे की बर्बादी है इससे सिख समाज को बचना चाहिए।

ऑपरेशन ब्लू स्टार देश के इतिहास पर काला धब्बा

सिख इतिहास का वह काला अध्याय जिसे आपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। भारतीय फौज ने दरबार साहिब पर टैंकों तोपों से हमला कर गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप को भी गोलियों से छलनी किया। पवित्र सरोवर बेगुनाहों के खून से भर गया। सूत्र इस बात की गवाही भरते हैं कि दरबार साहिब पर हमला उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोची समझी साजिश थी। इस आपरेशन को अंजाम देने के लिए इन्दिरा गांधी ने उस ब्रिटिश हकूमत की मदद ली जिसने सालों भारत को अपना गुलाम बनाकर रखा। आपरेशन से कुछ दिन पूर्व ब्रिटिश अधिकारी दरबार साहिब परिसर में रेकी करते भी पाए गये थे। अगर सरकार की मंशा केवल जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथियों को पकड़ने तक सीमित होती तो वह सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्हें फौज की एक-दो टुकड़ियों की मदद से ही बाहर निकाला जा सकता था उसके लिए सैंकड़ों बेकसूर सिखों और भारतीय फौज के जाबांज़ सिपाहियों का खून बहाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एजेंसियों के द्वारा सिखों को बदनाम करने हेतु तरह-तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे थे। सरकार की नियत अगर सही होती तो आम संगत को पहले ही दरबार साहिब जाने से रोका जा सकता था पर इसके विपरीत प्रशासन ने कर्फ्यू में कुछ समय की राहत देकर श्रद्धालुओं को पहले अंदर जाने दिया और उसके बाद घेराबंदी कर गोलीबारी शुरु कर दी। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था अगर वह भी होता तो शायद इसे रोकने में मदद मिल जाती। मगर अब कांग्रेस के बड़े नेता समझने लगे हैं और अपनी भूल का पछतावा करने ही बीते दिनों राहुल गांधी स्वयं श्री दरबार साहिब नतमस्तक होकर आए हैं।

रवनीत बिट्टू हार कर भी जीत गए

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू जो कि लम्बे समय तक कांग्रेस के सांसद रहे और इस बार चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने भी उन पर दाव खेलते हुए लुधियाना से टिकट दे दिया। जनता ने भले उन्हें जीत ना दी हो पर भाजपा ने पंजाब में 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए रवनीत सिंह बिट्टू को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल कर उन्हें फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जो कभी हरसिमरत कौर बादल संभाला करती थी। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भाजपा की सरकार बनने पर अमृतसर से

भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े तरनजीत सिंह सन्धु जो कि तेजा सिंह समुन्द्री के परिवार से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें मंत्रिमण्डल में स्थान दिया जायेगा क्योंकि पिछली बार भी अमृतसर से चुनाव हारने के बावजूद हरदीप सिंह पुरी को मंत्री बनाया गया था। मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गृहमंत्री अमितशाह लुधियाना की जनता से वायदा करके आए थे कि आप रवनीत सिंह बिट्टू को जितवाकर भेजिए उसे बड़ा आदमी हम बनाएंगे। दूसरा शायद इसलिए भी भाजपा ने ऐसा दाव खेला है क्योंकि रवनीत बिट्टू की किसानों में भी अच्छी पकड़ है। वह किसानों के संघर्ष में निरन्तर उनके साथ धरनों पर बैठते रहे हैं।

इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में वह सरकार और किसानों के बीच की कड़ी बनकर किसानी समस्याओं का हल करवाने में अहम रोल अदा करेंगे। वहीं जिस प्रकार अकाली दल से अलग होकर भाजपा ने अच्छी पकड़ पंजाब में बनाई है बिट्टू के सहारे 2027 विधान सभा चुनावों से पहले इसे और मजबूत किया जा सकता है।

सिख सुरक्षाकर्मियों को संयम रखने की आवश्यकता

देश की आजादी से लेकर आज तक सिख फौजी देश की रक्षा करते आए हैं और करते रहेंगे मगर उन्हें अपनी ड्यूटी के समय संयम बरतने की आवश्यकता है। बीते दिनों चण्डीगढ़ के मौहाली हवाई अड्डे पर जिस तरह से सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक सांसद को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई उसके बाद से देश भर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जिसमें ज्यादातर लोगों के द्वारा सांसद कंगना रनौत को ही दोषी माना जा रहा है। इस घटना के बाद कंगना ने अपनी टिप्पणी में समूचे पंजाब में उग्रवाद के बढ़ने की बात कही क्योंकि थप्पड़ मारने वाली सुरक्षा अधिकारी किसानी परिवार से सम्बन्धित थी और दूसरा सिख थी। ऐसा शायद पहली बार नहीं हुआ है इससे पहले भी कंगना रनौत के द्वारा कई तरह की अभद्र टिप्पणियां पंजाब के किसानों के खिलाफ की जा चुकी हैं। यहां गलती सुरक्षा अधिकारी कुलविन्दर कौर की भी है, माना जा सकता है कि उसके मन में कंगना रनौत की अभद्र टिप्पणियों के चलते उसके प्रति गुस्सा था मगर ड्यूटी करते समय उसका फर्ज बनता था कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों की हिफाजत करे पर उसने तो इसके विपरीत जाकर स्वयं ही हिंसा का रुख अख्तियार कर लिया। ऐसा करके उसके मन को भले ही शान्ति मिल गई हो मगर जहां एक ओर उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया वहीं सुरक्षा एजेन्सियां भी अब सिख और किसान परिवारों से सम्बिन्धित व्यक्तियों को कहीं ना कहीं नागरिकों यां फिर विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी देने में संकोच कर सकती हैं। हालांकि कुलविन्दर कौर का पिछला रिकार्ड बताता है कि वह पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। और ऐसा नहीं है कि कंगना इससे पहले कभी मोहाली हवाई अड्डे पर ना आई हो, अगर उसने जानबूझ कर कंगना से अपनी माताओं पर की गई टिप्पणी का बदला लेना होता तो वह पहले भी ले सकती थी फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ होगा उस समय जब उसने एक दम से थप्पड़ की घटना को अन्जाम दिया। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।

गैंगस्टर पुजारी ने अदालत परिसर में पाक समर्थित नारे लगाए, हुई मारपीट

बेलगावी, (पंजाब केसरी): जेल में बंद गैंगस्टर जयेश पुजारी ने अदालत परिसर में कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। यह घटना तब हुई जब गैंगस्टर को उसके खिलाफ लंबित एक मामले की सुनवाई के सिलसिले में अदालत में पेश होने के लिए लाया गया था। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि नारे लगाने के बाद वहां एकत्र हुए लोगों और वकीलों ने कथित तौर पर उसके साथ धक्का मुक्की की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमारे पास अभी इस बात का कोई निर्णायक जवाब नहीं है कि उसने यह नारे क्यों लगाए। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर जयेश पुजारी के खिलाफ 2018 में दर्ज एक मामले के संबंध में बुधवार को उसकी सुनवाई होनी थी और इसलिए उसे हिंडालगा स्थित केंद्रीय कारागार से अदालत लाया गया, जहां वह बंद है। पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि तत्कालीन एडीजीपी आलोक कुमार को कथित तौर पर धमकी देने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर पुजारी दोहरे हत्याकांड में भी दोषी है। उन्होंने कहा कि बुधवार को जब उसे पेशी के लिए अदालत में ले जाया जा रहा था, तभी उसने परिसर के अंदर 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे दबोचा और थाने ले आए। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने पर उस पर हमला किया गया, अधिकारी ने कहा, हम जांच कर रहे हैं, हमें अभी पता लगाना है कि क्या हुआ था। फुटेज में दिखाया गया है कि उस पर कथित रूप से हमला किया गया था, लेकिन क्या वास्तव में उस पर हमला किया गया था या नहीं, इसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। चोट का कोई निशान साफ साफ नहीं दिख रहा है। आज की घटना के संबंध में गैंगस्टर पुजारी के खिलाफ बेलगावी शहर के बाजार पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) और धारा 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

दो नई सरकारें

एन चंद्रबाबू नायडू ने आज चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए दौर की शुरुआत की, वहीं ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर एक नया इतिहास लिख दिया है। आंध्र प्रदेश में जहां तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में भाजपा की सहयोगी भूमिका से गठबंधन सरकार बनी है, तो वहीं ओडिशा में भाजपा ने अकेले दम पर सरकार बनाई है। चंद्रबाबू नायडू भारत में सूचना-प्रौद्योगिकी के नाम पर पहचान रखने वाले नेता हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने हैदराबाद को 'आईटी हब' के रूप में बदल दिया, अब जब वह फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तब उन्हें आईटी क्षेत्र में एक नई क्रांति के लिए काम करना चाहिए। भारत में, वह भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में आईटी के क्षेत्र में ज्यादा निवेश, नवाचार व सरकारी स्तर पर ज्यादा सहूलियत की जरूरत है। चंद्रबाबू को एक नया आंध्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। अमरावती में राजधानी बनाने की योजना पर वह बेशक काम करें, पर उन्हें रोजगार और प्रदेश के बुनियादी विकास के लिए ज्यादा सोचना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में संभावना के अनुरूप ही तेदेपा के 21 विधायकों, जन सेना के तीन विधायको और भाजपा के एक विधायक को शपथ दिलाई गई है। खास यह भी है कि आंध्र में इस बार पहली बार चुनाव जीतने वाले आठ विधायकों को मंत्री बनाया गया है। पहली बार चुनाव जीते लोकप्रिय अभिनेता पवन कल्याण ने भी सहर्ष मंत्री पद स्वीकार किया है, जिससे कला क्षेत्र में भी हलचल है। वैसे चंद्रबाबू नायडू भी महान अभिनेता एनटी रामाराव की विरासत ही संभाल रहे हैं। चंदबाबू ने कसम खाई है कि वह राज्य में केवल एक राजधानी बनाएंगे, तो उन्हें ध्यान रखना होगा कि भ्रष्टाचार के दाग न लगें। नई राजधानी का निर्माण एक बड़ी योजना है, उसे ईमानदार हाथों से पूरा होना चाहिए। चंद्रबाबू के लिए एक बड़ी चुनौती अपने किए वादे को पूरा करना है। ज्यादातर विश्लेषक यही मानते हैं कि पिछली बार भी वह अपने वादे न निभाने की वजह से ही हारे थे। दरअसल, दक्षिण में भांति-भांति की मुफ्त योजनाएं घोषित होती हैं, जिनको पूरा करना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं होता। जनता ने चंद्रबाबू की राजनीति पर भरोसा जताया है और इस भरोसे का कायम रखना नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है।

देश के अग्रणी राज्यों में शामिल आंध्र प्रदेश की प्रगति में तेजी लाने और अपेक्षाकृत पिछड़े राज्य ओडिशा का कायाकल्प करने का दायित्व अब नए कंधों पर आ गया है।

उधर, ओडिशा के भी कायाकल्प का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। नवीन पटनायक के समय यह राज्य लगभग ठहर गया था, हर तरह के संसाधनों के बावजूद ओडिशा उतना आगे नहीं बढ़ पाया, जितना उसके कुछ अन्य पड़ोसी राज्य बढ़ गए। छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया, बंगाल भी ठीक स्थिति में है, बिहार की जीडीपी भी तेजी से बढ़ रही है, मगर ओडिशा का हाल बुरा था, तो लोगों ने लगभग ढाई दशक बाद नवीन पटनायक को किनारे कर दिया। अब बागडोर भाजपा के हाथों में है, तो इसका सीधा अर्थ है कि ओडिशा के लोग तेज तरक्की चाहते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। अगर केंद्र सरकार का पूरा साथ मिला, तो ओडिशा वाकई बड़ी तेजी से देश की मुख्यधारा में आ सकता है। भाजपा में ओडिशा को लेकर उत्सव का माहौल है, पार्टी में जगन्नाथ शब्द इन दिनों बहुत प्रिय हो गया है। पार्टी के नेता अगर मानते हैं कि उन्हें भगवान जगन्नाथ की भूमि की सेवा का अवसर मिला है, तो यह अवसर हाथ से जाना नहीं चाहिए।

जम्मू में आतंकी चुनौती कितनी गंभीर

यहां स्कैन करें

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

ताजा आतंकी हमले घाटी नहीं, बल्कि जम्मू के उन इलाकों में हुए हैं, जहां कुछ वर्ष पहले तक माना जाता था कि आतंकवाद का करीब-करीब सफाया कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में गुजरे तीन दिनों में तीन आतंकी घटनाओं के गहरे निहितार्थ हैं। यह स्थिति तब दिख रही है, जब हालिया आम चुनाव में यहां के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। जम्मू-कश्मीर के पांचों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 58 फीसदी मत पड़े हैं, जो लोकतंत्र में स्थानीय लोगों के बढ़ते विश्वास का संकेत माना गया था। जाहिर है, सवाल यही है कि ऐसे हमले करके आतंकी अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उनकी यह कोई नई रणनीति है?

दरअसल, ताजा हमले कश्मीर घाटी में नहीं हुए हैं, बल्कि जम्मू के उन इलाकों में हुए हैं, जहां कुछ वर्ष पहले तक माना जाता था कि आतंकवाद का करीब-करीब सफाया कर दिया गया है। यहां बीते डेढ़-दो दशकों में कोई बड़ी आतंकी वारदात नहीं हुई थी, पर पिछले तीन-चार साल में 'एरिया ऑफ ऑपरेशन' नजर आने लगा था, यानी आतंकियों की मौजूदगी दिखने लगी थी। असल में, आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई गुब्बारे सरीखा नतीजा देती है, यानी एक जगह जब आप उसका दमन करते हैं, तो दूसरी तरफ से उसका उभार होने लगता है। कश्मीर घाटी के अंदर भी आतंकियों ने पहले श्रीनगर, फिर उत्तरी कश्मीर और बाद में दक्षिणी हिस्से में अपना ठिकाना बना लिया था। मगर धीरे-धीरे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके पर अपना दबदबा बना लिया, तो फिर जम्मू में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगीं, खासतौर से राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में। लिहाजा, सुरक्षा बलों ने जम्मू में भी अपना सुरक्षा घेरा फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए आतंकी अपनी मंशा में कुछ हद तक सफल हो गए।

ताजा हमलों में दहशतगर्द कहीं अधिक दक्ष दिख रहे हैं। घाटी में जब सुरक्षा बल असरंदाज हो गए थे, तो वहां होने वाली छिटपुट हिंसा अमूमन अकुशल आतंकी किया करते थे, लेकिन हाल के वर्षों में दक्ष आतंकियों द्वारा कार्रवाई किए जाने के मामले बढ़े हैं। उनके पास हथियार भी पहले से कहीं बेहतर हैं। यहां तक कि वे पहाड़ों व जंगलों का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं। जाहिर है, यह प्रशिक्षण उनको पड़ोसी मुल्क में मिला होगा। लगता यही है कि पाकिस्तान के अंदर घुसने का कोई अनधिकृत रास्ता है, जिसका इस्तेमाल ये सुरक्षा बलों से बचने के लिए करते हैं। एक प्रवृत्ति और दिख रही है। किसी बड़े समूह में नहीं, बल्कि एक-दो की संख्या में आतंकी अपने मनसूबे को अंजाम दे रहे हैं। मुमकिन है, इसमें एक स्थानीय आतंकी हो और दूसरा पड़ोसी देश से प्रशिक्षित दहशतगर्द। ऐसे में, अब इस इलाके में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की दरकार है, हालांकि यह कोई आसान काम भी नहीं।

सवाल यह भी है कि आखिर ये घटनाएं इस समय क्यों हो रही हैं? निस्संदेह, साल 2019 में जम्मू-कश्मीर को लेकर संविधान में किए गए सुधार के बाद यहां की स्थिति काफी बेहतर हुई है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी कायम हैं। निस्संदेह, यहां आतंकवाद से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लगाई गई है, प्रशासन में मौजूद अलगाववादी विचारधारा के लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए हैं और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है, पर विभाजनकारी सोच अब भी कुछ हद तक समाज में बनी हुई है। यह मानसिकता इसलिए खत्म नहीं हो सकी है, क्योंकि जरूरी राजनीतिक विकल्प देने में हम नाकाम रहे हैं। इस गलती को जल्द सुधारना उचित होगा।

यहां आम चुनाव में लोगों ने जमकर भागीदारी निभाई है और मुख्यधारा की पार्टियों पर भरोसा किया है। घाटी की दो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो जम्मू की दोनों सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। मगर बारामूला में अब्दुल राशिद शेख बतौर निर्दलीय उमर अब्दुल्ला जैसे नेता को हराने में सफल हो गए। आतंकियों को धन मुहैया कराने के आरोप में जेल में बंद राशिद की इस जीत से मुमकिन है कि दहशतगर्दों को प्रोत्साहन मिला हो। आतंकी घटनाएं बढ़ाकर वे अपने इरादे जाहिर कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी नजर में यह जीत समाज के एक तबके में उनकी स्वीकार्यता का प्रतीक हो सकती है। वैसे, इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी बदहाल माली हालत जगजाहिर है, इसलिए वह नई दिल्ली को यह संदेश देना चाह रहा होगा कि कश्मीर में अब भी उसका परोक्ष दखल कायम है।

बहरहाल, आतंकियों ने ऐसे समय में मोर्चा खोला है, जब भारत में चुनाव खत्म हुए हैं और सहयोगी दलों पर निर्भर सरकार सत्ता में है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ऐसा करके न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को चुनौती दी गई है, बल्कि इस संभावना को भी खत्म करने की कोशिश की गई है कि आम चुनाव निपटने के बाद भारत और पाकिस्तान बातचीत की मेज पर बैठ सकते हैं।

वैसे, अगले तीन-चार महीनों में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद इसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ऐसे में, कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो वहां शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराना। आशंका यह भी है कि राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति में यदि पुराने राजनेता सत्ता में लौटते हैं, तो उनका रवैया कैसा होगा? क्या वे फिर एक हाथ अलगाववादियों के कंधे पर रखेंगे और दूसरे हाथ से उनको हल्की थपकी देंगे? कौन इसकी गारंटी लेगा कि जम्मू-कश्मीर के हालात पूर्ववत नहीं हो जाएंगे? चूंकि अब तक यहां केंद्र का नियंत्रण रहा है, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य सरकार के पास तमाम अधिकार आ जाएंगे, लिहाजा अलगाववादी सोच से कैसे पार पाया जा सकेगा? लोकसभा चुनाव की तरह अगर अलगाववादी राज्य चुनाव में खड़े होते हैं व ठीक-ठाक संख्या में विधानसभा में पहुंच जाते हैं और सरकार के गठन में महत्वपूर्ण किरदार निभाने लगते हैं, तब इस प्रदेश की राजनीतिक बयार क्या रुख लेगी?

आशंकाएं कई हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि यहां के सियासी और सामाजिक हालात काबू में रहेंगे। हां, राजनीतिक विकल्प अगर जल्दी तैयार नहीं किया गया, तो तरक्की की ओर कदम बढ़ाता जम्मू-कश्मीर फिर से पिछड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में राशिद शेख की जीत चेतावनी जैसी है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला को दो लाख से भी अधिक मतों से तब हराया है, जब यहां के कई इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का खासा प्रभाव माना जाता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सुविधा की सियासत में सिर्फ एक हथियार वोटिंग मशीन

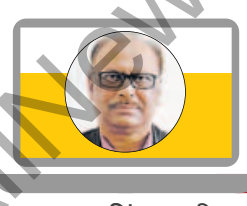

यहां स्कैन करें

राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

नव-निर्वाचित भाजपा सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईवीएम पर टिप्पणी थी, तो विपक्ष पर कटाक्ष, पर मतदान प्रक्रिया पर हमारी राजनीति को भी वह बेनकाब कर गई। मोदी ने कहा कि 4 जून को जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, तब उन्होंने किसी से पूछा कि ईवीएम जिंदा है या मर गई? मोदी का कटाक्ष विपक्ष द्वारा एक बार फिर चुनाव के वक्त ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में था। वीवीपैट के 100 प्रतिशत मिलान या बैलेट पेपर से मतदान की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष लगातार ईवीएम पर आशंकाएं जताता रहा। आरोप था कि संदेहास्पद ईवीएम व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता पक्ष चुनाव जीतने पर आमादा है, पर परिणामों के बाद इस मुद्दे पर मौन पसर गया। बेशक, चुनाव प्रणाली को संदेह से परे होना चाहिए, मगर उस पर बिना ठोस आधार के सवाल भी नहीं उठाए जाने चाहिए। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की साख पूरी दुनिया में है। उस पर देश में ही सवाल उठना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुखद तस्वीर पेश नहीं करता।

चुनाव प्रणाली को संदेह से परे होना चाहिए, मगर उस पर बिना आधार के सवाल भी नहीं उठाए जाने चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया की काफी साख है।

वैसे, विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी ईवीएम पर संदेह का शोर मचाने में पीछे नहीं रही। साल 2009 में भाजपा के नेता जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए पुस्तक लिखी थी। उसकी भूमिका लालकृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, जो तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मामला अदालत तक गया था। 2014 में भाजपा केंद्र की सत्ता में आ गई, तो उसके लिए ईवीएम पवित्र गाय-सी हो गई और विपक्ष में पहुंच गए दलों को उसमें खामियां नजर आने लगीं। मार्च, 2017 में जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, तो 13 दलों ने परिणामों पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग से शिकायत भी की, पर 2018 के अंत में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिल गई, तो ईवीएम पर विपक्ष मौन हो गया। पिछले साल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार पर ईवीएम पर उंगली उठाई गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जीत पर ईवीएम निर्दोष रही।

कुछ ही दिनों बाद दिसंबर में फिर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' लोकसभा चुनाव में वीवीपैट के 100 प्रतिशत मिलान की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसे खारिज करते हुए डेटा सुरक्षा संबंधी कुछ जरूरी निर्देश चुनाव आयोग को दिए गए। मामला चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास से जुड़ा है, इसलिए उसे और अधिक पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने के मुद्दे पर शीर्ष अदालत में सुनवाई आगे भी होगी, मगर उसकी इस नसीहत पर चुनाव आयोग व राजनीतिक दलों को गौर करना चाहिए कि संदेह जताने से जनता के मन में संशय पैदा होता है, जो अच्छा नहीं है। जब छेड़छाड़ के संदेह को साबित करने के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था, तब कोई दल नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने मतपत्रों से चुनावों का दौर देखा है, उन्हें मतदान केंद्रों पर कब्जे और मतपत्रों की लूट की डरावनी स्मृतियां होंगी, इसलिए नई प्रौद्योगिकी से मुंह मोड़कर उस युग में वापसी की मांग तर्कसंगत नहीं।

यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहां ईवीएम अचानक नहीं आ गई। जांच-परख के बाद चरणबद्ध ढंग से अपनाया गया है। देश में ईवीएम का विधिवत इस्तेमाल पहली बार 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे देश में इससे मतदान कराया गया और जीत सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की हुई। इस बीच मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट समेत कई सुधार भी किए गए हैं। याद रहे कि 2019 के चुनाव में आंध्र प्रदेश के मईदुकुर में ईवीएम और वीपीपैट की गिनती में 14 वोटों का अंतर पाया गया था, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की गिनती से पहले के बजाय बाद में गिने गए बैलेट पेपर हार-जीत के अंतर से ज्यादा रहे। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को संदेह से परे रखने के लिए जरूरी सुधार जारी रहने चाहिए। यह जिम्मेदारी सांविधानिक संस्था चुनाव आयोग की ज्यादा है, जिसकी साख पर इतने सवाल पहले कभी नहीं उठे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

हमें जो शिक्षा चाहिए

महान से महान ज्ञान और बड़ी से बड़ी संपदा जो किसी मनुष्य के पास हो सकती है, वह भारत को विरासत में मिली है; उसके पास तो वह है, जिसके लिए मानव जाति प्रतीक्षा कर रही है।... ऐसी संपूर्ण आत्मा, जो अतीत के उत्तराधिकार से, वर्तमान के विस्तृत होते लाभों से और भविष्य की विशाल संभावनाओं से संपन्न हो, केवल एक राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था से ही आ सकती है। वह व्यवस्था वर्तमान विश्वविद्यालयों के तंत्र के किसी विस्तार अथवा नकल से नहीं आ सकती, जिसके सिद्धांत बुनियादी रूप से मिथ्या हैं, प्रणालियां भ्रष्ट और मशीन की तरह हैं। उनकी परंपरा निष्क्रिय और नेमी है, और आत्मा संकीर्ण व दृष्टिहीन। उसे केवल एक नई चेतना और एक ऐसी नई संस्था ही सृजित कर सकती है, जिसका जन्म राष्ट्र के हृदय से हुआ हो और जो पुनरुज्जीवन के प्रकाश और आशा से भरपूर हो।...

नई शिक्षा ऐसी जीवन वृत्तियों को खोल देगी, जो एक साथ ही सम्मान और संपन्नता, प्रतिष्ठा और धन-वैभव के साधन होंगी तथा देश की सेवा के मार्ग भी। क्योंकि जो लोग उसकी संस्थाओं से हर प्रकार से लैस होकर बाहर निकलेंगे, वे ऐसे लोग होंगे, जो देश के आर्थिक जीवन और प्रयास को प्रोत्साहन देंगे। इसके बिना हमारा देश संसार के दबाव में जीवित नहीं रह सकता, अपनी उचित स्थिति प्राप्त करना तो दूर रहा। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ व राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही हैं और एक ही दिशा की मांग करते हैं।

व्यक्तिगत रूप से सदैव लीक पीटने के आदी होने के कारण हम सब एक महान और प्रभावकारी मार्ग की अपेक्षा किसी सुरक्षित व नियत किए हुए रास्ते को पसंद करते हैं, उसी पर चलना चाहते हैं, चाहे वह रास्ता हमें कहीं न पहुंचाए और इस तरह स्वयं अपना ही हित नहीं देख पाते, क्योंकि यह प्रवृत्ति अपने को एक नए और अपरीक्षित स्वरूप में प्रस्तुत करती है। मगर यह आत्मा का ओछापन है, जिसे राष्ट्र को उतार फेंकना चाहिए, ताकि उसमें अपनी नियति के लिए साहस प्राप्त हो।...

यह एक ऐसी घड़ी है, जिसमें जैसा भारत के लिए, वैसा ही विश्व के लिए भी, भारत की भावी नियति और आगामी एक सदी के लिए उसके कदमों का मोड़ सशक्त रूप से निर्णीत किया जा रहा है और वह भी किसी साधारण सदी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी सदी के लिए, जो स्वयं एक महान संधि-काल है और मानव जाति के आंतरिक व बाह्य इतिहास में एक विशद उलट-फेर करने वाला है। आज हम जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही हमें अपने कर्म का फल मिलेगा, और ऐसी घड़ी में इस प्रकार की प्रत्येक पुकार हमारे लोगों की आत्मा के लिए एक साथ अवसर भी है, एक पसंद भी और एक परीक्षा भी।

उसे केवल एक नई चेतना और एक ऐसी नई संस्था ही सृजित कर सकती है, जिसका जन्म राष्ट्र के हृदय से हुआ हो और जो पुनरुज्जीवन के प्रकाश और आशा से भरपूर हो।

श्री अरविंद

आशुतोष राणा | अभिनेता

असहमति और अशिष्टता में अंतर होता है। हम अक्सर अपनी अशिष्टता को असहमति का नाम देकर उसे गरिमा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मगर संबंधों की मधुरता विचारों से अधिक आचरण पर निर्भर होती है।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले | 13 जून, 1949

लंका में भारतीय

कोलम्बो १२ जून। हाल ही में लंका के भारत स्थित हाईकमिश्नर श्री अरुणाचलम महादेव ने मद्रास में जो वक्तव्य दिया था, उसका उत्तर देते हुए लंका भारतीय कांग्रेस ने बताया है कि लंका में भारतीयों की नागरिकता के संबंध में अनेक भ्रमपूर्ण बातें कही गई हैं। उनका प्रतिवाद किए बिना नहीं रहना चाहिए। श्री अरुणाचलम ने अपने वक्तव्य में कहा है कि लंका में जन्मजात नागरिकता और प्राप्त नागरिकता में कोई भेद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक कानून के अन्तर्गत नाम दर्ज कराने का विरोध करना भूल है। लंका से भारतीयों को निकालने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है।

वक्तव्य के उत्तर में कहा गया है कि हम उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहते हैं, जिनमें लंका के भारतीयों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने पड़ते हैं। भारतीय तथा पाकिस्तानी नागरिक कानून के अन्तर्गत इतनी शर्त लगायी गयी है कि ८।। लाख लंका निवासी भारतीयों के एक अंश के लिए नागरिकता पा लेना असम्भव है। शर्त है कि नागरिकता के लिए आवेदन पत्र देने वाले व्यक्ति को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि उसके पास अपने और अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त साधन हैं। यह लंका के भारतीयों के लिए दिन-प्रतिदिन दुस्तर होता जा रहा है। अनेक कारणों से बन्दरगाह और रबड़ तथा चाय के खेतों में काम करने वाले भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

दूसरी शर्त प्रवास-काल के सम्बन्ध में है। भारतीयों को इतनी कानूनी कार्रवाइयां तथा व्यय बरतनी पड़ती है कि वे यह महसूस करते हैं, कानून भारतीयों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए नहीं, उन्हें अधिकारों से वंचित करने के लिए बनाया गया है। इन शर्तों को पूरा कर लेने पर भी रजिस्ट्रेशन द्वारा ही नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जो जन्मजात नागरिकता से काफी भिन्न और घटिया है। इस बारे में श्री अरुणाचलम कुछ भी कह सकते हैं।

उत्तर में आगे कहा गया है कि लंका के भारतीयों ने दोहरी नागरिकता के लिए तीव्र इच्छा प्रदर्शित की है। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह दोहरी नागरिकता नागरिकता के अधिकारों के सम्बन्ध में दो पृथक बिल पास करके जारी की गई है।... इस प्रकार के उदाहरणों से लंका के भारतीयों में सरकार की सदिच्छाओं के प्रति संशय जागना स्वाभाविक है।

अब नेहरू के बराबर हो गया कद

आजाद भारत के इतिहास में करीब छह दशकों के बाद नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा राजनेता उभरा है, जिसे भारतीय जनता ने लगातार तीसरी बार जनादेश दिया है। साठ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह करिश्मा किया था। स्पष्ट है, आज के दौर में मोदी जैसा जीवट वाला राजनेता कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए उन्होंने लगातार तीसरी जीत का कीर्तिमान भी बनाया। वैसे, कुछ मामलों में उनकी यह उपलब्धि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मीलों आगे की मानी जाएगी। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम संपूर्ण विपक्ष के बीच हुआ था। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन के तमाम घटक दल मिलकर भी बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा सके, जबकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विपक्षी दलों से अधिक सीटें हासिल कीं। इतना ही नहीं, यह नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को मुख्यमंत्री पद मिला है, तो ओडिशा में बीजू जनता दल की करारी हार हुई है। ओडिशा में तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पहली बार बनी है। इन सबका श्रेय निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वह जवाहरलाल नेहरू से बेहतर इसलिए भी जान पड़ते हैं, क्योंकि आजादी के वक्त ज्यादातर राज्यों में आज जैसी दलीय चुनौतियां नहीं थीं।

ललित मिश्र, टिप्पणीकार

लगातार तीसरा जनादेश

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना आसान नहीं होता। नरेंद्र मोदी से पहले जवाहरलाल नेहरू ही यह कर सके थे। चूंकि दोनों नेता सत्ता-विरोधी रुझान को धता बताते हुए तीन बार जनादेश पाने में सफल रहे, इसलिए इन दोनों की तुलना स्वाभाविक है। यह सही है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ है और यह गठबंधन की सरकार है, पर पिछले दोनों कार्यकाल में भी गठबंधन सरकार ही थी। यह बात अलग है कि उनमें भाजपा को स्पष्ट बहुमत हासिल था। कहने वाले कहते हैं कि नेहरू जैसा जनादेश मोदी को नहीं मिला है, फिर भी सहयोगी दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ली ही है, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इतना ही नहीं, जिस तरह नेहरू ने देश की दशा-दिशा बदल दी और एक नई राह पर वह भारत को आगे ले गए थे, मोदी भी उसी तरह जटिल समस्याओं से पार पाते हुए देश को विकास के नए पथ पर ले जाने में सफल रहे हैं। आज जहां-तहां बुनियादी ढांचे पर काम हो रहा है और देश अनवरत तरक्की की नई ईबारत लिख रहा है।

रोहित नागर, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

नेहरू बनाम मोदी

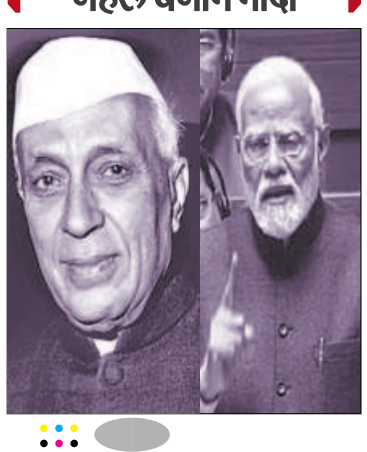

पंडित जी से कहीं कोई तुलना ही नहीं

बिना किसी भूमिका के कुछ बिंदु विचारणीय हैं, जिसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि मोदी और नेहरू की तुलना कितना सही है? नेहरू को जो देश मिला था, तब मुल्क की प्रति व्यक्ति आय थी 274 रुपये और सालाना कर संग्रहण 647 करोड़ रुपये कस था। कर संग्रहण का आंकड़ा 1950 का है, इससे पहले के तीन साल में तो यह संख्या और कम रही होगी। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उचित मॉडल की खोज भी पंडित नेहरू को करनी पड़ी थी। इसके मुकाबले मोदी जी को जब देश मिला, तब देश की प्रति व्यक्ति आय थी, 1,18,000 रुपये और उस समय हमारा कर संग्रहण 16 लाख करोड़ रुपये का सालाना था। हमारी अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन को पार कर चुकी थी। आर्थिक मॉडल क्या होता है या इसे किस तरह काम करना चाहिए, ऐसी चुनौतियों से मोदी जी का कोई वास्ता नहीं पड़ा।

देश जब आजाद हुआ था, तब यहां आधारभूत ढांचे का नितांत अभाव था। सड़कें, यातायात, हवाई उड़ानें, मंडियां, प्राधिकरण आदि सुविधाएं नाममात्र की थीं। बैंक अथवा बैंकिंग सिस्टम में लोगों का शायद ही विश्वास था। रोजगार सृजन के लिए बड़े कारखाने नहीं थे। कृषि कर्म के लिए पानी नहीं था, नहरों का अभाव था। किसी किस्मत वाले के घर साइकिल होती थी, टीवी-फ्रिज तो दूर की बात है। मगर प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला, तो बेहद मजबूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध था। छह लाख से अधिक गांव होने के बावजूद ज्यादातर गांवों में बिजली उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री खुद बताते थे कि जब उन्हें देश मिला, तो 18 हजार गांवों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसका अर्थ है कि लाखों गांवों में बिजली रोशन थी। उस समय कई बिजली संयंत्र काम कर रहे थे, जबकि नेहरू के समय इक्का-दुक्का संयंत्र ही बिजली पैदा कर रहे थे।

नेहरू जी के समय शिक्षा का कोई बेहतर ढांचा नहीं था। एम्स जैसे विश्वस्तरीय अस्पताल और शोध केंद्र खोलने में उन्होंने अपनी ऊर्जा लगाई। आईआईएम और आईआईटी जैसे संस्थानों की सौगात दी। वैज्ञानिक शोध, अंतरिक्ष विज्ञान आदि पर काम हुआ। चूंकि उस समय सीमाएं असुरक्षित थीं, तो सेना पर भी ध्यान दिया गया। सबसे बड़ी बात, सैकड़ों रियासतों में बंटे देश को एक करने की सफल रणनीति बनाई गई। क्या मोदी के सामने ऐसी चुनौतियां थीं? यहां हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तीनों बार नेहरू ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि मोदी तीसरी बार चूक गए।

वीरेंदर भाटिया, टिप्पणीकार

https://epaper.livehindustan.com

द्विवार्षिक प्रवेश की अनुमति

विश्वविद्यालयों को नियमित पाठ्यक्रमों में वर्ष में दो बार छात्रों के प्रवेश की अनुमति एक सराहनीय निर्णय है. पिछले वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओपन एवं दूरस्थ तथा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में ऐसे प्रवेश को मंजूरी दी थी. उल्लेखनीय है कि इन माध्यमों में जुलाई 2022 में 19.73 लाख छात्रों ने नामांकन कराया था. फिर जनवरी 2023 में और 4.28 लाख छात्रों का प्रवेश हुआ. इस उत्साहजनक परिणाम के बाद अब नियमित पाठ्यक्रमों के लिए भी यह सुविधा दी गयी है. बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे देर से आने या किन्हीं व्यक्तिगत वजहों से कई छात्र जुलाई/अगस्त में नामांकन नहीं करा पाते तथा उन्हें एक वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है. अब इस मुश्किल का समाधान हो सकेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विश्वविद्यालयों में साल में दो बार प्रवेश प्रक्रिया होती है. भारत में ऐसी व्यवस्था होने से इस वैश्विक प्रणाली के साथ एक साम्य स्थापित होगा तथा स्टूडेंट एक्सचेंज जैसे कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है. प्रवेश से संबंधित नये नियमों के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होंगे. अब देश में अधिकतर विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर सिस्टम है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सेमेस्टर में पाये गये ग्रेड को हस्तांतरित करने, पाठ्यक्रम के बीच में संस्थान बदलने तथा अंतराल के बाद पढ़ाई पूरी करने जैसे प्रावधान हैं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ताजा फैसले से इन प्रावधानों के लाभ भी बढ़ जायेंगे. हमारे देश में उच्च शिक्षा की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है तथा छात्रों के नामांकन में भी बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग जरूरी हो जाता है. साल में दो बार प्रवेश की व्यवस्था होने से संस्थानों को अपने संसाधनों के प्रभावी वितरण में भी सहायता मिलेगी. लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं. केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कई शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन होता है. जनवरी/फरवरी में नामांकन के लिए नियम बनाने का अधिकार संस्थानों को दिया गया है. नामांकन के दो आधार विसंगति पैदा कर सकते हैं. बड़े विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कई महाविद्यालय होते हैं. कहां कितने संसाधन हैं, द्विवार्षिक प्रवेश से पहले इसका आकलन करना आवश्यक होगा. नयी प्रवेश प्रक्रिया से वैश्विक शैक्षणिक स्तर के समकक्ष आने में हमारे संस्थानों को मदद जरूर मिलेगी, पर यह भी उल्लेखनीय है कि बहुत से संस्थानों में संसाधनों का अभाव है तथा शिक्षकों की उपलब्धता कम है. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. निश्चित रूप से नामांकन बढ़ना चाहिए तथा इच्छुक छात्रों को उच्च शिक्षा का समुचित अवसर मिलना चाहिए, पर संसाधन भी बढ़ने चाहिए.

साल में दो बार प्रवेश की व्यवस्था होने से संस्थानों को अपने संसाधनों के प्रभावी वितरण में भी सहायता मिलेगी. लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं.

विचारणीय हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातें

रामबहादुर राय
वरिष्ठ पत्रकार एवं अध्यक्ष
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
rbrai118@gmail.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने देश के राजनीतिक माहौल पर जो कहा है, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, जो लोकतंत्र के प्रति सचेत है और चाहता है कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों, वह उनकी बात से सहमत होगा. इस चुनाव में वास्तव में ऐसी चीजें हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक हैं. प्रचार के दौरान झूठ को बढ़ा-चढ़ाकर सच के रूप में पेश करने की कोशिश हुई. उदाहरण के लिए, राहुल गांधी अपनी सभाओं में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहते थे कि संविधान खतरे में है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जो बहुत अनुभवी नेता हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं, भी कह रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी जीत गये, अगर भाजपा जीत गयी, अगर एनडीए सत्ता में आयी, तो न संविधान बचेगा और न ही लोकतंत्र. यह भी कहा जा रहा था कि मोदी की जीत होने के बाद यह भारत का आखिरी चुनाव होगा. मेरी दृष्टि में यदि दुनिया में भारत की सबसे बड़ी पूंजी कुछ है, तो वह हमारा संविधान और लोकतंत्र ही है. इनके बारे में लोगों के मन में गंभीर संदेह पैदा कर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, इसके पीछे मंशा क्या थी, ये कुछ बड़े सवाल हैं. यह स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दो बातें हासिल कर रहा है- राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक उन्नति. तो क्या लोकतंत्र और संविधान पर खतरे पर आधारित प्रचार अभियान इन उपलब्धियों को बाधित करने की कोशिश नहीं मानी जानी चाहिए!

यह भी देखा गया कि विपक्ष के प्रचार को देश-विदेश में बैठे लोग यूट्यूब समेत विभिन्न सोशल मीडिया मंचों से बढ़ा-चढ़ाकर आगे बढ़ा रहे थे. मैं समझता हूं कि मोहन भागवत का एक संकेत ऐसी प्रवृत्तियों की ओर है. दूसरी तरफ, लोकसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल की ओर से प्रतिक्रिया में जो बातें कही गयीं, वैसी बातें कहने से परहेज किया जाना चाहिए था. यह भी संघ प्रमुख के संदेश में निहित है. एक प्रबुद्ध व्यक्ति और स्टेट्समैन के नाते भागवत जी ने जो कुछ कहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उस पर राजनीतिक दलों के नेता विचार करेंगे तथा समाज भी समुचित ध्यान देगा.

विमर्श का स्तर गिरने और खर्च में भारी बढ़ोतरी से यह चिंता होना स्वाभाविक है कि जैसा आदर्श लोकतंत्र होना चाहिए, उस कसौटी पर हमारा लोकतंत्र खरा नहीं उतरता. इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है और उस दिशा में मोहन भागवत के सुझाव बहुत अहम साबित हो सकते हैं. उनकी जो सलाह है, वह सरकार के लिए भी विचारणीय है और विपक्ष के लिए भी.

संघ प्रमुख की बातों में राजनीति के गिरते स्तर को लेकर चिंता भी अंतर्निहित है. मैं 1951-52 से लोकसभा चुनाव को देखता आ रहा हूं. यह पहला चुनाव है, जिसमें विमर्श का स्तर बहुत नीचे चला गया था. ऐसा होने की वजह यह है कि विपक्ष इस चुनाव को हाईजैक करना चाहता था. यह भी एक कारण रहा कि कांग्रेस का नेतृत्व वामपंथियों, या कहना चाहिए शहरी माओवादियों, के पूरे प्रभाव में है. कांग्रेस के नेतृत्व की कमान राहुल गांधी के हाथ में है और खरगे साहब चेहरा हैं. मुद्दे और एजेंडा राहुल गांधी तय करते हैं, जो उनके इर्द-गिर्द के लोग निर्देशित करते हैं.

भारत में लोकतंत्र का विकास होना चाहिए. संसदीय लोकतंत्र का हमारा अनुभव अच्छा रहा है. इसलिए संसदीय राजनीति जितनी स्वच्छ रहे, चुनाव जितने पारदर्शी हों, उसकी कोशिश की जानी चाहिए. इस संदर्भ में पहले की कुछ घटनाओं का संज्ञान लेना जरूरी है, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि आज ऐसा नकारात्मक माहौल कैसे पैदा हो गया है. साल 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराये थे. उससे पहले आम तौर पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे. उस चुनाव के बाद स्थिति बदल गयी और अधिकतर विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के लिए मतदान अलग-अलग होने लगे. इस कारण चुनाव का खर्च बेहिसाब बढ़ गया है. इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दोषी हैं. जब प्रधानमंत्री मोदी 'एक देश, एक चुनाव' की बात करते हैं, तो मेरी नजर में वे जयप्रकाश नारायण की मंशा को ही आगे बढ़ाते हैं, जो चाहते थे कि चुनाव खर्च में कमी आये. साल 1971 से पहले के चुनाव को देखा जाए, तो पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का खर्च अपेक्षाकृत कम होता था क्योंकि वे अपनी पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों के कंधे पर चुनाव लड़ते थे. अब उन्हें स्वतंत्र चुनाव लड़ना पड़ता है, तो खर्च करोड़ों में होता है. मैंने 2004 में ऐसे 20 लोगों से अपनी किताब के लिए बातचीत की थी, जो 1952 और 1957 के चुनाव में उम्मीदवार थे. ये लोग कांग्रेस से संबद्ध थे. उन्होंने बताया था कि पार्टी से उन्हें 10 हजार रुपये मिले थे. उनका खर्च तीन से सात हजार रुपये था और शेष उन्होंने पार्टी को वापस कर दिया था. पहले चुनाव में भारत सरकार के कुल 10 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि 2019 में निर्वाचन आयोग को 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़े थे. इस बार यह खर्च और भी अधिक होगा.

विमर्श का स्तर गिरने और खर्च में भारी बढ़ोतरी से यह चिंता होना स्वाभाविक है कि जैसा आदर्श लोकतंत्र होना चाहिए, उस कसौटी पर हमारा लोकतंत्र खरा नहीं उतरता. इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है और उस दिशा में मोहन भागवत के सुझाव बहुत अहम साबित हो सकते हैं. उन्होंने उचित ही कहा है कि सच्चे सेवक को अहंकारी नहीं होना चाहिए और अब बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए. मणिपुर जैसी हिंसा की घटनाओं पर रोक लगाने के प्रयास होने चाहिए. उनकी जो सलाह है, वह सरकार के लिए भी विचारणीय है और विपक्ष के लिए भी. सभी राजनीतिक दल और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि लोकसेवक ही होते हैं तथा सभी की चिंता के केंद्र में राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए. उनकी सलाह समाज के लिए भी है और उन सभी वर्गों के लिए भी, जो राजनीति से संबंधित हैं तथा जनमत बनाने के कार्य से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने सटीक बात कही है कि आप सत्ता में हों या विपक्ष में, अहंकार तो मस्तिष्क को भ्रष्ट ही करता है. हमारी संस्कृति में अहंकार-शून्यता को ही सराहनीय माना गया है. यह एक साधना भी है. मात्र बोल देने से तो कोई अहंकार-शून्य नहीं हो जाता. उसके लिए व्यक्ति, विशेषकर जो सार्वजनिक जीवन में है, को अपने भीतर झांकना होगा और अपनी कमियों को सुधारना होगा. मोहन भागवत की सलाह एक चेतावनी भी है. अगर समाज को समरस, समतामूलक और शांतिपूर्ण बनाना है, तो चाहे मणिपुर हो या देश को कोई अन्य हिस्सा हो, हर जगह सकारात्मक प्रयास होने चाहिए. तभी समृद्ध समाज बन सकेगा. आशा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष संघ प्रमुख की बातों पर ध्यान देंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

केंद्र में एनडीए को बहुमत मिलने के मायने

डॉ अश्वनी महाजन
राष्ट्रीय सह-संयोजक
स्वदेशी जागरण मंच
ashwanimahajan@rediffmail.com

वर्ष 2024 का आम चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है. हालांकि भाजपा को अपेक्षा से कम सीटें मिलीं, पर एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश जरूर मिला है. एक तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए पिछले दस वर्षों के अपने काम और प्रदर्शन पर वोट मांग रही थी, दूसरी तरफ विपक्षी दलों का 'इंडिया' गठबंधन मोदी सरकार के दौरान महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहा था. नरेंद्र मोदी 'जीवन को आसान बनाने' की गारंटी और अपनी नीतियों के साथ लोगों तक पहुंच रहे थे- जिसमें गरीबों के लिए आवास, अगले पांच वर्षों तक गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों के साथ-साथ 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना शामिल था.

कांग्रेस जो 'इंडिया' गठबंधन की मुख्य पार्टी थी, पिछले चुनावों की तरह ही, हर गरीब परिवार को एक लाख रुपये की राशि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, जाति आधारित सर्वेक्षण करके धन का पुनर्वितरण (जनसंख्या के अनुसार) आदि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में थी. इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य क्षेत्रीय दल भी मुफ्त योजनाओं का लालच देकर जनता को लुभा रहे थे. ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए वोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत दिलायी. यह साबित करता है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के दस वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपनायी गयी नीतियों का समर्थन करके एनडीए को विजयी बनाया है, हालांकि उस भारी बहुमत से नहीं, जिसका दावा सत्तारूढ़ गठबंधन कर रहा था. नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गयीं, जिनके लाभार्थियों ने स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है. चार करोड़ गरीब परिवारों के लिए पक्के मकानों का निर्माण, नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. यदि पांच लोगों को एक परिवार माना जाए, तो करीब 20 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थी रहे हैं. एनडीए को उन लाभार्थियों का समर्थन मिला है. इसके साथ ही, एलपीजी कनेक्शन से वंचित 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत न केवल धुएं से मुक्ति मिली है बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आया है. शौचालयों के निर्माण के कारण खुले में शौच से मुक्त हुई महिलाओं का समर्थन भी मौजूदा सरकार चला रही पार्टियों को मिला होगा. लगभग पूरे देश को नल से जल और शत-प्रतिशत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना क्रांति से कम नहीं माना जा सकता. लगभग 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन और किसानों को छह हजार रुपये प्रतिवर्ष की राशि जारी रखने की गारंटी भी लोकप्रिय कदम माना जा रहा है.

उधर कांग्रेस की नकद वितरण योजना कांग्रेस को वोट नहीं दिला पायी. इससे पहले भी कांग्रेस ने किसानों के 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किये थे और 2024 में भी इसी तरह की घोषणा की गयी थी. वर्ष 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, तब भी कांग्रेस को लोकसभा में मात्र 52 सीटें ही मिलीं. इस बार कांग्रेस ने चुनाव के दौरान हर गरीब परिवार को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा किया था. हालांकि, कांग्रेस के इस वादे के क्रियान्वयन को लेकर लोगों में काफी संदेह था और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 100 से कुछ कम ही रहीं. एक तरफ जनता द्वारा नकद वितरण योजना को नकारना और दूसरी तरफ मोदी सरकार द्वारा चलायी जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं पर दिखाया जा रहा भरोसा, मतदाताओं और लोकतंत्र की परिपक्वता दर्शाता है. सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें, तो देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है. यह सच है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी दो ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग चार ट्रिलियन डॉलर हो गयी है और देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. पर यह भी सच है कि देश में अमीर और गरीब के बीच असमानता अभी भी बनी हुई है. हालांकि, अत्यधिक गरीबी में काफी कमी आयी है. यह सही है कि राजकोषीय सूझबूझ के कारण सरकार का पूंजी निवेश बढ़ रहा है, देश में बड़ी मात्रा में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है.

उत्पादों के निर्माण में हमारी निर्भरता अभी भी दूसरे देशों पर बनी हुई है. आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत देश में विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के प्रयास भी फलीभूत हो रहे हैं, परंतु इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है. रोजगार के अवसर भी पैदा करने होंगे. यह सही है कि एआइ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के कारण पारंपरिक रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, परंतु तकनीक के साथ तालमेल बनाये रखना भी जरूरी होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मशीनों और एआइ का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में कम हो, जहां श्रम का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है. ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों को विकसित करने के प्रयास भी करने होंगे.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने मुफ्त योजनाओं के लिए वोट नहीं दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को जीत दिलायी. यह साबित करता है कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के दस वर्ष के कार्यकाल के दौरान अपनायी गयी नीतियों का समर्थन करके एनडीए को विजयी बनाया है.

देश दुनिया

पीएलए को विफल करने के लिए अमेरिकी रणनीति

अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने कहा है कि यदि चीन ताइवान पर सैन्य हमला शुरू करता है, तो अमेरिका की हजारों ड्रोन तैनात करने की योजना है. अमेरिकी रणनीति, जिसे पापारो ने 'हेलस्केप' कहा है, उसके अनुसार, जैसे ही चीनी सेना चीन और ताइवान को अलग करने वाले 100 मील के जलमार्ग पर आगे बढ़ना शुरू करेगी, अमेरिकी सेना कई मानव रहित पनडुब्बियों, मानव रहित जहाजों और हवाई ड्रोन को तैनात करेगी. 'हेलस्केप' रणनीति का खुलासा चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा ताइवान द्वीप के आसपास एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ. नौसेना विशेषज्ञ और सेवानिवृत्त पीएलए नौसेना अधिकारी वांग युनफेई की मानें, तो युद्ध का पारंपरिक तरीका ताइवान जलडमरूमध्य में पीएलए पर अमेरिका की जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती, इसलिए वह पीएलए को विफल करने के लिए तथाकथित हेलस्केप जैसी युद्ध स्थिति का सहारा ले रहा है. अमेरिका के पास दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक व सैन्य ड्रोन का सबसे बड़ा बेड़ा है. अमेरिका की कुल सैन्य ताकत पीएलए से बेहतर है. इसके बावजूद, ताइवान जलडमरूमध्य में अमेरिका पूरी तरह लाभ की स्थिति में नहीं होगा. यदि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने विमानवाहक पोत भेजता है, तो पीएलए अमेरिकी विमानवाहक पोतों को पहली द्वीप श्रृंखला से दूर रखने के लिए अपनी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग कर सकता है. इसके अतिरिक्त, अमेरिका को अपने हजारों मानव रहित हथियारों को कमांड करने के लिए कमांड प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है. पीएलए के पास इन प्लेटफार्मों को बंद करने या सिग्नल जाम करने की क्षमता है. ताइवान चीन का आंतरिक मामला है, चीन शांतिपूर्ण तरीकों से एकीकरण का प्रयास करेगा. परंतु, यदि जलडमरूमध्य में शांति बाधित होती है, तो अमेरिका को इससे निपटने के लिए चीनी तरीके को स्वीकारना होगा.

बोधि वृक्ष

वैराग्य का अर्थ

वैराग्य का अर्थ, जहां न राग रह गया, न विराग रह गया. जहां न किसी चीज का आकर्षण है, न विकर्षण है. न किसी चीज के प्रति खिंचाव है, न विपरीत भागना है. जहां न किसी चीज का बुलावा है, न विरोध है. जहां व्यक्ति थिर हुआ, सम हुआ, जहां पक्ष और विपक्ष एक से हो गये, वहां वैराग्य फलित होता है. पर इसे विराग या वैराग्य क्यों कहते हैं? जहां वैराग्य भी नहीं है, वहां वैराग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई उपाय नहीं है. शब्द की मजबूरी है, और कोई बात नहीं है. मनुष्य के पास सभी शब्द द्वंद्वात्मक हैं. मनुष्य की भाषा में ऐसा शब्द नहीं है जो द्वंद्वात्मक न हो. मनुष्य ने जो भाषा बनायी है, वह मन से बनायी है. मन द्वंद्व है. इसलिए मनुष्य जो भी भाषा बनाता है, उसमें विपरीत शब्दों में भाषा को निर्मित करता है. मजे की बात है कि हमारी भाषा बन ही नहीं सकती विपरीत के बिना. क्योंकि बिना विपरीत के हम परिभाषा नहीं कर सकते. अगर कोई आपसे पूछे कि अंधेरा यानी क्या? तो आप कहते हैं, जो प्रकाश नहीं है. कोई पूछे, प्रकाश क्या? तो आप कहते हैं, जो अंधेरा नहीं है. न आपको अंधेरे का पता है कि क्या है, न प्रकाश का पता है कि क्या है? अंधेरे को जब पूछते हैं तो कह देते हैं प्रकाश नहीं है. जब पूछते हैं प्रकाश क्या है? तो कह देते हैं अंधेरा नहीं है. यह कोई परिभाषा हुई? परिभाषा तो तभी हो सकती है, जब कम से कम एक का तो पता हो. ऐसे ही व्यक्ति से पूछो चेतना क्या है? वह कहता है, जो पदार्थ नहीं है. उससे पूछो पदार्थ क्या है? वह कहता है जो चेतना नहीं. बड़े से बड़े दार्शनिक भी इसको परिभाषा कहते हैं. यह परिभाषा नहीं हुई. क्योंकि इसमें से एक का भी पता नहीं है. मनुष्य की भाषा डायलेक्टिकल है. डायलेक्टिकल का मतलब यह कि जब आप पूछें 'अ' क्या, तो वह 'ब' की बात करता है. जब पूछें 'ब' क्या, तो वह 'अ' की बात करने लगता है. इससे भ्रम पैदा होता है कि सब पता है. पता कुछ भी नहीं है, केवल शब्द पता हैं. परंतु बिना शब्दों के काम नहीं चल सकता. राग है तो विराग है. पर तीसरा शब्द कहां से लाएं? और तीसरा शब्द ही सत्य है. वह कहां से लाएं?

-ओशो

कुछ अलग

पुरुषों में भी स्वास्थ्य सजगता आवश्यक

जून महीना पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सजगता लाने से भी जुड़ा है. इस माह को 'इंटरनेशनल मेन्स हेल्थ मंथ' के रूप में मनाया जाता है. विशेष रूप से जून का एक पूरा सप्ताह पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जागरूक होने को समर्पित है. इस वर्ष इन दिनों के तहत 10 से 16 जून तक 'अंतरराष्ट्रीय पुरुष स्वास्थ्य सप्ताह' मनाया जा रहा है. पिता के रूप में पुरुष की भूमिका महत्वपूर्ण होने के बावजूद हमारे परिवेश में उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कम ही सोचा जाता है.

दुनिया के हर हिस्से में पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लोगों में सजगता और संवेदनशीलता आवश्यक है. वर्ष 2024 के लिए पुरुष स्वास्थ्य सप्ताह का विषय 'मेन्स हेल्थ चेक्स', यानी 'पुरुष स्वास्थ्य जांच' है. यह थीम पुरुषों के बीच रोकथाम योग्य स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारियों की शीघ्र पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है. देखा जाये, तो यह विषय पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों

डॉ मोनिका शर्मा
टिप्पणीकार
monikasharma.writing@gmail.com

और उपचार संबंधित स्थितियों को समय रहते समझने के मोर्चे पर सामुदायिक परिवेश में जागरूकता, समर्थन और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है. पुरुषों द्वारा सक्रिय जीवनशैली अपनाने, रोगों से बचाने वाली जीवनचर्या को प्राथमिकता देने, नियमित स्वास्थ्य जांच का शेड्यूल बनाने, खुलकर संवाद करने और स्वस्थ खानपान अपनाने की सजगता को बल देने के लिए यह रेखांकित करने योग्य मुहिम है. अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों की प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए चिकित्सक के पास जाने की संभावना बहुत कम होती है. जिसके चलते दुनियाभर में हृदय रोग, कैंसर और दुर्घटना में लगी चोटें, उनका जीवन छीनने के तीन प्रमुख कारण बन गयी हैं. पांच में से चार आत्महत्या पुरुषों द्वारा की जाती हैं. पैंतीस वर्ष से कम आयु के पुरुषों में आत्महत्या जीवन गंवाने का सबसे बड़ा कारण है. बावजूद इसके, सामाजिक-पारिवारिक माहौल में पुरुषों के भावनात्मक स्वास्थ्य को लेकर सोचा ही नहीं जाता.

अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ और डिप्लोमैट बिल रिचर्ड्सन ने कहा था कि 'पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना और उन्हें रोकना केवल पुरुषों का मामला नहीं है. इसका असर पत्नियों, माताओं, बेटियों और बहनों पर भी पड़ता है. सो पुरुषों का स्वास्थ्य वास्तव में एक पारिवारिक मुद्दा है.' ध्यातव्य है कि 1994 में अमेरिकी सीनेटर बॉब डोल और कांग्रेसी बिल रिचर्ड्सन द्वारा प्रायोजित बिलों से ही पुरुषों और लड़कों में बीमारियों की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने से जुड़ी इस मुहिम की शुरुआत हुई थी.

आपके पत्र

कुटीर व लघु उद्योगों की हो स्थापना

बिहार में कई क्षेत्रों में काम हुआ है, लेकिन उद्योग के मामले में हम अब भी पिछड़े हैं. इसके कारण बिहार से रोजी-रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन होता है. यहां खनिज, वन, जल के साथ उर्वर भूमि है. लेकिन इसका लाभ सरकार नहीं उठा पा रही है. खास कर कृषि से संबंधित उद्योग लगाने की आवश्यकता है. इसके साथ डेयरी के क्षेत्र में और काम करना होगा. इससे ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे इनकी आमदनी बढ़ेगी. साथ ही ग्रामीण इलाकों से रोजगार के लिए लोगों का पलायन नहीं होगा.

सरोज शुक्ल, पटना

गिर रहे जल स्तर से बढ़ेगी परेशानी

पूरे देश में जल संकट गहराता जा रहा है. भूमिगत जल दोहन में भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है. प्राकृतिक जल स्रोतों का अतिक्रमण हो चुका है. आज सिर्फ 12 फीसदी बारिश का पानी ही धरती के गर्भ में जा रहा है और शेष बर्बाद हो रहा है. यदि हम बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजने में सफल रहे, तो काफी हद तक पानी की किल्लत दूर हो जायेगी. जल संकट की वजह से कृषि, पशुपालन, मत्स्य और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. प्राकृतिक जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना होगा.

हिमांशु शेखर, केसपा (गया)

https://t.me/epaperpdf

दैनिक जागरण

स्थिर मस्तिष्क परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है

आंतरिक सुरक्षा को खतरा

रियासी के बाद जम्मू संभाग के कठुआ और डोडा में आतंकी हमले गंभीर चिंता का कारण बनने चाहिए। ये हमले यही बता रहे हैं कि आतंकी बेलगाम होते जा रहे हैं और वे जम्मू क्षेत्र में वैसे ही हालात पैदा कर रहे हैं, जैसे एक समय उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कर दिए थे। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू के उन इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। यह सामान्य बात नहीं कि आतंकियों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ जाए कि वे 60 घंटे के अंदर तीन जगहों पर हमले करने में समर्थ रहें। उन्होंने न केवल निर्दोष-निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, बल्कि सुरक्षाकर्मियों को भी। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी होगी। ऐसी किसी कार्रवाई के ठोस नतीजे तब हासिल होंगे, जब पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि उसकी शह पर ही जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दो आतंकियों को मार गिराया गया, क्योंकि यह साफ है कि जम्मू के विभिन्न इलाकों में पाकिस्तान से आए अनेक आतंकी छिपे हुए हैं।

चिंता की बात केवल यह नहीं है कि जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि देश-विदेश में भारत विरोधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पंजाब में खालिस्तान समर्थक नए सिरे से सिर उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली आदि में भी। भारतीय प्रधानमंत्री की इटली यात्रा के पूर्व वहां खालिस्तान समर्थकों ने गांधीजी की प्रतिमा को जिस तरह खंडित किया, वह एक तरह से अलगाववादी तत्वों की ओर से भारत को दी जाने वाली सीधी चुनौती है। भारत सरकार को पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर में और अधिक सतर्कता बरतने के साथ उन देशों से भी दो टूक बात करनी होगी, जहां खालिस्तान समर्थक बेलगाम हो रहे हैं। भारत सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि लोकसभा चुनाव के पहले सार्वजनिक स्थलों पर बम रखे होने की झूठी सूचनाएं देकर दहशत फैलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले स्कूलों में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं दी गईं, फिर अस्पतालों में। इसके बाद विमानों में और अब संग्रहालयों में। चिंताजनक यह है कि ऐसी झूठी सूचनाएं देकर सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द बढ़ाने वाले तत्वों की पहचान नहीं हो रही है। माना जाता है कि ऐसे तत्व दूसरे देशों में छिपे हुए हैं। सच जो भी हो, भारत सरकार को आंतरिक सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनावों में कश्मीर और पंजाब में कई ऐसे अलगाववादी तत्व चुनाव जीतने में समर्थ रहे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

समन्वय जरूरी

सूरज की बढ़ती तपिश ने बुरी तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है। बिहार में लोग-बाग क्या, पशु-पक्षी भी बेहोश होकर चलते-उड़ते गिर रहे हैं। ऐसे लू के थपेड़ों के बीच स्कूली बच्चों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं। 10 जून को स्कूल खुलने के साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक बच्चे व शिक्षक स्कूल में ही बेहोश होकर गिर गए। उपचार के बाद इनके होश में आने तक स्कूल प्रबंधन की सांसें अटकी रहीं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिसंख्य बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं। इनके अभिभावक इनकी शिक्षा के प्रति उस स्तर तक सजग नहीं रहते हैं, जिस स्तर तक प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के मां-पिता। मई में भी बच्चों के स्कूलों में बेहोश होने की सूचनाएं आई थीं। इन स्कूलों में जाने वाले अधिसंख्य बच्चों के पास पानी की बोतल तक नहीं होती। गर्मी की छुट्टियों के बाद 10 जून को बच्चों के लिए फिर स्कूल खुले तो लू के थपेड़ों ने उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ऐसे में आनन-फानन शिक्षा विभाग ने 11 से 15 जून तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया। 16 को रविवार है। ऐसे में 17 जून से बच्चों को फिर स्कूल जाना होगा। स्कूली बच्चों को भी अक्सर जाम लगने की स्थिति में एक-दो घंटे तक बीच सड़क पर कड़ी धूप में वाहनों में फंसे रहना होता है। स्कूल बसों की तुलना में छोटे चारपहिया वाहन या आटो सड़क पर खड़े-खड़े काफी गर्म हो जाते हैं। इस स्थिति में छोटे बच्चों का स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसे में शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि मौसम विभाग से समन्वय स्थापित कर बच्चों के स्कूल खुलने की समयसीमा का निर्धारण करे। ऐसा नहीं करने पर हर बार आपात स्थिति में ही स्कूल बंद करने होंगे।

शिक्षा विभाग की यह जिम्मेदारी बनती है कि मौसम विभाग से समन्वय स्थापित कर स्कूल खुलने की समयसीमा का निर्धारण किया जाए

सुधारों पर सहमति बनाने का समय

जीएन वाजपेयी

बहुदलीय लोकतंत्र में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना एक चतुराई भरा काम है। चूंकि इसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य की परीक्षा भी होती है

आम चुनाव के नतीजों की तरह-तरह से व्याख्या हो चुकी है और यह सिलसिला अब भी कायम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव परिणाम कुछ अनपेक्षित रहे। प्रतीत होता है कि आर्थिक दुश्वारियां, बेरोजगारी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरे और संविधान बदलने जैसे नैरेटिव ने नतीजों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जनमत को व्यापक रूप से प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं का यह स्वप्न था कि देश प्रगति के शिखर को छुए। अंडमान की एक यात्रा के दौरान मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी का यह संदेश पढ़ने को मिला कि 'कृपया उन्हें यह बताना कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब उनकी बारी है।' जिन क्रांतिकारी ने यह संदेश लिखा था, उन्हें फांसी होने वाली थी। उन्होंने यह संदेश अंडमान से रिहा होकर गांव जाने वाले अपने साथी को दिया था कि वह ग्रामीणों के नाम उनका यह संदेश दें। मौजूदा पीढ़ी को भी उस संदेश के व्यापक मर्म को समझते हुए देश में विपन्नता के दायरे को समाप्त कर उसे समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए उसे प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। मौजूदा सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अगले 23 वर्षों तक कम से कम सात प्रतिशत या उससे अधिक की औसत सालाना जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी।

जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से तीन उत्पादन कारकों-भूमि, श्रम और पूंजी की उपलब्धता एवं उत्पादकता से प्रभावित होती है। भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यापक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य यह मांग करता है कि इन तीनों कारकों के बीच उचित समन्वय, दूरदर्शी नियोजन और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जहां पूंजी दक्षता के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है, वहीं वह श्रम उत्पादकता के मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है। 2017 की क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के आधार पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में श्रम उत्पादकता के मोर्चे पर भारत को 126वें स्थान पर रखा था। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि भूमि की उपलब्धता एवं लागत बुनियादी ढांचा विकास और उद्योगीकरण की राह में अवरोध बने हुए हैं। जीडीपी वृद्धि दर की गति बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की क्षमताएं भी एक बाधा बनी हुई हैं। यदि कृषि क्षेत्र का योगदान भी मैन्यूफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के अनुपात में बढ़ जाए तो 2024 की जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर जाएगी।

अवधेश राजपूत

वास्तव में ये तीनों क्षेत्र व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में इस तात्कालिक आवश्यकता को समझते हुए अपनी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगाकर सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन सहमति के अभाव में ऐसे सुधार अधर में अटक गए।

भूमि, श्रम और कृषि भावनात्मक मुद्दे हैं। भारत के जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना एक बहुत चतुराई भरा काम है। चूंकि इसमें समय लगता है अतः धैर्य की परीक्षा भी होती है। एक समय नगालैंड में मुख्यमंत्री के पूर्ण वरदहस्त के साथ राज्य के मुख्य सचिव आरएस पांडेय ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसे क्षेत्रों में 'कम्युनिटाइजेशन' यानी समुदायों की भूमिका को बढ़ावा दिया था। यह कवायद विभिन्न समुदायों के नेताओं, राजनीतिक दलों, मीडिया से लेकर विभिन्न प्राधिकरणों जैसे तमाम अंशभागियों के सहयोग से संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था ने भी उसका संज्ञान लिया था। मोदी ने भी 2017 में जीएसटी जैसी सार्वभौमिक कर व्यवस्था के सूत्रपात के साथ ऐसा करिश्मा कर दिखाया था। पूर्व की कई सरकारें यह नहीं कर पाईं। मोदी के नेतृत्व में एक लंबी कवायद के बाद ऐसी व्यवस्था की राह में लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध दूर हुआ। तत्कालीन वित्त सचिव ने बताया था कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जीएसटी को लेकर समझ बनाने में कैसी भूमिका निभाई और कितने धैर्य का परिचय दिया। मोदी 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। यह भारत के आर्थिक उत्थान की राष्ट्रीय इच्छा का प्रतीक है। यह आह्वान सभी दलों को प्रेरित करने वाला बने कि वे अपने संकीर्ण हितों को पीछे छोड़कर विकसित राष्ट्र बनाने के बिंदुओं पर सहमति के साथ आगे बढ़ें।

कारोबार को सुगम बनाने की राह में वास्तविक कुंजी अनुबंधों के प्रवर्तन में निहित है। किसी अनुबंध के प्रवर्तन में औसतन 1445 दिन का समय लगता है और लागत में 31.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखती है। अपने देश में आम नागरिक न्यायिक अक्षमताओं से भी कुछ त्रस्त हो चुका है। न्यायपालिका व्यापक सुधारों की मांग कर रही है। इसमें देरी से तंत्र के प्रति भरोसा और घटेगा। यहां भी किसी प्रकार के कायाकल्प के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, नेताओं और नागरिक समाज से जुड़े संस्थानों सरीखे विभिन्न अंशभागियों के बीच सहमति आवश्यक होगी।

बढ़ती आर्थिक असमानता चिंता बढ़ा रही है। यह असमानता मुख्य रूप से दो श्रेणियों में है। एक तो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और दूसरी राज्यों के स्तर पर। आर्थिक असमानता समान अवसरों के अभाव से उपजती है। जबकि संविधान की प्रस्तावना ही प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की उद्घोषणा करती है। नागरिक प्रशासन के पास नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व है, जो अपनी न्यूनतम दक्षता से काम करता है, जिससे लोगों में निराशा विशेषकर वंचितों में असंतोष उत्पन्न होता है। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जिस नौकरशाही की संकल्पना की गई थी, उसे नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के बीच आय एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्तर पर बढ़ रही असमानता को भी जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन, निवेशकों में भरोसा बढ़ाना और क्रियान्वयन क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत की जनता अपनी नई सरकार के भावी कदमों की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही है। तमाम लोग प्रचंड गर्मी के दौरान जान जोखिम में डालकर सरकार चुनने के लिए वोट डालने बाहर निकले। यदि लोगों को सरकार से निराशा हाथ लगती है तो उनकी पीड़ा आक्रोश में बदल सकती है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

निराधार थे लोकतंत्र पर उठे सवाल

गिरीश्वर मिश्र

हाल के संसदीय चुनावों में लोकतंत्र और ईवीएम पर जो सवाल उठे, उन्हें नतीजों ने गलत साबित किया

बेवजह बदनाम किया गया ईवीएम को। प्रेट्र

विश्व के सबसे बड़े चुनाव के दौरान देश की जनता को भारतीय लोकतंत्र की चाल-ढाल की विलक्षण छटाएं देखने को मिलीं। 11 लाख और 8 लाख से अधिक के अंतर से लोग जीते तो नोटा का भी इस्तेमाल किया गया। निर्वाचन आयोग पर तोहमतें लगती रहीं, पर उसने मुस्तैदी से और निष्पक्षता से कार्य किया। संविधान, लोकतंत्र और ईवीएम पर सवाल उठे, लेकिन नतीजों ने ऐसा करने वालों को गलत साबित कर आईना दिखाया। नतीजे बता रहे कि भारतीय लोकतंत्र को कहीं कोई खतरा नहीं। चुनावी सरगर्मी कभी नर्म-गर्म रही तो कभी तल्ख हुई। एक ओर से अतिरेक का उत्तर भी अतिरेक से ही दिया जाता रहा। ऐसे क्षण भी आए, जब शिष्टाचार की मर्यादाएं टूटती नजर आईं। इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उचित ही टिप्पणी की। निर्वाचन आयोग ने प्रचारकों को सख्त हिदायत दी और कुछ को प्रचार कार्य से अलग भी किया। सत्ताधारी दल में अतिआत्मविश्वास था कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। उसे सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो मिला, लेकिन पिछली बार से कम सीटें ही मिल सकीं। मोदी काल में कई मोर्चों पर सक्रियता का ही फल है कि छह दशक पहले का इतिहास दोहराते हुए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग लगातार तीसरी बार सरकार बना सका। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया।

चुनाव में तमाम सवाल उठे। सनातन और राम-मंदिर निर्माण को लेकर भी अनर्गल प्रश्न उछलते रहे। विपक्षी दलों ने अपनी शक्ति-सामर्थ्य के बिंदु गिनाने में जितना श्रम किया, उससे अधिक विरोधी के छिद्रान्वेषण में लगाया। शक्ति और सामर्थ्य के नाम पर दिवास्वप्न सरीखे प्रलोभनों की यह लंबी सूची तैयार की जाती रही कि अगर सरकार बन गई तो किसे क्या-क्या दिया जाएगा। चुनाव के बीच अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के विवाद को भी तूल दिया गया। बहुसंख्यक होने से हिंदू और हिंदुत्व को संशयग्रस्त पहचान के रूप में स्थापित करना और अल्पसंख्यक के लिए खतरे से रक्षा का नाटक अपने वोट सुरक्षित करने के लिए किया जाता रहा। यह राष्ट्र बोध और देश, संस्कृति सभ्यता सबको हाशिए पर धकेलने का उपक्रम बन गया।

हमेशा की तरह जाति को लेकर टिकट बांटने और मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश सभी दलों ने की। जाति समाज की एक सच्चाई है और सभी दल उसकी निंदा करते हैं, परंतु उसी का सहारा भी लेते हैं। चुनाव नतीजों ने जाति के बनते-बिगड़ते समीकरणों की भूमिका फिर दिखा दी। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे भी छाए रहे। इसके बाद भी सबके मन में केंद्र में एक मजबूत सरकार लाने की इच्छा थी। भाजपा को इससे लाभ मिला। भाजपा दक्षिण भारत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। चुनाव परिणाम जनता के विश्वासमत की पुष्टि करते हैं। परिणाम इसके परिचायक हैं कि लोकतंत्र के भविष्य को लेकर जो सवाल-संदेह उठाए जा रहे थे, वे निराधार थे। संदेह जताने वालों को जनता ने यही जवाब दिया कि यह महज एक दुष्प्रचार ही था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।

चुनावों में कई पार्टियों के दावों, वादों, आरोप-प्रत्यारोप की भाषा जमीनी वास्तविकताओं की जगह दिवास्वप्न को रेखांकित कर रही थी। इससे जनता के सामने चकित, भ्रमित और भयभीत होने की स्थितियां भी आती रहीं। लोकतंत्र के आसन्न विनाश, संविधान का समापन, आरक्षण नीति पर ग्रहण आदि से जुड़ा दुष्प्रचार तथा राजकीय तंत्र के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों को लेकर भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता रहा। हास्यास्पद टिप्पणियों और तर्कहीन अधकचरे प्रस्तावों के साथ कर्ज माफी, विभिन्न समुदायों को सहायता राशि की सौगातें बांटने, आरक्षण की सीमा घटाने-बढ़ाने और उसे पंथ-समुदाय की सदस्यता से जोड़ने की घोषणाओं से जनता को लुभाने के प्रयास किए जाते रहे। चूंकि मोदी सरकार ने एक दशक में जमीनी परिस्थिति को बदलने का काम किया था, इसलिए इसका सीधा अनुभव जनता को हुआ था। इस बार का जनादेश मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता की पुष्टि करता है। अमृतकाल में विकसित भारत का संकल्प लेकर उस दिशा में अग्रसर होने को उद्यत मोदी भारत के प्रतिनिधि के रूप में अब पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

एक समर्थ, शक्तिशाली और संभावनाशील भारत की छवि को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की रीति-नीति परीक्षा की कसौटी पर कसी जाएगी। महंगाई और रोजगार के सवाल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय अभी भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जहां अतिरिक्त संसाधनों का निवेश और व्यवस्थागत परिवर्तन स्वाभाविक हो गए हैं। यदि समाज, विशेषतः युवा वर्ग स्वस्थ और सुशिक्षित नहीं होगा तो विकास के सपने अपूर्ण रह जाएंगे। इससे इन्कार नहीं कि ये विषय अभी भी उपेक्षित हैं। इसी तरह से न्याय व्यवस्था और उसके कायदे-कानून तकनीकी दृष्टि से बड़े पेचीदा, खर्चीले और अनावश्यक रूप से समयसाध्य बने हुए हैं, जिनसे न्याय पाने में विलंब होता है और लोग बेवजह सताए जाते हैं। इनमें जरूरी बदलाव अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह व्यवस्थागत सुधार ले आने की आवश्यकता भी सभी महसूस करते हैं। नौकरशाही के जोर के आगे उसमें बदलाव लाना टेढ़ी खीर है, पर उसे करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई पाटना भी सरल नहीं है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश की आकांक्षाओं को आकार देने का ऐतिहासिक कार्य प्रभावी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। आशा है नई सरकार इन प्रश्नों पर प्राथमिकता से ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी।

(लेखक प्रोफेसर एवं कुलपति रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्व की पहचान

जीवन में आपकी महत्ता तभी बढ़ सकती है जब आपको स्वयं अपना महत्व पता हो। इसके लिए स्वयं को समझना होगा। जीवन को आगे बढ़ाने और उसके साथ कदमताल के लिए खुद की पहचान इतनी आवश्यक है कि उसी से हमें अपनी क्षमताओं एव सीमाओं का भलीभांति भान होता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है। इसीलिए हम सभी को सम्मान के साथ व्यवहार करने और यह व्यक्त करने का अधिकार है कि हम वास्तव में कौन हैं? जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो प्रायः बेहतर निर्णय लेते हैं। अपने अनूठे और विशेष गुणों को अपनाना सीखें। अपने लिए खड़े हों और अपनी इच्छानुसार जीवन जिएं।

अगर आप खुद को दूसरों के सामने कठपुतली बना देंगे तो लोग आपका अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करने लगते हैं। इस परिस्थिति में आप सामने वाले के द्वारा उपयोगिता समाप्त होने के बाद दूध में मक्खी की भांति बाहर कर दिए जाएंगे। जब तक आपको इसकी भनक लगे तब तक संभवतः बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अपने करीबियों के व्यवहार पर सदैव दृष्टि बनाए रखनी चाहिए कि सुख की अवस्था में और दुख की अवस्था में आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था। आपमें इतनी क्षमता एवं बुद्धिमत्ता अवश्य होनी चाहिए कि आप दूसरों का उचित आकलन कर सकें।

जीवन में अधिक सहज महसूस करने के लिए अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ पूर्ण ध्यान दें। जैसे आप दूसरों के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही आप अपने लिए भी हमेशा खड़े रहें। जीवन में सदैव सकारात्मक और संतोषजनक रिश्ते रखें, जिसमें दोनों साझेदारों को महत्व और सम्मान दिया जाता हो। ऐसे संबंध, जिनमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समझौता न करना पड़े। यह सब स्वयं को पहचानने से ही संभव होगा।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

बारिश की बूंद-बूंद सहेजने का समय

आयुषी दवे

जब धरती संतृप्त होगी, तभी बचे हुए कुएं और तालाब भी नहीं सूखेंगे। हमें पानी की चिंता भी नहीं होगी

मानसून अपनी राह पर चल पड़ा है। हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी है कि उनके यहां वर्षा कब होगी? वास्तव में यह मानसून का नहीं, बल्कि उन अमृतमयी बूंदों की प्रतीक्षा है जिनकी आस में झुलसती गर्मी ने सभी को व्याकुल कर रखा है। इसीलिए मानसून का इंतजार है। पहले भी इंतजार होता था, पर व्याकुलता नहीं थी। गर्मी, तपन, झुलसन इतनी प्रचंड नहीं होती थी। गांवों, बड़े और मझोले कस्बों में भी लोगों के पास कूलर नहीं होते थे, बिजली के पंखे तक दुर्लभ थे। हाथ से बने बांस और कपड़े के पंखे ही सबके लिए पर्याप्त थे। ऐसी बेचैनी नहीं थी, क्योंकि घरों के आसपास बाग-बगीचों में छायादार पेड़ गर्मी को सहन कर लेते थे।

आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। न तो पेड़-पौधों की वही संख्या रही, न ही बाग-बगीचे बचे हैं। जहां ये सब हुआ करते थे, वहां अब कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। कच्ची पगडंडियां और सड़कें सीमेंट से पक्की हो गई हैं। कुएं, बावली, तालाब होली आते-आते सूख जाते हैं। अब लहलहाते खेतों और बाग-बगीचों की जगह मानव निर्मित बस्तियां हैं, जहां शाम को ठंडक का अहसास अब नहीं होता। तालाबों में बच्चों से लेकर बड़ों और बुजुर्गों का नहाना भी अब सिर्फ एक सपना प्रतीत होता है। सच में, मेरा गांव ही नहीं, पूरा देश और दुनिया बदल चुकी है। बसाहट जिस तेजी से बढ़ी है, उसके अनुसार प्राकृतिक खानापूर्ति नहीं हो पाई है। कभी यह नहीं सोचा कि सूखते जलस्रोत और उजड़ते जंगल हमें कैसे दिन दिखाएंगे? भू-गर्भ में संग्रहित जल का बोरिंग और ट्यूबवेल से अत्यधिक दोहन किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगा? पहले फरवरी-मार्च में गर्मी का अहसास नहीं होता था, लेकिन आज फरवरी में गर्मी और मार्च में लू के थपेड़े सहने पड़ते हैं।

क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब हमारी अपनी करतूत है? मात्र आधी सदी में उद्योगीकरण के कारण जिस गति से वन उजड़े, पहाड़ खंडित हुए और नदियों की रेत के लिए खुदाई हुई, उसने पर्यावरण के संतुलन को इतना बिगाड़ दिया कि मौसम भी अपने मिजाज को बदलने के लिए मजबूर हो गया। पुराने दिन तो अब लौटकर नहीं आ सकते। परंतु क्या हम इतने जागरूक नहीं हो सकते कि जो गलतियां हुई हैं, उन्हें सुधारें? पश्चाताप की भावना से ही सोचें कि जिस धरती से हम रोज पानी लेते हैं, क्या उसे भी प्यास लगती होगी? क्या हम अपने बनाए कंक्रीट के जंगलों में धरती की कोख तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सकते? हमें गांवों, कस्बों, शहरों में उस क्रांति के लिए एकजुट होना होगा जिसमें बारिश की हर बूंद को सहेजकर, विभिन्न पारंपरिक और अन्य तरीकों से वापस धरती की कोख तक पहुंचाया जा सके। हम अपने घरों या आस-पास पेड़ लगाना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

निरंतरता को प्राथमिकता

'निरंतरता के साथ बदलाव भी जरूरी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान का आकलन बिल्कुल ठीक है कि नई सरकार को कुछ नवीनता की अनुभूति कराने के लिए परिवर्तन भी करने चाहिए थे। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया और विभिन्न मंत्रालयों में जारी सुधारवादी कदमों में निरंतरता का भाव बनाए रखने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी अनुभूति होनी चाहिए कि उनकी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए। इनमें कुछ दिग्गज नाम भी शामिल हैं। इसलिए थोड़े-बहुत परिवर्तन किए जाने चाहिए थे। अभी भी कुछ मंत्रियों पर कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व है और ये सभी विभाग स्वतंत्र रूप में चलाए जाने के योग्य हैं। संभव है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री के सौ दिनों के एजेंडे को सिरे चढ़ाने का एक पहलू हो। उल्लेखनीय है कि पिछले कार्यकाल के शुरुआती सौ दिनों में भी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार से भी कुछ इसी प्रकार की अपेक्षाएं हैं।

केशव तिवारी, आजमगढ़

बेहतर संतुलन की जरूरत

'निरंतरता के साथ बदलाव भी जरूरी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान ने मोदी सरकार और भाजपा संगठन के तौर-तरीकों में बदलाव की जो बात की है, वह विचारणीय है। अति आत्मविश्वास से लबरेज चार सौ पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरने वाली भाजपा को इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि आखिर किस वजह से वह न केवल अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई अपितु बहुमत के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। भाजपा अपने गठबंधन के साथ तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब जरूर हो गई, लेकिन अस्थिरता की तलवार हमेशा उसके सामने लटकी रहेगी। ऐसे में मजबूती के साथ सरकार चलाने के लिए सहयोगी दलों के साथ बेहतर संतुलन की जरूरत है। नागपुर से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो नसीहत दी है, भाजपा नेतृत्व को उस पर भी गौर करने की जरूरत है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा अपनी मातृसंस्था के साथ वैसा सामंजस्य नहीं बना पाई जैसा होना चाहिए था। बावजूद इसके संघ के स्वयंसेवकों ने चुनाव में अपनी सामर्थ्य भर सहयोग किया। इस चुनाव में भाजपा की और भी बहुत सी खामियां रही हैं जिसकी वजह से उसे अनेक राज्यों में अपेक्षा से कम सीटें मिलीं। ऐसे में केंद्र में निरंतर तीसरी बार सरकार बनाने वाली भाजपा को इठलाने के बजाय गंभीरता से अपनी खामियों पर विचार-मंथन कर अपेक्षित सुधार करने की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उप्र, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खोने वाली भाजपा को निकट भविष्य में उप्र सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में नई ऊर्जा से युक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए नए सिरे से चुनावी समीकरण बनाने होंगे। इसके लिए एनडीए घटक दलों के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दिशा-निर्देश प्राप्त करना भी अपेक्षित है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

कुपित विपक्ष

देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी को विश्व के पचास से ज्यादा शासनाध्यक्षों द्वारा बधाई संदेश प्रेषित किए गए, लेकिन देश के विपक्षी महागठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं द्वारा बधाई संदेश देना तो दूर स्वयं ही 99 के आंकड़े और भ्रम की राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। निस्संदेह ऐसी नकारात्मक राजनीति मनभेद एवं राग-द्वेष की छिछली राजनीति को चरितार्थ करती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी टीडीपी और जेडीयू को आइएनडीआइए में आने का खुला निमंत्रण दे रहे हैं। बस किसी भी तरह एनडीए का प्री पोल एलांयस टूट जाए। कुल मिलाकर विपक्षी दलों का एक ही ख्याली पुलाव है कि किसी भी तरह छीका टूट जाए और सत्ता की मलाई खाने को मिल जाए।

दीपक गौतम, सोनीपत

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

स्थिर मस्तिष्क परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है

आंतरिक सुरक्षा को खतरा

रियासी के बाद जम्मू संभाग के कठुआ और डोडा में आतंकी हमले गंभीर चिंता का कारण बनने चाहिए। ये हमले यही बता रहे हैं कि आतंकी बेलगाम होते जा रहे हैं और वे जम्मू क्षेत्र में वैसे ही हालात पैदा कर रहे हैं, जैसे एक समय उन्होंने दक्षिण कश्मीर में कर दिए थे। इस नतीजे पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू के उन इलाकों को अपने निशाने पर ले लिया है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। यह सामान्य बात नहीं कि आतंकियों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ जाए कि वे 60 घंटे के अंदर तीन जगहों पर हमले करने में समर्थ रहें। उन्होंने न केवल निर्दोष-निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, बल्कि सुरक्षाकर्मियों को भी। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी होगी। ऐसी किसी कार्रवाई के ठोस नतीजे तब हासिल होंगे, जब पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि उसकी शह पर ही जम्मू में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि दो आतंकियों को मार गिराया गया, क्योंकि यह साफ है कि जम्मू के विभिन्न इलाकों में पाकिस्तान से आए अनेक आतंकी छिपे हुए हैं। चिंता की बात केवल यह नहीं है कि जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि देश-विदेश में भारत विरोधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां पंजाब में खालिस्तान समर्थक नए सिरे से सिर उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली आदि में भी। भारतीय प्रधानमंत्री की इटली यात्रा के पूर्व वहां खालिस्तान समर्थकों ने गांधीजी की प्रतिमा को जिस तरह खंडित किया, वह एक तरह से अलगाववादी तत्वों की ओर से भारत को दी जाने वाली सीधी चुनौती है। भारत सरकार को पंजाब एवं जम्मू-कश्मीर में और अधिक सतर्कता बरतने के साथ उन देशों से भी दो टूक बात करनी होगी, जहां खालिस्तान समर्थक बेलगाम हो रहे हैं। भारत सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि लोकसभा चुनाव के पहले सार्वजनिक स्थलों पर बम रखे होने की झूठी सूचनाएं देकर दहशत फैलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले स्कूलों में बम रखे जाने की झूठी सूचनाएं दी गईं, फिर अस्पतालों में। इसके बाद विमानों में और अब संग्रहालयों में। चिंताजनक यह है कि ऐसी झूठी सूचनाएं देकर सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द बढ़ाने वाले तत्वों की पहचान नहीं हो रही है। माना जाता है कि ऐसे तत्व दूसरे देशों में छिपे हुए हैं। सच जो भी हो, भारत सरकार को आंतरिक सुरक्षा पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनावों में कश्मीर और पंजाब में कई ऐसे अलगाववादी तत्व चुनाव जीतने में समर्थ रहे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

गंभीरता से कार्रवाई जरूरी

किसी भी मामले में अगर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हो तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। पकड़े गए मानव तस्करों पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से ही बिहार में किशोरियों की तस्करी जैसे अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। गत दिवस मधुबनी में नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) की सतर्कता की वजह से मुजफ्फरपुर की दो किशोरियां तस्करों के चंगुल से मुक्त तो करा करा ली गईं, लेकिन उनके जाल में ये पहुंचीं कैसे, यह पता लगाना अभी बाकी है। अगर एसएसबी सीमा पर जांच नहीं करती तो ये किशोरियां नेपाल में बेच दी जातीं। जानकारी मिली है कि मुक्त कराई गईं इन किशोरियों को तस्करों ने दरभंगा की एक महिला से खरीदा था। पकड़े गए तस्करों को मधुबनी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब पुलिस को गंभीरता दिखानी होगी। वह शीघ्रता से मामले की जांच करे और कड़ी से कड़ी जोड़कर इसकी जड़ तक पहुंचे। पुलिस को यह पता करना चाहिए कि ये किशोरियां उस महिला के पास आखिर पहुंचीं कैसे। किसने उक्त किशोरियों को उस महिला के पास भेजा। अगर पुलिस मामले की तह में जाकर सरगना तक पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से ऐसी कई अन्य किशोरियां बिकने से बच जाएंगी। कहने की जरूरत नहीं कि तस्कर गरीब परिवार की बच्चियों को ही निशाना बनाते हैं। इन्हें अमीर बनाने के झूठे वादे कर देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में धकेल देते हैं। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में पहले भी युवतियों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आ चुका है। पकड़े जाने पर कई लड़कियों को मुक्त भी कराया गया, लेकिन असली सरगना तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ही इस तरह की घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं।

> पुलिस गंभीरता से मामले की जांच करे और पकड़े गए मानव तस्करों पर कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से इस तरह के कुकृत्य पर लगाम लग जाएगी।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या विभागों के बंटवारे से स्पष्ट है कि मोदी सरकार सहयोगी दलों के दबाव से मुक्त है?

आज का सवाल

क्या प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों को उनके पुराने विभाग देने का फैसला सही है?

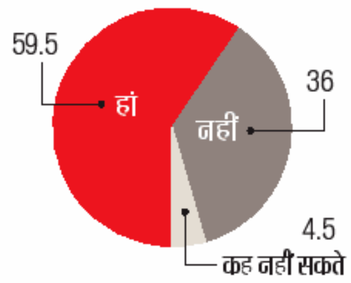

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सुधारों पर सहमति बनाने का समय

जीएन वाजपेयी

बहुदलीय लोकतंत्र में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना एक चतुराई भरा काम है। चूंकि इसमें समय लगता है, इसलिए धैर्य की परीक्षा भी होती है

आम चुनाव के नतीजों की तरह-तरह से व्याख्या हो चुकी है और यह सिलसिला अब भी कायम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव परिणाम कुछ अनपेक्षित रहे। प्रतीत होता है कि आर्थिक दुश्वारियां, बेरोजगारी एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरे और संविधान बदलने जैसे नैरेटिव ने नतीजों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जनमत को व्यापक रूप से प्रभावित किया। भारतीय राष्ट्र के निर्माताओं का यह स्वप्न था कि देश प्रगति के शिखर को छुए। अंडमान की एक यात्रा के दौरान मुझे एक स्वतंत्रता सेनानी का यह संदेश पढ़ने को मिला कि 'कृपया उन्हें यह बताना कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब उनकी बारी है।' जिन क्रांतिकारी ने यह संदेश लिखा था, उन्हें फांसी होने वाली थी। उन्होंने यह संदेश अंडमान से रिहा होकर गांव जाने वाले अपने साथी को दिया था कि वह ग्रामीणों के नाम उनका यह संदेश दें। मौजूदा पीढ़ी को भी उस संदेश के व्यापक मर्म को समझते हुए देश में विपन्नता के दायरे को समाप्त कर उसे समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए उसे प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। मौजूदा सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो अगले 23 वर्षों तक कम से कम सात प्रतिशत या उससे अधिक की औसत सालाना जीडीपी वृद्धि दर हासिल करनी होगी।

जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से तीन उत्पादन कारकों-भूमि, श्रम और पूंजी की उपलब्धता एवं उत्पादकता से प्रभावित होती है। भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यापक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य यह मांग करता है कि इन तीनों कारकों के बीच उचित समन्वय, दूरदर्शी नियोजन और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जहां पूंजी दक्षता के मामले में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है, वहीं वह श्रम उत्पादकता के मोर्चे पर पिछड़ा हुआ है। 2017 की क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के आधार पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2022 में श्रम उत्पादकता के मोर्चे पर भारत को 126वें स्थान पर रखा था। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि भूमि की उपलब्धता एवं लागत बुनियादी ढांचा विकास और उद्योगीकरण की राह में अवरोध बने हुए हैं। जीडीपी वृद्धि दर की गति बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की क्षमताएं भी एक बाधा बनी हुई हैं। यदि कृषि क्षेत्र का योगदान भी मैन्यूफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों के अनुपात में बढ़ जाए तो 2024 की जीडीपी वृद्धि दर 10 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर जाएगी। वास्तव में ये तीनों क्षेत्र व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कार्यकाल में इस तात्कालिक आवश्यकता को समझते हुए अपनी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगाकर सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन सहमति के अभाव में ऐसे सुधार अधर में अटक गए।

अवधेश राजपूत

भूमि, श्रम और कृषि भावनात्मक मुद्दे हैं। भारत के जीवंत बहुदलीय लोकतंत्र में भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक सहमति बनाना एक बहुत चतुराई भरा काम है। चूंकि इसमें समय लगता है अतः धैर्य की परीक्षा भी होती है। एक समय नगालैंड में मुख्यमंत्री के पूर्ण वरदहस्त के साथ राज्य के मुख्य सचिव आरएस पांडेय ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसे क्षेत्रों में 'कम्युनिटाइजेशन' यानी समुदायों की भूमिका को बढ़ावा दिया था। यह कवायद विभिन्न समुदायों के नेताओं, राजनीतिक दलों, मीडिया से लेकर विभिन्न प्राधिकरणों जैसे तमाम अंशभागियों के सहयोग से संपन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था ने भी उसका संज्ञान लिया था। मोदी ने भी 2017 में जीएसटी जैसी सार्वभौमिक कर व्यवस्था के सूत्रपात के साथ ऐसा करिश्मा कर दिखाया था। पूर्व की कई सरकारें यह नहीं कर पाईं। मोदी के नेतृत्व में एक लंबी कवायद के बाद ऐसी व्यवस्था की राह में लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध दूर हुआ। तत्कालीन वित्त सचिव ने बताया था कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जीएसटी को लेकर समझ बनाने में कैसी भूमिका निभाई और कितने धैर्य का परिचय दिया। मोदी 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहरा रहे हैं। यह भारत के आर्थिक उत्थान की राष्ट्रीय इच्छा का प्रतीक है। यह आह्वान सभी दलों को प्रेरित करने वाला बने कि वे अपने संकीर्ण हितों को पीछे छोड़कर विकसित राष्ट्र बनाने के बिंदुओं पर सहमति के साथ आगे बढ़ें।

कारोबार को सुगम बनाने की राह में वास्तविक कुंजी अनुबंधों के प्रवर्तन में निहित है। किसी अनुबंध के प्रवर्तन में औसतन 1445 दिन का समय लगता है और लागत में 31.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखती है। अपने देश में आम नागरिक न्यायिक अक्षमताओं से भी कुछ त्रस्त हो चुका है। न्यायपालिका व्यापक सुधारों की मांग कर रही है। इसमें देरी से तंत्र के प्रति भरोसा और घटेगा। यहां भी किसी प्रकार के कायाकल्प के लिए न्यायाधीशों, वकीलों, नेताओं और नागरिक समाज से जुड़े संस्थानों सरीखे विभिन्न अंशभागियों के बीच सहमति आवश्यक होगी।

बढ़ती आर्थिक असमानता चिंता बढ़ा रही है। यह असमानता मुख्य रूप से दो श्रेणियों में है। एक तो अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और दूसरी राज्यों के स्तर पर। आर्थिक असमानता समान अवसरों के अभाव से उपजती है। जबकि संविधान की प्रस्तावना ही प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता की उद्घोषणा करती है। नागरिक प्रशासन के पास नीतियों के क्रियान्वयन का दायित्व है, जो अपनी न्यूनतम दक्षता से काम करता है, जिससे लोगों में निराशा विशेषकर वंचितों में असंतोष उत्पन्न होता है। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए जिस नौकरशाही की संकल्पना की गई थी, उसे नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है। विभिन्न राज्यों के बीच आय एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के स्तर पर बढ़ रही असमानता को भी जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन, निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाना और क्रियान्वयन क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इन सुधारों के अभाव में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न दूर की कौड़ी ही सिद्ध होगा।

भारत की जनता अपनी नई सरकार के भावी कदमों की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही है। तमाम लोग प्रचंड गर्मी के दौरान जान जोखिम में डालकर सरकार चुनने के लिए वोट डालने बाहर निकले। यदि लोगों को सरकार से निराशा हाथ लगती है तो उनकी पीड़ा आक्रोश में बदल सकती है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

निराधार थे लोकतंत्र पर उठे सवाल

गिरीश्वर मिश्र

हाल के संसदीय चुनावों में लोकतंत्र और ईवीएम पर जो सवाल उठे, उन्हें नतीजों ने गलत साबित किया

विश्व के सबसे बड़े चुनाव के दौरान देश की जनता को भारतीय लोकतंत्र की चाल-ढाल की विलक्षण छटाएं देखने को मिलीं। 11 लाख और 8 लाख से अधिक के अंतर से लोग जीते तो नोटा का भी इस्तेमाल किया गया। निर्वाचन आयोग पर तोहमतें लगती रहीं, पर उसने मुस्तैदी से और निष्पक्षता से कार्य किया। संविधान, लोकतंत्र और ईवीएम पर सवाल उठे, लेकिन नतीजों ने ऐसा करने वालों को गलत साबित कर आईना दिखाया। नतीजे बता रहे कि भारतीय लोकतंत्र को कहीं कोई खतरा नहीं। चुनावी सरगर्मी कभी नर्म-गर्म रही तो कभी तल्ख हुई। एक ओर से अतिरेक का उत्तर भी अतिरेक से ही दिया जाता रहा। ऐसे क्षण भी आए, जब शिष्टाचार की मर्यादाएं टूटती नजर आईं। इस ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उचित ही टिप्पणी की। निर्वाचन आयोग ने प्रचारकों को सख्त हिदायत दी और कुछ को प्रचार कार्य से अलग भी किया। सत्ताधारी दल में अतिआत्मविश्वास था कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। उसे सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा तो मिला, लेकिन पिछली बार से कम सीटें ही मिल सकीं। मोदी काल में कई मोर्चों पर सक्रियता का ही फल है कि छह दशक पहले का इतिहास दोहराते हुए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग लगातार तीसरी बार सरकार बना सका। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया।

चुनाव में तमाम सवाल उठे। सनातन और राम-मंदिर निर्माण को लेकर भी अनर्गल प्रश्न उछलते रहे। विपक्षी दलों ने अपनी शक्ति-सामर्थ्य के बिंदु गिनाने में जितना श्रम किया, उससे अधिक विरोधी के छिद्रान्वेषण में लगाया। शक्ति और सामर्थ्य के नाम पर दिवास्वप्न सरीखे प्रलोभनों की यह लंबी सूची तैयार की जाती रही कि अगर सरकार बन गई तो किसे क्या-क्या दिया जाएगा। चुनाव के बीच अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक के विवाद को भी तूल दिया गया। बहुसंख्यक होने से हिंदू और हिंदुत्व को संशयग्रस्त पहचान के रूप में स्थापित करना और अल्पसंख्यक के लिए खतरे से रक्षा का नाटक अपने वोट सुरक्षित करने के लिए किया जाता रहा। यह राष्ट्र बोध और देश, संस्कृति सभ्यता सबको हाशिए पर धकेलने का उपक्रम बन गया।

हमेशा की तरह जाति को लेकर टिकट बांटने और मतदाताओं को अपने पक्ष में लेने की कोशिश सभी दलों ने की। जाति समाज की एक सच्चाई है और सभी दल उसकी निंदा करते हैं, परंतु उसी का सहारा भी लेते हैं। चुनाव नतीजों ने जाति के बनते-बिगड़ते समीकरणों की भूमिका फिर दिखा दी। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दे भी छाए रहे। इसके बाद भी सबके मन में केंद्र में एक मजबूत सरकार लाने की इच्छा थी। भाजपा को इससे लाभ मिला। भाजपा दक्षिण भारत में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रही। चुनाव परिणाम जनता के विश्वासमत की पुष्टि करते हैं। परिणाम इसके परिचायक हैं कि लोकतंत्र के भविष्य को लेकर जो सवाल-संदेह उठाए जा रहे थे, वे निराधार थे। संदेह जताने वालों को जनता ने यही जवाब दिया कि यह महज एक दुष्प्रचार ही था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। करीब 64 करोड़ वोटों के आधार पर आए नतीजे ये बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र सबल है और उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं।

बेवजह बदनाम किया गया ईवीएम को • प्रेट्र

चुनावों में कई पार्टियों के दावों, वादों, आरोप-प्रत्यारोप की भाषा जमीनी वास्तविकताओं की जगह दिवास्वप्न को रेखांकित कर रही थी। इससे जनता के सामने चकित, भ्रमित और भयभीत होने की स्थितियां भी आती रहीं। लोकतंत्र के आसन्न विनाश, संविधान का समापन, आरक्षण नीति पर ग्रहण आदि से जुड़ा दुष्प्रचार तथा राजकीय तंत्र के दुरुपयोग से जुड़े आरोपों को लेकर भारत में लोकतंत्र के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया जाता रहा। हास्यास्पद टिप्पणियों और तर्कहीन अधकचरे प्रस्तावों के साथ कर्ज माफी, विभिन्न समुदायों को सहायता राशि की सौगातें बांटने, आरक्षण की सीमा घटाने-बढ़ाने और उसे पंथ-समुदाय की सदस्यता से जोड़ने की घोषणाओं से जनता को लुभाने के प्रयास किए जाते रहे। चूंकि मोदी सरकार ने एक दशक में जमीनी परिस्थिति को बदलने का काम किया था, इसलिए इसका सीधा अनुभव जनता को हुआ था। इस बार का जनादेश मोदी की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता की पुष्टि करता है। अमृतकाल में विकसित भारत का संकल्प लेकर उस दिशा में अग्रसर होने को उद्यत मोदी भारत के प्रतिनिधि के रूप में अब पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं।

एक समर्थ, शक्तिशाली और संभावनाशील भारत की छवि को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की रीति-नीति परीक्षा की कसौटी पर कसी जाएगी। महंगाई और रोजगार के सवाल नीतिगत हस्तक्षेप की मांग करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय अभी भी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जहां अतिरिक्त संसाधनों का निवेश और व्यवस्थागत परिवर्तन स्वाभाविक हो गए हैं। यदि समाज, विशेषतः युवा वर्ग स्वस्थ और सुशिक्षित नहीं होगा तो विकास के सपने अपूर्ण रह जाएंगे। इससे इन्कार नहीं कि ये विषय अभी भी उपेक्षित हैं। इसी तरह से न्याय व्यवस्था और उसके कायदे-कानून तकनीकी दृष्टि से बड़े पेचीदा, खर्चीले और अनावश्यक रूप से समयसाध्य बने हुए हैं, जिनसे न्याय पाने में विलंब होता है और लोग बेवजह सताए जाते हैं। इनमें जरूरी बदलाव अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह व्यवस्थागत सुधार ले आने की आवश्यकता भी सभी महसूस करते हैं। नौकरशाही के जोर के आगे उसमें बदलाव लाना टेढ़ी खीर है, पर उसे करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की खाई पाटना भी सरल नहीं है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश की आकांक्षाओं को आकार देने का ऐतिहासिक कार्य प्रभावी नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। आशा है नई सरकार इन प्रश्नों पर प्राथमिकता से ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी।

(लेखक प्रोफेसर एवं कुलपति रहे हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

स्व की पहचान

जीवन में आपकी महत्ता तभी बढ़ सकती है जब आपको स्वयं अपना महत्व पता हो। इसके लिए स्वयं को समझना होगा। जीवन को आगे बढ़ाने और उसके साथ कदमताल के लिए खुद की पहचान इतनी आवश्यक है कि उसी से हमें अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं का भलीभांति भान होता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति मूल्यवान है। इसीलिए हम सभी को सम्मान के साथ व्यवहार करने और यह व्यक्त करने का अधिकार है कि हम वास्तव में कौन हैं? जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो प्रायः बेहतर निर्णय लेते हैं। अपने अनूठे और विशेष गुणों को अपनाना सीखें। अपने लिए खड़े हों और अपनी इच्छानुसार जीवन जिएं।

अगर आप खुद को दूसरों के सामने कठपुतली बना देंगे तो लोग आपका अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करने लगते हैं। इस परिस्थिति में आप सामने वाले के द्वारा उपयोगिता समाप्त होने के बाद दूध में मक्खी की भांति बाहर कर दिए जाएंगे। जब तक आपको इसकी भनक लगे तब तक संभवतः बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए अपने करीबियों के व्यवहार पर सदैव दृष्टि बनाए रखनी चाहिए कि सुख की अवस्था में और दुख की अवस्था में आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था। आपमें इतनी क्षमता एवं बुद्धिमत्ता अवश्य होनी चाहिए कि आप दूसरों का उचित आकलन कर सकें और समय रहते उनके साथ संबंधों की समीक्षा कर उसी अनुरूप उनसे दूरी या मेलजोल बढ़ा सकें।

जीवन में अधिक सहज महसूस करने के लिए अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ पूर्ण ध्यान दें। जैसे आप दूसरों के लिए किसी भी परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं, वैसे ही आप अपने लिए भी हमेशा खड़े रहें। जीवन में सदैव सकारात्मक और संतोषजनक रिश्ते रखें, जिसमें दोनों साझेदारों को महत्व और सम्मान दिया जाता हो। ऐसे संबंध, जिनमें अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप समझौता न करना पड़े। यह सब स्वयं को पहचानने से ही संभव होगा।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

निरंतरता को प्राथमिकता

'निरंतरता के साथ बदलाव भी जरूरी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव सचान का आकलन बिल्कुल ठीक है कि नई सरकार को कुछ नवीनता की अनुभूति कराने के लिए परिवर्तन भी करने चाहिए थे। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोर टीम में कोई बदलाव नहीं किया और विभिन्न मंत्रालयों में जारी सुधारवादी कदमों में निरंतरता का भाव बनाए रखने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी अनुभूति होनी चाहिए कि उनकी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए। इनमें कुछ दिग्गज नाम भी शामिल हैं। इसलिए थोड़े-बहुत परिवर्तन किए जाने चाहिए थे। अभी भी कुछ मंत्रियों पर कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व है और ये सभी विभाग स्वतंत्र रूप में चलाए जाने के योग्य हैं। संभव है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री के सौ दिनों के एजेंडे को सिरे चढ़ाने का एक पहलू हो। उल्लेखनीय है कि पिछले कार्यकाल के शुरुआती सौ दिनों में भी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार से भी कुछ इसी प्रकार की अपेक्षाएं हैं।

केशव तिवारी, आजमगढ़

दबाव में नहीं दिखती सरकार

संपादकीय आलेख 'काम पर सरकार' पढ़ा। दबाव और सौदेबाजी की राजनीति से इतर एनडीए की सरकार के त्वरित काम-काज को देखकर यह नहीं लग रहा है कि इस सरकार पर सहयोगियों का कोई दबाव है। कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद राक मेमोरियल में 45 घंटे तक मौन साधना की समाप्ति के बाद ऊर्जा से भरे पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के रोड मैप की तैयारियों को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की थी। चुनाव की घोषणा से पहले पीएम मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों को अगली सरकार के 100 दिन के कामकाज का रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी रोड मैप को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने पुराने सहयोगियों को अपने पुराने मंत्रालय में ही काम करने का निर्देश दिया है। पीएम ने चुनाव के पूर्व और चुनावी रैलियों में एक बात बार-बार आत्मविश्वास से कही थी कि उनकी तीसरी पारी कुछ अलग होगी। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि नरेन्द्र मोदी अपना विजन अगले पचीस साल का लेकर चल रहे हैं, जिसमें देश को एक सशक्त बुनियादी ढांचा और आर्थिक मजबूती देने का उद्देश्य समाहित है। भारत की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर ले जाने और देश को विकसित करने के जूनून को पूरा करने के लिए पीएम मोदी काम के अलावा और कुछ नहीं सोचते। यह उनके निरंतर प्रयास में साफ परिलक्षित होता है। वे विरोधियों पर टीका-टिप्पणी से बचना चाहते हैं, इसका सदुपयोग वे देश के विकास में करना पसंद करते हैं। तीसरी बार कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला पीएम किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किश्त जारी करने को लेकर किया। इसका लाभ 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा, उनके बैंक खातों में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। नई सरकार का फोकस पहले 100 दिनों में कृषि क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया में गति और किसानों को उपज का सही मूल्य व उनके कल्याण पर होगा। यह अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिखेगा।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

राष्ट्रहित सर्वोपरि

शंकर शरण द्वारा लिखित आलेख 'संघवाद पर राष्ट्रीय सहमति बने' पढ़ा। सभी राजनीतिक दलों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। आजादी के उपरांत संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की, साथ ही राज्यों को भी कई प्रमुख विषयों पर विशेषाधिकार प्रदान किए। कभी-कभी राज्यों को प्रदान किया गया विशेषाधिकार राष्ट्रहित के मार्ग में अड़ंगा पैदा करता है, तो कभी-कभी केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने का कार्य करती है। इससे राज्य की जनता एक योग्य शासक से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर राज्य सरकार को बर्खास्त किया है, एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता कायम की है। कई बार राजनीतिक दल अपने मनोनुकूल व्यक्ति को राज्य पर थोप देती है, इससे जनता एक योग्य मुख्यमंत्री से वंचित रह जाती है। बंगाल में घुसपैठियों की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देश में मतांतरण की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है, लेकिन कई राजनीतिक दल इस गंभीर खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। राष्ट्र की एकता जैसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए राज्य और केंद्र के बीच राष्ट्रीय मुद्दों पर सहमति की आवश्यकता है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

आंध्र प्रदेश की फिल्में हों या वहां आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण जैसे राजनीतिक समारोह, भारतीय संस्कृति की असली झलक इनमें ही दिखाई पड़ती है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

तीन दिनों के दौरान जम्मू में तीन आतंकी हमले हुए। पहले रियासी, फिर कठुआ और डोडा। जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव अब आतंकियों के निशाने पर हैं। यह सब कुछ पाकिस्तान की शह पर हो रहा है।

शालिनी कपूर तिवारी@ShaliniKTiwari

पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हों या फिर पूर्व विधायक संगीत सोम, ऐसे उदाहरण भाजपा के भीतर चल रहे कई अंतर्द्वंद्वों की तरफ इशारा करते हैं। खुलकर बोलने दिया जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आएंगे। चिंताजनक यही है कि पार्टी इन्हें बंद कमरे में सुलझाने के बजाय बाहर इनका तमाशा बनने दे रही है।

द सोशल साइंटिस्ट@socially321

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से कौशल विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। भारत को यदि अपनी युवा आबादी और जनसांख्यिकी का लाभ उठाना है तो इस विभाग को सक्रियता से अपनी भूमिका निभानी होगी।

राजीव कुमार मिश्रा@rajivjournalist

जनपथ

झूठे वादे ठोक कर लिया थोक में वोट,
अब महिलाएं कह रहीं हमें दीजिए नोट।
हमें दीजिए नोट खोट है यही हमारी,
कर लेती विश्वास सहज जनता बेचारी।
हम भारत के लोग बहुत ही सीधे सादे,
तभी जीतते लोग ठोक कर झूठे वादे!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 62

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 13 जून 2024

राजनीति इतना गंभीर मसला है कि इसे राजनेताओं पर नहीं छोड़ सकते।
-चार्ल्स डी गॉल

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में तीन आतंकी घटनाएं होना आतंकियों और उनके आका की हताशा व बौखलाहट को ही दर्शाता है। देश के सुरक्षा बल इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है।

बौखलाहट के हमले

बीते रविवार की शाम जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के दो दिनों के भीतर एक ही रात में पहले कठुआ और फिर डोडा जिलों में हुए आतंकी हमले आतंकियों की बौखलाहट को तो दिखाते ही हैं, पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में जारी शांति और सुकून को लेकर उनकी हताशा को भी बयां करते हैं। कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में आतंकियों के पहले हमले और इसके कुछ घंटों बाद डोडा जिले में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की चेक पोस्ट पर हुए दूसरे हमले पर भारतीय सुरक्षा बल स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बावजूद, तीन दिनों में हुई तीनों आतंकी वारदात को देखें, तो इनमें कई श्रद्धालुओं की मौत और एक जवान का बलिदान होना वाकई दुखद है। दरअसल, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की बदली स्थितियां पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहीं और इसी वजह से उसके द्वारा समर्थित आतंकी गुटों ने इस क्षेत्र में अपनी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, जबकि सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों में वहां शांति व सद्भाव का नया अध्याय शुरू हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है और सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान तो हुआ ही, पर्यटकों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में अस्सी लाख से ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे व रोजमर्रा की दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी व अव्यवस्था के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलन तो कर ही रहे थे, भारतीय ध्वज का समर्थन करना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, बलूचिस्तान में भी लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जाहिर है कि इससे पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और भी अधिक बौखला गया है। रविवार को हुए हमलों की जिम्मेदारी जहां पाकिस्तान से संचालित हो रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट

टीआरएफ ने ली थी, तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी गुट ने ली है, जो जैश-ए-मोहम्मद का ही एक गुट है। पहले जहां आतंकी घटनाएं कश्मीर घाटी के क्षेत्र तक सीमित रहती थीं, पिछले दिनों हुई वारदात दिखाती हैं कि अब जम्मू क्षेत्र पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो वाकई चिंताजनक है। देश के सुरक्षा बल ऐसे आतंकी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आसन्न घोषणा को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी जरूरत है।

पांडियन का पराभव

चुनाव खत्म होने तक हर जगह दिखाई देने वाले पांडियन ने परिणाम आने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि पार्टी में उनके खिलाफ फैले आक्रोश के मद्देनजर यह 'टैक्टिकल रिट्रीट' ज्यादा लगती है और मामला ठंडा होने पर परोक्ष रूप से ही सही, उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

मोहन चरण माझी ने ओडिशा में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, लेकिन इन चुनावों में चर्चाओं में रहे आईएएस अफसर से नेता बने वीके पांडियन की अविश्वसनीय कहानी की मिसाल भारतीय राजनीति में पहले शायद ही कभी देखी गई होगी। राजनीति में इतना छोटा कॅरिअर भी शायद ही किसी और नेता का होगा। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद 27 नवंबर, 2023 को उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया और ओडिशा के तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल (बीजद) में शामिल हुए। लेकिन चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद नौ जून को उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर डाला। उनका राजनीतिक जीवन सिर्फ 195 दिनों का रहा।

संदीप साहू
वरिष्ठ पत्रकार

सन 2000 में आईएएस बनने के बाद वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अपनी मेहनत और लीक से हटकर काम करने की असाधारण क्षमता के कारण उन्होंने खूब प्रशंसा बटोरी। पहले मयूरभंज, फिर गंजाम जिले के कलेक्टर के रूप में उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को लोग आज भी याद करते हैं। दोनों ही जिलों में कामों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया । ये सब थीं एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पांडियन की उपलब्धियां। लेकिन सत्ता की राजनीति में उनका प्रवेश तब हुआ, जब गंजाम के जिलाधीश के रूप में उनके काम से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें सन 2011 में अपना निजी सचिव बनाया। अपनी काबिलियत के जरिये पांडियन ने नवीन का विश्वास जीता और धीरे-धीरे अपनी काया विस्तार करने लगे ।

2019 में लगातार पांचवीं बार चुनाव जीतने के बाद नवीन पटनायक ने सरकार को अधिक लोकाभिमुखी करने के लिए 5टी (टीमवर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमलाइन) नामक एक नया विभाग खोला और पांडियन को इसका सचिव बना दिया। सरकार के सभी विभागों को इस नए विभाग के अंदर लाया गया। इसके बाद सरकार में

पांडियन का दबदबा और भी बढ़ गया। पांडियन के नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्हें इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, ताकि सरकार में उनकी पकड़ बनी रहे। और 2019 के चुनाव के बाद नवीन ने अपने निवास से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया और दल व सरकार दोनों का पूरा जिम्मा पांडियन को सौंप दिया। कोविड के बाद मुख्यमंत्री न सचिवालय गए, न विधानसभा। कैबिनेट की बैठक में भी वे वीडियो लिंक के जरिये अध्यक्षता करने लगे। अपने दल के नेता, मंत्री, विधायकों से मिलना उन्होंने लगभग बंद कर दिया। यहां तक कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के लिए भी सलाह-मशवरे के लिए मुख्यमंत्री से मिलना दूभर हो गया और वे पांडियन के आदेश पर काम करने लगे।

अब पांडियन की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह राज्य सरकार के चॉपर का इस्तेमाल कर पूरे राज्य का दौरा करने लगे। बहाना था कि लोगों से उनकी शिकायतें लेकर तत्काल कार्रवाई करना। बाद में पता चला कि पांडियन राजनीति में प्रवेश करने के लिए अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। वह जहां भी गए पूरा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेता, विधायक और मंत्री उनकी सेवा करते हुए नजर आए। मंच पर पांडियन के अलावा कोई भी देखने को नहीं मिला। साफ था कि उनकी ताजपोशी की तैयारी चल रही थी। इस बात की जमकर चर्चा हुई कि वह नवीन के उत्तराधिकारी हैं। नवीन ने ऐसी चर्चाओं का खंडन करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे ओडिशा के लोगों में यह धारणा और भी पुख्ता होती गई कि नवीन ने पांडियन को अपना उत्तराधिकारी बनाने का मन बना लिया है। इस धारणा को तब और बल मिला, जब पांडियन ने औपचारिक रूप से बीजद में योगदान किया। इस वर्ष मार्च में जब बीजद और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, तब बीजद की ओर से पांडियन ही इसके सूत्रधार थे। प्रेक्षकों का मानना था कि भाजपा से गठबंधन कर वह अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि नवीन के डर से पार्टी के जो नेता चुप बैठे हैं, वे नवीन के बाद उनके खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे, तब उन्हें भाजपा के समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि बात बनी नहीं और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी।

इस बार चुनाव का पूरा मोर्चा पांडियन ने संभाला। उम्मीदवारों के चयन से लेकर रणनीति तैयार करने और आर्थिक संसाधन के उपयोग से लेकर मीडिया कैंपेन तक लगभग सब कुछ उन्हीं की देखरेख में हुआ। करीब डेढ़ महीने के चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर अकेले पांडियन ही प्रचार करते नजर आए। मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक बीच-बीच में उनके साथ प्रचार के लिए जाते रहे, लेकिन पार्टी के 40 'स्टार प्रचारकों' में से 38 पूरे चुनाव के दौरान नदारद रहे। और पार्टी को इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा। भाजपा ने भी एक सोची-समझी रणनीति के तहत 'ओड़िया अस्मिता' को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा नेता हर आमसभा में इसी बात को दोहराते रहे कि नवीन साढ़े चार करोड़ ओड़िया लोगों की अस्मिता को पैरों तले रौंदते हुए तमिलनाडु में जन्मे एक आदमी को ओडिशा के लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा की यह रणनीति काम कर गई। राज्य में चौथे और अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले नवीन ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

चुनाव में हार के बाद अब तक सहमे हुए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब पांडियन को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ खुलकर नारेबाजी करने लगे हैं। चुनाव खत्म होने तक हर जगह दिखाई देने वाले पांडियन परिणाम आने के बाद से कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद नवीन ने पांडियन को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहराने या उनकी निंदा करने से साफ इन्कार कर दिया है। इसके उलट उन्होंने पांडियन की जमकर प्रशंसा की है और उनके खिलाफ हो रही बयानबाजी को अनुचित बताया है। नवीन के इसी आचरण और उच्चारण के कारण राजनीति से संन्यास लेने की पांडियन की घोषणा के बाद भी बहुत कम लोग यह मानने के लिए तैयार हैं कि अब राजनीति में कभी उनकी वापसी नहीं होगी। ज्यादातर प्रेक्षक मानते हैं कि पार्टी में उनके खिलाफ फैले आक्रोश के मद्देनजर यह एक 'टैक्टिकल रिट्रीट' भर है और मामला ठंडा होने पर प्रत्यक्ष नहीं, तो परोक्ष रूप से उनकी वापसी की पूरी संभावना है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

स्वामी विवेकानंद

सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए।

दुर्बलता ही मनुष्य को गुलाम बनाती है

हमारे जीवन में एक बड़ा दोष यह है कि हम आदर्श से बेहद आकर्षित रहते हैं। लक्ष्य ही हमारे लिए इतना ज्यादा आकर्षक और मोहक हो जाता है और हमारे मानस पर इतना विशाल बन जाता है कि इन सबके चलते बारीकियां हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। लेकिन असफलता मिलने पर हम यदि बारीकी से इसकी छानबीन करें, तो निन्यानबे प्रतिशत यही पाएंगे कि असफलता का प्रमुख कारण साधनों की ओर ध्यान न दिया जाना था। इसलिए हमें जरूरत है अपने साधनों को पुष्ट कर उन्हें पूर्ण बनाने की। यदि हमारे साधन बिल्कुल ठीक हैं, तो साध्य की प्राप्ति निश्चित ही होगी। हम यह भूल जाते हैं कि कारण ही कार्य का जन्मदाता है। कार्य स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब तक कारण अभीष्ट, समुचित और सशक्त न हों, कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि कारण के विषय में हम सावधान रहें, तो कार्य स्वतः ही सम्पन्न हो जाएगा।

इसलिए साधन की ओर ध्यान देते रहना जीवन का एक बड़ा रहस्य है।

हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम कोई काम हाथ में लेते हैं और उसमें पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसमें असफलता मिलने पर भी उसे छोड़ते नहीं हैं। हम जानते हैं कि उससे हमें नुकसान हो रहा है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर पा रहे, उससे चिपके हुए हैं। यह ठीक वैसा ही है, जैसे मधुमक्खी आई तो शहद पीने थी, लेकिन उसके पैर ही शहद में धंस गए और फिर वह वहां से निकल नहीं सकती। यही हमारे अस्तित्व का संपूर्ण रहस्य है। यही आसक्ति है, जो दुख की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में छोटी-छोटी बातों में यह चीज मौजूद है और हम इसे अनुभव भी करते हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है-निरंतर काम करते रहो, पर बंधन में मत पड़ो, आसक्त मत हो। प्रत्येक वस्तु से अपने को स्वतंत्र बना लेने की शक्ति स्वयं में संचित रखो। कोई वस्तु तुम्हें कितनी प्यारी क्यों न हो, तुम्हारा मन उसके लिए कितना ही लालायित क्यों न हो, उसे त्यागने में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, फिर भी उसे त्यागने की शक्ति को अपने भीतर संजोए रखो। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सारे शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सत्य यह है कि बल ही अनंत सुख है, अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। पर आसक्ति ही हमारे सुखों की जननी भी है। हम अपने मित्रों, सगे-संबंधियों में आसक्त रहते हैं। हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों में आसक्त रहते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनसे हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी और कारण से हम पर दुख आता है? इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अनासक्त होना चाहिए।

अनासक्ति की शक्ति

सूत्र

यदि हमारे भीतर इच्छामात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती, तो हमें कभी दुख नहीं होता। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है, जो किसी वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्ति के साथ लगा देने के साथ ही, अपनी इच्छा से उससे अलग होने की शक्ति भी जुटा लेता है। सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का रहस्य यही है कि बदले में कुछ भी न चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति ही सबसे सफल व्यक्ति होता है।

दूसरा पहलू

लाइलाज बीमारी से लड़ते हुए चालीस साल की महिला ने दिखाया कि इलाज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आत्मबल।

अपार्टमेंट की खिड़कियां साफ रहने लगी हैं

वह (गुप्त नाम) चालीस वर्ष की थी। अपने अपार्टमेंट की गंदी खिड़कियां देख रही थी। वह उन्हें साफ करना चाहती थी। चालीस वर्ष की उम्र इतनी भी नहीं होती कि कोई कुर्सी से खड़ा भी न हो सके। लेकिन यह काम उसके लिए असंभव था। वह जानती थी कि अगर वह खड़ी हो भी गई, तो कुछ ही मिनट में उसके पैर कांपने लगेंगे और वह गिर पड़ेगी। जब वह अपनी उम्र के पहले ही दशक में थी, तभी उसे पता चला कि वह लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एलजीएमडी) रोग से पीड़ित है।

लिसा सैंडर्स, एमडी

वह अपनी उम्र के पहले ही दशक में थी, तभी उसे पता चला कि वह लिम्ब-गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (एलजीएमडी) रोग से पीड़ित है।

डॉ. पप्पास ने ही उसे बताया कि उसकी बीमारी लाइलाज नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दवाएं चलीं। कुछ ही महीने में फर्क दिखने लगा।

यह मांसपेशियों का एक वंशानुगत विकार है, जिसमें मरीज अपने बाल काढ़ने व दांतों को ब्रश करने में भी असमर्थ हो जाता है। उसके इस दर्द को सिर्फ डॉ. मैरी लिन चू ही समझती थीं, जो एनवाईयू लैंगोन ऑर्थोपेडिक अस्पताल में बाल चिकित्सा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसोसिएशन केयर सेंटर की चिकित्सा निदेशक हैं और शुरुआत से ही इस महिला का इलाज कर रही हैं। चू इस महिला के बारे में सब जानती हैं। उसकी मां ने बैले नृत्य, ताइक्वांडो और टैप डांसिंग सिखाने के लिए भेजा, ताकि उसके हाथ-पैर में ताकत आए, लेकिन कोई फायदा नहीं। न्यूयॉर्क शहर का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था, जिसे उसे दिखाया न गया हो। आखिरकार एक डॉक्टर ने बताया कि उसे लाइलाज एलजीएमडी है। तब एक दिन, उसकी डॉक्टर मेरी लिन ने उससे कहा कि वह किसी जेनेटिक काउंसलर से मिले। लेकिन वर्षों से इस बीमारी से लड़ते-लड़ते वह इतना थक गई थी कि वह कहीं जाना नहीं चाहती थी। मेरी लिन के समझाने पर उसने जीनों की जांच कराई, लेकिन रिपोर्ट नकारात्मक आई। मेरी लिन ने हिम्मत नहीं हारी और न ही उसने। दो साल बाद, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन की तरफ से उसकी जांच हुई, लेकिन सब बेकार। उसने सोच लिया कि वह अब कभी कोई परीक्षण नहीं कराएगी। वह टूट चुकी थी। लेकिन उस रोज, जब वह खिड़कियां भी साफ नहीं कर पाई, उसने सोच लिया कि वह लड़ेगी इस बीमारी से। डॉ. मैरी लिन ने उसे लैंगोन बाल रोग विभाग में क्लिनिक जेनेटिक्स के प्रमुख डॉ. जॉन पप्पास के पास भेजा। जांच हुई। तीन महीने बाद डॉ. पप्पास का फोन आया। उसे दरअसल जन्मजात मायस्थेनिक सिंड्रोम यानी सीएमएस नामक बीमारी थी, जो एक खास जीन में असामान्यता की वजह से होती है। डॉ. पप्पास ने ही उसे बताया कि उसकी बीमारी लाइलाज नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी दवाएं चलीं। कुछ ही महीने में फर्क दिखने लगा। अब उसके अपार्टमेंट की खिड़कियां साफ रहने लगी हैं।

©The New York Times 2024

आंकड़े

पढ़ी-लिखी सरकार

नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 71 मंत्रियों में 80 फीसदी मंत्री स्नातक या इससे ज्यादा शिक्षित हैं। 2019 में यह आंकड़ा 84 फीसदी था।

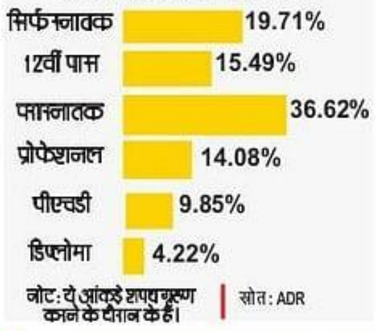

नोट: ये आंकड़े शपथ ग्रहण कराने के दौरान के हैं। | स्रोत: ADR

मां के कहने पर बालक उपमन्यु ने घोर तप किया। पिशाचों के बाधा डालने पर भी वह डिगे नहीं। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए।

शिव ने उपमन्यु को दी खीर

अंतर्यात्रा

संकलित

महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र उपमन्यु ने एक दिन अपनी मां से दूध मांगा। मां ने चावल का आटा घोलकर बेटे को दिया। उन्होंने कहा कि मां यह दूध तो नहीं है। मां बोलीं-बेटा, हम तपस्वियों को यहां दूध कहां से मिल सकता है। यदि तुम दूध चाहते हो, तो भगवान शिव को प्रसन्न करो। उपमन्यु ने पूछा, वे कैसे प्रसन्न होंगे। मां ने कहा, नमःशिवाय महामंत्र का जाप करो।

माता के उपदेश से उपमन्यु घर से निकल गए। उन्होंने घोर तप किया, पर पिशाच बाधा डालने लगे। उपमन्यु डरे नहीं। उल्टा नमःशिवाय मंत्र सुनकर पिशाचों को मुक्ति मिल गई। उपमन्यु का तप बढ़ने पर भगवान शिव भक्त की परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में पहुंचे। उन्होंने कहा- बालक हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बताओ क्या चाहिए। उपमन्यु ने कहा, देवराज हमें भगवान शिव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। काफी जतन के बाद भी बालक उपमन्यु नहीं डिगे, तो इंद्र के वेश में भोलेनाथ भगवान शिव की निंदा करने लगे।

भगवान की निंदा सुनने पर उपमन्यु क्रोधित हो गए और इंद्र को भस्म करने के लिए आग्नेय धारण करने लगे। यह देख भगवान शिव असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा आज से तुम्हारे सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तुम मेरे अनन्य भक्त हो। भोलेनाथ ने दूध-भात से बनी खीर उपमन्यु को प्रदान की। मान्यता है कि उपमन्यु ने ही भगवान श्रीकृष्ण को शिवमंत्र की दीक्षा दी थी।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 03 जून, 1955

गुलाम मुहम्मद योजना भारत को अमान्य

गुलाम मुहम्मद योजना भारत को अमान्य नेहरूजी ने ठोस प्रस्ताव रखे

भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर वार्ता हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के अमेरिकी कैंप में शामिल होने से अब स्थिति दूसरी हो गई है। भारत को गुलाम मुहम्मद की योजना अमान्य है।

अपनी ही जिंदगी से यह कैसी लापरवाही

अप्रैल से जून तक बर्फ पिघलती है। स्थानीय लोग भी जुलाई से सितंबर के बीच सहस्रताल जाते हैं। बिना जानकारी ट्रैकिंग जानलेवा साबित होती है।

सुरेश भाई

पहाड़

बीते 29 मई को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सिल्ला गांव की ओर कुस-कल्याण होते हुए सहस्रताल (14,500 फुट) तक ट्रैकिंग के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के 22 लोग बर्फीली हवा में फंस गए थे, जिनमें छह महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हो गई। शेष 13 लोगों को राज्य एवं केंद्र सरकार की आपदा प्रबंधन एजेंसी और वायुसेना की मदद से बचाया गया।

वर्ष 2021 में आईटीबीपी पेट्रोलिंग के दौरान हिमस्खलन से तीन कुलियों की मौत हो गई थी। वर्ष 2022 में द्रौपदी का डांडा-2 चोटी पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन में 28 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2023 में रूनसारा-ताला ट्रैक और गंगोत्री कालिंदी खाल में तीन ट्रैकर्स की मौत हो गई थी, जबकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया था। हिमालय में साहसिक पर्यटन और पर्वतारोहण के लिए लाखों देशी-विदेशी सैलानी प्रतिवर्ष ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियों पर पहुंचकर

गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन पीढ़ियों से रह रहे स्थानीय लोग ही बता सकते हैं कि किस महीने में किस चोटी पर जाना अधिक उचित और सुरक्षित हो सकता है। स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष सहस्रताल पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई पार करते हैं। लेकिन उनके वहां जाने का समय जुलाई के अंतिम सप्ताह से सितंबर के अंत तक है। वहां ऐसे अनेकों रास्ते हैं, जहां से बहुत सारे लोग बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। अप्रैल से जून तक तेजी से बर्फ पिघलने का समय होता है, इसलिए बर्फीले तूफान भी आते हैं। जुलाई के बाद बारिश होने से बर्फीले तूफान की गति धीमी पड़ जाती है और बर्फ पिघलना कम हो जाता है। इन महीनों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बहुत पतली वर्षा देखने को मिलती है, जिसमें भीगने पर पर्यटकों को आनंद महसूस होता है। यहां ब्रह्मकमल के पुष्प और बुग्याल के मनोरम दृश्य, सामने ऊंची चोटियों पर चांदी की तरह चमकने वाली बर्फ स्वर्ग का एहसास कराती है। सहस्रताल ग्लेशियर लगभग 40 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 'सहस्रताल' नाम इसलिए है कि यहां पर बर्फ की सैकड़ों झीलें हैं, जहां से धर्मगंगा, बालगंगा, भिलंगना, पिलंगना जैसी पवित्र नदियां बहकर टिहरी बांध के जलाशय में भागीरथी में मिलती हैं। इसलिए सहस्रताल ट्रैकिंग के लिए टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध तीर्थ बूढ़ा केदारनाथ और भिलंग से होकर भी जाते हैं।

चूंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, इसलिए 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वहां पहुंचने में कठिनाई होती है। यहां ट्रैकिंग पर निकले 22 लोगों की टीम में चार लोग 60 वर्ष से ऊपर थे, जिनका पहले स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं किया गया था। उनके पास ट्रैकिंग संबंधी पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने एक स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसी पर रोक लगाई है, क्योंकि उसने 22 ट्रैकर्स के साथ मात्र तीन पोर्टल गाइड ही भेजे थे। इसके लिए कोई 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) भी नहीं बनाई गई है। सच्चाई यह भी है कि स्थानीय ट्रैकिंग एजेंसियों का काम सिंगल विंडो सिस्टम में पंजीकरण और गाइड उपलब्ध कराने तक ही सीमित है। बड़ी ट्रैकिंग कंपनियों से कम बजट मिलने से भी स्थानीय एजेंसियां नियमों के पालन पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं। स्थानीय मौसम और उपयुक्त समय को नजर अंदाज करने वाली बंगलूरू, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे, कोलकाता आदि की मुनाफाखोर ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां जाने के लिए पर्वतारोहण जैसे अभियान के स्तर की तैयारी होनी चाहिए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमन भदौरिया कहते हैं कि ट्रैकिंग व पर्वतारोहण अभियान के दौरान मौसम पूर्वानुमान लेना जरूरी होता है। जलवायु परिवर्तन के दौर में कम और अनुभवहीन कर्मचारी को 20-25 पर्यटकों को संभालने का दायित्व सौंपना खतरनाक हो सकता है।

हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पर्यटकों के पहुंचने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वे जंगल की लकड़ी से खाना बनाकर आग भी नहीं बुझाते और कूड़ा-कचरा भी छोड़कर चले आते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम में ट्रैकिंग अनुभव और बीमा की निगरानी व परीक्षण की तो कोई बात ही नहीं है। इसके लिए अब एसओपी बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर अब भी लापरवाही बरती गई, तो सैलानियों के जीवन की सुरक्षा मुश्किल में पड़ जाएगी।

कल्पमेधा

किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक तर्क को यह विश्वास न हो जाए कि वह पूजनीय है।

– वाल्तेयर

साख पर सवाल

चिकित्सा विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा यानी नीट में धांधली के आरोपों को सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। उसने राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी यानी एनटीए से इस मामले से जुड़े सवालों का जवाब देने को कहा है। दरअसल, इस बार की नीट परीक्षा के नतीजों में कई तरह की विसंगतियां देखी गई हैं। जब परीक्षा ली गई, तब बिहार और राजस्थान के कुछ केंद्रों पर गलत पर्चे बांट दिए गए थे। बाद में उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। तब विद्यार्थियों ने आरोप लगाया था कि पर्चाफोड़ हुआ है, परीक्षा रद्द कर दुबारा कराई जानी चाहिए। लेकिन एनटीए ने इससे इनकार कर दिया। उसका कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से गलत पर्चा बंट गया था। फिर नतीजे तय तिथि से दस दिन पहले ही घोषित कर दिए गए। नतीजों में सड़सठ विद्यार्थियों को पूरे सात सौ बीस अंक मिले हैं। यह पहली बार हुआ है। एनटीए का कहना है कि जिन विद्यार्थियों को देर से पर्चे मिले, उन्हें समय की हानि होने के चलते कृपांक दिए गए। उसका क्या आधार है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

हालांकि एनटीए अब भी अपनी बात पर कायम है कि पर्चाफोड़ नहीं हुआ और न गलत तरीके से किसी विद्यार्थी को अंक दिए गए। परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता और शुचिता बरती गई है। उसका यह तर्क सर्वोच्च न्यायालय के सामने सही ठहर पाता है या नहीं, देखने की बात है। एनटीए ने कृपांक की शिकायतों के समाधान के लिए एक जांच समिति गठित कर दी है, लेकिन उस पर विद्यार्थियों को भरोसा नहीं है। दरअसल, चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दाखिले में धांधली की शिकायतें पुरानी हैं। उन शिकायतों को दूर करने के मकसद से ही एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय किया गया था। एनटीए की बनाई गई व्यवस्था के तहत नीट की परीक्षा के प्रश्नपत्र देश के सभी केंद्रों पर एक साथ विद्यार्थियों को मिलते हैं। उनमें किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम रहने का दावा किया जाता है। फिर भी, जिस तरह एनटीए की दूसरी परीक्षाओं में पर्चे बाहर निकल गए और कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, उससे नीट को लेकर भी आशंका गहरी हुई है। एनटीए को बहुत भरोसेमंद और चाक-चौबंद संस्था माना जाता है, अगर उसकी परीक्षाओं में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, तो स्वाभाविक ही इससे उसकी साख पर सवाल उठते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के पर्चे बाहर होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। न केवल छोटे सरकारी पदों के लिए, बल्कि राज्यों के लोकसेवा आयोगों की परीक्षाओं के भी पर्चे बाहर होने की घटनाएं हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं इसीलिए रद्द करनी पड़ीं कि उनके पर्चे परीक्षा से पहले ही बाहर निकल चुके थे। इसे लेकर पहले उत्तराखंड सरकार ने कड़े कानून बनाए, फिर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाने की घोषणा की। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए हर सरकार कमर कसती दिखती है, लेकिन नकल कराने वालों के हौसले पस्त पड़ते नजर नहीं आते। परीक्षाएं रद्द होने से बहुत सारे विद्यार्थियों की मेहनत पर पानी फिरता, उनका मनोबल टूटता और पैसे की बर्बादी होती है। इस हताशा में कई विद्यार्थी खुदकुशी तक का रास्ता अख्तियार करते देखे जा रहे हैं। जब तक सरकारें इस मामले में दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखाएंगी, यह सिलसिला शायद ही रुके।

बदलाव की बयार

ओड़ीशा में चौबीस वर्ष बाद किसी दूसरे दल की सरकार बनी है। पिछले पांच विधानसभा चुनावों से बीजू जनता दल ही लगातार सत्ता में बनी हुई थी। इस बार भाजपा बीजद से अलग होकर स्वतंत्र चुनाव लड़ी और सत्ता में पहुंच गई। यह निस्संदेह वहां के लोगों की बदलाव की आकांक्षा का ही प्रतिफल है। इस तरह भाजपा को भी पूरब में अपनी जगह बनाने का मौका मिला है। पहली बार ओड़ीशा में उसकी सरकार बनी है। नए मुख्यमंत्री के रूप में आदिवासी समाज के मोहन चरण माझी को राज्य की कमान सौंपी गई है। माझी ने शपथग्रहण से पहले ही आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लिया था, उम्मीद है, वे इसे पूरा करेंगे। हालांकि उन्हें चौबीस वर्ष लंबे नवीन पटनायक के कार्यकाल के प्रभाव से लोगों को बाहर निकालना एक चुनौती होगी। लोगों में नवीन पटनायक के कामकाज को लेकर कोई खास नाराजगी नहीं थी, इसलिए भी माझी को कुछ अलग करके दिखाना होगा।

माझी के साथ एक अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी उनकी पार्टी की सरकार है, इसलिए योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में किसी अड़चन की गुंजाइश नहीं रहेगी। हालांकि नवीन पटनायक के भी केंद्र सरकार के साथ रिश्ते कभी कड़वे नहीं रहे। नवीन पटनायक ने ओड़ीशा को बीमारू प्रदेशों की श्रेणी से बाहर निकालने, वहां के लोगों की गरीबी दूर करने, शिक्षा और चिकित्सा आदि के क्षेत्र में बेहतरी के लिए जो विकास परिजनाएं चलाईं और प्रदेश का विकास किया, उसकी सभी सराहना करते हैं। मगर विकास परियोजनाओं के चलते नियमगिरी जैसे कुछ इलाकों के आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण को लेकर जो नाराजगी देखी जा रही थी, उन्हें जरूर माझी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा, एक चुनौती होगी वहां सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने की। नवीन पटनायक सदा एनडीए के साथ रहे, मगर जब कंधमाल में ईसाई मिशनरियों पर हमले हुए तो वे उससे अलग हो गए थे। ओड़िया समाज पर इसका बहुत असर पड़ा था। माझी सरकार उसे कितना सुरक्षित रख पाती है, यह देखने की बात है। अब भी ओड़ीशा की छवि अत्यंत गरीब और पिछड़े प्रदेश की है, उस छवि को माझी कितना बदल पाएंगे, उनकी कामयाबी इसी से आंकी जाएगी।

भूख, भुखमरी और भोजन की बर्बादी

'वैश्विक भूख सूचकांक 2023' के मुताबिक, 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 'भोजन' से जुड़ी दो बेहद महत्त्वपूर्ण रपटें आईं। इनमें एक भोजन की बर्बादी से संबंधित है।

चेतनादित्य आलोक

भारतीय संस्कृति में 'सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद् दुखभाग भवेत्' की भावना के साथ समस्त जीव-जगत के कल्याण की बात कही गई है। वहीं 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना इस संपूर्ण वसुधा को ही एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। हमारी संस्कृति ने जीवन में 'एकल' को स्वीकार करने, उसका मानवर्धन करने या उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई, बल्कि 'एकल' की जगह 'सकल' को स्थापित करने का कार्य किया। हमारे पूर्वजों ने 'व्यष्टि' के स्थान पर 'समष्टि' को महत्त्व और प्राथमिकता दी। हमारे ऋषि-मुनियों ने सिखाया कि इस नश्वर संसार में 'मैं' का कोई महत्त्व नहीं है। यहां तो 'हम' के बिना मनुष्य के जीवन में कुछ होने ही वाला नहीं है। वैसे यह सच है कि मनुष्यता का ऐसा औदात्य भाव, संस्कारों की ऐसी तरलता, सरलता और ऐसी सांस्कृतिक गहराई दुनिया के किसी भी अन्य समाज, संस्कृति या धर्म में नहीं मिलती, जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान तथा हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली प्राण-धारा के समान हैं।

मगर क्या कारण है कि समस्त जीव-जगत के कल्याण की चिंता करने वाला समाज आज स्वयं इतना लापरवाह, लाचार और गैरजिम्मेदार हो गया कि अपने इर्द-गिर्द के भय, भूख, तड़प, पीड़ा, संकट और समाधान से उसका कोई वास्ता ही नहीं रहा। आखिर यह कैसे संभव हुआ कि स्वयं से पहले दूसरों को भोजन कराने वाले समाज में देश के करोड़ों लोगों को आज भी दो जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। 'वैश्विक भूख सूचकांक 2023' के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 'भोजन' से जुड़ी दो बेहद महत्त्वपूर्ण रपटें आईं। इनमें एक भोजन की बर्बादी से संबंधित है और दूसरी भोजन के अभाव और भुखमरी से जुड़ी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भोजन की बर्बादी वाली रपट को अधिक महत्त्व प्रदान करते हुए पहले प्रकाशित किया और भोजन के अभाव यानी भुखमरी वाली रपट को बाद में जारी किया।

संभव है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा सोचा भी न हो और इन रपटों के आगे और पीछे होने का कारण महज कोई तकनीकि अवरोध, अड़चन या उन समितियों की कार्य प्रणाली रही हो, जो इन्हें तैयार करती हैं, क्योंकि रपटों के प्रकाशन की प्रक्रिया से कई मानवीय, तकनीकि और यांत्रिक पहलू भी जुड़े होते हैं, पर यह सच है कि कहीं न कहीं भोजन के अभाव का संबंध भोजन की बर्बादी से है। हालांकि भोजन के अभाव के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, पर इस समस्या की शुरुआत भोजन की बर्बादी से ही होती है। इसलिए अगर भोजन की बर्बादी सौ फीसद रोक दी जाए तो भोजन के अभाव की समस्या के बहुत बड़े हिस्से का निदान हो जाएगा।

अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की 'ग्लोबल रिपोर्ट आन फूड क्राइसिस' में बताया गया है कि विश्व भर के कुल इनसठ देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। रपट के अनुसार, युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के हालात के कारण 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को भूखे रहना पड़ा। गौरतलब है कि भोजन के अभाव को लेकर रपट जारी करने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में की थी।

> संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक रपट वर्ष 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण करती है। इस रपट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भुखमरी समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि एक अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 79 किलोग्राम प्रतिवर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है।

गौर करें तो पहली रपट की तुलना में ताजा रपट में भूखे लोगों की संख्या में चार गुना वृद्धि हो चुकी है। साथ ही, खाद्य सामग्री के अभाव में भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। हालांकि भूखे रहने का कारण गरीबी और बेरोजगारी भी हो सकती है, जो भोजन के अभाव और भूख से संबद्ध भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रतीत होती है।

बहरहाल, भुखमरी की समस्या का विश्लेषण करते हुए विश्व भर के विशेषज्ञों ने भूख को समझने के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो के अनुसार इसके कुल पांच चरण हैं। इनमें भूख से सर्वाधिक पीड़ित लोगों को पांचवें चरण में रखा गया है, जिसके अंतर्गत भारत समेत पांच देशों के सत्तर लाख पांच हजार लोग शामिल किए गए हैं। इनमें से अस्सी फीसद यानी सत्तावन लाख सात हजार लोग तो अकेले युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हैं। गौरतलब है कि 'वैश्विक भूख सूचकांक 2023' के अनुसार भुखमरी के शिकार 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है।

जरा सोचिए कि इक्कीसवीं सदी में पहुंच कर भी हमारे देश की पहचान भुखमरी से पीड़ित लोगों वाले देश के रूप में हो रही है, जबकि दूसरी ओर हम दुनिया के तमाम विकसित देशों के समांतर तमाम अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम तक पहुंचाने तथा रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात समेत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा प्रणाली और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक अवदानों को दुनिया भर में स्वीकृति मिल रही है। हम पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य शीघ्र ही कुछ वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है।

मार्च के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की अधीनस्थ इकाई 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यूएनईपी) की 'खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024' की रपट में कहा गया है कि रोजाना दुनिया में जितने लोग भूखे सो जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होटल और रेस्तरां वाले निभाते हैं। रपट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल अनाज उत्पादन का उन्नीस फीसद यानी लगभग 1.05 अरब टन अनाज बर्बाद हो गया था। रपट के अनुसार खेत से थाली तक पहुंचने में तेरह फीसद अनाज बर्बाद हो जाता है।

बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक रपट वर्ष 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण करती है। इस रपट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भुखमरी समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोग गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि एक अरब लोगों का खाना बर्बाद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 79 किलोग्राम प्रतिवर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है, जो दुनिया भर में प्रतिदिन बर्बाद होने वाले कम से कम एक अरब लोगों के भोजन की थाली के बराबर है। देखा जाए तो भोजन की बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी है, जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समस्या न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के नुकसान के लिए भी जिम्मेदार है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

सीखना बनाम सिखाना

प्रभात कुमार

दुनिया जानती और मानती है कि पढ़ने-लिखने, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। जबसे सोशल मीडिया ने इंसानी दिमाग पर कब्जा किया है, हर विषय पर सूचनाओं के अंबार लगे हैं। यह साबित हो रहा है कि कुछ भी सीखने की उम्र तो नहीं होती, समय भी नहीं होता। सुबह से शाम तक, चौबीसों घंटे सीखते रहा जा सकता है। दुनिया भर के लोग और खासकर हमारे देशवासी सामाजिक मंच पर ज्यादा जमा हैं। ये लोग हर समय एक-दूसरे को उपदेश दे रहे होते हैं, यानी सिखा रहे होते हैं। उन्हें सुबह शुभदिन का संदेश भेजा जाए, तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपने हाथों से शुभदिन लिख कर यानी मोबाइल के की बोर्ड पर टाइप नहीं करते, बल्कि कहीं से भेजे गए उपदेश को सिर्फ अग्रेषित कर देते हैं, जिनमें कोई न कोई सीख होती है। यह बात दीगर है कि वह सीख आज के माहौल में ऐसी होती है मानो महाभारत के समय में रामायण की सीख पर चलने के लिए आग्रह किया गया हो।

सुबह जल्दी उठें या देर से, दूसरों को सिखाना, बताना और समझाना शुरू हो जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठकर क्या-क्या करें। इस बारे में सैकड़ों लोग सिखा रहे हैं कि नाश्ते में क्या खाएं, दोपहर को क्या और रात का भोजन और भजन कितने बजे करें। आपकी पसंद, सेहत और आर्थिक हालात, सिखाने वालों को पता नहीं होते। उनका नैतिक कर्तव्य तो सुबह से रात तक क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे सिखाना है। खाने के साथ-साथ पोशाक पहनने के बारे में कई पाठ हैं। किस दिन कौन-सा रंग पहनें, किस राशि के लोग कौन से वस्त्र धारण करें, कौन से नक्षत्र में पैदा होने वालों को कौन से रंग के फल और सब्जियां खानी चाहिए।

आशंका है कि शायद आने वाले वक्त में यह बताया जा सकता है कि किस राशि के व्यक्ति को सोमवार को किस आकार के कालर की टीशर्ट या कमीज पहननी चाहिए। मंगलवार को बिना कालर की लाल कमीज पहननी चाहिए या नहीं। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं कि जो बताएं कि रविवार को घर पर खाना नहीं चाहिए। इसी तरह अलग-अलग दिन के लिए अलग रंग के कपड़े पहनना निर्धारित किया जाएगा और बताया जाएगा कि उसे कोई खास कपड़ा पहनना शुभ है या नहीं। पसंद पर इस तरह की धारणाएं और बाजार की मांग या कारोबार हावी रहेंगे। यह बात दीगर है कि बदलते फैशन पर फिल्मी शैली का कब्जा है। कपड़ों के आकार-प्रकार या डिजाइन के मामले में अशालीनता रोजाना नए पहाड़ पर चढ़ना सिखा रही है। किसी की पसंद दूसरों की नापसंद होती है। मसला सुविधा और चुनाव का है, जिस पर बंदिश संभव नहीं है और न ही उचित है।

आसपास सिखाने वालों की कतार लगी है। अब नई और हैरान करने वाली चीजें पकाने वाले दर्जनों लोग सामाजिक मंच पर सक्रिय हैं। उनके बारे में बताने वाले दिन-रात जुटे हुए हैं। यूट्यूब के वीडियो में खाना पकाना, सिखाना और कमाना, प्रतियोगिता में लिपटा व्यवसाय है। रसोई चलाने वाले लाखों लोग इनसे सीख रहे हैं। इतना ज्यादा सिखाया जाने लगा है, लगता है सुनने वाले तमाम लोग बुद्धू हैं। किसी को कुछ पता नहीं है। सिखाने वाले मानते नहीं होंगे कि सभी अपने तरीके से खाना, पीना, पहनना चाहते हैं, उन्हें बस सिखाना है, इसलिए उनकी बातें, लहजा और भाव भी उपदेशक की होती है। वे मान कर चलते हैं कि वे सिखा रहे हैं और बाकी सब लोग सीख रहे हैं।

इससे इतर एक स्थिति यह है कि अधिकांश लोग इस सच को आत्मसात कर चुके हैं कि जिंदगी एक बार मिली है। इसे अपने अंदाज में जीना, मजा लेना जरूरी है। सवाल है कि ऐसे में सिखा रहे लोगों को सुनने वाले लोग सुनने के बावजूद कितना सीखते होंगे? कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने सिखाया कि सफाई करने से पहले जरूरत के मुताबिक सूची बना कर रख लें। यह बताया गया कि कमरा खाली कर सफाई करें। सफाई का पूरा फार्मूला बता दिया गया। जिंदगी तकनीक के शिकंजे में फंसती जा रही है। सुझाया गया कि थकान से बचने के लिए एक दिन में एक ही कमरा साफ करें। पुराने पालिथिन, बोतलें, कपड़े और प्लास्टिक पात्र संभालकर न रखने, बल्कि किसी को देने या बेचने के बारे में सुझाया गया। बाजार ने दबाव बना कर खूब सामान खरीदना सिखा दिया है। जिंदगी में स्वच्छता, पर्यावरण प्रेम, ईमानदारी और अनुशासन बहुत हो गया, अब तो बस सिखाया जा रहा है कि टीशर्ट, कार्डिगन, पैंट या हूडी कैसे तह करें। इसे आसान बनाकर फोटो और वीडियो सहित बताया जा रहा है। घरेलू सफाई के लिए छोटे से छोटे उपाय बताए जा रहे हैं। यानी कोई भी काम हो तो व्यक्ति अपना दिमाग खर्च न करे, बस यूट्यूब या कोई अन्य मंच खोल ले और सब कुछ निर्देशित तरीके से सीख ले।

पहले भी तो संतान होती थी। कितना सहज और सरल था सब कुछ। इतने विकास के बाद भी यह सीखने में कम आता है कि लड़का लड़की समान होते हैं। यह समझाया जा रहा है कि लड़का चाहिए तो क्या, कैसे करें, क्योंकि हमारे समझदार और अति विकसित होते जा रहे समाज की मानसिकता में लड़के की चाहत कम नहीं होती। अब स्कूल-कालेज की पढ़ाई से सीखने का दौर गया, अब तो हर विषय पर वीडियो बनाकर सिखाया जा रहा है। वाट्सएप की दुनिया में अध्यापक बढ़ते जा रहे हैं। सिखाना ज्यादा हो रहा है और सीखना कम। इन सिखाने वालों के लिए अब यह सीखने का वक्त आ गया है कि किसी भी मामले में उपयुक्त, स्तरीय सलाह कैसे और कितनी दी जाती है। मेहनती और तार्किक आधार पर सीखने वालों को भी जागने की जरूरत है।

दुनिया मेरे आगे

> अधिकांश लोग इस सच को आत्मसात कर चुके हैं कि जिंदगी एक बार मिली है। इसे अपने अंदाज में जीना, मजा लेना जरूरी है। सवाल है कि ऐसे में सिखा रहे लोगों को सुनने वाले लोग सुनने के बावजूद कितना सीखते होंगे?

चिंताजनक सिलसिला

संपादकीय 'परीक्षा पर सवाल' (10 जून) अत्यंत अहम है। बड़े दुख का विषय है कि साल-दर-साल और एक के बाद दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे फूटना और अधिकांश ऐसी परीक्षाओं का संदिग्ध पाया जाना, वर्तमान तकनीकी रूप से बेहद संपन्न और विकसित भारत में 'एक सामान्य प्रचलन' बन गया है। प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की शिकायतें मिलती हैं और परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। अक्सर सरकार द्वारा रस्मी तौर पर जांच दलों या जांच आयोगों का गठन किया जाता है, पर उनके निष्कर्ष कभी सामने नहीं आते। नतीजा यह होता है कि यह सिलसिला चलता रहता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं से ऊपर उठकर अब यह घटनाक्रम अखिल भारतीय स्तर पर पहुंच चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने और उनके रद्द होने से जाहिर तौर पर इनमें बैठने वाले छात्रों की वर्षों की जी-तोड़ मेहनत, उनके अभिभावकों का कड़ी मेहनत से कमाया पैसा, उनके तथा परिवारों के असंख्य सुनहरे सपने और सबसे अनमोल 'बेशकीमती समय', सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यह घृणित क्रम समाप्त होना चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

दबाव का मानस

कोटा में अज्ञात भय से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए छात्रावासों आदि में माकूल प्रबंध भी किए गए हैं, मगर नतीजा सिफर ही आ रहा है। हाल ही में एक छात्रा ने 'नीट' का परिणाम आने के बाद पांचवी मंजिल से कूद कर जान दे दी। इस वर्ष की कोटा में यह दसवीं घटना है। दो विद्यार्थी लंबे समय से लापता बताए जा रहे हैं। ये घटनाएं अवसाद की वजह से हो रही हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दबाव कोचिंग का, पालक का या दोनों का रहा है। प्रायः मां-बाप अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें लगा बैठते हैं। कोचिंग संस्थान भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए बच्चों पर दबाव बनाते रहते हैं। इस दोहरे दबाव को बहुत कम बच्चे झेल पाते हैं। ऐसे में ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक हैं। सरकार को संस्थानों और पालकों के बीच सेतु बन कर व्यावहारिक समाधान निकालना होगा, ताकि विषम परिस्थितियों में बच्चों को अवसाद से बचाया जा सके।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

बचपन के दिन

दुनिया मेरे आगे 'बचपन की छुट्टियां' (10 जून) एक बार फिर बचपन में लौटा ले गया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तो उन दिनों पूरे दो महीने की गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थीं और हम सब भाई-बहन बेसब्री से इंतजार किया करते थे कि छुट्टियां कब आएंगी और कब नानी के घर जाएंगे। नानी के घर में मनपसंद खाने-पीने के अलावा, खेलने-कूदने और मस्ती करने की पूरी आजादी होती थी। किताब-कापियों का आज जितना बोझ नहीं हुआ करता था। आज के बदले हुए दौर में परीक्षाओं के बाद अतिरिक्त गतिविधियों के चलते बच्चे नानी के घर जाने के लिए इतने उतावले नहीं दिखाई देते हैं। परीक्षाओं के बाद, स्कूलों द्वारा शारीरिक और बौद्धिक विकास के नाम पर 'समर कैंप' आयोजित कर बच्चों को पूरे साल व्यस्त रखा जाने लगा है। मां-बाप भी उनके भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहने लगे हैं। इसी के चलते छुट्टियों में नानी के घर जाने का बच्चों में उत्साह कम पड़ता जा रहा है।

– नरेश कानूनगो, देवास

जमीन की सेहत

पर्यावरण जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भूमि, पर्यावरण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। भूमि की उपयोगिता कृषि के साथ-साथ वन्य जीवों के आवास, जल संरक्षण और जलवायु विनियमन में भी होती है। पिछले कुछ दशकों में भूमि का अत्यधिक दोहन और गलत प्रबंधन ने इसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषण के कारण बंजर भूमि का बढ़ना, खाद्य सुरक्षा में कमी और जैव विविधता का नाश होता है। तीव्र सूखा, पानी की कमी, भीषण आग, समुद्र का बढ़ता स्तर, बाढ़, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, विनाशकारी तूफान और घटती जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के परिणामों का ही हिस्सा है। सतत कृषि, मृदा संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से हम भूमि पुनर्स्थापन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

– शंकर सुवन सिंह, प्रयागराज

चिंतन

खालिस्तान समर्थक देशों से दो टूक बात करनी होगी

देश में नब्बे के दशक के बाद से खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन से रह रहकर ऐसी आवाजें आती रहीं। देश में भी बीते पांच सालों के दौरान ऐसी ही चिंगारी को हवा देने की कोशिश हो रही है। इसमें घी का काम किया लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह की जीत ने। असम की जेल में बंद अमृतपाल सिंह का सांसद बनना बताता है कि खालिस्तान आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। असल में 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान दो देश बने। इसी के साथ पंजाब सूबे का बंटवारा हुआ जिसका बड़ा भाग पाकिस्तान के पास चला गया और कुछ हिस्सा हमारे पास बचा। लाहौर, जो कभी सिख साम्राज्य की राजधानी था वो पाकिस्तान में चला गया। इसके बाद पंजाबी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की शुरुआत पंजाबी सूबा आंदोलन से हुई थी। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए और अंत में 1966 में ये मांग मान ली गई। भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। उसी दौर में 'खालिस्तान' के तौर पर स्वायत्त राज्य की मांग उठाई गई जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया। खालिस्तान की मांग ने 1970 के दशक में जोर पकड़ना शुरू कर दिया। 1980-1984 के बीच पंजाब में हिंसा की घटनाओं में भारी उछाल आया। 1983 में भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। तब भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को अंजाम दिया और उसके बाद पंजाब में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की अगुवाई में पूरे आंदोलन को लगभग खत्म कर दिया गया। 1990 के दशक में भारत में तो यह खत्म हो गया, लेकिन कनाडा में जीवित रहा। इसके चलते रह रहकर भारत और कनाडा सरकार के बीच तनाव भी होता रहा। अब एक बार फिर इस आंदोलन को अंदर ही अंदर सुलगाने की कोशिशें हो रही है। अब नया मामला इटली में सामने आया है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले खालिस्तान समर्थकों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया और उसके नीचे हरदीप सिंह निज्जर का नाम भी लिख दिया। निज्जर की बीते दिनों हत्या कर दी गई थी। इटली में 13 से 15 जून तक जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। पीएम मोदी जी7 बैठक में शामिल होने के लिए आज रवाना होंगे। पीएम मोदी, इटली पीएम जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। जी7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जापान के पीएम फुमियो किशिदा और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के अलावा कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे मौके पर खालिस्तान समर्थकों का मूर्ति को तोड़ देना कायरता के अलावा कुछ भी नहीं। इससे पहले आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय दूतावासों, प्रवासियों और मंदिरों पर घृणा से प्रेरित हमलों और अपराधों का सिलसिला साफ दर्शाता है कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य पंजाब में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना है। पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादी प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज करके पंजाब में दोबारा नफरत की आग लगाने की चेष्टा हो रही है। समस्या केवल यह नहीं है कि खालिस्तानी अतिवादियों को उदार पश्चिमी देशों में शरण मिल रही है, बल्कि यह भी है कि वहां की सरकारें इस खतरे की अनदेखी करने में लगी हैं। इस पूरे फसाद की जड़ वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है, जो दशकों से विदेशी धरती पर खालिस्तान समर्थकों को तैयार करने में सक्रिय रही है। यह मामला गिने-चुने सिरफिरे खालिस्तानी कट्टरपंथियों का नहीं, बल्कि भारत के विरुद्ध एक बड़ा विदेशी षड्यंत्र का है। इसे समय रहते ही कुचलना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो न केवल एक बार फिर पंजाब में कानून एवं व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा बल्कि देश की एकता व अखंडता पर भी आंच आएगी। पश्चिमी देशों में रचे जा रहे इस भारत विरोधी प्रपंच से सख्ती से निपटा जाना समय की मांग भी है। हमें ऐसे देशों से दो टूक बात करने होगी जो हमारे दुश्मनों के सहायक बने हुए हैं। इन्हें बताना होगा कि ऐसे तत्वों को शरण देना बंद नहीं किया तो भारत क्या कर सकता है। आज हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। अगर ऐसे देशद्रोहियों न कुचला तो विकसित भारत का संकल्प अधूरा रह जाएगा।

विडंबना
शिशिर शुक्ला

कब रुकेगी परीक्षाओं में धांधली

हाल ही में आयोजित हुई नीट परीक्षा विवादों के घेरे में है। देश के 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर नीट यूजी का आयोजन विगत 5 मई को किया गया था। परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया। परिणाम आने के बाद परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा परिणाम में धांधलेबाजी का आरोप लगाते हुए यह तर्क दिया गया कि परिणाम में 67 अभ्यर्थियों को शीर्ष रैंक के साथ 720 में से पूरे पूरे 720 अंक प्राप्त हुए हैं। खास बात तो यह है कि इसमें हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के छह अभ्यर्थी शामिल हैं। एनटीए के द्वारा परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता का खंडन करते हुए कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों में समय जाया होने के कारण हुई परीक्षा में देरी के कारण 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के कारण अप्रत्याशित परिणाम आया है। एनटीए का यह भी कहना है कि

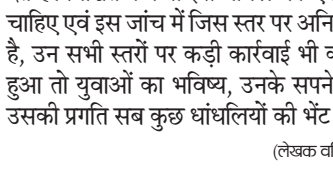

परीक्षार्थियों को कृपांक परीक्षा के नियमों के अनुसार ही दिया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी कि छह केंद्रों पर परीक्षार्थियों को कम समय मिल पाया। कारण यह बताया जाता है कि पहले प्रश्न पत्र गलत वितरित हुआ और उसके बाद जब तक सही प्रश्न पत्र वितरित किया गया तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रश्नपत्र के गलत वितरित होने पर किसको दोषी ठहराया जाना चाहिए। क्यों परीक्षा केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं थीं। यह तो सर्वथा अनुचित है कि परीक्षा केंद्र के द्वारा बरती गई अनियमितताओं की भरपाई अभ्यर्थियों को कृपांक देकर कर दी जाए। क्या कहीं न कहीं यह बाकी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा गहन स्तर पर जांच करके उन कारणों को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया जिनकी वजह से परीक्षार्थियों को परीक्षा हेतु कम समय मिलने जैसी स्थितियां उत्पन्न हुईं। सर्वप्रथम तो ऐसे परीक्षा केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर नेटवर्क के द्वारा परीक्षा में अनियमिताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा कराए जाने की मांग की गई है। नीट जैसी परीक्षा में इस तरह की गड़बड़ियों का पाया जाना निश्चित रूप से पूरे देश के परीक्षा तंत्र को प्रश्न चिह्नों के घेरे में खड़ा कर देता है। महज प्रश्न पत्र गलत वितरित हो जाने की वजह से हुई परीक्षा में देरी के आधार पर परीक्षार्थियों को कृपांक दे दिया जाना अनुचित है क्योंकि इसका सीधा-सीधा नकारात्मक प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है जो कि इस दायरे से बाहर थे। इस बात की क्या गारंटी है कि समय कम मिलने की वजह से उन 1563 अभ्यर्थियों के जो प्रश्न छूट गए थे, पूरा समय मिल जाने पर वे उन प्रश्नों को बिल्कुल ठीक-ठीक हल कर लेते। क्या इन स्थितियों के लिए पूर्णतया परीक्षा केंद्र उत्तरदायी नहीं हैं। आखिरकार ऐसे केंद्रों के हवाले परीक्षा कर देने से पहले किस स्तर पर आकलन एवं परीक्षण किया गया था। कुल मिलाकर अनेक ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा को एवं परीक्षा नियामक एजेंसी को आरोपों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। निश्चित रूप से इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए एवं इस जांच में जिस स्तर पर अनियमितता एवं ढिलाई उजागर होती है, उन सभी स्तरों पर कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवाओं का भविष्य, उनके सपने एवं अंततः देश का भविष्य एवं उसकी प्रगति सब कुछ धांधलियों की भेंट चढ़ जाएंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

निर्यात बढ़ाने की चुनौती

नई सरकार
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में घटते व्यापार के बीच भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में नई सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों सहित दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। देश के विदेश व्यापार को नई दिशाएं देनी होंगी। वस्तुतः इस समय वैश्विक सुस्ती के बीच दुनिया में केवल उन देशों के विदेश व्यापार का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां मजबूत सरकारों ने विदेश व्यापार की चुनौतियों के बीच अपने देश के अनुकूल विदेश व्यापार बढ़ाने के कदम उठाए हैं। नई गठबंधन सरकार को रणनीतिक प्रयास करते रहने होंगे।

आगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार के सामने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं में घटते व्यापार के बीच भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में नई सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों सहित दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात बढ़ाने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। देश के विदेश व्यापार को नई दिशाएं देनी होंगी। वस्तुतः इस समय वैश्विक सुस्ती के बीच दुनिया में केवल उन देशों के विदेश व्यापार का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां मजबूत सरकारों ने विदेश व्यापार की चुनौतियों के बीच अपने देश के अनुकूल विदेश व्यापार बढ़ाने के रणनीतिक कदम उठाए हैं। नई गठबंधन सरकार को ऐसे देशों की तरह लगातार रणनीतिक प्रयास करते रहने होंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों और बेहतर व्यापार की नई संभावनाओं का पहला कदम 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के शीर्ष सात नेताओं को ससम्मान शामिल करके आगे बढ़ा दिया है। इन देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका,नेपाल, मालदीव, सेशेल्स, भूटान तथा मॉरीशस शामिल हैं। निःसंदेह पिछले एक दशक में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए पड़ोसी प्रथम नीति (नेबरहुड फर्स्ट), दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों (आसियान) के साथ एक्ट ईस्ट नीति और प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने की रणनीति सहित नई विदेश व्यापार नीति 2023 लागू की है। जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं।

निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई गठबंधन सरकार को विदेश व्यापार की इन विभिन्न रणनीतियों को बदलते हुए वैश्विक व्यापार के नए दौर के अनुरूप सुधारों के साथ आगे बढ़ाना होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारत के विदेश व्यापार में लगातार वृद्धि के साथ निर्यात की ऊंचाइयां भी बढ़ती गई है। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डॉलर रहा था। जहां पिछले वित्त वर्ष में कुल आयात 854.80 अरब डॉलर का रहा, वहीं वर्ष 22-23 में कुल आयात 898 अरब डॉलर मूल्य का रहा था। ऐसे में पिछले वित्त वर्ष में आयात में कमी से कुल व्यापार घाटे में 36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि देश की प्रभावी सरकार के दम पर ही पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी भारत ने रूस से डिस्काउंट पर कच्चे तेल का आयात करना जारी रखा और कच्चे तेल की रणनीतिक खरीदी से भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 5 अरब डॉलर और 2023-24 में करीब 8 अरब डॉलर की बड़ी बचत की। अब नई गठबंधन सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि विदेश व्यापार मोर्चे पर पिछले कई वर्षों से डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रभावी भूमिका नहीं निभाए जाने से अपने विदेश व्यापार को बढ़ाने के कई अन्य कदम तेजी से आगे बढ़ाए जाने होंगे। गौरतलब है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को की गई थी। इसे दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद एक परिवर्तनकारी वैश्विक आर्थिक-

व्यापार सुधार कहा गया था। वस्तुतः डब्ल्यूटीओ क तहत जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स ऐंड ट्रेड (जीएटीटी) का विस्तार करते हुए सेवाओं और बौद्धिक संपदा को व्यापार में शामिल कर दिया गया था। गरीब और विकासशील देशों को यह विश्वास बना था कि उन्हें डब्ल्यूटीओ की छतरी के नीचे विकास के अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन बहुपक्षीय समझौतों पर प्रगति नहीं होने से डब्ल्यूटीओ के देशों में लगातार हताशा बढ़ी है और वैश्विक व्यापार में धीमापन आने लगा है। ऐसे में भारत के लिए विदेश व्यापार बढ़ाने के प्रयासों को तेजी से बढ़ाना जरूरी है।

यद्यपि पाकिस्तान के रवैये ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को दक्षिण एशिया में आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है, मगर भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से दक्षिण एशिया सहित सबसे कम विकसित देशों को एकतरफा शुल्क मुक्त एवं शुल्क तरजीह योजना की पेशकश की है। भारत-आसियान व्यापार भी बढ़कर वर्ष 2022-23 में 131.58 अरब डॉलर हो गया है। ऐसे में अब नई गठबंधन सरकार को आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। उल्लेखनीय है कि जहां एक ओर 15 नवंबर, 2020 को अस्तित्व में आये दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड समझौतें रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में भारत ने अपने आर्थिक व कारोबारी हितों के मद्देनजर शामिल होना उचित नहीं समझा वहीं आरसेप से दूरी के बाद भारत एफटीए की डगर पर आगे बढ़ने की नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। इस समय भारत विदेश व्यापार नीति को नया मोड़ देते हुए दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अब तक तीन एफटीए किए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मई 2022 में लागू द्विपक्षीय कारोबार में पिछले दो वर्षों में 15 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

अब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की नई संभावनाएं उभर कर दिखाई दे रही हैं। दुनिया के जी-20 देशों में भारत की नई अहमियत और दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और मजबूत सरकार के रूप में भारत की पहचान भारत के विकास को तेज रफ्तार दे रही है। ये सारी बातें भारत के लिए नए एफटीए की नई संभावनाओं की बड़ी आधार हैं। निश्चित रूप से 2024 में जब वैश्विक व्यापार में आर्थिक निराशाओं का दौर बढ़ रहा है, तब भारत को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में अपने रिकॉर्ड विदेश व्यापार और रिकॉर्ड निर्यात का स्तर बनाए रखने के लिए कुछ और रणनीतिक कदम उठाने होंगे। भारत के लिए पड़ोसी देशों, आसियान देशों के साथ विदेश व्यापार बढ़ाने के साथ निर्यात पक्ष को पूरी तरह ध्यान से रखते हुए मुक्त व्यापार समझौतों पर अधिक यकीन करना होगा। भारत के द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने की डगर पर आगे बढ़ना होगा। नई गठबंधन सरकार के द्वारा निर्यात की बढ़ती हुई वैश्विक संभावनाओं को मुट्ठी में लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। नई सरकार चाहिए कि पिछले वर्ष जी-20 में जिस 55 देशों वाले अफ्रीकी संगठन को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाई जाने में भारत के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है, उन देशों में निर्यात बढ़ाने होंगे।

हम उम्मीद करें कि नई गठबंधन सरकार रणनीतिक प्रयासों से वैश्विक व्यापार और निर्यात चुनौतियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से देश को बचाते हुए वर्ष 2030 तक 2 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

अनासक्त हुए बिना करे दूसरों की भलाई

संकलित
दर्शन

यह सोचना भूल है कि हमने संसार का भला किया। इस विचार से दुख उत्पन्न होता है। हम किसी की सहायता करने के बाद सोचते हैं कि वह हमें इसके बदले में धन्यवाद दे, पर वह धन्यवाद नहीं देता, तो हमें दुख होता है। हम जो कुछ भी करें, उसके बदले में किसी चीज की आशा क्यों रखें? बल्कि उल्टे हमें उसी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी हम सहायता करते हैं, उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए। मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है? यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं, तो हमें यह प्रत्याशा जनक कष्ट क्यों होना चाहिए? अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नतापूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं। अनासक्त किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं आएगी। यदि हम यह जान लें कि आसक्ति रहित होकर किस तरह कर्म करना चाहिए, तभी हम दुराग्रह और मतांधता से परे हो सकते हैं। जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे, तभी अच्छी तरह कार्य कर सकोगे। जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है, जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है, जिसके स्नायु सहज ही उत्तेजित नहीं होते तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है, केवल वही व्यक्ति संसार में परोपकार कर सकता है और इस तरह वह अपना भी कल्याण कर सकता है। यह संसार चरित्र गठन की एक विशाल व्यायामशाला है। इसमें हम सभी को अभ्यास रूप में कसरत करनी पड़ती है, जिससे हम आध्यात्मिक बल से अधिकाधिक बलवान बनते रहें।

भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि दुख नहीं आएंगे

संकलित
प्रेरणा

महाभारत युद्ध के बाद का किस्सा है। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उस समय भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर लेटे हुए थे और प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। एक दिन श्रीकृष्ण पांडवों के साथ भीष्म से मिलने पहुंचे। श्रीकृष्ण ने भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दें, ताकि ये अपना राज-पाठ अच्छी तरह चला सके। बातचीत करते समय पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए थे। पांडवों को इस बात की हैरानी हुई कि भीष्म पितामह जैसे महारथी को भी मृत्यु का डर सता रहा है, इस वजह से इनकी आंखों में आंसु आ गए हैं। जबकि इन्हें तो इच्छामृत्यु का वरदान मिला हुआ है। पांडवों के मन की बात समझकर श्रीकृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? श्रीकृष्ण का प्रश्न सुनकर भीष्म ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूं। मेरी आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गए। पांडवों पुत्रों के साथ स्वयं श्रीकृष्ण साथ हैं। फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे। कदम-कदम पर पांडवों के जीवन में मुश्किलें आईं। इन्हें देखकर मुझे समझ आया कि अगर हमारे भगवान हैं, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की मदद से हम दुखों का सामना पूरे साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान हमें दुखों से लड़ने का साहस देंगे।

अंतर्मन

आज की पाती

बाल श्रम का कलंक कैसे मिटेगा?

12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाएगा। बच्चों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों से बचाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कोई भी गरीब माता-पिता नहीं चाहता होगा कि उनके बच्चे छोटी उम्र में दिहाड़ी मजदूरी करें, लेकिन मजबूरी मजदूरी करवाने के लिए विवश कर देती है। जिनके बाप गलत आदतों के शिकार हैं, वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को मजदूरी करने के लिए मजबूर भी करते होंगे। बहुत ही अफसोस और शर्मनाक है कि आज आजाद भारत में छोटे छोटे बाल गरीबी के कारण मजदूरी करने को विवश हैं। आज भारत की बच्चों के कुपोषण के मामले में स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। गरीब लोग भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए सुनहरी सपने देखते हैं, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोगों के सपने चकनाचूर हो जाते हैं।

– *मोहित पाठक, रायगढ़*

ट्रेंड

बाल श्रम के खाते को प्रतिबद्ध

विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर, आइए बाल श्रम को समाप्त करने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें जहां हर बच्चा अपने बचपन का आनंद ले सके। हम बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

-मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री

बाल श्रम

भले ही आज हम बालश्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं, लेकिन जो बात परेशान करती है वह यह है कि हमने बच्चों को विफल कर दिया है। उचित धन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल विजेता

मेरे भगवान गरीब लोग

भारत के लोगों ने कहा है-प्यार ने नफरत को हरा दिया है। मोदी जी के पास अजीब "परमात्मा" है जो उन्हें अडानी-अंबानी के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। मैं एक 'जैविक' इंसान हूं। मेरे भगवान भारत के गरीब लोग हैं। मैं वही करता हूं जो आप मुझे कहते हैं।

-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा

इस देश के करोड़ों मां बाप दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते है, बच्चे पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, मगर देश की सरकार इनका दर्द समझने को तैयार नहीं है। पेपर लीक के कारण करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है।

-संजय सिंह, आप सांसद

करंट अफेयर

नोबल विजेता यूनुस व अन्य पर गबन के आरोप तय

बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 20 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि के गबन मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस और 13 अन्य पर बुधवार को आरोप तय किये। गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद करने के लिए सूक्ष्म ऋण की शुरुआत करने के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित 83 वर्षीय यूनुस ने खुद को निर्दोष बताया। फिलहाल यूनुस जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी उन्हें और उनके अन्य सहयोगियों को 'परेशान' कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया। ढाका के विशेष न्यायाधीश सैयद अराफात हुसैन ने खचाखच भरी अदालत में यूनुस के गैर-लाभकारी 'ग्रामीण टेलीकॉम' पर लगे आरोपों को हटाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष ने यूनुस और अन्य लोगों पर 'ग्रामीण टेलीकॉम' के श्रमिक कल्याण कोष से करीब 20 लाख अमेरिकी डॉलर का गबन करने का आरोप लगाया है। 'ग्रामीण टेलीकॉम' देश की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी 'ग्रामीणफोन' की 34.2 प्रतिशत हिस्सेदार है।

ऑफ बीट

हरियाली देखने भर से ठीक होता है मानसिक स्वास्थ्य

यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रकृति में समय बिताने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को फायदा हो सकता है। लेकिन मेरे सहकर्मियों और मेरे द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि यह लाभ हासिल करने के लिए आपको वास्तव में प्रकृति में रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी शहर के मध्य में भी, केवल प्राकृतिक तत्वों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से भी खुशहाली बढ़ सकती है। शहरी जीवन, अपनी तेज़ गति और तनाव के उच्च स्तर के साथ, चिंता और अवसाद सहित कई मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा हुआ है। प्रतिभागियों को बेतरतीब ढंग से तीन समूहों में बांटा गया : एक जो पेड़ों (हरा समूह) जैसे प्राकृतिक तत्वों पर केंद्रित था, एक जो इमारतों (ग्रे समूह) जैसे मानव निर्मित तत्वों पर केंद्रित था और तीसरा समूह जो दोनों के मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करता था । शहर और परिसर में 45 मिनट की गाइडेड वॉक के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी ने विशेष आई-ट्रैकिंग चश्मा पहना था। मार्ग में समूह के आधार पर प्राकृतिक या मानव निर्मित तत्वों पर जोर देने के लिए डिज़ाइन किए गए दस निर्दिष्ट ठहराव शामिल थे।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://epaper.haribhoomi.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

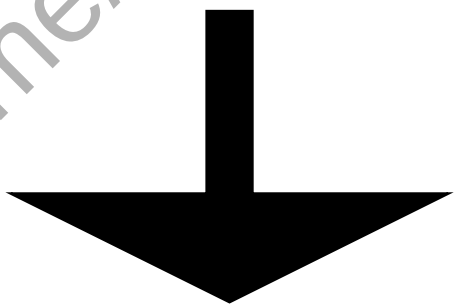

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid